राष्ट्रीय संस्करण

दैनिक जागरण

वर्ष 3 अंक 137

मूल्य ₹6.00, नई दिल्ली, शुक्रवार, 25 अक्टूबर 2019

www.jagran.com

पृष्ठ 16

ॐ धन्वंतरये नमः ।।

हरियाणा और महाराष्ट्र में फिर भाजपा सरकार

- हरियाणा में 40 सीटों पर जीती भाजपा, छह निर्दलीय आए साथ
- हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस को बड़ी सफलता, 31 पर जीत
- चमत्कार के बाद भी किंगमेकर नहीं बन पाए दुष्यंत चौटाला
- महाराष्ट्र में भाजपा-शिवसेना गठबंधन को स्पष्ट बहुमत

जेएनएन, नई दिल्ली: लोकसभा चुनाव में जबर्दस्त जीत के बाद अब हरियाणा और महाराष्ट्र में जनता ने फिर भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार पर मुहर लगा दी है। गुरुवार को आए विधानसभा चुनाव के नतीजे भाजपा के लिए अनुमानों से कमतर रहे, लेकिन पार्टी दोनों राज्यों में सरकार बनाने जा रही है। हरियाणा में 90 में से 40 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी भाजपा को छह निर्दलीयों का समर्थन मिला है। महाराष्ट्र में भाजपा और शिवसेना गठबंधन को 288 में से 161 सीटों पर जीत के साथ स्पष्ट बहुमत मिला है। भाजपा नेतृत्व ने भी दोनों राज्यों में अपने मुख्यमंत्रियों पर भरोसा जताया है। जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर और महाराष्ट्र में देवेंद्र फड़नवीस को फिर कमान सौंपने की पुष्टि की है। मनोहर लाल शुक्रवार को राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे।

हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद गुरुवार को नई दिल्ली भाजपा मुख्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ● प्रेट्र

हरियाणा और महाराष्ट्र के सीएम ने स्वच्छ प्रशासन दिया। दोनों राज्यों की जनता ने भी उन पर भरोसा जताया है। अगले पांच साल उन्हें और मेहनत से जनता की सेवा करनी होगी। - नरेंद्र मोदी

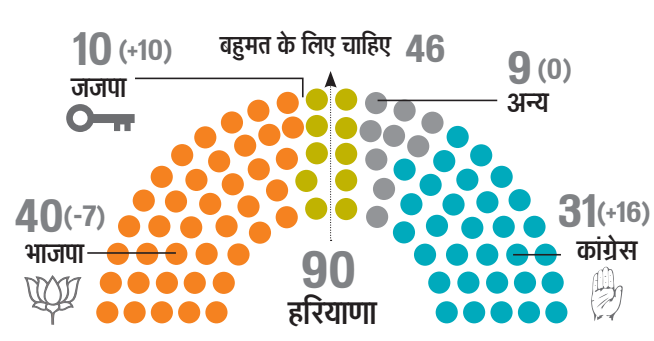

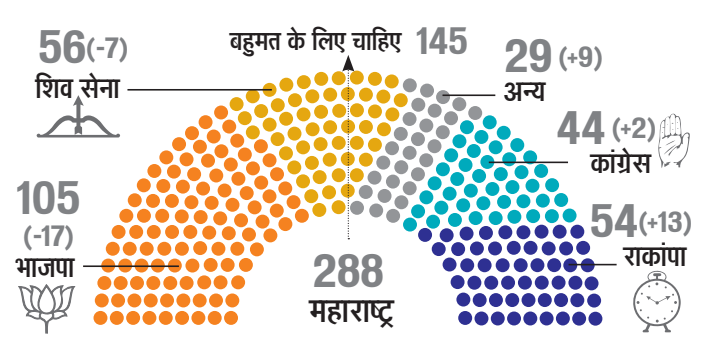

वाले हैं। सीटों के लिहाज से नतीजे भाजपा के लिए थोड़ा निराशाजनक रहे। पिछले साल 47 सीटें जीतने वाली भाजपा 40 सीटों पर आ गई। हरियाणा के नतीजों में भाजपा के लिए सोचने वाली बात यह है कि सात निर्दलीयों में से छह भाजपा से जुड़े रहे हैं। भाजपा के लिए बड़ा झटका यह भी है कि राज्य सरकार में कैबिनेट का हिस्सा रहे आठ मंत्री चुनाव हार गए हैं।

महाराष्ट्र के नतीजे बहुत ज्यादा उलटफेर वाले तो नहीं कहे जा सकते हैं, लेकिन उम्मीदों से दूर जरूर हैं। विश्लेषकों का मानना है कि देश में फैला आर्थिक सुस्ती का साया महाराष्ट्र में भाजपा के नतीजों पर दिखा है। 2014 में अकेले लड़कर 288 में 122 सीटें जीतने वाली भाजपा के खाते में इस बार नतीजों और रुझानों के आधार पर 105 सीटें आती दिख रही हैं। शिवसेना भी 63 से 56 पर आ गई है। सबसे ज्यादा फायदे में शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) रही है। राकांपा का आंकड़ा इस बार 41 से 54 पर पहुंच गया है। सोनिया गांधी के हाथ में दोबारा कमान आने के बाद कांग्रेस भी बढ़त में दिखी। पार्टी को 2014 के 42 के मुकाबले 44 सीट मिली है। नतीजों से सरकार गठन के गणित पर ज्यादा असर पड़ने की उम्मीद नहीं है। हालांकि उपमुख्यमंत्री शिवसेना को मिलेगा या नहीं, इस मुद्दे पर न तो फड़नवीस ने मुंह खोला है, न ही उद्धव ठाकरे ने। फिलहाल उद्धव यह कहकर ताना मारने से नहीं चूके कि जिनके नेत्र बंद थे, उन्हें खोलकर जनता ने अंजन लगा दिया है। उम्मीद है कि अब पीछे की गई गलतियां दोहराई नहीं जाएंगी।

जनादेश (विशेष) >> पेज 4,5

क्या रहे कारण?

हरियाणा

- सीट बंटवारे में जाट समुदाय की अनदेखी भाजपा पर भारी पड़ी
- भाजपा कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर संवाद बनाने में विफल रहे
- बागियों को नहीं साध पाना भी सत्ताधारी दल की विफलता रही
- हुड्डा के हाथ में कमान देना कांग्रेस के लिए फायदेमंद रहा

महाराष्ट्र

- विदर्भ क्षेत्र में कोशिशों के बाद भी किसानों की आत्महत्याएं नहीं रुकीं
- पवार के परिवार पर ईडी का प्रहार मराठा समाज को हजम नहीं हुआ
- भाजपा-शिवसेना गठबंधन के कारण कई दावेदार बागी हो गए
- मंदी और बेरोजगारी का असर भी भाजपा के लिए संकट बना

नतीजों के मायने

- पुरजोर ताकत झोंकने के बाद भी दोनों विधानसभा चुनाव के उम्मीदों से कमतर नतीजे भाजपा को सोचने पर मजबूर करेंगे
- नतीजे यह भी दिखाते हैं कि विस चुनाव में केवल राष्ट्रीय मुद्दे नहीं बल्कि स्थानीय मसलों पर भी तवज्जो की जरूरत
- लोकसभा चुनाव में मिली शिकस्त के बाद कांग्रेस के लिए नतीजे कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने वाले साबित होंगे

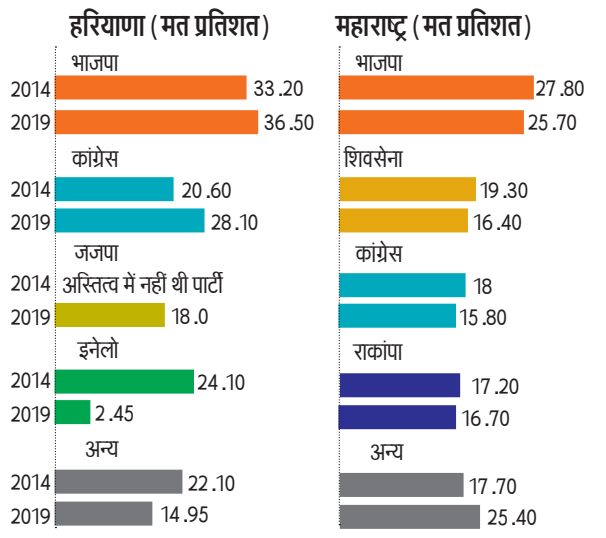

अब आगे क्या होगा?

हरियाणा: भाजपा को सात में से छह निर्दलीयों का समर्थन मिलना तय माना जा रहा है। इससे बहुमत के लिए जरूरी 46 विधायकों का आंकड़ा पूरा हो जाएगा। पार्टी को जजपा का भी साथ मिल सकता है। कांग्रेस के लिए राह मुश्किल है। उसे न केवल जजपा बल्कि पांच निर्दलीयों का साथ जरूरी होगा।

महाराष्ट्र: भाजपा-शिवसेना गठबंधन की सरकार आसानी से बन जाएगी। हालांकि सरकार गठन की शर्तों पर थोड़ा-बहुत पेच फंस सकता है। नतीजों के तुरंत बाद शिवसेना की ओर से आए बयानों में भी ऐसे संकेत मिले हैं।

17 राज्यों में उपचुनावों में ये रही तस्वीर

विधानसभा सीटें	
अरुणाचल प्रदेश (1)	
निर्दलीय	1
असम (4)	
एआइयूडीएफ	1
भाजपा	3
बिहार (5)	
एआइएमआइएम	1
निर्दलीय	1
जदयू	1
राजद	2
छत्तीसगढ़ (1)	
कांग्रेस	1
गुजरात (6)	
भाजपा	3
कांग्रेस	3
हिमाचल प्रदेश (2)	
भाजपा	2
केरल (5)	
माकपा	2
कांग्रेस	2
आइयूएमएल	1
मध्य प्रदेश (1)	
कांग्रेस	1
मेघालय (1)	
यूडीएफ	1
ओडिशा (1)	
बीजद	1
पुडुचेरी (1)	
कांग्रेस	1
तेलंगाना (1)	
टीआरएस	1
पंजाब (4)	
कांग्रेस	3
शिअद	1
राजस्थान (2)	
कांग्रेस	1
रालोपा	1
सिक्किम (3)	
भाजपा	2
एसकेएम	1
तमिलनाडु (2)	
अन्नाद्रमुक	2
उत्तर प्रदेश (11)	
अपना दल (सोनेलाल)	1
भाजपा	7
सपा	3

लोकसभा सीटें					
समस्तीपुर (बिहार)	लोजपा	सतारा (महाराष्ट्र)	राकांपा

सरोकार

आइये मिलकर मनाएं 'यह दिवाली अलग निराली'

नई दिल्ली: यह दिवाली अलग और निराली कैसे मनाएं..., देशभर के हजारों स्कूली

बच्चों ने लंग केयर फाउंडेशन की वेबसाइट एलसीएफ. ओआरजी.इन पर एक से एक उपाय साझा किए हैं। बच्चों ने वीडियो और पोस्टर अपलोड कर दिल को छू जाने वाले सुझाव दिए हैं, जो बताते हैं कि पर्यावरण व स्वास्थ्य संरक्षण उनके लिए प्राथमिक विषय है। (पेज-10)

जागरण विशेष

अठन्नी जिन जाना, इ हौ मइया क खजाना...

वाराणसी: साल में सिर्फ चार दिनों के लिए खुलने वाले काशी के स्वर्णमयी

अन्नपूर्णेश्वरी दरबार में वितरण के लिए इस साल मंदिर प्रबंधन ने 4.50 लाख अठन्नियां (पचास पैसे का सिक्का) मंगाई हैं। अपनी सौभाग्यशाली अठन्नी पाने के लिए देश-विदेश से भक्तों की भीड़ उमड़ आई है। (पेज-10)

ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में शीर्ष 50 के और करीब पहुंचा भारत

- विश्व बैंक की इस वर्ष की रैंकिंग में भारत 77वें से 63वें स्थान पर आया
- जीएसटी को सरल बनाने से रैंकिंग में और सुधार की उम्मीद : सीतारमण

नई दिल्ली में गुरुवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विश्व बैंक द्वारा जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की नवीनतम रैंकिंग पर प्रेसवार्ता की। प्रेट्र

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के क्षेत्र में लंबी छलांग लगाने की कोशिशों के चलते भारत ने फिर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। विश्व बैंक की नवीनतम रैंकिंग में भारत ने 14 पायदान की छलांग लगाते हुए दुनियाभर में 63वां स्थान हासिल किया है। पिछले वर्ष 190 देशों में भारत की रैंकिंग 77वीं थी। ताजा रैंकिंग जारी होने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, जीएसटी को और सरल बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। उम्मीद है इससे रैंकिंग और सुधरेगी। भारत का लक्ष्य अगले वर्ष शीर्ष 50 देशों में शामिल होने का है। सीतारमण ने कहा कि इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए राज्यों को भी गंभीर प्रयास करने होंगे। संपत्ति के रजिस्ट्रेशन को लेकर नियम व प्रक्रिया सरल बनाने की जरूरत है। उन्होंने कहा, अगले वर्ष की रैंकिंग के आकलन में दिल्ली, मुंबई के साथ ही कोलकाता व बेंगलुरु भी शामिल होंगे।

विश्व बैंक के मुताबिक, भारत की रैंकिंग में सुधार की मुख्य वजह दिवालिया कानून को सफलतापूर्वक लागू करना रहा है। लगातार तीसरी बार देश बेहतर प्रदर्शन करने वाले शीर्ष 10 देशों में है। न्यूजीलैंड इस बार भी पहले स्थान पर रहा। सिंगापुर दूसरे, हांगकांगको तीसरा स्थान मिला है। रैंकिंग की इस सूची में अमेरिका छठे नंबर पर है।

रिपोर्ट के मुताबिक, पीएम मोदी के मेक इन इंडिया अभियान ने ना सिर्फ विदेशी निवेश को आकर्षित किया, बल्कि मैन्यूफैक्चरिंग को भी गति दी है। डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के निदेशक सिमोन जानकोव ने कहा, भारत शीर्ष 50 देशों में शामिल होने की राह पर है। शीर्ष 25 में शामिल होने के लिए सरकार को अगले चरण के सुधारों पर काम शुरू करना होगा। रैंकिंग की घोषणा ऐसे वक्त में हुई है जब विश्व बैंक, आइएमएफ और आरबीआइ समेत कई एजेंसियों ने भारत की विकास दर के अनुमान में कमी की है।

नई शिक्षा नीति में बदलाव, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का होगा गठन

नई दिल्ली: प्रस्तावित नई शिक्षा नीति जल्द ही कुछ बदलावों के साथ सामने आएगी। इसकी पूरी तैयारी की जा चुकी है। इसे अंतिम रूप दे दिया गया है। जो बड़े बदलाव सामने आए हैं, उनमें शिक्षा को मजबूती देने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा आयोग की जगह अब राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन सबसे अहम है। (पेज-3)

भारतीय श्रद्धालुओं के लिए साल भर खुला रहेगा करतारपुर कॉरिडोर

गुरदासपुर: पाकिस्तान स्थित गुरुद्वारा श्री करतारपुर साहिब के खुले दर्शन के लिए भारत-पाकिस्तान के बीच बनाए गए कॉरिडोर को लेकर गुरुवार को डेरा बाबा नानक में दोनों देशों के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। अंतरराष्ट्रीय सीमा पर जीरो लाइन पर हुई बैठक में विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय के अधिकारी शामिल थे। (पेज-6)

बांग्लादेश में किशोरी को जिंदा जलाने में 16 को मौत की सजा

ढाका: बांग्लादेश की एक अदालत ने मदरसे में किशोरी को जिंदा जलाने के मामले में गुरुवार को 16 लोगों को मौत की सजा सुनाई। 18 साल की नुसरत जहां रफी ने मदरसे के मौलवी के खिलाफ दुष्कर्म की शिकायत की थी। शिकायत वापस नहीं लेने पर उसे जिंदा जला दिया गया था। इस घटना के खिलाफ देशभर में विरोध प्रदर्शन हुए थे। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने आरोपितों को न्याय के दायरे में लाने का भरोसा दिया था। (पेज-13)

टेलीकॉम कंपनियों को चुकाने होंगे 92,000 करोड़ रुपये

- सुप्रीम कोर्ट ने कहा, एजीआर पर दूरसंचार विभाग की गणना का तरीका सही
- पहले से आर्थिक दबाव झेल रहे सेक्टर पर इस फैसले से पड़ेगी जबर्दस्त मार

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

वित्तीय संकट से गुजर रही टेलीकॉम कंपनियों को सुप्रीम कोर्ट से जबर्दस्त झटका लगा है। कोर्ट ने दूरसंचार विभाग (डीओटी) को तीन प्रमुख टेलीकॉम कंपनियों से एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (एजीआर) मद में 92,000 करोड़ रुपये वसूलने की याचिका को मंजूरी दे दी है। इस बकाए का भुगतान कितने दिनों में किया जाएगा, इसका निर्धारण भी कोर्ट ही करेगा।

सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा, एजीआर में लाइसेंस फीस और स्पेक्ट्रम उपयोग के अलावा अन्य आय भी शामिल करने का डीओटी का तर्क उचित है। जस्टिस अरुण मिश्र की अध्यक्षता वाली तीन जजों की बेंच ने इस संबंध में टेलीकॉम कंपनियों की दलीलों को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा, टेलीकॉम कंपनियों को पूरी राशि ब्याज के साथ विभाग को अदा करनी होगी। अदालत के फैसले का असर शेयर बाजार पर भी दिखा और वोडाफोन आइडिया के शेयर में 19 फीसद की गिरावट दर्ज की गई।

बेंच ने स्पष्ट किया, इस मुद्दे पर अब कोई मुकदमेबाजी नहीं होगी। अदालत इस राशि की गणना और टेलीकॉम कंपनियों के भुगतान की समय सीमा तय करेगी। इसी साल जुलाई में केंद्र सरकार ने कोर्ट को बताया था कि भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और एमटीएनएल व बीएसएनएल पर लाइसेंस फीस का 92,000 करोड़ रुपये बकाया है। नई टेलीकॉम पॉलिसी के तहत टेलीकॉम लाइसेंस में कंपनियों को एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू का एक हिस्सा सरकार के साथ साझा करना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त टेलीकॉम कंपनियों पर स्पेक्ट्रम के प्रयोग के लिए यूसेज चार्जेज देना भी होगा।

टेलीकॉम कंपनियां टीडीसैट के निर्णय के विरोध में शीर्ष अदालत पहुंची थीं। टेलीकॉम डिसप्यूट्स सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल (टीडीसैट) ने फैसले में कहा था कि गैर-टेलीकॉम सेवाओं से प्राप्त रेवेन्यू मसलन किराया, अचल संपत्तियों की बिक्री, लाभांश और ट्रेजरी इनकम को एजीआर में शामिल किया जाना चाहिए। (पेज-12 भी देखें)

इन कंपनियों पर आंच

कंपनी	बकाया
भारती एयरटेल	21,682.13
वोडाफोन	19,823.71
आरकॉम	16,456.47
बीएसएनएल	2,098.72
एमटीएनएल	2,537.48

(नोट : आंकड़े करोड़ रुपये में)

जम्मू-कश्मीर के बीडीसी चुनाव में रिकॉर्ड, 98.3 फीसद मतदान

राज्य ब्यूरो, जम्मू: नए जम्मू-कश्मीर में वाकई बदलाव की बयार बहने लगी है। पहली बार हुए जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में ब्लॉक डेवलपेंट काउंसिल (बीडीसी) के अध्यक्ष पद के चुनाव में 98.3 फीसद पंचों-सरपंचों ने मतदान कर अनुच्छेद 370 को समाप्त करने के फैसले पर मुहर लगा दी। कश्मीर में भी मतदान में खासा उत्साह दिखाई दिया। श्रीनगर में 100 फीसद तो शोपियां में 65 फीसद मतदान हुआ। इसके साथ ही चुनाव में विजयी रहे चेयरमैनों के कंधों पर ग्रामीण विकास की जिम्मेदारी आ गई है।

बीडीसी चुनाव में भाजपा ने शानदार प्रदर्शन दोहराया है। 316 ब्लॉकों में से 307 में हुए चुनाव में भाजपा को 81, कांग्रेस को एक और पैंथर्स पार्टी को आठ सीटें मिलीं। चुनाव में निर्दलीयों का दबदबा रहा। कुल मिलाकर 217 निर्दलीय उम्मीदवार जीतकर सामने आए हैं। इनमें से भी बड़ी संख्या में भाजपा के बागी हैं।

जम्मू-कश्मीर में 22 जिलों में 316 ब्लॉक हैं। इनमें से कोरम पूरा न होने के कारण 9 ब्लॉक में चुनाव नहीं हो सके। प्रदेश में कड़ी सुरक्षा के बीच हुए मतदान में 280 ब्लॉकों में चेयरपर्सन चुने गए। प्रदेश के 27 ब्लॉकों में चेयरपर्सन पहले निर्विरोध चुने गए थे। मतदान की प्रक्रिया सुबह नौ बजे से दोपहर एक बजे तक चली। सुबह 11 बजे तक अधिकतर पंच-सरपंचों ने वोट डाल दिया था। दोपहर तीन बजे मतगणना शुरू हुई थी।

आतंकी धमकियों को दिखाया ठेंगा पेज>>6

बदली तस्वीर

महाराष्ट्र-हरियाणा में सरकार तो इस बार भी भाजपा की बनने जा रही है लेकिन तस्वीर बदली हुई है, जीतने वाले को कसक है, वहीं हारने वाले उत्साहित नजर आ रहे हैं

बड़ी रोचक है विधानसभा चुनावों की यह जीत-हार

त्वरित टिप्पणी

प्रशांत मिश्र

- देवेंद्र फड़नवीस और मनोहर लाल खट्टर फिर से सीएम बनेंगे, पर शक्ति कम हो गई
- मन से हार चुकी कांग्रेस पार्टी ने दोनों राज्यों में बना ली है बढ़त

पांच साल पहले इसी वक्त भाजपा ने महाराष्ट्र और हरियाणा में एक रिकार्ड बनाया था। दोनों राज्यों में भाजपा ने न सिर्फ गौरव के साथ बड़ी जीत हासिल की थी बल्कि पहली बार अपना मुख्यमंत्री बनाया था। वह जीत केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार बनने के चार महीने बाद हुई थी। केंद्र में तो दोबारा नरेंद्र मोदी सरकार और बड़ी संख्या से जीतकर आ गई लेकिन इन दो राज्यों में क्या बदल गया? जीत तो इस बार भी हुई। सरकार भी बनने जा रही है लेकिन बहुत कुछ बदला-बदला सा है। दरअसल, इस बार चेहरा बदल गया। पिछली बार राज्यों में भी चेहरा मोदी ही थे। इस बार देवेंद्र फड़नवीस और मनोहर लाल खट्टर चेहरा थे और जनता ने स्पष्ट कर दिया कि उन्हें उनके प्रदर्शन, उनकी विश्वसनीयता पर परखा जाएगा। दोनों फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं लेकिन शक्ति थोड़ी कम हो गई है। जो नतीजे आए हैं वह विपक्ष की निष्क्रियता के बावजूद हैं। अनुमान लगाया जा सकता है कि अगर विपक्ष स्थानीय मुद्दों के साथ आक्रामक होता और भाजपा में अभियान की कमान मोदी और अमित शाह जैसे सशक्त लोगों पर केंद्रित न होती तो क्या होता। अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कहा जा सकता है कि राहुल गांधी से कमान लेने के बाद सोनिया गांधी ने समझदारी के फैसले लेने की शुरुआत की है। अगर राहुल की लीक पर ही हरियाणा में भूपेंद्र हुड्डा को दूर रखा जाता तो कांग्रेस इस मुकाम पर नहीं पहुंचती कि उत्साह का संचार हो।

महाराष्ट्र में अपेक्षा से काफी नीचे प्रदर्शन की अलग-अलग दलीलें दी जा सकती हैं। कहा जा सकता है कि अलग-अलग लड़े होते तो ज्यादा अच्छा प्रदर्शन होता क्योंकि तब त्रिकोणीय लड़ाई होती और भाजपा के पास आजमाने को ज्यादा सीटें होतीं। अब उस शिवसेना पर निर्भरता बढ़ गई है जिसने रुझान आने के साथ आंखें भी दिखानी शुरू कर दी हैं। सरकार तो बन गई लेकिन वहां मंत्रिमंडल गठन में कितनी खींचतान होगी यह समझा जा सकता है। और हरियाणा...? अभी अभी लोकसभा चुनाव में भाजपा का जो प्रदर्शन था उसके अनुसार भाजपा 80 सीटें जीतती। लेकिन नतीजा आया तो कांटे की टक्कर में फंस गई। वह भी उस कांग्रेस से जो मन से चुनाव हार चुकी थी। आखिर क्या कारण था। प्रदेश नेतृत्व ने केंद्र को सच्चाई नहीं बताई थी? क्या खेमेबाजी फिर हावी रही? या फिर प्रदेश के प्रभावी जाट समुदाय के लिए यह संदेश कि भाजपा में उनके लिए फिलहाल बड़ा स्थान नहीं है, यह भारी पड़ा। ये सभी कारण हो सकते हैं। और केंद्रीय नेतृत्व को इस सभी के जवाब ढूंढने होंगे वरना आश्चर्य नहीं कि दूसरे राज्यों में भी इसका असर दिखे। खासकर दिल्ली में जहां अगले कुछ महीनों में ही चुनाव हैं। और उससे पहले झारखंड में जहां विपक्ष फिलहाल बिखरा हुआ तो है लेकिन मौजूद है। इन दोनों राज्यों के लिए भाजपा को रणनीति तय करनी होगी। भाजपा को एक बात और याद रखनी होगी कि विधानसभा चुनावों में स्थानीय मुद्दों की ज्यादा अहमियत होती है। अगर यह कहा जाए कि केंद्र सरकार के हाल में अनुच्छेद 370 हटाने जैसे फैसले की चर्चा नहीं होती तो स्थिति और खराब हो सकती थी तो गलत नहीं होगा।

अगर विपक्ष के नजरिए से देखा जाए तो उनके लिए पीठ थपथपाने की बात नहीं है क्योंकि भूमिका जनता की है विपक्ष तो खुद हैरत में है। विपक्ष की ओर से ऐसा कुछ नहीं किया गया इसके लिए उन्हें श्रेय दिया जाए। जनता ने प्रदेश सत्ता के खिलाफ थोड़ी नाराजगी जताई। नजारा मतदान के वक्त ही दिख गया था जब लगभग आठ फीसद कम मतदान हुए थे। यह जागने का वक्त है। भाजपा के लिए भी और विपक्ष के लिए भी। भाजपा को अतिविश्वास से बाहर आकर झांकना होगा और विपक्ष को यह अहसास करना होगा कि जमीनी लड़ाई में मजबूती से डटने के लिए संगठन से लेकर नेतृत्व तक मजबूत करने होंगे।

कश्मीर में आतंकियों ने की दो ट्रक चालकों की हत्या

- सुधरते हालात से हताश आतंकी ट्रक चालकों को बना रहे निशाना
- एक चालक लापता, दो ट्रकों और एक लोड कैरियर को लगाई आग

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर

कश्मीर के सुधरते हालात से हताश आतंकियों ने गुरुवार को शोपियां में हमला कर सेब लेने आए दो ट्रक चालकों की हत्या कर दी। हमले में एक अन्य चालक जख्मी है। एक लापता भी बताया जा रहा है। इसके अलावा आतंकियों ने दो ट्रकों और एक लोड कैरियर को आग लगा दी। सुरक्षाबलों ने आतंकियों को पकड़ने के लिए अभियान चलाया है। इसी बीच, पुलिस ने राष्ट्रीय राजमार्ग व दक्षिण कश्मीर के भीतरी इलाकों में सेब लेने गए चालकों को उनके वाहनों समेत निकटवर्ती सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया है। बता दें कि पिछले 15 दिनों में अन्य राज्यों के ट्रक चालकों और सेब व्यापारियों पर तीसरा आतंकी हमला है।

राज्य के पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने बताया कि शोपियां के चित्रीगाम में आतंकियों ने हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के ट्रकों को रोक कर अंधाधुंध फायरिंग की। इसमें दो ट्रक चालकों की मौत हो गई और एक अन्य जख्मी हो गया। मृतकों में एक की पहचान राजस्थान के अलवर निवासी इलियास खान के रूप में हुई है। सूत्रों के अनुसार, दूसरा चालक भी राजस्थान का रहने वाला था। वहीं, हमले में घायल गुरदासपुर (पंजाब) निवासी ट्रक चालक जीवन सिंह को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने बताया कि आतंकियों का निशाना बने ट्रक चालक बिना सुरक्षाबलों को सूचित किए शोपियां के भीतरी इलाके जैनपोरा में अंधेरा होने के बाद अपने वाहन लेकर आ गए थे। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक आतंकी वहां से भाग निकले थे।

596 लोगों के खिलाफ चालान काटे गए उत्तरी, दक्षिणी और पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने। निगमों ने यह कार्रवाई धूल उड़ने, निर्माणाधीन इमारतों पर प्रदूषण से निपटने के लिए पर्याप्त इंतजाम नहीं करने पर की।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
शुक्रवार 25 अक्टूबर 2019

अब दो श्रेणियों में नियमित होंगी अनधिकृत कॉलोनियां

किया बदलाव ▸ उपराज्यपाल की अध्यक्षता में गठित उच्चस्तरीय समिति ने तीन श्रेणियों में बांटने की सिफारिश की थी

डीडीए पार्क तथा सामुदायिक भवन जैसी सुविधाएं भी मुहैया कराएगा

संजीव गुप्ता, नई दिल्ली

लंबी रस्साकशी के बाद अंततः केंद्र सरकार से नियमितीकरण की मंजूरी पाने वाली दिल्ली की 1797 अनधिकृत कॉलोनियों को दो श्रेणियों में बांटा जाएगा। पहली श्रेणी में सरकारी और ग्रामसभा की भूमि पर बसी कॉलोनियां होंगी, जबकि दूसरी श्रेणी में प्राइवेट जमीन पर बसी कॉलोनियां। ग्रामसभा की भूमि पर बसी कॉलोनियों को शहरीकृत गांवों की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। खास बात यह है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ही इन कॉलोनियों को नियमित करने की प्रक्रिया पूरी करेगा। साथ ही इनमें विकास के मानक भी तय करेगा। खाली जमीन चिह्नित कर वहां पार्क तथा सामुदायिक भवन जैसी सुविधाएं भी मुहैया कराएगा।

उपराज्यपाल (एलजी) अनिल बैजल की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति द्वारा केंद्र को सौंपी गई रिपोर्ट में इन अनधिकृत कॉलोनियों को तीन श्रेणियों में बांटने की सिफारिश की गई थी। पहली श्रेणी में वे कॉलोनियां जो सरकारी जमीन पर बसी हैं। दूसरी श्रेणी में वे कॉलोनियां, जो ग्रामसभा की उस जमीन पर बसी हैं, जिस पर सरकार कब्जा नहीं ले सकी। तीसरी श्रेणी में प्राइवेट जमीन पर बसी अनधिकृत कॉलोनियां। लेकिन केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय ने कैबिनेट नोट में पहली और दूसरी श्रेणी को आपस में जोड़कर एक ही श्रेणी बना दिया है। पहली श्रेणी में सरकारी जमीन पर बसी अनधिकृत कॉलोनियां एवं दूसरी श्रेणी में प्राइवेट जमीन पर बसी कॉलोनियां शामिल हैं।

एलजी की रिपोर्ट के आधार पर ही इन कॉलोनियों को नियमित करने के संदर्भ में विकास प्राधिकरण (डीडीए) की बड़ी भूमिका तय की गई है। सबसे पहले डीडीए दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग की मदद से इन कॉलोनियों की रिमोट सेंसिंग और ड्रोन के जरिये मैपिंग करेगा ताकि उनका डाटा अपडेट किया जा सके। इसके बाद एक सिंगल विंडो या पोर्टल शुरू कर शुल्क लेने की व्यवस्था करेगा। इन कॉलोनियों में विकास के मानक सामान्य कॉलोनियों से थोड़ा नरम एवं अलग होंगे।

इन 69 कॉलोनियों को राहत नहीं : एलजी की रिपोर्ट के आधार पर ही केंद्र सरकार ने तीन बड़ी कॉलोनियों सैनिक फार्म, महेंद्रू एनक्लेव और अनंतराम डेयरी सहित 69 अनधिकृत कॉलोनियों को नियमितिकरण की प्रक्रिया से बाहर कर दिया है। दरअसल, ये वे कॉलोनियां हैं, जो वन विभाग, यमुना खादर, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की जमीन और मास्टर प्लान रोड पर बसी हुई हैं। केंद्र का मानना है कि इन कॉलोनियों में जमीन काफी महंगी है, उसे इतने सस्ते दाम पर नियमित करने की छूट नहीं दी जा सकती। इनमें प्लॉट महंगे व आर्थिक रूप से संपन्न लोगों के हैं। इसलिए उन्हें राहत देने का फिलहाल कोई प्लान नहीं है।

डीडीए ने अपना काम शुरू कर दिया है। सर्वे ऑफ इंडिया की मदद से इन कॉलोनियों की मैपिंग कराई जा रही है। इसके बाद इनकी चारदीवारी की जाएगी। वेब पोर्टल तैयार हो रहा है। इसे तैयार होने में करीब तीन माह का समय लगेगा। इसके बाद मालिकाना हक के लिए इसी पर आवेदन करना होगा। उम्मीद है कि जनवरी के आखिर या फरवरी की शुरुआत में इन कॉलोनियों को नियमित करने का काम शुरू हो जाएगा।

–तरुण कपूर, उपाध्यक्ष, दिल्ली

अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने की घोषणा से लोगों में उत्साह : आप

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने की केंद्र सरकार की घोषणा के बाद आम लोगों में इसे लेकर खासा उत्साह है। इस निर्णय से दिल्ली की आप सरकार को भी मदद है क्योंकि यह निर्णय अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाएगा।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस ऐतिहासिक प्रयास को कामयाबी मिलने की खुशी में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में मंडल स्तर पर धन्यवाद यात्रा का आयोजन किया। मंडल पदाधिकारियों की ओर से आयोजित की गई इस यात्रा में प्रदेश संगठन के सभी पदाधिकारी, क्षेत्रीय विधायक, निगम पार्षद, आप के कार्यकर्ता एवं इलाके की जनता ने भी हिस्सा लिया। यात्रा के दौरान पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपने-अपने क्षेत्र में मिठाइयां बांटी और ढोल बजाकर खुशी का इजहार किया। पार्टी ने एक बयान जारी कर कहा कि 2015 में दिल्ली की जनता ने ऐतिहासिक बहुमत के साथ ईमानदार केजरीवाल सरकार को चुनकर भेजा। दिल्ली की सत्ता में आने के बाद से अब तक पिछले लगभग पांच सालों में दिल्ली की आप सरकार ने राजधानी में कई विकास और जनता की भलाई के काम किए। इस बयान में यह भी कहा गया है कि आप ने अपने 2015 के चुनावी घोषणा पत्र में दिल्ली की जनता से बहुत सारे वादे किए थे। इसमें से एक वादा दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों को पक्का करना था। आप की सरकार बनते ही सीएम केजरीवाल ने दो नवंबर 2015 को दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों को पक्का करने का एक प्रस्ताव तैयार करके केंद्र सरकार को भेज दिया था। लेकिन केंद्र सरकार पांच साल तक इस प्रस्ताव को दबाकर बैठी रही। इस बाबत दिल्ली सरकार ने कई बार केंद्र की भाजपा सरकार को चिट्ठी लिखकर भी जल्द से जल्द फैसला लेने का अनुरोध किया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके बावजूद मुख्यमंत्री चुप नहीं बैठे। उन्होंने लगभग 6000 करोड़ रुपये की लागत से सभी अनधिकृत कॉलोनियों में नालियां बनवाने, सड़कें बनवाने, सीवर बनवाने, पीने के पानी की पाइप लाइन बिछाने आदि जैसे ढेरों विकास के काम करवाए। इसके बाद केजरीवाल के लगातार संघर्ष के परिणाम स्वरूप अंततः केंद्र को दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों को पक्का करने के दिल्ली सरकार के इस प्रस्ताव पर मुहर लगानी पड़ी।

केंद्र की सौगात का श्रेय दूसरे को नहीं लेने देगी भाजपा

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : विधानसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार द्वारा अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने की घोषणा से भाजपा नेता उत्साहित होने के साथ ही सतर्क भी हैं। यह दिल्ली के लाखों लोगों से जुड़ा हुआ मामला है इसलिए भाजपा के नेता इसे अपने पक्ष में भुनाने के लिए जनता के बीच पहुंचने लगे हैं। उनका कहना है कि कॉलोनियों को नियमित करने में बाधा डालने वाली आम आदमी पार्टी (आप) की सरकार अब इसका श्रेय लेने की कोशिश कर रही है, जिसे भाजपा सफल नहीं होने देगी। बड़े नेताओं के साथ ही बूथ व मंडल स्तर के पदाधिकारी भी लोगों के बीच जाकर उन्हें इस बारे में जागरूक कर रहे हैं। वे लोगों को बता रहे हैं कि आप व कांग्रेस अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने के नाम पर लाखों लोगों को धोखा देती रही है। अब नरेंद्र मोदी सरकार ने इन्हें न्याय दिलाया है। अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वालों का प्रतिनिधिमंडल पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री और राज्य सभा सदस्य विजय गोयल से उनके आवास पर मिला और नियमितीकरण के बारे में जानकारी हासिल की। गोयल ने बताया कि केंद्र सरकार संसद के शीतकालीन सत्र में इस बारे में विधेयक लेकर आएगी। इन कॉलोनियों के सीमांकन की जिम्मेदारी दिल्ली विकास प्राधिकरण को सौंपी गई है। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने बताया कि जिन संपत्तियों को पंजीकृत जनरल पावर ऑफ अटार्नी अथवा पंजीकृत सेलडीड द्वारा खरीदा अथवा हस्तांतरित किया गया है, उन्हें मान्य दस्तावेजों का दर्जा देकर संबंधित व्यक्ति को मालिकाना हक दिया जाएगा।

दिवाली पर चीन में बनी मूर्तियों का बाजार 70 फीसद गिरा

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : दिवाली पर देश में बनी मूर्तियों की बिक्री में बड़ा उछाल आया है। चीन से आयात होने वाली मूर्तियों में 70 फीसद की गिरावट आई है। व्यापारियों का कहना है कि ऐसा इसलिए हुआ है, क्योंकि लोग चीनी दिखावटी और सस्ते सामान के बजाय पारंपरिक और देश में बने सामान पर विश्वास जताने लगे हैं। वे दिवाली पर पूजा और उपहार के लिए चीन में निर्मित लक्ष्मी-गणेश, भोले शंकर और मां सरस्वती की मूर्तियों को खरीदने से बच रहे हैं। इसी वजह से व्यापारियों ने इस बार चीन से इन वस्तुओं का आयात 80 से 10 फीसद कर दिया है। पिछले पांच से छह वर्षों में यह 70-80 फीसद होता था।

कंफेडेरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के महासचिव प्रवीण खंडेलवाल का कहना है कि लोग पर्यावरण को लेकर जागरूक हो रहे हैं। वे अब त्योहारों में भी पर्यावरण अनुकूल वस्तुओं की खरीदारी को तरजीह दे रहे हैं। इसलिए व्यापारियों ने देश में बनी मूर्तियों को बिक्री के लिए चुना है। चीन से वस्तुओं को आयात कम करने की वजह से इस बार बुराड़ी, पंखा रोड और गाजीपुर व मेरठ की इकाइयों से सामान खरीदा गया। बाजार में स्वदेशी उत्पादों की बिक्री हो रही है। दिल्ली व्यापार महासंघ के अध्यक्ष देवराज बवेजा ने कहा कि चीन तकनीक का उपयोग कर सस्ता सामान भारत के बाजारों में बिक्री के लिए भेजता था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में यहां के उत्पादक भी चीन की तकनीक पर काम कर रहे हैं। अब ज्यादातर उत्पाद भारत में ही तैयार किए जा रहे हैं और वे बाजार में उपलब्ध हैं। पिछले कुछ वर्षों से चीन निर्मित उत्पादों की बिक्री भी कम हो रही थी।

न्यूज गैलरी

दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर गिलानी का निधन

नई दिल्ली : दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर एसएआर गिलानी का गुरुवार को नई दिल्ली के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। सांस लेने में तकलीफ एवं अन्य समस्याओं के बाद उन्हें गुरुवार शाम फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया गया था। ह्दय गति रुकने के बाद उनका उनका निधन हो गया। 2001 में गिलानी को दिल्ली पुलिस ने संसद पर हमला मामले में गिरफ्तार किया था, लेकिन सुबूत के अभाव में दिल्ली हाई कोर्ट ने अक्टूबर 2003 में उन्हें बरी कर दिया। अगस्त 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को बरकरार रखा, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि संदेह की सुई उनकी ओर इशारा करती है। दिल्ली विश्वविद्यालय के जाकिर हुसैन कॉलेज में गिलानी अरबी के प्रोफेसर थे। फरवरी 2016 में भी उन्हें देशद्रोह एवं अन्य आरोपों में गिरफ्तार किया गया था। उस समय वह नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में भाग ले रहे थे जहां भारत विरोधी नारे लगे थे। (आइएएनएस)

कनॉट प्लेस में दिवाली उत्सव की तैयारियां शुरू

नई दिल्ली : कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में 26–29 अक्टूबर तक होने वाले दिवाली उत्सव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। यहां 50–60 फुट के अस्थायी पिलर खड़े किए जा रहे हैं, जिन पर संभवतः पांच साल में दिल्ली सरकार की उपलब्धियों को भी दिखाया जाएगा। प्रवेश और निकास द्वार भी बनाए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस मौके पर होने वाला लेजर शो भव्य होगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लोगों से प्रदूषण रहित दिवाली मनाने व सरकार के साथ कनॉट प्लेस में दिवाली उत्सव में शामिल होने को कहा है, जिसमें लेजर शो होगा। इस दौरान पूरा कनॉट प्लेस सजाया जाएगा। लेजर शो एक–एक घंटे का होगा। (जासं)

आइसा ने बहुमंजिला इमारत के खिलाफ किया प्रदर्शन

नई दिल्ली : दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) के नॉर्थ कैंपस में विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन के पास बन रही 39 मंजिला इमारत के विरोध में गुरुवार को ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (आइसा) ने प्रदर्शन किया। आइसा के कार्यकर्ताओं और छात्र संगठन से जुड़े कई छात्रों ने डीयू की आर्ट्स फैकल्टी के गेट नंबर–4 से विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन तक मार्च भी निकाला। छात्र संगठन ने आरोप लगाते हुए कहा कि यह सरकारी जमीन है, जिसमें एक निजी निर्माण किया जा रहा है। हमारी मांग है कि इस जमीन पर छात्रों के लिए छात्रावास तैयार किया जाए (जासं)

सोनिया गांधी के एक करीबी नेता ने चटकाई थी कीर्ति की विकेट

संजीव गुप्ता, नई दिल्ली

दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर पूर्व क्रिकेटर कीर्ति आजाद का नाम तय हो जाने के बावजूद प्रदेश के अनुभवी नेता सुभाष चोपड़ा की नियुक्ति 12 दिन तक चली सियासी जोड़तोड़ का नतीजा है। पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी के एक करीबी नेता ने इसमें मुख्य भूमिका निभाई। हालांकि कीर्ति को चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष बनाकर संतुलन साधने की कोशिश की गई है, लेकिन तब भी राजनीतिक गलियारों में इस जोड़तोड़ की चर्चा खूब हो रही है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक तीन माह से खाली पड़े हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए कीर्ति आजाद सोनिया की पसंद थे। उनके नाम पर औपचारिक मुहर लगाने से पहले उन्होंने कीर्ति से बाकायदा बात भी की थी। 11 अक्टूबर को जब प्रदेश प्रभारी पीसी चाको ने सोनिया के पास फाइनल नोट में कीर्ति आजाद और सुभाष चोपड़ा का नाम भेजा तो सोनिया ने कीर्ति के नाम पर ही मुहर लगाई। कीर्ति का नियुक्ति पत्र भी टाइप होने चला गया। चाको की ओर से पूर्व प्रदेश अध्यक्षों को फोन पर इसकी सूचना भी दे दी गई।

सूत्र बताते हैं कि इसके तुरंत बाद अध्यक्ष पद के ही अन्य दावेदार ने सोनिया के राजनीतिक सलाहकार अहमद पटेल को फोन कर इस नियुक्ति पर कड़ी आपत्ति जता दी। आनन-फानन में पटेल की ओर से भी सोनिया को फोन कर कीर्ति के नाम की औपचारिक घोषणा रोकने के लिए अनुरोध कर दिया गया। तर्क दिया गया कि 25 साल तक भाजपा में रहे और कुछ ही माह पूर्व कांग्रेस में शामिल हुए नेता को अध्यक्ष बनाया गया तो पार्टी में बगावत हो जाएगी। कुछ वरिष्ठ नेताओं के पार्टी छोड़ देने की आशंका भी जताई गई।

सूत्रों बताते हैं कि एक बार जो मामला लटका, फिर लटक ही गया। इसी दौरान कुछेक नेताओं ने कीर्ति को बाहरी नेता बताते हुए अध्यक्ष पद पर उनकी संभावित नियुक्ति के विरोध में हस्ताक्षर अभियान भी चला दिया, जिसकी प्रति चाको, एआइसीसी के महासचिव केसी वेणुगोपाल, पटेल और सोनिया को भी भिजवा दी गई। करीब 12 दिनों में माहौल एकदम बदल दिया गया। बताया जाता है कि बुधवार को सोनिया ने चाको के साथ मंत्रणा करके फाइनल नोट पर ही निर्णय लेते हुए विकल्प स्वरूप अध्यक्ष पद पर सुभाष चोपड़ा के नाम पर हामी भर दी। पूर्वांचल के मतदाताओं को साधने तथा आलाकमान की जुबान का मान रखने के लिए कीर्ति को चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया।

मिलकर काम करने और सभी को साथ लेकर चलने की दी सलाह

कांग्रेस पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ सुभाष चोपड़ा और कीर्ति आजाद। सौजन्य : कांग्रेस

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रदेश कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा व चुनाव अभियान समिति के चेयरमैन कीर्ति आजाद को मिलकर काम करने और सभी को साथ लेकर संगठन को मजबूत बनाने की सलाह दी है। दरअसल, गुरुवार को इन दोनों नेताओं ने सोनिया से भेंट की और अपनी नियुक्ति के लिए उनका आभार जताया। दोनों नेताओं ने कांग्रेस अध्यक्ष को विश्वास दिलाया कि दिल्ली का कांग्रेस कार्यकर्ता मजबूत है और भाजपा और आम आदमी पार्टी को शिकस्त देने की ताकत रखता है। दिल्ली में हम पूरी एकजुटता व सभी को साथ लेकर अभियान पर निकलेंगे। सोनिया ने दोनों नेताओं से कहा कि मिलकर काम करो और सभी को साथ लेकर चलो। दोनों नेताओं ने सोनिया को भरोसा दिलाया कि इस बार विधानसभा चुनावों में कांग्रेस दिल्ली में अच्छा प्रदर्शन करेगी। दूसरी तरफ प्रदेश कांग्रेस के कई नेताओं, पदाधिकारियों ने सुभाष और कीर्ति से मिलकर उन्हें बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। आदर्श नगर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हरिकिशन जिंदल और चांदनी चौक जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मो. उस्मान सहित अनेक जिला अध्यक्षों ने नए प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर सुभाष चोपड़ा को गुलदस्ता भेंटकर बधाई दी। प्रदेश कांग्रेस सेवादल के अध्यक्ष सुनील कुमार ने कीर्ति आजाद को माला पहनाकर उनका अभिनंदन किया।

अध्यक्ष बनाने का फैसला पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी का है। वह किसी को भी बनाती, हमें मंजूर होता। जहां तक कीर्ति की बात है तो वह मेरे लिए भाई जैसा है। हम मिलकर प्रदेश कांग्रेस के लिए काम करेंगे।

–सुभाष चोपड़ा, अध्यक्ष दिल्ली कांग्रेस

मैं इस बारे में कुछ नहीं कहूंगा। मुझे अगर पार्टी कोई भी जिम्मेदारी नहीं देती तो भी काम करता और अब चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष बनाया है तो उसके लिए भी आभारी हूं। मैंने 25 साल तक भाजपा में मेहनत की, लेकिन पार्टी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने पर मुझे दूध में से मक्खी की तरह निकाल दिया। कांग्रेस ने मुझे मान दिया है तो मैं भी पार्टी की मजबूती के लिए कोई कसर नहीं छोड़ूंगा।

–कीर्ति आजाद, अध्यक्ष, चुनाव अभियान समिति

मेट्रो कॉरिडोर का ड्रोन से सर्वे कराएगा डीएमआरसी

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) ने चार पुराने कॉरिडोर का सर्वे ड्रोन से कराने का फैसला किया है। इसकी जिम्मेदारी किसी निजी एजेंसी को दी जाएगी। इसके लिए डीएमआरसी ने टेंडर प्रक्रिया शुरू की है। हालांकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि ड्रोन से किस तरह का सर्वे कराया जाएगा लेकिन रेड लाइन (रिठाला-गाजियाबाद न्यू बस अड्डा), यलो लाइन (समयपुरी बादली-गुरुग्राम), ग्रीन लाइन (कीर्ति नगर-मुंडका-बहादुरगढ़) व वायलेट लाइन (कश्मीरी गेट-फरीदाबाद-बल्लभगढ़) का सर्वे कराने की योजना है। ये चारों लाइनें एनसीआर के पांच शहरों को मेट्रो नेटवर्क से जोड़ती हैं।

बताया जा रहा है कि डीएमआरसी मैनुअली अपने सभी मेट्रो कॉरिडोर और स्टेशन का सर्वे कराता रहा है। इसका एक मकसद मेट्रो की संपत्तियों के आसपास अतिक्रमण का पता लगाना भी है। पारंपरिक तरीके से मेट्रो कॉरिडोर का सर्वे करना ज्यादा मेहनत भरा काम है। इसलिए अब तकनीक का इस्तेमाल करने का फैसला किया गया है।

पानी के बकाया बिल पर माफी छूट की अवधि 31 जनवरी तक बढ़ी

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

दिल्ली जल बोर्ड ने पानी के बकाया बिल पर छूट की अवधि बढ़ा दी है। अब अगले साल 31 जनवरी तक उपभोक्ता इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निर्देश पर जल बोर्ड ने यह फैसला किया है। जिन उपभोक्ताओं के घर पानी का मीटर काम कर रहा है, वही उपभोक्ता बकाया बिल में छूट का लाभ पा सकेंगे।

जल बोर्ड ने अगस्त में पानी के बकाया बिल पर माफी योजना शुरू की थी। इसके तहत ई, एफ, जी व एच श्रेणी की कॉलोनियों के उपभोक्ताओं का 31 मार्च 2019 तक का मूल बिल व सरचार्ज पूरी तरह माफ करने का प्रावधान किया गया है। इसी तरह ए, बी, सी व डी श्रेणी की कॉलोनियों के उपभोक्ताओं का सरचार्ज पूरी तरह माफ करने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा ए व बी श्रेणी के कॉलोनियों के उपभोक्ताओं के मूल बकाया बिल में 25 फीसद, सी श्रेणी के कॉलोनियों के बिल में 50 फीसद व डी श्रेणी के कॉलोनियों के उपभोक्ताओं का बिल 75 फीसद बिल माफ करने का प्रावधान है। पहले इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए 30 नवंबर, 2019 तक तारीख निर्धारित थी। अब यह तारीख बढ़ाकर 31 जनवरी, 2020 निर्धारित कर दी गई है। जल बोर्ड के अनुसार मार्च 2019 के बाद के बिल पर भी सरचार्ज माफ कर दिया गया है।

जल बोर्ड को इस योजना से 600 करोड़ की आमदनी होने की उम्मीद है क्योंकि 13.5 लाख उपभोक्ताओं पर करीब चार हजार करोड़ का बकाया है। घरलू श्रेणी के उपभोक्ताओं पर ढाई हजार करोड़ व व्यावसायिक श्रेणी के उपभोक्ताओं पर डेढ़ हजार करोड़ रुपया बकाया है। व्यावसायिक श्रेणी के उपभोक्ता भी निर्धारित समय तक मूल बकाया बिल जमा कराकर सरचार्ज माफ करा सकते हैं।

साथी पार्षद के अपहरण, हत्या मामले में शारदा जैन को उम्रकैद

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व कांग्रेस पार्षद शारदा जैन को अपने साथी पार्षद आत्माराम गुप्ता का अपहरण और उसकी हत्या की साजिश रचने के लिए उम्रकैद की सजा सुनाई है। यह मामला 17 साल पुराना है। जैन उस समय उत्तर पश्चिम दिल्ली में केशवपुरम से पार्षद थी। उस पर त्रिनगर से वरिष्ठ पार्षद गुप्ता की हत्या की साजिश रचने का आरोप था। वह पार्टी की दूसरी पार्षद मेमवती बरवाला से गुप्ता की नजदीकियों को लेकर नाराज थी।

24 अगस्त 2002 को गुप्ता जैन के साथ फिरोजशाह कोटला मैदान में कांग्रेस की रैली में हिस्सा लेने गए थे। उनका अपहरण कर लिया गया और पांच दिनों बाद उप्र के बुलंदशहर जिले में एक नहर में उनका शव मिला। जस्टिस एमएम शांतनागौदर और जस्टिस अजय रस्तोगी की पीठ ने दिल्ली हाई कोर्ट और रोहिणी निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा। शीर्ष कोर्ट ने हालांकि तीसरे आरोपित राजेश कुमार को आरोपों से बरी कर दिया। जैन ने अपने भाई राजकुमार और दो अन्य राजेंदर एवं रोशन सिंह के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची थी।

दिल्ली–एनसीआर में कल से 30 तक प्रदूषण का हाई अलर्ट

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

दिवाली और बिगड़ी हवा के चलते 26 से 30 अक्टूबर तक दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण का हाई अलर्ट रहेगा। 28 अक्टूबर से कोहरे की भी संभावना है। इसी के मद्देनजर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने गुरुवार को टास्क फोर्स की बैठक कर उक्त समयावधि में ही कई तरह के प्रतिबंधों की भी घोषणा की है। इसमें हॉट मिक्स प्लांट, स्टोन क्रशर, कोयला आधारित उद्योगों को शामिल किया गया है। प्रदूषण फैलाने वाले कारकों के खिलाफ कार्रवाई के अभियान को तेज करने के निर्देश भी दिए गए हैं।

दिल्ली में इस दौरान केवल पीएनजी चालित औद्योगिक इकाइयां ही चल सकेंगी। गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, सोनीपत और बहादुरगढ़ में कोयले से चलने वाले उद्योगों को बंद कर दिया गया है। हालांकि इस प्रतिबंध में ऊर्जा संयंत्र शामिल नहीं हैं। दिल्ली और उक्त शहरों में चलने वाले हॉट मिक्स प्लांट और स्टोन क्रशर भी इस दौरान शाम छह बजे से सुबह छह बजे तक काम नहीं करेंगे। हॉट मिक्स प्लांट में रात के समय ही अधिकांश काम होता है।

सीपीसीबी के सदस्य सचिव डॉ. प्रशांत गार्गवा ने बताया कि दिवाली के दौरान प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए ही ये कदम उठाए गए हैं। पंजाब और हरियाणा को निर्देश दिए गए हैं कि वह इस दौरान पराली न जलने दें। दिल्ली के चयनित हाई ट्रैफिक कॉरिडोरोंपर भी दिल्ली पुलिस से अतिरिक्त स्टाफ लगाने को कहा गया है।

अवैध फैक्टरियों पर अभियान तेज : सीपीसीबी ने अवैध उद्योगों और अनधिकृत ईंधन का इस्तेमाल करने वाले उद्यमों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति की घोषणा की है। इन सभी उद्योगों के खिलाफ अभियान तेज किया जाएगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण पर रोकथाम करने वाली सभी एजेंसियों को भी हाई अलर्ट पर रहने को कहा गया है जिससे प्रदूषण पैदा करने वाले सभी कारकों पर तत्काल और सख्त कार्रवाई की जा सके।

दिवाली से पहले बहुत खराब स्तर पर पहुंचा प्रदूषण

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : दिवाली से दो दिन पहले ही दिल्ली–एनसीआर की हवा बिगड़कर बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गई है। इसी का असर रहा कि गुरुवार को दिनभर स्मॉग की चादर छाई रही। वहीं एयर इंडेक्स तीन सौ का आंकड़ा पार कर गया। दिवाली पर पटाखे जलने से हालात और बिगड़ने की आशंका है। हालांकि सफर का दावा है कि दिवाली पर पिछले साल जितनी खराब स्थिति नहीं रहेगी। गुरुवार को दिल्ली का एयर इंडेक्स बढ़कर 311 पर पहुंच गया। इसके अलावा गाजियाबाद में 335, ग्रेटर नोएडा में 320, गुरुग्राम में 294 और नोएडा में 319 एयर इंडेक्स रहा। यह हवा का स्तर बहुत खराब श्रेणी में आता है। गाजियाबाद देश भर में सबसे अधिक प्रदूषित शहर रहा। यदि दिल्ली की बात करें तो सबसे अधिक प्रदूषित क्षेत्रों में मुंडका है। यहां का एयर इंडेक्स सुबह से ही खतरनाक स्थिति में पहुंच गया था। शाम करीब छह बजे यहां का एयर इंडेक्स 424 तक पहुंच गया। इस स्तर के प्रदूषण में सांस लेना काफी घातक होता है। इसके अलावा आनंद विहार का एयर इंडेक्स भी 390 तक पहुंच गया।

ऑड–इवेन के दौरान बढ़ेंगे मेट्रो के फेरे

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : ऑड–इवेन के चार नवंबर से लागू होने को लेकर दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) ने मेट्रो के फेरे बढ़ाने का फैसला किया है। इस तरह ऑड–इवेन के दौरान मेट्रो प्रतिदिन 61 फेरे अधिक लगाएगी। इससे यात्रियों का सफर आसान होगा। दिल्ली सरकार के निर्देश पर डीएमआरसी ने यह फैसला किया है। साथ ही डीएमआरसी सोशल मीडिया पर सार्वजनिक परिवहन के इस्तेमाल के लिए अभियान चलाएगा। दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) के प्रबंध निदेशक मंगू सिंह ने कहा कि इस मसले पर दिल्ली सरकार से कई बार बातचीत हुई है। दिल्ली सरकार को कार्ययोजना के बारे में बताया गया है। इसके मुताबिक ऑड–इवेन के दौरान मेट्रो के फेरे बढ़ाए जाएंगे ताकि लोगों को आवागमन में असुविधा न हो। बहरहाल, डीएमआरसी द्वारा गुरुग्राम की रैपिड रेल के परिचालन की जिम्मेदारी संभालने के बाद दिल्ली–एनसीआर में मेट्रो का नेटवर्क करीब 389 किलोमीटर हो गया है। रैपिड रेल को छोड़कर मौजूदा समय में दिल्ली मेट्रो के नेटवर्क में करीब 336 ट्रेने हैं। इनमें करीब 2200 कोच इस्तेमाल हो रहे हैं।

सुविधा

राजीव गांधी सुपरस्पेशियलिटी अस्पताल में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कई सेवाओं का किया शुभारंभ

अब यमुनापार में भी होगी दिल की बाईपास सर्जरी

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

यमुनापार के सरकारी अस्पतालों में पहली बार दिल की बाईपास (ओपन हार्ट) सर्जरी की सुविधा शुरू हो गई है। ताहिरपुर स्थित राजीव गांधी सुपरस्पेशियलिटी अस्पताल में इस सुविधा की शुरुआत गुरुवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने की। इसके साथ मुख्यमंत्री ने कई अन्य सेवाओं का भी शुभारंभ किया। इसमें 16 बिस्तरों वाले आइसीयू और एक ऑपरेशन थियेटर परिसर शामिल हैं। इसके अलावा पेट की बीमारियों का पता लगाने और इलाज में सक्षम ईआरसीपी जांच की भी सुविधा यहां शुरू की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित देश वही हैं, जहां शिक्षा और स्वास्थ्य पर सबसे ज्यादा निवेश किया गया है। उन्होंने कहा कि राजधानी दिल्ली में यही काम आप सरकार ने किया है।

उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अस्पताल में इतनी सुविधाओं को देखकर संतुष्टि मिलती है। उन्होंने अस्पताल के पास स्थित सुंदर नगरी में बिताए दिनों को भी याद किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2000 से 2010 तक सुंदर नगरी में उन्होंने कार्य किया था। इस दौरान यहां वह इस अस्पताल को बनते हुए देखते थे। उस समय गरीब परिवारों के लिए एकमात्र सहारा जीटीबी अस्पताल था। यहां वह किसी मरीज को लेकर जाते थे तो डॉक्टरों के पास लंबी लाइन लगी होती थी। कई बीमारियों का यहां इलाज नहीं होता था। अब गरीब लोगों को भी यहां अत्याधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। राजीव गांधी सुपरस्पेशियलिटी अस्पताल आज निजी अस्पतालों से बराबरी कर पा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार बनने के बाद यहां कई सुविधाएं शुरू हुई हैं। इसके लिए वह उन सभी लोगों के आभारी हैं जिन्होंने इसमें सहयोग किया। उनकी सरकार ने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभूतपूर्व काम किए। 300 से अधिक मोहल्ला क्लीनिक चल रहे हैं। इसके साथ कई पॉलीक्लीनिक शुरू हो चुके हैं। मल्टी स्पेशलिटी और सुपरस्पेशियलिटी अस्पतालों का विस्तार हो रहा है। केजरीवाल ने सरकारी डॉक्टरों की काबिलियत की प्रशंसा करते हुए एक किस्सा भी सुनाया। उन्होंने कहा कि एक जानकार को निजी अस्पताल ने चार-पांच दिन का मेहमान बता दिया था। उन्हें जीबी पंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां डॉक्टरों ने एक हफ्ते में उन्हें पूरी तरह से स्वस्थ कर दिया। इससे पहले स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि दिल्ली सरकार ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में ऐसे कदम उठाए हैं, जो विकसित देशों में ही नजर आते हैं।

इस मौके पर समाज कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम, स्वास्थ्य महानिदेशक डॉ. अशोक राणा, राजीव गांधी सुपरस्पेशियलिटी अस्पताल के निदेशक डॉ. बीएल शेरवाल, डीएमएस डॉ. छवि गुप्ता आदि मौजूद रहे।

राजीव गांधी सुपरस्पेशियलिटी अस्पताल में ऑपरेशन थियेटर और आइसीयू का उद्घाटन करते अरविंद केजरीवाल। साथ में स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, समाज कल्याण मंत्री राजेंद्रपाल गौतम और अन्य। जागरण

आरएमएल में शुरू होगी एचएलए जांच

रणविजय सिंह, नई दिल्ली

किडनी खराब होने की बीमारी से पीड़ित मरीजों के लिए एक अच्छी खबर है। केंद्र सरकार के अटल बिहारी वाजपेयी आयुर्विज्ञान संस्थान व आरएमएल अस्पताल में एचएलए (ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन) जांच की सुविधा शुरू होगी। इससे किडनी प्रत्यारोण के लिए मरीजों व डोनर को निजी लैब में यह जांच कराने से छुटकारा मिलेगा। आरएमएल अस्पताल में यह जांच निःशुल्क होगी। इसलिए मरीजों के 20-30 हजार रुपये बचेंगे।

दरअसल, किडनी या लिवर प्रत्यारोपण से पहले मरीज और डोनर को गहन जांच से गुजरना पड़ता है। ब्लड ग्रुप के अलावा एचएलए जांच भी कराई जाती है। यह एक तरह की डीएनए जांच होती है। प्रत्यारोपण के लिए मरीज व डोनर के ब्लड ग्रुप के साथ-साथ एचएलए भी आपस में मैच (मिलान) करना जरूरी है। अक्सर यह देखा गया है कि मरीज व डोनर का एचएलए मिलान करना ही मुश्किल होता है। डोनर का एचएलए मरीज से मिलान नहीं होने पर सामान्य तौर पर प्रत्यारोपण नहीं किया जाता। यही वजह है कि किडनी व लिवर फेल्योर के मरीजों को डोनर मिल पाना मुश्किल होता है। हालांकि अब ऐसी तकनीक उपलब्ध हो गई है जिससे एचएलए का मिलान नहीं होने पर भी प्रत्यारोपण हो रहे हैं, लेकिन इसकी प्रक्रिया जटिल होती है। इसके लिए यह जांच जरूरी है।

मौजूदा समय में दिल्ली में सरकारी क्षेत्र के तीन अस्पतालों एम्स, सफदरजंग व आरएमएल अस्पताल में किडनी प्रत्यारोपण की सुविधा है। इनमें से सिर्फ एम्स में ही इस जांच की सुविधा है। इस वजह से मरीजों व डोनर को निजी लैब में यह जांच करानी पड़ती है। निजी लैबों में इस जांच का शुल्क 10-15 हजार रुपये है। इस तरह मरीज व डोनर दोनों को यह जांच कराने में 20-30 हजार रुपये खर्च करने पड़ते हैं।

अस्पताल की चिकित्सा अधीक्षक डॉ. मीनाक्षी भारद्वाज ने कहा कि पैथोलॉजी विभाग में छह माह में यह जांच शुरू कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि अस्पताल में लिवर प्रत्यारोपण शुरू करने की भी योजना है।

10 हजार पांच सौ करोड़ रुपये रक्षा निर्यात हो गया है भारत का वित्त वर्ष 2018-19 में। निर्यात के मामले में पिछले दो वर्षों के दौरान सात गुना वृद्धि हुई है। मोदी सरकार रक्षा क्षेत्र में मेड इन इंडिया पर खास जोर दे रही है।

संयुक्त राष्ट्र में एनआरसी की गलत व्याख्या पर भारत ने चिंता जताई

संयुक्त राष्ट्र, प्रेट्र : भारत ने संयुक्त राष्ट्र में निराशा व्यक्त करते हुए कहा कि असम में एनआरसी को अल्पसंख्यक अधिकारों के मुद्दे के साथ गलत तरीके से जोड़ा जा रहा है। साथ ही कहा कि अधूरी जानकारी के आधार पर कोई निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए।

संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन की प्रथम सचिव पालोमी त्रिपाठी ने कहा कि राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) को अपडेट करना एक संवैधानिक, कानूनी और पारदर्शी प्रक्रिया है जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में की जाती है। एनआरसी का मुद्दा भारत में असम राज्य में अल्पसंख्यकों के अधिकारों का मुद्दा नहीं है।

त्रिपाठी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा की तीसरी समिति (सामाजिक, मानवीय और सांस्कृतिक) के एक सत्र में कहा कि हम निराश हैं कि यह मुद्दा अल्पसंख्यक अधिकारों के मुद्दे के साथ गलत तरीके से जुड़ा हुआ है। भारत में अल्पसंख्यक संवैधानिक सुरक्षा अधिकारों का पूरा इस्तेमाल करते हैं। त्रिपाठी ने अल्पसंख्यक मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत फर्नांड डी वर्नेज की ओर से की गई टिप्पणियों का जवाब देने के लिए मंच का उपयोग किया। फर्नांड ने एनआरसी मुद्दे पर कहा था कि यह संभावित मानवीय संकट में योगदान दे सकता है। हजारों की संख्या में जोखिम के कारण अस्थिर स्थिति और शायद लाखों लोग जो मुख्य रूप से भारत में बंगाली और मुस्लिम अल्पसंख्यक हैं, उन्हें असम राज्य में विदेशी और संभावित गैर-नागरिक माना जा रहा है। अपनी प्रतिक्रिया में त्रिपाठी ने कहा कि एनआरसी से बाहर करने से असम के किसी भी निवासी के अधिकारों का हनन नहीं किया गया है।

जिनका नाम अंतिम सूची में नहीं हैं, उन्हें हिरासत में नहीं लिया गया है। यह उन्हें एक बहिष्कृत या विदेशी नहीं बनाता है। उन्होंने कहा कि अधूरी समझ पर आधारित गलत निष्कर्षों में कूदने के बजाय न्यायिक प्रक्रियाओं को पूरा करने की अनुमति दी जानी चाहिए।पालोमी त्रिपाठी ने पाकिस्तान पर करारा प्रहार करते हुए कहा कि मानवाधिकार की वैधता सबसे अधिक कमजोर तब होती है जब एक लालची देश आतंकी नेटवर्कों की धुरी बनकर उन्हें सुरक्षित पनाहगाह देता है। दुर्भाग्य से एक और प्रतिनिधिमंडल ने हमारे देश के आंतरिक मामले में दखल देने का एक और प्रयास किया है। त्रिपाठी ने विगत सोमवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा की तीसरी कमेटी (सामाजिक, मानवाधिकार और सांस्कृतिक) में किया। उन्होंने कहा कि सच्चाई यह है कि पूरी दुनिया में आतंकवाद के शिकार बहुत लोग हैं। लेकिन उन सबको पीड़ा देने वाले आतंकी नेटवर्क के आका इस देश (पाकिस्तान) में सारे ऐश-ओ-आराम और सुरक्षित पनाह पाते हैं।

पाक पर निशाना

- आंतरिक मुद्दे को अल्पसंख्यक अधिकारों से जोड़ने पर कहा- अधूरी जानकारी पर निष्कर्ष निकालना गलत
- मानवाधिकार सबसे अधिक कमजोर तब होता है जब एक देश आतंकी नेटवर्कों की सुरक्षित पनाहगाह बनता है

पालोमी त्रिपाठी फाइल फोटो

सिविल सोसाइटी की चिंताओं के बीच संशोधित आरटीआइ कानून लागू

नई दिल्ली, प्रेट्र : सिविल सोसाइटी की चिंताओं के बीच केंद्र ने गुरुवार को सूचना का अधिकार (संशोधन) कानून-2019 को लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी है।

कार्मिक मंत्रालय ने बिना किसी विस्तार के जारी अधिसूचना में कहा है, 'केंद्र सरकार ने सूचना का अधिकार (संशोधन) कानून-2019 के प्रावधानों को प्रभाव में लाने की तिथि 24 अक्टूबर 2019 तय कर दी है।' इस विधेयक को संसद के दोनों सदनों में जुलाई में पारित किया गया था, जबकि अगस्त में राष्ट्रपति ने इसे अनुमोदित कर दिया था।

हालांकि, सरकार के इस कदम का सूचना का अधिकार (आरटीआइ) कार्यकर्ताओं ने विरोध किया था। उन्होंने इसे समिति की स्वतंत्रता पर आघात बताया था। तब कार्मिक राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा था कि यह कदम जल्दबाजी में तैयार किए गए आरटीआइ कानून-2005 को सशक्त बनाने के लिए उठाया गया है, क्योंकि पहले इसमें कई कमियां रह गई थीं।

संशोधित कानून के तहत सरकार मुख्य सूचना आयुक्त (सीआइसी) व सूचना आयुक्तों (आइसी) के कार्यकाल से लेकर वेतन तक का निर्धारण कर सकती है। आरटीआइ कानून-2005 में सीआइसी व आइसी का कार्यकाल पांच साल या 65 वर्ष तक निर्धारित था, जबकि उनका वेतन चुनाव आयुक्तों के समान होता था। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस मदन लोकुर ने हाल ही में कहा था कि आरटीआइ कानून में बदलाव नुकसानदेह हो सकते हैं।

सऊदी अरब और भारत में होगा रणनीतिक साझेदारी समझौता

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- पीएम मोदी अगले हफ्ते मंगलवार को जाएंगे रियाद
- क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ होगी द्विपक्षीय वार्ता
- भारत समेत आठ देशों के साथ रणनीतिक साझेदारी कर रहा सऊदी अरब

नरेंद्र मोदी और सऊदी क्राउन प्रिंस सलमान (फाइल)

भारत और सऊदी अरब का रिश्ता बदल चुका है। इसका बड़ा उदाहरण अगले हफ्ते तब देखने को मिलेगा जब पीएम नरेंद्र मोदी सऊदी अरब की यात्रा पर जाएंगे। वैसे इस यात्रा में आर्थिक सहयोग को लेकर कई बड़ी घोषणाएं होने की उम्मीद है, लेकिन सबसे अहम बिंदु होगा दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी काउंसिल को लेकर की जाने वाली घोषणा। इस काउंसिल के तहत दो प्रमुख समितियां होंगी। एक समिति में दोनों देशों के विदेश व रक्षा मंत्री और दूसरी में वाणिज्य व वित्त मंत्री होंगे। इन दोनों समितियों के तहत भी कई उप समितियां होंगी जो दोनों देशों के भावी रिश्तों को तय करने पर समय-समय पर अहम सुझाव देंगी। सऊदी अरब इस तरह का समझौता सिर्फ आठ देशों के साथ कर रहा है।

पीएम मोदी की इस यात्रा के बारे में जानकारी देते हुए विदेश मंत्रालय में सचिव (आर्थिक मामले) टीएस त्रिमूर्ति ने बताया कि सऊदी अरब ने भारत, ब्रिटेन, यूएसए, चीन, फ्रांस, जर्मनी, कोरिया और जापान के साथ रणनीतिक साझेदारी काउंसिल स्थापित करने का फैसला किया है। भारत व सऊदी अरब के बीच गठित होने वाले परिषद की अध्यक्षता पीएम नरेंद्र मोदी और सऊदी क्राउन प्रिंस सलमान करेंगे। पीएम अपनी इस आधिकारिक यात्रा के दौरान रियाद में निवेश व कारोबार पर आयोजित होने जा रहे अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन एफआइआइ में मुख्य वक्ता होंगे। इस सम्मेलन को पूर्व के दाओस की तर्ज पर जाना जाता है। दाओस स्विट्जरलैंड का एक शहर है जहां वर्ल्ड इकोनामिक फोरम की तरफ से दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित निवेश सम्मेलन का आयोजन होता है।

यह पूछे जाने पर कि क्या मोदी और क्राउन प्रिंस सलमान के बीच द्विपक्षीय वार्ता में कश्मीर का मुद्दा उठेगा तो त्रिमूर्ति का जवाब था, 'दोनों नेताओं के बीच क्या बात होती है उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता लेकिन भारत को यह पता है कि कश्मीर मुद्दे पर सऊदी अरब हमारे पक्ष को बखूबी समझता है। वैसे भी फरवरी, 2019 में सऊदी क्राउन प्रिंस के भारत आने के बाद रिश्तों में गर्माहट और बढ़ गई है।'

पीएम की इस यात्रा के दौरान ऊर्जा क्षेत्र में कई अहम समझौते होने के भी उम्मीद है। एक समझौता भारत के पश्चिमी तट पर स्थापित होने वाली रिफाइनरी में सऊदी कंपनी अरामको बड़ा निवेश करने जा रही है। यह भारत की सबसे बड़ी रिफाइनरी होगी। इंडियन आयल और सऊदी अरब की एक कंपनी में भी समझौता होगा जिसके बाद भारतीय तेल कंपनी वहां रिटेल कारोबार में उतर सकेगी। भारत में कच्चे तेल के रणनीतिक भंडार में सऊदी अरब की तरफ से किए जाने वाले निवेश के मसौदे को भी अंतिम रूप दिया जाएगा। सनद रहे कि सऊदी अरब भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश है।

विदेश मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक, दोनों देशों के बीच रक्षा क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाने पर भी बात होगी। भारत और सऊदी अरब की नौसेना के बीच पहला संयुक्त अभ्यास इस वर्ष के अंत में होने जा रहा है। सऊदी अरब के सैन्य अफसरों को भी भारत में बड़े पैमाने पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसे और बढ़ाया जाएगा। भारत की रक्षा उपकरण कंपनियां सउदी अरब को एक बड़े बाजार के रूप में देख रही हैं। वहां रूपे कार्ड के इस्तेमाल को लेकर भी एक समझौता होगा।

पीएमसी बैंक घोटाले में न्यायिक हिरासत में भेजे गए वधावन पिता-पुत्र

मुंबई, प्रेट्र : एक विशेष अदालत ने गुरुवार को पंजाब एंड सिंध कोऑपरेटिव (पीएमसी) बैंक में हुए 4,355 करोड़ रुपये के घोटाले के आरोपित व एचडीआइएल के प्रवर्तक राकेश वधावन तथा उनके पुत्र सारंग को न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने हिरासत अवधि खत्म होने के बाद हाउसिंग डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (एचडीआइएल) के चेयरमैन व प्रबंध निदेशक राकेश व उनके बेटे को प्रिवेंशन ऑफ मनी लांड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) कोर्ट के विशेष न्यायाधीश पी. राजवैद्य के समक्ष प्रस्तुत किया। ईडी ने जब हिरासत की मांग नहीं की तो कोर्ट ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

उल्लेखनीय है कि मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने पीएमसी बैंक घोटाले में वधावन पिता-पुत्र व बैंक अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। आरोप है कि बैंक प्रबंधन ने वधावन की कंपनी एचडीआइएल की बड़ी देनदारी को फर्जीवाड़े के जरिये नियामकों से छिपाने का प्रयास किया था। इसके लिए बैंक अधिकारियों ने एचडीआइएल के 44 कर्ज खातों को 21,049 फर्जी खातों में तब्दील कर दिया था। ईओडब्ल्यू की तरफ से दर्ज मुकदमे के आधार पर ईडी ने मनी लांड्रिंग की रिपोर्ट दर्ज की है।

नई शिक्षा नीति बदलेगी, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का होगा गठन

बड़ा कदम ▶ मानव संसाधन विकास मंत्री होंगे मुखिया, पहले बनना था आयोग

कैब की तर्ज पर राज्यों के साथ मिलकर शिक्षा सुधारों व नीति के अमल पर होगा काम

अरविंद पांडेय, नई दिल्ली

प्रस्तावित नई शिक्षा नीति अब जल्द ही कुछ बड़े बदलावों के साथ सामने आएगी। इसकी पूरी तैयारी की जा चुकी है। इसे लगभग अंतिम रूप दे दिया गया है। जो बड़े बदलाव सामने आए हैं, उनमें शिक्षा को मजबूती देने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा आयोग की जगह अब राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन सबसे अहम है। इसके मुखिया मानव संसाधन विकास मंत्री होंगे। सभी राज्यों के शिक्षा मंत्री और शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी हस्तियां बतौर सदस्य इसमें शामिल होंगे।

इससे पहले प्रस्तावित नीति में आयोग बनाने की सिफारिश की गई थी। जिसका मुखिया प्रधानमंत्री को बनाया गया था, जबकि उपाध्यक्ष के लिए मानव संसाधन विकास मंत्री के नाम का प्रस्ताव था। सूत्रों के मुताबिक, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने नीति को अंतिम रूप देते हुए इस सिफारिश को खारिज कर दिया है। हालांकि इसके पीछे प्रधानमंत्री की व्यस्तताएं बताई जा रही हैं, जिसके चलते उनके लिए ऐसे आयोगों की जिम्मेदारी को ठीक तरीके से देख पाना मुश्किल होगा। इसके साथ ही राष्ट्रीय शिक्षा परिषद के गठन को मंजूरी दी गई है। यह कैब (केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड) की तर्ज पर ही राज्यों को साथ लेकर काम करेगी। हालांकि इसका मुख्य फोकस शिक्षा को मजबूती देने के साथ नई शिक्षा नीति को राज्यों के साथ मिलकर लागू करना है।

इसी बीच प्रस्तावित नई शिक्षा नीति को लेकर आए करीब दो लाख सुझावों को अंतिम रूप दिया जा चुका है। नीति को अंतिम रूप दे रही टीम से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक, प्रस्तावित नीति को लेकर आए सुझावों में बड़े पैमाने पर दोहराव था। यही वजह है कि इस काम को तय समय से पहले पूरा कर लिया गया है।

प्रतीकात्मक फोटो

संसद में भी पेश होगी नीति

मानव संसाधन विकास मंत्रालय से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक, नई शिक्षा नीति को जल्दी ही इसे कैबिनेट के सामने रखा जाएगा। इसके बाद कोई बड़ा उलटफेर नहीं हुआ तो संसद में भी पेश किया जाएगा। गौरतलब है कि कई वर्षों की मशक्कत के बाद नई शिक्षा नीति सामने आई है। इसे इसी साल 30 मई को मानव संसाधन विकास मंत्री को सौंपा गया था। प्रस्तावित नीति को इसरो के पूर्व प्रमुख और वरिष्ठ वैज्ञानिक के. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने तैयार किया था।

मिशेल की याचिका पर ईडी व सीबीआइ से मांगा जवाब

क्रिश्चियन मिशेल फाइल फोटो

जासं, नई दिल्ली : अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले में आरोपित बिचौलिये क्रिश्चियन मिशेल की जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सीबीआइ और ईडी से जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति अनु मल्होत्रा की पीठ ने सीबीआइ और ईडी को दो सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हुए सुनवाई 13 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी।

क्रिश्चियन मिशेल के खिलाफ सीबीआइ ने भ्रष्टाचार और व ईडी ने मनी लांड्रिंग का मामला दर्ज किया है। वह 5 जनवरी से न्यायिक हिरासत में है। भ्रष्टाचार के मामले में नियमित जमानत की मांग करते हुए उसने दलील दी है कि पूरा मामला दस्तावेज के रूप में मौजूद सुबूत पर आधारित है और सभी दस्तावेज जांच एजेंसी के पास हैं। ये सीबीआइ की विशेष अदालत में पेश भी किए जा चुके हैं। वीवीआइपी हेलीकॉप्टर के कांट्रैक्ट में भारत सरकार को कोई आर्थिक नुकसान नहीं हुआ है। वह किडनी स्टोन की समस्या से जूझ रहा है और इस वजह से उसका वजन भी काफी कम हुआ है।

हजेला के मप्र तबादले के लिए केंद्र ने समय मांगा

- सुप्रीम कोर्ट ने एनआरसी समन्वयक को उनके मूल राज्य में भेजने का आदेश दिया था

प्रतीक हजेला फाइल फोटो

नई दिल्ली, प्रेट्र : केंद्र सरकार असम नेशनल सिटीजन रजिस्टर (एनआरसी) समन्वयक प्रतीक हजेला को मध्य प्रदेश स्थानांतरित करने संबंधी औपचारिकताएं पूरी करने की समयसीमा बढ़ाने के लिए को सुप्रीम कोर्ट पहुंची। कोर्ट ने केंद्र और असम सरकार को 18 अक्टूबर को निर्देश दिया था कि हजेला को सात दिनों में उनके मूल राज्य मध्य प्रदेश स्थानांतरित कर दिया जाए।

केंद्र के वकील ने मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अगुवाई वाली पीठ से गुरुवार को कहा कि हालांकि सरकार ने असम-मेघालय काडर के 1995 बैच के आइएएस अधिकारी को स्थानांतरित करने के लिए कदम उठाए हैं लेकिन प्रक्रियागत औपचारिकताएं पूरी करने में कुछ और समय लगेगा। इस पीठ में जस्टिस एसए बोब्डे और जस्टिस एसए नजीर भी शामिल हैं।

पीठ ने कहा, 'आप याचिका दायर कीजिए।' हजेला को शीर्ष कोर्ट ने एनआरसी को अंतिम रूप देने और इसके आंकड़ों के प्रकाशन की संवेदनशील कवायद के लिए समन्वयक नियुक्त किया था। शीर्ष कोर्ट ने हजेला को अधिक संभव अवधि के लिए अंतर-काडर तबादले पर उनके गृह राज्य में प्रतिनियुक्ति पर भेजने का आदेश दिया। पीठ ने यह आदेश पारित करने की कोई वजह स्पष्ट नहीं की लेकिन इससे इन अटकलों को बल मिला कि असम एनआरसी को अंतिम रूप से देने के विशाल और संवेदनशील काम की निगरानी के बाद इस अधिकारी को शायद किसी प्रकार के खतरे की आशंका है।

असम एनआरसी संबंधी याचिकाओं की सुनवाई पहले से ही 26 नवंबर तय है। असम की बहुप्रतीक्षित एनआरसी अंतिम रूप दिए जाने के बाद 31 अगस्त को प्रकाशित हुई थी और इससे राज्य में 19 लाख से अधिक आवेदकों के नाम बाहर कर दिए गए थे। एनआरसी में नाम शामिल करने के लिए 3,30,27,661 व्यक्तियों ने आवेदन किया था। इनमें से 3,11,21,004 लोगों को इसमें शामिल किया गया है।

चिदंबरम की जमानत याचिका पर ईडी से मांगा जवाब

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

आइएनएक्स मीडिया डील के मनी लांड्रिंग मामले में आरोपित पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदंबरम की जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति सुरेश कैट की पीठ ने ईडी को एक सप्ताह में जवाब दाखिल करने का आदेश देते हुए सुनवाई 4 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी। सीबीआइ द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार के मामले में सुप्रीम कोर्ट से उनको जमानत मिल चुकी है।

चिदंबरम ने अपनी जमानत याचिका में दलील दी है कि मामले से जुड़े सभी सुबूत दस्तावेज के रूप में एजेंसी के पास हैं। ऐसे में इनसे छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। वह पूछताछ के लिए ईडी के समक्ष हमेशा उपलब्ध रहे और जब भी समन किया गया उन्होंने पूछताछ में शामिल होकर सभी सवालों का जवाब दिया। अंतिम बार ईडी ने उनसे 8 फरवरी को पूछताछ की थी। बीते 16 अक्टूबर तक उनसे सवाल करने के लिए ईडी ने कोई कदम नहीं उठाया, जबकि वह 5 सितंबर से लेकर 16 अक्टूबर तक जेल में थे। उन्होंने कहा कि 74 वर्ष की उम्र होने के कारण उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है, वह हृदय-धमनी की बीमारी से जूझ रहे हैं।

आइएनएक्स मीडिया डील मामले में सीबीआइ ने चिदंबरम को इस साल 21 अगस्त को गिरफ्तार किया था। आरोप है कि चिदंबरम के वित्त मंत्री रहते हुए वर्ष 2007 में 305 करोड़ रुपये की विदेशी धनराशि प्राप्त करने के लिए आइएनएक्स मीडिया समूह को दी गई विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआइपीबी) की मंजूरी में अनियमितताएं हुईं। इसमें ईडी ने भी मनी लांड्रिंग का मामला दर्ज किया था।

नई दिल्ली में गुरुवार को अदालत ने आइएनएक्स मीडिया डील के मनी लांड्रिंग मामले में आरोपित पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदंबरम को 30 अक्टूबर तक प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत में भेज दिया। प्रेट्र

अदालत में आए चिदंबरम ने चुनाव परिणामों पर कसा तंज

राउज एवेन्यू की विशेष अदालत के बाहर चिदंबरम ने गुरुवार को ही आए चुनाव परिणामों पर तंज कसा। कहा कि शांत देशभक्ति दिखावे की राष्ट्रीयता को हरा देगी। विशेष न्यायाधीश अजय कुमार कुहार ने आइएनएक्स मीडिया डील के मनी लांड्रिंग मामले में चिदंबरम को 30 अक्टूबर तक ईडी की रिमांड पर सौंप दिया। ईडी ने कहा कि अभी पूछताछ पूरी नहीं हो सकी है, जांच अहम पड़ाव से गुजर रही है। विशेष न्यायाधीश ने कहा कि तथ्यों एवं मामले की गंभीरता को देखते हुए चिदंबरम की हिरासत बढ़ाई जाती है। उनको घर का खाना और एम्स में मेडिकल की सुविधा मिलती रहेगी।

न्यायमित्र बोले-मंत्रियों को बयानबाजी से बचना चाहिए

- अभिव्यक्ति की आजादी की सुप्रीम कोर्ट में समीक्षा जारी
- न्यायमित्र साल्वे ने सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ को दी सलाह

नई दिल्ली, आइएएनएस : सर्वोच्च न्यायालय में अभिव्यक्ति की आजादी की समीक्षा पर सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने गुरुवार को कहा,मंत्रियों और उच्च पदों पर आसीन अफसरों को सार्वजनिक रूप से बयानबाजी से बचना चाहिए। शीर्ष अदालत ने दो वरिष्ठ अधिवक्ताओं हरीश साल्वे और फली नरिमन को न्यायमित्र नियुक्त किया है। यह दोनों निर्वाचित प्रतिनिधियों और राजनेताओं को लंबित आपराधिक मामलों में बयानबाजी करने से रोकने संबंधी कवायद में अदालत के मददगार हैं। कोर्ट जानना चाहती है कि क्या नेताओं की बयानबाजी पर रोक से अभिव्यक्ति की आजादी के मूलभूत अधिकार का हनन होता है?

जस्टिस अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच जजों की संविधान पीठ ने गुरुवार को इस मामले की सुनवाई की। मामले की सुनवाई के दूसरे दिन साल्वे ने कहा, मंत्रियों और उच्च पदों पर आसानी लोगों को बिना सोचे-समझे कुछ भी बोलने से बचना चाहिए। चूंकि इससे सरकार के कामकाज पर भी असर दिखता है और फिर कुछ भी बोलने के एवज में सुरक्षा मांगी जाती है। कोर्ट ने पूछा कि जिस मामले में मंत्री को बोलने से रोकना पड़े, उसे आखिर किस तरह से संभाला जाए? इस पर साल्वे ने कहा कि प्रशासन से जुड़े लोगों या सरकारी कामकाज से जुड़े लोगों को अपनी राय नहीं देनी चाहिए। चूंकि इससे सरकार का कामकाज प्रभावित हो सकता है।

साल्वे ने सोशल मीडिया से होने वाली समस्याओं का भी हवाला देते हुए कहा कि इससे सबसे अधिक निजता का अधिकार प्रभावित होता है। उन्होंने कहा कि फेसबुक, वाट्सएप यूजर के मामले में कई दफा निजता प्रभावित होती है। आज गैर सरकारी कंपनियां या संस्थाएं का व्यापक नियंत्रण होता है। साथ ही निजी कंपनियां भी सार्वजनिक क्षेत्र के प्रमुख हिस्सों पर नजर रखती हैं।

केंद्र की जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों की तैयार हो रही कुंडली

नई दिल्ली, प्रेट्र : केंद्रीय लोकनिर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) ने केंद्र सरकार की संपत्तियों पर कब्जा करने वालों संग सख्ती से निपटने के लिए ऐसे लोगों की कुंडली तैयार करनी शुरू कर दी है। ब्योरा जुटाने के बाद संपत्तियों से अवैध कब्जेदारों को हटाने की कवायद शुरू होगी।

एक अधिकारी ने बताया, 'अधिकारियों को अतिक्रमणकारियों की सूची तथा उनके कब्जे वाली जमीन का ब्योरा तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। इन सूचनाओं को 31 अक्टूबर तक प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।' सीपीडब्ल्यूडी ने यह भी जानकारी मांगी है कि जमीन को कब्जामुक्त कराने के लिए अब तक क्या कार्रवाई की गई है। उल्लेखनीय है कि केंद्रीय आवास व शहरी मामलों के मंत्रालय ने सरकारी जमीन, बंगलों व फ्लैटों को अवैध कब्जे से बचाने के लिए निजी सुरक्षा एजेंसी की मदद लेने का फैसला किया है। योजना के तहत एक संपत्ति पर दो निजी सुरक्षाकर्मी तैनात किए जाएंगे, जो दिन-रात उसकी रक्षा करेंगे। इससे पहले सुरक्षाकर्मियों का दिल्ली पुलिस से सत्यापन कराया जाएगा।

कार्रवाई

एंटी करप्शन ब्रांच और रेलवे विजिलेंस यूनिट प्रयागराज की संयुक्त कार्रवाई, कबाड़ की नीलामी की फाइलें और दस करोड़ के जनरेटर को लेकर की छानबीन

मप्र में रेलवे स्प्रिंग कारखाने पर सीबीआइ का छापा

नईदुनिया, ग्वालियर

मध्य प्रदेश में ग्वालियर से करीब 12 किमी दूर सिथौली स्थित रेलवे के स्प्रिंग कारखाने पर गुरुवार को सीबीआइ की एंटी करप्शन ब्रांच एवं रेलवे की विजिलेंस यूनिट प्रयागराज की टीम ने संयुक्त रूप से छापामार कार्रवाई की। टीम के निशाने पर मुख्य रूप से जनरेटर खरीदारी एवं कबाड़ की नीलामी की फाइलें थी। 10 करोड़ में खरीदे गए जनरेटर को कबाड़ की तरह एक कोने में रखा गया था। सूत्रों के अनुसार, डिप्टी जनरल मैनेजर (डीजीएम) एवं पर्सनल ऑफिसर से पूछताछ की गई। हालांकि, एंटी करप्शन ब्रांच की तरफ से मामले में कोई अधिकृत बयान जारी नहीं किया गया है।

रेलवे स्प्रिंग कारखाने में आर्थिक अनियमितताओं को लेकर सीबीआइ को कई शिकायतें मिली थीं। इसमें उत्पादन प्रभावित होने वाली शिकायतें भी थीं। सीबीआइ की एंटी करप्शन ब्रांच की 25 सदस्यीय टीम गुरुवार दोपहर 12 बजे रेलवे स्प्रिंग कारखाने में पहुंची और जनरेटर खरीदारी एवं कबाड़ की नीलामी संबंधित फाइलें जब्त कीं। खरीदारी की फाइलों की भी जांच की गई। कंप्यूटर डाटा की पड़ताल से यह पता किया जा रहा है कि पिछले 6-7 साल में नीलाम किए गए कबाड़ की प्रक्रिया क्या रही है। जनरेटर का कितना और कब-कब उपयोग हुआ है। कार्रवाई के दौरान कारखाने के कर्मचारियों को दूर रखा गया। कारखाने के बाहर तैनात आरपीएफ के जवानों को भी अंदर चल रही कार्रवाई की कोई जानकारी नहीं दी गई।

करोड़ों के जनरेटर का उपयोग ही नहीं : कारखाने में डीजीएम एसके गुप्ता करीब छह साल तक पदस्थ रहे थे। जब रेलवे ने ट्रांसफर किया तो जुगाड़ लगाकर दोबारा स्प्रिंग कारखाने में पहुंच गए। सीबीआइ को यहां आर्थिक अनियमितताओं को लेकर शिकायतें पहले से मिल रही थीं, इसलिए डीजीएम के दोबारा यहां पदस्थ होते ही जांच एजेंसी सतर्क हो गई। सीबीआइ ने डीजीएम गुप्ता को हिरासत में लेकर पूछताछ की। जांच में पता चला कि कारखाने में 10 करोड़ के उच्च गुणवत्ता के जनरेटर खरीदे गए थे। इसे लेकर तर्क दिया गया था कि यहां अक्सर बिजली की लाइन ब्रेक होती है। प्रोडक्शन प्रभावित नहीं हो, इसलिए जनरेटर की खरीदारी जरूरी है। चौंकाने वाली बात ये है कि जनरेटर का उपयोग किया ही नहीं गया और इन्हें कबाड़ की तरह एक कोने में डाल दिया गया।

प्रतीकात्मक फोटो

कुप्रबंधन के कारण फैक्ट्री को घाटा

रेलवे स्प्रिंग कारखाने की स्थापना 1989 में हुई थी। यह देश के सबसे बेहतरीन स्प्रिंग कारखानों में शुमार है। यहां पर हैली केल हॉट क्वाइल स्प्रिंग बनाई जाती है, जिसका उपयोग सामान्य के साथ ही एलएचवी कोच में भी होता है। बेहतरीन क्वालिटी की स्प्रिंग का निर्माण एवं बहुत ज्यादा मांग होने के बाद भी फैक्ट्री का घाटे में जाना रेलवे एवं सीबीआइ को गले नहीं उतर रहा था। यह प्लांट एलपीजी से संचालित होता है। सूत्रों के मुताबिक, सीबीआइ को प्राथमिक जांच में पता चला कि डीजीएम के कुप्रबंधन के कारण ही फैक्ट्री घाटे में जा रही है।

जमानत रद करने की ईडी की याचिका पर सना से मांगा जवाब

जासं, नई दिल्ली : मीट कारोबारी मोईन कुरैशी से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में आरोपित कारोबारी सतीश सना बाबू की जमानत को चुनौती देने वाली प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सतीश सना से जवाब मांगा है।

न्यायमूर्ति चंद्र शेखर की पीठ ने सना को जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हुए सुनवाई 29 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दी। ईडी ने 19 अगस्त को निचली अदालत द्वारा दी गई जमानत को चुनौती दी है। ईडी की तरफ से पेश हुए स्टैंडिंग काउंसल अमित महाजन ने कहा कि जांच एजेंसी ने तमाम सुबूत जुटाए हैं जिनसे पता चलता है कि सना मनी लांड्रिंग मामले में आरोपित हैं। इस मामले में बड़े पैमाने में नौकरशाह ही नहीं अन्य लोग भी शामिल रहे, जो नौकरशाहों के तरफ से रुपये एकत्रित करते थे। सना को सिर्फ इसलिए जमानत दी गई क्योंकि मामले में मोईन कुरैशी को जमानत दी गई, जबकि कुरैशी की जमानत को भी ईडी ने चुनौती दी है।

कह के रहेंगे माधव जोशी

12.62% हरियाणा के 2014 विधानसभा चुनाव में भाजपा और कांग्रेस के मतों का अंतर। 2019 में यह अंतर कम होकर 8.27 फीसद रह गया।

9.8% 2014 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में दो राष्ट्रीय दलों भाजपा, कांग्रेस के मतों का अंतर। 2019 में यह अंतर 9.74 फीसद रहा।

विदर्भ ने भी नहीं दिया फड़नवीस का साथ

ओमप्रकाश तिवारी, मुंबई

- पश्चिम महाराष्ट्र ने इस बार कांग्रेस-राकांपा पर जताया ज्यादा भरोसा
- मराठवाड़ा और कोंकण में फायदे में दिखा भाजपा-शिवसेना गठबंधन

महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में भाजपा की सीटों में आई कमी में भूमिका विदर्भ क्षेत्र की रही, जहां से स्वयं मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी चुनकर आते हैं। इसके अलावा कांग्रेस-राकांपा का गढ़ रहे पश्चिम महाराष्ट्र ने भी इस बार भाजपा-शिवसेना का साथ देने के बजाय कांग्रेस-राकांपा के साथ ही रहना बेहतर समझा।

62 सीटों वाले विदर्भ की खासियत रही है कि यह जिसके साथ जाता है, एकतरफा जाता है। 2014 में विदर्भ ने 44 सीटें भाजपा को, चार शिवसेना को, 10 कांग्रेस को और सिर्फ एक सीट राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को दी थी। इस बार भाजपा के खाते में सिर्फ 27 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। दूसरी ओर कांग्रेस को 17, राकांपा को छह और शिवसेना को फिर से चार ही सीटें मिली हैं। यदि भाजपा को विदर्भ ने पिछली बार जितनी ही सीटें दी होतीं, तो भाजपा कुल सीटों में भी पिछली बार के आंकड़े तक पहुंचने में कामयाब हो सकती थी। भाजपा नेताओं का दावा रहा है कि केंद्र और राज्य में भाजपानीत सरकार के कार्यकाल में कृषि संकट से जूझ रहे विदर्भ के लिए काफी काम किया गया है, लेकिन किसानों की आत्महत्याएं न रुकने से विपक्ष को सरकार के इस दावे पर सवाल खड़ा करने का मौका मिला। अब भाजपा की सीटों में आई कमी ने भाजपा को सोचने पर मजबूर कर दिया है।

देवेंद्र फड़नवीस। एपी

कांग्रेस और राकांपा से अनेक दिग्गज नेताओं की मेगा भर्ती कर चुकी भाजपा को उम्मीद थी कि इस बार कांग्रेस-राकांपा के गढ़ पश्चिम महाराष्ट्र में उसे बहुत अच्छी सफलता मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। पश्चिम महाराष्ट्र में पिछली बार भाजपा-शिवसेना को अलग-अलग लड़कर भी कुल 37 सीटें मिली थीं। इस बार गठबंधन में लड़ने के बावजूद इस क्षेत्र में 26 सीटों पर सिमट गई हैं। खासतौर से इस क्षेत्र में राकांपा को अच्छा फायदा हुआ है। इसी क्षेत्र में राकांपा और कांग्रेस छोड़कर आए उदयनराजे भोसले एवं हर्षवर्धन पाटिल जैसे नेता भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़कर हार गए हैं। इसी प्रकार उत्तर महाराष्ट्र में भी भाजपा-शिवसेना की सीटें घटी हैं। पिछली बार इस क्षेत्र से भाजपा को 14 और शिवसेना को सात सीटें मिली थीं। इस बार भाजपा को 13 और शिवसेना को पांच सीटें मिली हैं।

बहरहाल मराठवाड़ा और कोंकण में गठबंधन कुछ फायदे में दिख रहा है। मराठवाड़ा में पिछली बार भाजपा 15 और शिवसेना 11 सीटों पर जीती थी जबकि इस बार भाजपा को 16 और शिवसेना को 13 सीटें मिली हैं। इसी क्षेत्र की परली सीट से पंकजा मुंडे की हार ने मराठवाड़ा की उपलब्धि को उदासी में बदल दिया है। पूरे राज्य में गठबंधन के बावजूद कोंकण में शिवसेना-भाजपा कुछ सीटों पर आमने-सामने लड़ी। इसके बावजूद इस क्षेत्र में भाजपा अपने पिछले आंकड़े 10 पर कायम रही, तो शिवसेना पिछली बार के 14 से बढ़कर 17 पर पहुंचने में सफल हुई। आमने-सामने लड़ी गई सीटों में ही एक सीट कणकवली की थी, जहां भाजपा प्रत्याशी ने शिवसेना प्रत्याशी को हराकर जीत हासिल की।

भाजपा की सीटें मुंबई में भी बढ़ी हैं। पिछली बार मुंबई में भाजपा सिर्फ 15 सीटों पर जीती थी जबकि इस बार उसे 16 सीटें हासिल हुई हैं जबकि शिवसेना यहां घाटे में दिखाई दे रही है। पिछली बार की तुलना में उसे मुंबई ने दो सीटें कम दी हैं, लेकिन मुंबई की वरली सीट से शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के पुत्र आदित्य की भारी मतों से जीत से शिवसेना खुश है।

फीकी पड़ी रंगत

महाराष्ट्र के 2019 विधानसभा चुनावों के क्षेत्रवार नतीजे कम रोचक नहीं हैं। उदाहरण के लिए जिस गन्ना बेल्ट में पिछले चुनाव में भाजपा को 14 सीटें मिली थीं, इस बार 9 पर सिमट गई। शिवसेना भी 14 से घटकर 6 पर रही। कांग्रेस को भी यहां नौ सीटों का घाटा उठाना पड़ा जबकि राकांपा को 20 सीटों की बढ़त मिली। प्रदेश के क्षेत्रवार सियासी नतीजों पर एक नजर:

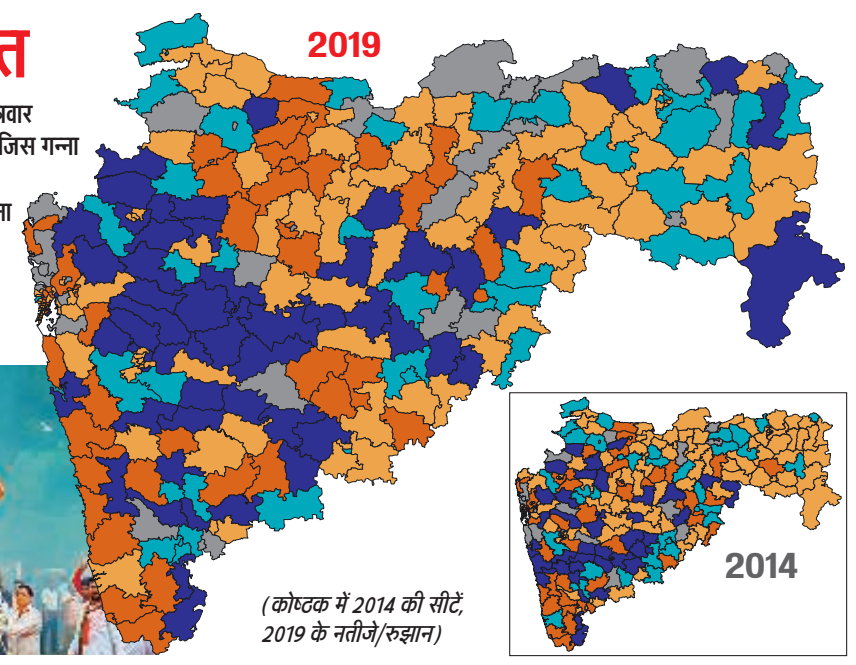

(कोष्ठक में 2014 की सीटें, 2019 के नतीजे/रुझान)

पार्टी	गन्ना बेल्ट	मराठवाड़ा	उत्तर महाराष्ट्र	कोंकण	विदर्भ	प. महाराष्ट्र	शहरी	ग्रामीण	नक्सल प्रभावित	मुंबई
भाजपा	9 (14)	14 (15)	13 (14)	11 (10)	27 (44)	18 (24)	48 (53)	50 (69)	5 (10)	15 (15)
शिवसेना	6 (14)	13 (11)	6 (7)	15 (14)	4 (4)	6 (13)	24 (24)	34 (39)	0 (1)	14 (14)
राकांपा	29 (9)	8 (9)	7 (7)	5 (1)	6 (10)	29 (10)	7 (10)	49 (32)	2 (2)	1 (5)
कांग्रेस	11 (20)	9 (8)	5 (5)	0 (8)	15 (1)	12 (19)	16 (7)	30 (34)	4 (0)	5 (0)
अन्य	5 (3)	2 (3)	4 (2)	8 (6)	10 (3)	5 (4)	4 (5)	26 (15)	2 (0)	1 (2)

महाराष्ट्र में उद्धव ने फेंका फिफ्टी-फिफ्टी का दांव

दिखाए तेवर ▸ शिवसेना प्रमुख ने कहा-जो तय किया गया था, उस पर चर्चा होनी चाहिए

बोले, मैं हर समय समझौता नहीं कर सकता

राज्य ब्यूरो, मुंबई

विधानसभा चुनाव परिणाम आते ही शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने अपने तीखे तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। उद्धव ने कहा कि नई सरकार के गठन के समय वह फिफ्टी-फिफ्टी फार्मूले को लागू करने पर दृढ़ हैं।

महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में भाजपा-शिवसेना को मिली जीत के बाद एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उद्धव से जब पूछा गया कि मुख्यमंत्री कौन बनने जा रहा है तो उन्होंने कहा कि हम भाजपा को वह फार्मूला याद दिलाना चाहते हैं जब पार्टी अध्यक्ष अमित शाह हमारे घर आए थे। तब हमने गठबंधन के लिए फिफ्टी-फिफ्टी का फार्मूला तय किया था। हम भाजपा से कम सीटों पर चुनाव लड़ने को राजी हुए थे, लेकिन हर समय मैं समझौता नहीं कर सकता। मैं अपनी पार्टी का विकास चाहता हूं।

उन्होंने कहा, महत्वपूर्ण सवाल यह है कि मुख्यमंत्री कौन होगा? जब लोकसभा चुनाव हुए थे तो हमने राज्य में फिफ्टी-फिफ्टी के फार्मूले पर फैसला किया था। चंद्रकांत पाटिल ने कुछ मुद्दे उठाए थे जिन्हें हमने समझा। फार्मूले को लागू करने के लिए अगर जरूरत है तो अमित (शाह) को भी आगे आना चाहिए।

मुंबई में विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद प्रेसवार्ता करते शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे। प्रेट्र

उद्धव ने कहा, जो तय किया गया था, उस पर चर्चा होनी चाहिए और फिर तय किया जाए कि मुख्यमंत्री कौन होगा। उन्होंने कहा कि नई सरकार गठन के पहले मैं अपने और भाजपा नेताओं से पारदर्शी और शांतिप्रिय तरीके से सरकार गठन के फार्मूले पर चर्चा करूंगा।

जनादेश को अनेक लोगों के लिए आंखें खोल देनेवाला बताते हुए उद्धव ने कहा कि जनता ने लोकतंत्र को जीवित रखा है। कोई भी ईवीएम पर सवाल नहीं उठा सकता। कहा कि राजनीतिक दलों को अपने पैर जमीन पर रखने चाहिए, नहीं तो जनता औकात दिखा देती है।

शरद पवार ने भाजपा-शिवसेना पर बोला हमला

चुनाव परिणामों के बाद 220 के लक्ष्य से पीछे रहने पर भाजपा-शिवसेना पर हमला बोलते हुए राकांपा नेता शरद पवार ने कहा कि जनता सत्ता का अहंकार बर्दाश्त नहीं करती। उन्होंने कहा कि जनता ने हमें विपक्ष की भूमिका निभाने को कहा है। हम सरकार गठन की कोशिश नहीं करेंगे। पवार ने कहा कि वे लोग (भाजपा-शिवसेना) 288 में 220 सीटें मिलने का दावा कर रहे थे जिसे जनता ने नकार दिया। राकांपा ने जनादेश स्वीकार कर लिया है। उन्होंने कहा कि जिन्होंने सत्ता के लिए दलबदल किया, जनता ने अस्वीकार कर दिया। पवार ने कहा कि जनता ने उदयनराजे भोसले का भाजपा में जाना स्वीकार नहीं किया। यह पूछने पर कि विपक्ष का नेता कौन होगा, उन्होंने कहा कि दिवाली बाद हम और हमारे गठबंधन के विधायक मिलेंगे और भविष्य की रणनीति तय करेंगे। उन्होंने यह भी साफ कर दिया कि शिवसेना के साथ गठबंधन नहीं होगा।

प्रेसवार्ता करते राकांपा अध्यक्ष शरद पवार। प्रेट्र

एक-दो दिन में गठबंधन की शर्तों के अनुसार नई सरकार पर फैसला : फड़नवीस

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस दावा कर रहे हैं कि इस बार भाजपा के कम सीटों पर लड़ने के बावजूद स्ट्राइक रेट, यानी लड़ी गई सीटों में से जीती गई सीटों की संख्या का फीसद अधिक रहा है। पिछली बार भाजपा का स्ट्राइक रेट 47 फीसद, जबकि इस बार 70 फीसद रहा है। फड़नवीस का मानना है कि उन्हें और शिवसेना का यह नुकसान भाजपा और शिवसेना के बागियों के कारण हुआ है, न कि कांग्रेस-राकांपा की मजबूती के कारण। फड़नवीस के अनुसार जीत के आए दोनों दलों के करीब 15 बागी विधायक उनसे संपर्क कर चुके हैं और भविष्य में वह अपने पूर्व दलों में शामिल हो सकते हैं। शिवसेना के साथ सरकार बनाने को लेकर पूरी तरह आश्वस्त फड़नवीस के अनुसार एक-दो दिन में ही वह शिवसेना नेताओं के साथ बैठकर गठबंधन की शर्तों के अनुसार फैसला कर लेंगे।

महाराष्ट्र की लातूर ग्रामीण सीट पर दूसरे स्थान पर रहा 'नोटा'

लातूर, प्रेट्र : महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में लातूर ग्रामीण सीट का नतीजा बेहद दिलचस्प रहा। यहां दूसरे नंबर पर 'नोटा' (उपरोक्त में से कोई नहीं) रहा। इस सीट से पूर्व मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख के बेटे धीरज देशमुख ने 1,35,006 (67.64 फीसद) वोट पाकर जीत हासिल की। यहां 'नोटा' को 27,500 वोट (13.78 प्रतिशत) मिले। तीसरे स्थान पर शिवसेना प्रत्याशी सचिन देशमुख रहे। उन्हें महज 13,459 वोट (6.78 प्रतिशत) वोट मिले। वंचित बहुजन अघाड़ी के उम्मीदवार मंचकराव चौथे स्थान पर रहे, उन्हें 12,966 (6.5 प्रतिशत) मिले। यहां से कुल 15 उम्मीदवार मैदान में थे और 16वां विकल्प 'नोटा' था।

रामदेव ने चेताया, शिवसेना को राजग से छीन सकता है विपक्ष

नई दिल्ली, एएनआइ : योग गुरु बाबा रामदेव ने गुरुवार को चेतावनी दी कि महाराष्ट्र में भाजपा को सतर्क रहना चाहिए क्योंकि विपक्ष शिवसेना को राजग से छीनने की फिराक में लगा है। रामदेव ने कहा कि महाराष्ट्र में भाजपा अगर शिवसेना को सफलतापूर्वक साथ लेकर चली तो सरकार बनना निश्चित है। लेकिन विपक्ष शिवसेना को राजग से छीनने के लिए उसे मुख्यमंत्री पद का प्रस्ताव भी दे सकता है। हरियाणा चुनाव परिणामों पर कहा जजपा के अध्यक्ष दुष्यंत चौटाला किंगमेकर हो सकते हैं।

चुनाव के नतीजों के बाद प्रधानमंत्री का अभिनंदन...

हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद नई दिल्ली भाजपा मुख्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अभिनंदन किया गया। इस दौरान पीएम मोदी को पुष्पमाला पहनाते केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी और पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा। प्रेट्र

बसपा ने महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष को हटाया, उप्र में भी बड़े फेरबदल की संभावना

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : महाराष्ट्र व हरियाणा विधानसभा के आम चुनाव और सूबे के उपचुनावों में बसपा को मिली करारी हार के बाद संगठन में खलबली मच गई है। नतीजों के पीछे सत्ताधारी भाजपा का षड्यंत्र देख रहीं मायावती ने अपने खेमे में भी निगाह टेढ़ी कर ली है। बसपा प्रमुख ने महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष सुरेश साखरे को पार्टी विरोधी गतिविधियों का जिम्मेदार मानते हुए निष्कासित कर दिया है। संभावना है कि उप्र और हरियाणा के संगठन में भी जल्द ही बड़े फेरबदल हो सकते हैं। उन्होंने संदेश दे दिया है कि संगठन में बड़े पैमाने पर फेरबदल हो सकता है।

उत्तर प्रदेश की 11 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में बसपा को कोई सीट न मिलने पर बसपा अध्यक्ष मायावती ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने इसे कार्यकर्ताओं का मनोबल गिराने का षड्यंत्र बताया है। नतीजे आने के बाद उन्होंने ट्वीट किया, 'यूपी विधानसभा आम चुनाव से पहले बीएसपी के लोगों का मनोबल गिराने के षड्यंत्र के तहत बीजेपी द्वारा इस उपचुनाव में सपा की कुछ सीटें जिताने व बीएसपी को एक भी सीट नहीं जीतने देने को पार्टी के लोग अच्छी तरह से समझ रहे हैं। वे उनके इस षड्यंत्र को फेल करने के लिए पूरे जी-जान से जरूर जुटेंगे।'

विधानसभा उपचुनाव

उप्र में भाजपा गठबंधन आठ व सपा तीन सीटों पर जीती

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

- 11 सीटों पर हुए उपचुनाव में बसपा और भाजपा को गंवानी पड़ी एक-एक सीट
- दो सीटों के फायदे में रही समाजवादी पार्टी

उत्तर प्रदेश में 11 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में सात सीटों पर भाजपा और एक सीट पर सहयोगी अपना दल (एस) ने जीत दर्ज की है। तीन सीटों पर समाजवादी पार्टी का परचम लहराया है। 2017 के सापेक्ष अगर इस चुनाव परिणाम का आकलन करें तो भाजपा और बसपा को एक-एक सीट गंवानी पड़ी है, लेकिन समाजवादी पार्टी को दो सीटों का लाभ हुआ है। भाजपा ने इस चुनाव को जीतने के लिए पूरी ताकत लगा दी थी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव सिर्फ रामपुर सीट पर प्रचार करने गये। बसपा और कांग्रेस के शीर्ष नेता कहीं नहीं गये।

गुरुवार को घोषित परिणाम के मुताबिक सहारनपुर की गंगोह सीट पर भाजपा के किरत सिंह ने कांग्रेस के नोमान मसूद को 5419 मतों से हरा दिया। रामपुर में डा. तजीन फातमा अपने पति सपा सांसद आजम खान की सीट बचाने में कामयाब हुई हैं। उन्होंने भाजपा के भारत भूषण के मुकाबले 7716 मतों से जीत दर्ज की। सपा के ही सुभाष राय ने अंबेडकरनगर की जलालपुर सीट पर बसपा की डा. छाया वर्मा को 790 मतों से हरा दिया। 2017 में यह सीट बसपा ने जीती थी।

बाराबंकी की जैदपुर सीट जीतने में भी सपा को कामयाबी मिली है। इस सीट पर सपा के गौरव कुमार ने भाजपा के अंबरीश रावत को 4165 मतों से हरा दिया। पिछली बार यह सीट भाजपा के खाते में थी। प्रतापगढ़ में अपना दल एस के राजकुमार पाल ने सपा के ब्रजेश वर्मा को 29721, लखनऊ कैंट में भाजपा के सुरेश तिवारी ने सपा के मेजर आशीष को 35428, कानपुर के गोविंदनगर में भाजपा के सुरेंद्र मैथानी ने कांग्रेस की करिश्मा ठाकुर को 21244, अलीगढ़ के इगलास में भाजपा के राजकुमार सहयोगी ने बसपा के अभय कुमार को 25937, चित्रकूट के मानिकपुर में भाजपा के आनन्द शुक्ल ने सपा के निर्भय पटेल को 12840 मतों से हराया है। बहराइच के बलहा में भाजपा की सरोज सोनकर ने सपा की किरन भारती को 43683 मतों से हराया जबकि घोसी में विजय राजभर ने सपा समर्थित सुधाकर सिंह को 1773 मतों से हरा दिया।

राजनीतिक दलों को मिले मतों का प्रतिशत	
भाजपा	35.64
सपा	22.61
बसपा	17.02
कांग्रेस	11.49
नोटा	0.85

राजस्थान में उपचुनाव परिणाम भाजपा के लिए अच्छे संकेत नहीं

मनीष गोधा, जयपुर : राजस्थान में दो सीटों झुंझुनूं जिले की मंडावा और नागौर जिले की खींवसर विधानसभा सीट के उपचुनाव परिणाम ने प्रतिपक्ष में बैठी भाजपा के लिए अच्छे संकेत नहीं दिए हैं। पार्टी ने अपने दम पर मंडावा का चुनाव लड़ा और वहां करारी हार हुई। खींवसर का चुनाव राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (रालोपा) के साथ मिलकर लड़ा था, ऐसे में वहां की जीत का लगभग पूरा श्रेय गठबंधन दल के मुखिया हनुमान बेनीवाल के खाते में चला गया। भाजपा ने यह चुनाव राज्य की कांग्रेस सरकार के 10 माह के कामकाज और राष्ट्रवाद के मुद्दे पर लड़ा था, पर परिणाम बता रहा है कि पार्टी के ये दोनों ही मुद्दे असर नहीं डाल पाए। ऐसे में नवंबर में होने वाले निकाय चुनाव पार्टी के लिए मुश्किल साबित हो सकते हैं। मंडावा में भाजपा ने अपने कार्यकर्ताओं की अनदेखी कर सुशीला देवी को टिकट दिया था, जो पहले कांग्रेस में थी। पार्टी को यहां करारी हार का सामना करना पड़ा। जाट मतदाता बहुल्य वाली इस सीट पर जीत के लिए भाजपा ने उपचुनाव से कुछ समय पहले ही सतीश पूनिया के रूप में एक जाट नेता को प्रदेश अध्यक्ष बनाया था और रालोपा के हनुमान बेनीवाल जैसे बड़े जाट चेहरे के साथ गठबंधन किया था। लेकिन, जाटों के वोट अधिक मिलने का भाजपा का अनुमान गलत साबित हो गया। खींवसर में भाजपा से गठबंधन कर चुनाव लड़ने वाली रालोपा के प्रत्याशी नारायण बेनीवाल ने जीत तो हासिल कर ली, लेकिन कांग्रेस ने यहां कड़ी टक्कर दी।

39 साल में पहली बार बस्तर संभाग भाजपा मुक्त

अनिल मिश्र, जगदलपुर : छत्तीसगढ़ का आदिवासी बहुल्य बस्तर संभाग 39 साल में पहली बार भाजपा मुक्त हो गया है। हाल में हुए दंतेवाड़ा उपचुनाव में भाजपा इस संभाग की अपनी इकलौती सीट नहीं बचा पाई थी। चित्रकोट सीट छीनने पर पूरा जोर लगाया, लेकिन गुरुवार को आए जनादेश ने भाजपा को मायूस कर दिया। इससे पहले राज्य के दूसरे आदिवासी बाहुल्य सरगुजा संभाग से भाजपा का सूपड़ा साफ हो गया था। अब राज्य में आदिवासी बेल्ट की विधानसभा सीटों पर भाजपा का एक भी विधायक नहीं है। इस बात को लेकर भाजपा के रणनीतिकार स्तब्ध हैं। वजह यह है कि बस्तर से निकला संदेश देशभर के आदिवासी बहुल्य राज्यों में जाता है।

बीजद की रीता साहू ने तोड़ा नवीन की जीत का रिकॉर्ड

जेएनएन, भुवनेश्वर : ओडिशा की बीजेपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में बीजद (बीजू पटनायक जनता दल) उम्मीदवार रीता साहू ने 97,990 मतों से जीत दर्ज कर पार्टी प्रमुख और मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की जीत का रिकॉर्ड तोड़ दिया। रीता को कुल 1,35,957 मत मिले। उनके निकटतम प्रतिद्वंदी भाजपा उम्मीदवार सनत गड़तिया को 37,967 एवं कांग्रेस के दिलीप पंडा को 5,876 मत मिले। इसी वर्ष लोकसभा चुनाव के साथ हुए विधानसभा में इस सीट पर खुद नवीन पटनायक ने चुनाव लड़ा था। उनको एक लाख 10 हजार 308 मत मिले थे। उनके प्रतिद्वंदी सनत गड़तिया को 53 हजार 482 मत मिले थे।

छत्रपति पर भारी पड़े क्षत्रप

राज्य ब्यूरो, मुंबई

- मतदाताओं को पसंद नहीं आया उदयनराजे भोसले का दलबदल करना
- 2009 से लगातार राकांपा के टिकट पर जीत रहे थे भोसले, इसी वर्ष छोड़ा साथ

इसी साल हुए लोकसभा के आम चुनाव में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के टिकट पर 1,26,528 मतों से जीत दर्ज करनेवाले छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज उदयनराजे भोसले को राकांपा छोड़कर भाजपा का दामन थामना भारी पड़ा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के साथ ही हुए सतारा संसदीय सीट के उपचुनाव में उन्हें पराजय का मुंह देखना पड़ा है। यह क्षेत्र हमेशा से कांग्रेस-राकांपा का मजबूत गढ़ माना जाता था।

कांग्रेस के टिकट पर यहां से यशवंतराव चह्वाण और प्रतापराव भोसले सरीखे दिग्गज चुनाव जीतकर संसद में जाते रहे। शरद पवार द्वारा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठन करने के बाद से यह सीट राकांपा के पास रहती आई है। राकांपा के ही टिकट पर 2009 से उदयनराजे भोसले लगातार चुने जाते रहे। छह माह पहले 2019 का लोकसभा चुनाव भी उन्होंने राकांपा के टिकट पर जीतने के बाद विधानसभा चुनाव से कुछ माह पहले ही उन्होंने राकांपा के साथ-साथ लोकसभा से भी त्यागपत्र दे दिया था।

विधानसभा चुनाव के साथ हुए सतारा लोकसभा सीट के उपचुनाव में वह भाजपा के टिकट पर मैदान में थे। दूसरी ओर मराठा क्षत्रप के नाम से मशहूर शरद पवार ने दो बार के सांसद रहे पूर्व प्रशासनिक अधिकारी एवं सिक्किम के पूर्व राज्यपाल श्रीनिवास पाटिल को उम्मीवारी दी और उनके पीछे अपनी पूरी ताकत झोंक दी। शरद पवार ने सतारा में ही चुनाव से दो दिन पहले बरसात में भीगते हुए चुनावी रैली को संबोधित किया।

राकांपा ने यहा नारा दिया था - मान छत्रपति की गद्दी का, मत राष्ट्रवादी पार्टी को। यहां उदयनराजे के पक्ष में सभा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी हुई। माना जा रहा है कि पवार और कांग्रेस के वर्षों पुराने जनाधार को अपनी व्यक्तिगत ताकत समझते रहे उदयनराजे भोसले का जीत के तीन महीने बाद ही इस्तीफा देकर दलबदल करना क्षेत्र की जनता को रास नहीं आया और उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा।

उदय हुआ ठाकरे परिवार का 'आदित्य'

मुंबई में गुरुवार को वर्ली विधानसभा सीट से जीत हासिल करने के बाद समर्थकों के साथ खुशी मनाते शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे। मिड-डे

यह पहला अवसर था, जब महाराष्ट्र के ठाकरे परिवार का कोई सदस्य सीधे चुनाव में उतरा। शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के पुत्र आदित्य न सिर्फ मुंबई की वरली सीट से चुनाव मैदान में उतरे, बल्कि अपने प्रतिद्वंद्वी राकांपा प्रत्याशी को उन्होंने 67,672 मतों से पराजित कर एक बड़े अंतर से जीत भी दर्ज कराई। अब तक ठाकरे परिवार रिमोट कंट्रोल से शासन चलाने के लिए जाना जाता रहा है। स्थानीय निकाय से लेकर विधानसभा या लोकसभा तक ठाकरे परिवार अपनी पार्टी के शिवसैनिकों को चुनवाकर भेजता रहा है, लेकिन शिवसेना संस्थापक बालासाहब ठाकरे से लेकर उनके पुत्र उद्धव और भतीजे राज तक कभी कोई स्वयं चुनाव मैदान में नहीं उतरा। 29 वर्षीय आदित्य को चुनाव लड़वाना शिवसेना को भविष्य के लिए तैयार करने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। माना जा रहा है कि इस बार आदित्य ठाकरे उपमुख्यमंत्री पद के भी दावेदार हो सकते हैं।

हारीं खडसे-मुंडे की बेटियां

भारतीय जनता पार्टी को दो जोर के झटके परली और मुक्ताई नगर विधानसभा सीटों पर लगे। परली में भाजपा के दिग्गज नेता रहे गोपीनाथ मुंडे की बेटी एवं फड़नवीस सरकार में ग्राम विकास मंत्री पंकजा मुंडे अपने ही चचेरे भाई राकांपा उम्मीदवार धनंजय मुंडे से चुनाव हार गईं। पंकजा पिछला चुनाव धनंजय को ही 25,895 मतों से हरा कर विधानसभा पहुंची थीं। ग्राम विकास मंत्री पद संभालने के दौरान पंकजा को चिक्की घोटाला समेत कुछ और घोटालों का सामना करना पड़ा था।

दूसरी ओर मुंडे कैंप के ही नेता माने जानेवाले उत्तर महाराष्ट्र के एकनाथ खडसे की बेटी रोहिणी खडसे भी चुनाव हार गईं। 2014 में मुक्ताई नगर सीट से चुनकर आने के बाद एकनाथ खडसे भाजपा में सीएम पद के प्रबल दावेदार थे। देवेंद्र फड़नवीस के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद उन्हें राजस्व मंत्री बनाया गया था, लेकिन कुछ संगीन आरोप लगने के बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। इस बार चुनाव घोषित होने के बाद उम्मीदवारों की सूचियों से नाम गायब होने के बाद उन्होंने बगावती तेवर दिखाने शुरू कर दिए थे। हालांकि बाद में उनकी पुत्री रोहिणी को पार्टी ने टिकट दिया, लेकिन खडसे बेटी की भी जीत का रास्ता नहीं निकाल सके।

गुजरात में अपनी सीट भी नहीं बचा पाए अल्पेश

राज्य ब्यूरो, अहमदाबाद : गुजरात में छह सीटों के लिए हुए उपचुनाव में सत्तारूढ़ भाजपा व कांग्रेस ने तीन-तीन सीटों पर जीत दर्ज की है। हालांकि, वर्चित ओबीसी नेता व कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए अल्पेश ठाकोर अपनी सीट भी नहीं बचा पाए। अहमदाबाद की अमराईवाड़ी सहित लूनावाड़ा व खेरालु सीट पर भाजपा का कब्जा बरकरार रहा। अमराईवाड़ी पर भाजपा के जगदीश पटेल ने कांग्रेस के धर्मेंद्र पटेल को, लूनावाड़ा पर भाजपा के जिगेश सेवक ने कांग्रेस के गुलाब सिंह को व खेरालु पर भाजपा के अजमलसिंह ठाकोर ने बाबूजी ठाकोर को हरा दिया। कांग्रेस ने राधनपुर व बायड सीटों पर कब्जा बरकरार रखते हुए थराद को भी 15 साल बाद भाजपा से छीन लिया। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर जिस राधनपुर सीट से अल्पेश ठाकोर जीते थे, वहीं से उपचुनाव में भाजपा के टिकट पर हार गए। उन्हें कांग्रेस प्रत्याशी रघुभाई देसाई ने हराया। अल्पेश के साथ ही भाजपा में शामिल हुए धवलसिंह झाला भी बायड की सीट नहीं बचा पाए। यहां कांग्रेस के जशु पटेल को जीत हासिल हुई। थराद सीट पर कांग्रेस के गुलाबसिंह राजपूत ने भाजपा के जीवराज पटेल को हरा दिया।

36.46 % वोट मिले हैं भाजपा को हरियाणा विधानसभा चुनाव में। पार्टी के वोट फीसद में 3.25 प्रतिशत का इजाफा हुआ है।

18 % वोट मिले हैं हरियाणा विधानसभा चुनाव में सबसे नई पार्टी जजपा को। वहीं, इनेलो का 22.25 प्रतिशत वोट खिसक गया है।

फड़नवीस व खट्टर पर भाजपा को फिर भरोसा

दिया श्रेय ▶ पीएम मोदी ने हरियाणा और महाराष्ट्र की जीत को बताया अभूतपूर्व

अमित शाह ने कहा, जनता ने पांच साल के काम पर मुहर लगाई

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

महाराष्ट्र और हरियाणा के विधानसभा चुनाव में भाजपा को भले ही पिछली बार की तुलना में कम सीटें मिली हों, लेकिन भाजपा नेतृत्व ने मनोहर लाल खट्टर और देवेंद्र फड़नवीस पर एक बार फिर भरोसा जताया है। साथ ही दोनों राज्यों की जनता को भरोसा भी दिया कि अगले पांच साल प्रदेश सरकार और जीजान से जनता की अपेक्षाओं को पूरा करेगी। भाजपा अध्यक्ष और गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्र की मोदी सरकार के कामकाज को अभूतपूर्व करार देते हुए कहा कि उसी अनुसार महाराष्ट्र और हरियाणा में भी मुख्यमंत्रियों ने पांच साल तक 'जीरो करप्शन' वाली सरकारें दीं।

हरियाणा में सबसे बड़ी पार्टी बनने और निर्दलीयों के समर्थन से दोबारा सरकार बनने की निश्चितता के बाद प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ने भाजपा कार्यालय में आकर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। दरअसल, यह संबोधन उत्साह बरकरार रखने के लिए भी था और अपेक्षाकृत कम सीटें आने के लिए प्रदेश नेतृत्व पर पार्टी के अंदर से किसी तरह के सवाल न उठें इसलिए भी था। प्रधानमंत्री मोदी ने पांच साल पहले तक दोनों राज्यों में भाजपा की हैसियत याद दिलाते हुए कहा कि हरियाणा में भाजपा को कोई गंभीरता से नहीं लेता था और गठबंधन की स्थिति में भी पांच से 10 सीटें ही मिलती थीं। इसी तरह महाराष्ट्र में भाजपा लगातार शिवसेना की बी टीम के रूप में रही। 2014 के बाद यह स्थिति बदली। अनुभवहीन देवेंद्र फड़नवीस और मनोहर लाल खट्टर ने पिछले पांच साल में जनता को ईमानदार और सबको साथ लेकर चलने वाली सरकार देने का काम किया और जनता ने उस पर मुहर लगा दी है। उन्होंने भरोसा दिया, 'अगले पांच साल हरियाणा और महाराष्ट्र के विकास की ऊंचाइयों को पार करने वाला काल रहेगा।'

महाराष्ट्र और हरियाणा में भाजपा के प्रदर्शन को खराब कहने को अनुचित बताते हुए प्रधानमंत्री ने दोनों राज्यों में जीत को अभूतपूर्व करार दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे दौर में जब राज्यों में किसी दल के दोबारा जीतने की घटनाएं काफी कम होती हैं, हरियाणा में न सिर्फ सबसे बड़ी पार्टी के रूप में सामने आना, बल्कि पिछली बार 33 फीसद तुलना में 36 फीसद वोट हासिल करना बड़ी बात है।

देवेंद्र फड़नवीस। एपी

मनोहरलाल खट्टर। फाइल

जबकि पांच साल में सरकार से थोड़ी बहुत नाराजगी होना स्वाभाविक बात है। वहीं, महाराष्ट्र में पिछले 50 में पांच साल का कार्यकाल पूरा करने वाले देवेंद्र फड़नवीस पहले मुख्यमंत्री हैं। युवा और नया नेतृत्व होने के बावजूद फड़नवीस ने बिना किसी दाग के सरकार चलाई। उन्होंने दोनों राज्यों की जनता को जीत के लिए धन्यवाद देते हुए भरोसा दिया कि अगले पांच साल में और भी ज्यादा मेहनत करेंगे।

वहीं, अमित शाह ने भी हरियाणा और महाराष्ट्र के भाजपा के परंपरागत राज्य नहीं होने बावजूद हुई जीत का श्रेय देवेंद्र फड़नवीस और मनोहर लाल खट्टर को दिया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की दूसरी पारी में हुए पहले दोनों ही चुनावों में भाजपा की जीत के खास मायने हैं। इसके साथ ही उन्होंने साफ कर दिया कि अगली बारी दिल्ली की है। अनियमित कॉलोनियों को नियमित करने के फैसले की ओर ध्यान दिलाते हुए उन्होंने कहा किो मोदी सरकार ने दिल्ली को दिवाली का तोहफा दिया है।

बादल बनेंगे हरियाणा में भाजपा के संकट मोचक!

इन्द्रप्रीत सिंह, चंडीगढ़ : शिरोमणि अकाली दल के सरपरस्त और पंजाब के तीन बार मुख्यमंत्री रहे सरदार प्रकाश सिंह बादल हरियाणा में भाजपा के लिए संकटमोचक बनकर उभरे हैं। चर्चा है कि भाजपा के अनुरोध पर बादल जननायक जनता पार्टी के दुष्यंत चौटाला को उसके करीब लाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। अकाली दल से जुड़े सूत्रों ने बताया कि भाजपा ने जजपा को भाजपा के करीब लाने का काम शिअद को सौंपा है। बादल के अलावा दोनों पार्टियों के पास शायद ही कोई नेता ऐसा हो जो उनमें समझौता करा सके। दरअसल, चौटाला परिवार और बादल परिवार के आपसी संबंध बहुत गहरे हैं। कई सालों से दोनों परिवार मिलकर ही चुनाव लड़ते रहे हैं, लेकिन चौटाला परिवार में आई दरार के बाद बादल परिवार के सामने संकट रहा कि वह किसके साथ जाए। प्रकाश सिंह बादल ने अजय चौटाला और अभय चौटाला के बीच समझौता करवाने की कोशिश की। उन्होंने दुष्यंत चौटाला से भी बात की, लेकिन कामयाब नहीं हो सके। अजय और दुष्यंत बादल की काफी इज्जत करते हैं। अकाली दल के वरिष्ठ उपप्रधान व पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉ. दलजीत सिंह चीमा ने कहा कि प्रकाश सिंह बादल गांव में हैं, इसलिए मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि बादल क्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि चौटाला परिवार के साथ बादल के मधुर संबंध हैं।

किसमें कितना दम

हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों को समझने और मतदाताओं के मूड को जानने-परखने के लिए प्रदेश का सियासी क्षेत्रों के आधार विश्लेषण अहम है। भौगोलिक स्थिति, मुद्दों और सियासत के आधार पर प्रदेश को तीन हिस्सों में बांटा जाता है। जीटी रोड बेल्ट, मध्य हरियाणा और दक्षिण हरियाणा। जीटी रोड बेल्ट में कांग्रेस पर पिछले चुनाव की तुलना में इस बार मतदाताओं की इनायत रही। मध्य हरियाणा में भी कांग्रेस को फायदा दिखा। उसकी सीटें आठ से बढ़कर 11 पहुंच गई।

गढ़ रहे मध्य हरियाणा से इनेलो का पत्ता हुआ साफ। 11 से एक सीट पर सिमटी

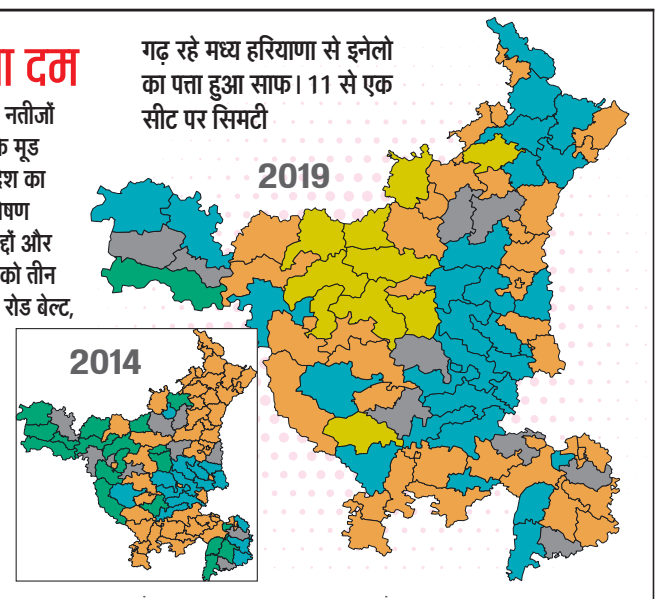

पार्टी	जीटी रोड बेल्ट		मध्य हरियाणा		दक्षिण हरियाणा	
	2019	2014	2019	2014	2019	2014
भाजपा	17	24	8	9	15	14
कांग्रेस	14	6	11	8	6	3
जजपा	5	0	5	0	0	0
इनेलो	0	4	1	11	0	4
हलोपा	–	–	1	0	–	–
अकाली	–	–	0	1	–	–
बसपा	–	–	–	–	0	1
निर्दलीय	2	4	3	0	2	1
कुल	38	38	29	29	23	23
जिले	सोनीपत, पानीपत, जींद, कैथल, कुरुक्षेत्र, करनाल, यमुनानगर, अंबाला पंचकूला		सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, चरखी दादरी, भिवानी, रोहतक, झज्जर		गुरुग्राम, नूंह, फरीदाबाद, पलवल, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़	

संगठन और सरकार के बीच गहरी होती गई खाई

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़ : हरियाणा में 75 से अधिक सीटें जीतने के लक्ष्य के साथ दूसरी बार सरकार बनाने का भाजपा का सपना यूं ही नहीं टूटा। इसके पीछे कई अहम वजह रहीं। भाजपा को जहां संगठन और सरकार के बीच गहरी होती खाई के कारण नुकसान उठाना पड़ा, वहीं पार्टी में कार्यकर्ताओं की नाराजगी ने उसके अभियान को रोक दिया।

भाजपा के प्रांतीय नेताओं ने कभी संगठन और सत्ता के बीच की खाई पाटने की कोशिश नहीं की। इसका नतीजा अब पराजय के रूप में सामने आया है। हालांकि भाजपा के वोट बैंक में पहले से बढ़ोतरी हुई है, लेकिन इन चुनाव नतीजों के आधार पर भाजपा को आत्ममंथन कर सबक लेने की जरूरत है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ को चुनाव से करीब एक पखवाड़े पहले ही भाजपा की सीटों में कमी का आभास हो गया था। रात को एक-एक बजे तक चली बैठकों में इस संभावित हार को जीत में बदलने की कोशिश भी हुई, मगर कुछ भाजपा नेताओं के जीत के अति विश्वास की वजह से आरएसएस को अपने इन प्रयासों में सफलता नहीं मिल पाई।

भाजपा ने इस बार लोकसभा चुनाव में जीत के लिए पन्ना प्रमुख और बूथ प्रमुख का कांसेप्ट दिया था। इसी के आधार पर भाजपा विधानसभा चुनाव भी जीतने के प्रति आश्वस्त थी। आरएसएस इस नतीजे पर पहुंचा था कि इस कांसेप्ट पर धरातल पर जाकर वास्तव में काम ही नहीं किया गया। इस पर अब गहराई से मंथन की जरूरत है। भाजपा के इस बार जितने भी नेता चुनाव हारे, वह अधिकतर संघ की पृष्ठभूमि वाले हैं। इनमें जाट नेताओं के साथ-साथ करीब एक दर्जन गैर जाट नेता भी शामिल हैं। संघ से आने के बावजूद उन्होंने परंपरा को कायम नहीं रखा।

मुद्दों की अनदेखी पड़ी भारी : 40 साल तक वनवास झेलने के बाद पांच साल पहले सत्ता में आई भाजपा प्रचार के दौरान हरियाणा के लोगों की नब्ज नहीं पकड़ सकी। उसने प्रचार के दौरान हरियाणा के मुद्दों की बजाए राष्ट्रीय मुद्दों को उठाया। प्रचार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सात और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने 15 बड़ी रैलियां की।

चमत्कार के बावजूद किंग मेकर नहीं बन पाएगी जजपा

बिजेंद्र बंसल, नई दिल्ली

पूर्व उपप्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल के राजनीतिक घराने की पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल से अलग होकर 11 माह पहले नई बनी जननायक जनता पार्टी (जजपा) ने बेशक हरियाणा में बड़ा राजनीतिक चमत्कार किया है, लेकिन नई सरकार के गठन में वह किंग मेकर की भूमिका में नहीं रहेगी।

अपने पहले विधानसभा चुनाव में जजपा दस सीटों पर विजेता और 10 ही सीटों पर उपविजेता रही है। उसकी यह उड़ान और फिर सत्तारूढ़ दल के बहुमत से दूर होने के कारण साफ है कि नई सरकार के गठन बाद भी दुष्यंत चौटाला की पार्टी की अहम भूमिका रहेगी। हालांकि उसने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं मगर माना जा रहा है कि वह अगर किंग मेकर के रूप में नहीं तो मजबूत विपक्षी दल के रूप में राजनीतिक परिदृश्य पर दिखाई देगी। उसके हाथ में सत्ता से टकराने की चाबी रहेगी। सत्तारूढ़ भाजपा को यदि खुद के बूते 40 और सात जीते निर्दलीयों में से छह का समर्थन नहीं मिलता तो जजपा और बड़ी भूमिका में आ सकती थी।

दुष्यंत संभालेंगे देवीलाल की विरासत : हरियाणा की सरकार पांच साल पहले तक सियासी घरानों से चलती रही है, मगर भाजपा की मनोहर सरकार के दौरान ये घराने हाशिए पर आ गए थे। चौधरी देवीलाल का घराना और सियासी विरासत दो हिस्सों में बंट गई थी। कांग्रेस में भी पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा परिवार अपनी सियासी विरासत को बचाने की चुनौती से जूझते रहे। पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल और बंसीलाल की सियासी विरासत भी सत्ता के नजदीक नहीं पहुंच पाई। मगर इस बार के नतीजों से साफ है कि देवीलाल की राजनीतिक विरासत अब जजपा नेता दुष्यंत चौटाला के पास पहुंच गई है। दुष्यंत ने 90 सीटों में से 20 पर अपना वजूद दिखाकर साबित कर दिया है कि वही देवीलाल की राजनीति और विचारों के असल वारिस हैं। देवीलाल परिवार की मूल पार्टी इनेलो 90 में सिर्फ दो ही सीटों पर अपना वजूद दिखा पाई जबकि जीत सिर्फ एक ही सीट पर हुई। वहीं, जजपा ने दस सीटों पर विजेता और दस सीटों पर उपविजेता के रूप में अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन किया है।

मतगणना के बाद उचाना से जजपा प्रत्याशी दुष्यंत चौटाला को जीत का प्रमाण पत्र देते अधिकारी। जागरण

इनेलो का नहीं होता बिखराव तो होती स्थिति मजबूत

यदि विघटन नहीं होता तो सहयोगी बसपा के साथ इनेलो मजबूत स्थिति में होता। अब भी दोनों दलों के मत फीसद मिला लिए जाएं तो ये कांग्रेस के मत फीसद पर भारी पड़ेंगे। इनेलो के 2.32 के अलावा बसपा ने भी 3.92 फीसद मत इस चुनाव में पाए हैं।

देवीलाल के परिवार से इस बार पांच विधायक

सिरसा जिले के चौटाला गांव के चौ. देवीलाल परिवार के एक साथ पहली बार पांच सदस्य विधानसभा में पहुंचे हैं। इनमें दुष्यंत चौटाला, नैना चौटाला, अभय चौटाला, आदित्य देवीलाल और रणजीत सिंह शामिल हैं।

कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में मिले मत फीसद को रखा बरकरार

1991 में कांग्रेस पार्टी को हरियाणा में करीब चालीस फीसद मत हासिल होते थे। यानी हर सौ वोट में से चालीस वोट कांग्रेस पार्टी को मिलते थे। क्षेत्रीय दलों के उभार ने भी कांग्रेस की इस बादशाहत को चुनौती नहीं पेश की। हालांकि भाजपा की सुस्त लेकिन सधी शुरुआत ने कांग्रेस सहित क्षेत्रीय दलों के वोट बैंक में सेंधमारी की कोई कसर नहीं छोड़ी।

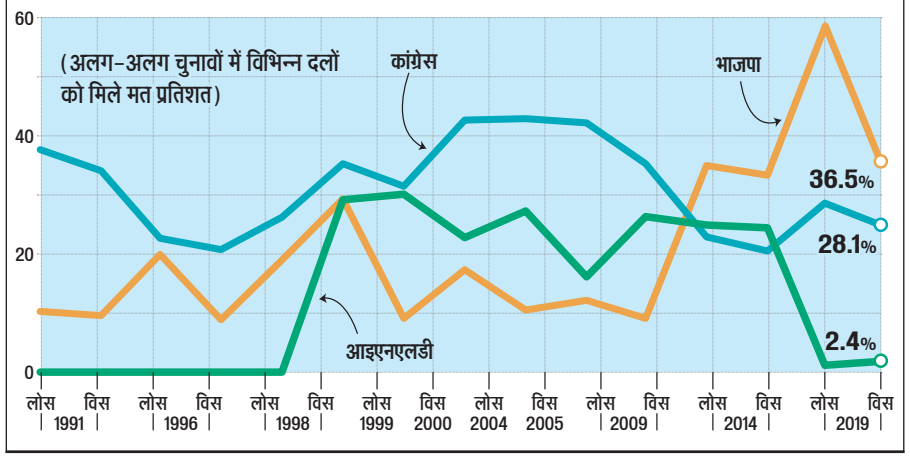

दी जीत की बधाई...

हरियाणा के हिसार में आदमपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी कुलदीप बिश्नोई के जीतने पर उनकी पत्नी रेणुका बिश्नोई को बधाई देती भाजपा प्रत्याशी सोनाली फोगाट (पीली साड़ी में)। फेमस टिक-टॉक स्टार सोनाली को कुल 34,222 वोट मिले हैं, जबकि उन्हें हराने वाले कुलदीप बिश्नोई को 69,693 वोट मिले हैं। जागरण

नतीजों ने दी कांग्रेस को हौसले भरी उम्मीद

संजय मिश्र, नई दिल्ली

कांग्रेस के लिए हरियाणा में चाहे जीत थोड़ी दूर रह गई हो और महाराष्ट्र की सत्ता एक बार फिर हाथ नहीं आई हो। फिर भी दोनों सूबों के नतीजों ने पार्टी को सियासी चुनौतियों से उबरने की नई उम्मीद जरूर दे दी है। चुनावी राजनीतिक विमर्श में विपक्षी मुद्दों के नैरेटिव को जगह नहीं मिल पाने की निराशा में कांग्रेस ने वैसे तो दोनों सूबों में मुकाबले की हिम्मत पहले ही छोड़ दी थी, मगर मतदाताओं ने कांग्रेस की झोली में उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा सीटें डालकर उसे निराशा के दौर से सहसा जगा दिया है।

लोकसभा चुनाव की हार और राहुल गांधी के अध्यक्ष पद से इस्तीफे के दोहरे झटके का सामना कर रही कांग्रेस मुकाबले को सम्मानजक बनाने की उम्मीद भी छोड़ चुकी थी। खासकर चुनाव से ठीक पहले महाराष्ट्र में कांग्रेस के अंदर जैसा जबर्दस्त बिखराव हुआ। उसके कई बड़े नेता भाजपा या शिवसेना में चले गए। पार्टी की सियासी स्थिति ऐसी हो गई कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने भी चुनाव प्रचार में दम लगाना मुनासिब नहीं समझा। हरियाणा में भी पार्टी की स्थिति इससे बहुत अलग नहीं रही।

अपनी अंदरूनी चुनौतियों से जूझ रही कांग्रेस की मुश्किलों को चुनाव अभियान के दौरान

- **जनता का संदेश साफ, कांग्रेस बने मजबूत विपक्षी विकल्प**
- **हरियाणा-महाराष्ट्र में नहीं लगाया दम मगर मिलीं उम्मीद से ज्यादा सीटें**

अनुच्छेद 370, तत्काल तीन तलाक, राष्ट्रवाद और पाकिस्तान जैसे मुद्दों पर भाजपा के शीर्ष नेतृत्व की गर्जनाओं ने और बढ़ाया। लोकसभा चुनाव में ऐसे ही संवेदनशील मुद्दों पर मात खा चुकी कांग्रेस इन मसलों पर दोनों सूबों में सहमी ही नजर आई। कांग्रेस के अपने सियासी विमर्श को इन मुद्दों से दूर रखने की कोशिशें इस बात का साफ संकेत थीं। शायद यही वजह रही कि दोनों सूबों में कांग्रेस जनता को भाजपा को दमदार चुनौती देने में सक्षम होने का संदेश नहीं दे पाई। हरियाणा के नतीजे तो कम से कम इसी ओर इशारा कर रहे हैं।

चुनाव अभियान में कांग्रेस जनता को भले ही दोनों सूबों में दमदार विकल्प होने का संदेश नहीं दे पाई मगर जनता ने नतीजों के जरिये अपना स्पष्ट संदेश दे दिया। जनता का संदेश साफ है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में उसे केवल एक दलीय सत्ता नहीं बल्कि मजबूत वैकल्पिक विपक्ष भी चाहिए। इसीलिए उम्मीद की जानी चाहिए कि अपनी लचर राजनीतिक रणनीति के दौर को विराम देते हुए देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस जनता के इस संदेश को गंभीरता से लेगी। इन चुनावों में सत्ता भले न मिली हो मगर जनता ने कांग्रेस को भविष्य का सियासी हौसला तो दे ही दिया है। नतीजों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने इसे लोकतंत्र को अक्षुण्ण रखने वाला परिणाम बताकर इस संदेश की गंभीरता का अहसास होने की बात कबूल भी की। शर्मा ने यह भी जोड़ा कि लोकतंत्र में जो संतुलन बिगड़ रहा था उसे जनता ने काबू में लाने का काम किया है। शायद जनता के इस गंभीर संदेश का ही असर रहा कि आनंद शर्मा ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नेतृत्व सौंपने में हुई देरी से हरियाणा में नुकसान की बात खुले तौर पर कबूल की। चुनाव नतीजे कांग्रेस के लिए इस लिहाज से भी मायने रखते हैं कि केवल राष्ट्रीय मुद्दों के सहारे ही सूबों के चुनाव लंबे समय तक प्रभावित नहीं किए जा सकते।

'लोग मुश्किल में हों तो काम नहीं आता कट्टर राष्ट्रवाद'

नई दिल्ली, प्रेट्र : महाराष्ट्र और हरियाणा चुनाव परिणामों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए माकपा ने गुरुवार को कहा कि जब लोग मुश्किल में रह रहे हों तो कट्टर राष्ट्रवाद काम नहीं आता। माकपा महासचिव सीताराम येचुरी ने कहा, 'सिर्फ इन दो राज्यों के ही नहीं बल्कि गुजरात, बिहार और केरल में हुए उपचुनावों के परिणाम भी यह दिखाते हैं कि जब लोग नौकरियों और आर्थिक मंदी के कारण मुश्किल में हों तो सांप्रदायिक कट्टर राष्ट्रवाद काम नहीं आता। लोगों की तरफ से संदेश साफ है कि भाजपा को पीछे धकेल दिया गया है।' वहीं, भाकपा महासचिव डी. राजा ने कहा, 'लोगों ने उन्हें अपना फैसला सुनाया है कि उन्हें हलके में नहीं लिया जा सकता। उन्होंने बता दिया है कि असली मुद्दे क्या हैं- बेरोजगारी, रुपये में गिरावट आदि।

हरियाणा में चुनाव प्रबंधन में चूक हुई : कैलाश

जासं, कोलकाता : हरियाणा विधानसभा चुनाव में भाजपा के खराब प्रदर्शन पर पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव व बंगाल के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि वहां चुनाव के प्रबंधन में चूक हुई। चुनाव नतीजों पर पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि हरियाणा में पिछले पांच वर्षों में भाजपा सरकार ने शानदार काम किया था, लेकिन हमें लगता है कि पार्टी व मतदाताओं के बीच कुछ कम्युनिकेशन गैप रह गया। उन्होंने कहा कि चुनाव जीतने के लिए मैनेजमेंट अहम होता है। हमें लगता है कि चुनावी मैनेजमेंट (प्रबंधन) करने में थोड़ी कमी रह गई। अच्छा काम करने के बावजूद संवाद में कमी के कारण शायद मतदाताओं तक यह संदेश नहीं पहुंचा सके।

पुराने क्षत्रप ही बन रहे कांग्रेस के संकटमोचक

संजय मिश्र, नई दिल्ली

हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि कांग्रेस को अपनी राजनीतिक वापसी के लिए क्षेत्रीय क्षत्रपों का ही सहारा लेना होगा। त्रिशंकु विधानसभा की हालत में सत्ता की तराजू भले ही भाजपा के पक्ष में झुक जाए मगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा में कांग्रेसी सियासत के तराजू को एक बार फिर मजबूती से पकड़ लिया है। हरियाणा ही नहीं बीते तीन साल में आधा दर्जन राज्यों के चुनाव नतीजों से साफ है कि पुराने क्षत्रप ही कांग्रेस के संकटमोचक बन रहे हैं।

हरियाणा के नतीजों के बाद शायद इसीलिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सूबे की कमान आखिरी समय में देने की कांग्रेस नेतृत्व की रणनीति पर सवाल उठाए जा रहे हैं। हाईकमान ने काफी मशक्कत के बाद हुड्डा को कमान तब सौंपी जब चुनाव में महीनेभर का भी समय नहीं रह गया था। वैसे यह फैसला भी सोनिया गांधी के दोबारा अध्यक्ष बनने के बाद तब हुआ जब हुड्डा ने कांग्रेस छोड़ने तक की चेतावनी दे डाली। राहुल गांधी अध्यक्ष रहते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सूबे की कमान सौंपने को तैयार नहीं थे। मगर हरियाणा चुनाव में हुड्डा ने तमाम राजनीतिक पंडितों को गलत साबित करते हुए कांग्रेस की सीटों का आंकड़ा 30 के पार करा दिया। जबकि चुनाव से पहले ही नहीं, मतदान के बाद भी खुद कांग्रेस नेताओं की उम्मीद पार्टी का आंकड़ा बमुश्किल दोहरे अंकों तक पहुंचने से ज्यादा नहीं थी। मगर हुड्डा ने कुमारी सैलजा के साथ मिलकर महीनेभर में ही पार्टी के ग्राफ को सत्ता की होड़ तक ला खड़ा किया है।

हरियाणा से पहले पड़ोसी राज्य पंजाब में भी 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत की कहानी कम दिलचस्प नहीं रही थी। पंजाब में आम आदमी पार्टी के बढ़ते ग्राफ की गूंज के बीच कैप्टन अमरिंदर ने अकाली-भाजपा के साथ आप की दोहरी चुनौती को धराशायी करते हुए कांग्रेस की जीत का परचम लहराया। वैसे कैप्टन अमरिंदर को भी कांग्रेस ने सूबे की चुनावी कमान बिल्कुल अंतिम में दी थी और मुख्यमंत्री उम्मीदवार तो उन्हें चुनाव अभियान के दौरान घोषित किया गया। दिलचस्प यह है कि राहुल गांधी उस समय भी कैप्टन अमरिंदर को नेतृत्व सौंपने के पक्ष में नहीं थे। तब नाराज कैप्टन के अलग क्षेत्रीय पार्टी बनाने तक की अटकलें उड़ीं थी। उस वक्त भी सोनिया गांधी ने दखल देते हुए दस जनपथ में राहुल के साथ कैप्टन अमरिंदर की बैठक कराई और फिर उन्हें प्रदेश कांग्रेस की चुनावी बागडोर सौंपी गई। चुनाव नतीजों के बाद साफ हो गया कि कैप्टन की वजह से ही कांग्रेस को पंजाब की सत्ता मिली।

क्षेत्रीय नेताओं के सहारे गुजरात के 2017 के चुनाव में भाजपा को बेहद कांटे की टक्कर देने का अनुभव तो खुद राहुल गांधी ने सीधे महसूस किया। मगर 2018 में बात जब मध्य प्रदेश की आई तो मामला एक बार फिर पुराने दिग्गजों और नई पीढ़ी के नेतृत्व के बीच फंसा। इसीलिए मध्य प्रदेश में कमलनाथ को कांग्रेस का चेहरा बनाने में भी देरी हुई। लेकिन यहां भी दिग्गज कमलनाथ ने दूसरे क्षत्रप दिग्विजय सिंह को साथ लेकर भाजपा को शिकस्त देते हुए 15 साल बाद कांग्रेस की सत्ता में वापसी कराई। छत्तीसगढ़ में भी पार्टी के पुराने भरोसेमंद नेता भूपेश बघेल पर दांव लगाना कांग्रेस के लिए फायदेमंद रहा। सूबे में 15 साल बाद पार्टी की सत्ता में वापसी ही नहीं हुई बल्कि भाजपा को सूबे में अपनी सबसे करारी पराजय का सामना करना पड़ा। कर्नाटक में बेशक कांग्रेस को पिछले चुनाव में सत्ता गंवानी पड़ी मगर सिद्दरमैया की वजह से पार्टी की राजनीतिक ताकत बरकरार रही। शायद इसीलिए येदियुरप्पा सरकार बनने के बाद सोनिया गांधी ने सूबे के तमाम नेताओं के एतराज को दरकिनार करते हुए सिद्दरमैया को हाल ही में कर्नाटक में विपक्ष का नेता बनाकर एक बार फिर क्षत्रप पर ही भरोसा करने का संदेश दिया।

भूपेंद्र सिंह हुड्डा।

कैप्टन अमरिंदर सिंह।

भूपेश बघेल। सभी फाइल

कमलनाथ। फाइल

कमलनाथ के प्रबंधन से कांग्रेस की झोली में आया झाबुआ

ऋषि पाण्डे, झाबुआ : मध्य प्रदेश के झाबुआ विधानसभा उपचुनाव को मुख्यमंत्री कमलनाथ के राजनीतिक प्रबंधन की सफलता के तौर पर देखा जाना चाहिए। दरअसल, दस माह पहले जिस सीट पर पार्टी दस हजार से ज्यादा वोटों से हारी हो, वहां उपचुनाव में तीन गुना अंतर से जीत दर्ज करना साबित करता है कि उन्होंने आदिवासी मतदाता को कांग्रेस से जुदा नहीं होने दिया। विधानसभा में कांग्रेस का आंकड़ा उस जादुई अंक के करीब आ गया है, जिसे देखकर सरकार गिराने की धमकी देना भाजपा के लिए मुश्किल होगा। कांतिलाल के जीतते ही कांग्रेस का आंकड़ा 115 पर पहुंच गया है, अब जादुई आंकड़े का अंतर महज एक का रह गया है। वहीं, भाजपा को न सिर्फ एक सीट का नुकसान हुआ, बल्कि बहुमत के लिए जरूरी अंक के लिए फासला बढ़कर आठ विधायकों का हो गया। नवंबर 2018 में हुए विस चुनाव में कांतिलाल भूरिया के बेटे डॉ. विक्रांत भूरिया चुनाव हार गए थे। उन्हें भाजपा के गुमान सिंह डामोर ने हराया था। तब कांग्रेस के बागी जेवियर मेढ़ा भी मैदान में थे, जो विक्रांत की हार की वजह बने। भाजपा इस चुनाव में ऐसे ही किसी मेढ़ा के इंतजार में थी, लेकिन कमलनाथ ने मेढ़ा और भूरिया को उन्होंने टिकट वितरण के समय ही साथ-साथ बैठाया और कांतिलाल भूरिया के नाम पर सहमत कर लिया। उनके मुकाबले इस बार भाजपा ने नए चेहरे भानू भूरिया पर दांव लगाया था।

हरियाणा में दिग्गजों को मिली हार

अनुराग अग्रवाल, चंडीगढ़ : हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे कई मामलों में चौंकाने वाले रहे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल तो करनाल से चुनाव जीत गए, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज और जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी राज्यमंत्री डॉ. बनवारी लाल को छोड़कर उनकी कैबिनेट के आठ मंत्री चुनाव हार गए। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा व कुमारी सैलजा के नेतृत्व में कांग्रेस ने 31 सीटों पर जीत हासिल की।

जननायक जनता पार्टी के संयोजक और पूर्व सांसद दुष्यंत सिंह चौटाला के पक्ष में आए नतीजों ने दिग्गजों को चकित कर दिया। दुष्यंत और उनकी मां नैना चौटाला समेत 10 विधायक चुनाव जीते हैं। हरियाणा लोकहित पार्टी के गोपाल कांडा भी चुनाव जीत गए। हालांकि उनके भाई गोबिंद कांडा को हार नसीब हुई। मनोहर की टीम में शामिल रामबिलास शर्मा, कैप्टन अभिमन्यु और ओमप्रकाश धनखड़ जैसे नेता चुनाव हारे हैं। वहीं, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला को भी कैथल से निराशा हाथ लगी। बीते साल हुए जींद विधानसभा उपचुनाव में भी वह हार गए थे। जाट आंदोलन को लेकर चर्चित रहे पूर्व भाजपा सांसद राजकुमार सैनी भी चुनाव हार गए हैं। भाजपा में शामिल होने वाले खिलाड़ियों व कलाकारों में सिर्फ भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान संदीप सिंह ही चुनाव जीत सके। अंतरराष्ट्रीय महिला पहलवान बबीता फोगाट, ओलंपियन पहलवान योगेश्वर दत्त और टिक-टॉक गर्ल सोनाली फोगाट भी चुनाव हार गईं।

चुनाव परिणाम भाजपा की नैतिक हार : कांग्रेस

नई दिल्ली, प्रेट्र : कांग्रेस ने गुरुवार को कहा कि हरियाणा और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव परिणाम भाजपा की नैतिक हार हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता आनंद शर्मा ने कहा, भाजपा अध्यक्ष अमित शाह का हरियाणा में जीत का दावा सही नहीं है क्योंकि वहां पार्टी बहुमत से दूर है और उसके वोट प्रतिशत में भी उल्लेखनीय कमी आई है। आनंद शर्मा ने दावा किया कि हरियाणा के चुनाव परिणाम भाजपा के खिलाफ हैं। वहीं, वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम ने ट्वीट कर कहा, 'कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भरोसा होना चाहिए कि भाजपा को हराया जा सकता है। शांत राष्ट्रभक्ति जबर्दस्ती के राष्ट्रवाद को हरा सकती है।'

11000 दीये से दीपावली पर जगमग होगा तख्त श्रीहरिमंदिर पटना साहिब। ऐसा ईको फ्रेंडली दीपावली मनाने के लिए किया जाएगा। यह जानकारी प्रबंधक समिति के महासचिव सरदार एमपीएस ढिल्लन व सचिव सरदार एमएस छाबड़ा ने दी।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
शुक्रवार 25 अक्टूबर 2019

पक्षकार की मांग : कोई मालिक साबित न हो तो सरकार को दें विवादित भूमि

सलाह ▶ पक्षकार उमेश चंद्र पांडेय के लिखित नोट को सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉर्ड पर लिया

- पांडेय की ही अर्जी पर कोर्ट ने 1986 में राम जन्मभूमि का ताला खोलने का आदेश दिया था
- पक्षकार ने कहा है कि जमीन राज्य सरकार की घोषित की जाए और वह तय करे कि विवादित भूमि का क्या करना है

माला दीक्षित, नई दिल्ली

अयोध्या राम जन्मभूमि विवाद में एक पक्षकार उमेश चंद्र पांडेय ने सुप्रीम कोर्ट में मोल्डिंग ऑफ रिलीफ यानी वैकल्पिक राहत पर लिखित नोट दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर भगवान श्रीराम विराजमान और सुन्नी-सेंट्रल वक्फ बोर्ड दोनों जमीन पर मालिकाना हक साबित करने में नाकाम रहते हैं तो कोर्ट प्रदेश सरकार को भूमि का मालिक घोषित करे। साथ ही राज्य सरकार यह तय करे कि उस विवादित जमीन का क्या करना है। पांडेय की ओर से दाखिल नोट को सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉर्ड पर ले लिया है।

पेशे से वकील उमेश चंद्र पांडेय की उपासक की हैसियत से दाखिल अर्जी पर 1986 में फैजाबाद की जिला अदालत ने राम जन्मभूमि का ताला खोलने का आदेश दिया था। पांडेय सुन्नी वक्फ बोर्ड, रामलला और निर्मोही अखाड़ा तीनों के मुकदमों में प्रतिवादी पक्षकार हैं। गुरुवार को पांडेय की ओर से पेश वरिष्ठ वकील वी. शेखर ने मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की पीठ के समक्ष वैकल्पिक राहत पर अपना लिखित नोट देते हुए कोर्ट से उसे स्वीकार करने का आग्रह किया। मुख्य न्यायाधीश ने सुनवाई खत्म होने के सात दिन बाद वैकल्पिक राहत पर लिखित नोट देने पर हल्के-फुल्के अंदाज में टिप्पणी करते हुए कहा कि क्या अयोध्या केस अभी भी चल रहा है। हमें तो लगता है कि अब सुनवाई पूरी हो गई। हालांकि कोर्ट ने नोट को रिकॉर्ड पर ले लिया।

नोट में कहा गया है कि अगर कोर्ट इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि वाद संख्या पांच यानी भगवान श्रीराम विराजमान और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड दोनों ही जमीन पर अपना मालिकाना हक साबित करने में नाकाम रहे हैं तो कोर्ट राज्य सरकार को विवादित जमीन का मालिक घोषित कर दे। कहा गया है कि ये मामले में स्वीकृत तथ्य है कि जब 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने अवध के नवाब को अचानक हटा दिया था और लॉर्ड कैनिन ने 3 मार्च 1858 को अवध की संपत्ति अधिकार ब्रिटिश सरकार ने जब्त करने की घोषणा की थी जो कि 30 अप्रैल 1858 कलकत्ता गजट में छपी थी। ऐसे में अयोध्या की विवादित जमीन सहित सभी संपत्तियों के अधिकार जब्त हो गए और वह जमीन सरकारी जमीन (नजूल) घोषित हो गई।

यह भी कहा गया है कि सुन्नी वक्फ बोर्ड ने अपने मुकदमे में स्वीकार किया है कि विवादित जमीन नजूल की जमीन है। यह भी स्वीकृत तथ्य है कि उसके बाद सरकार ने वह विवादित जमीन किसी को आवंटित नहीं की न ही अनुदान में दी, इसलिए वह जमीन आज भी नजूल की जमीन है। ऐसे में कोर्ट वैकल्पिक राहत पर विचार करते समय यह देखे कि अगर रामलला और सुन्नी वक्फ बोर्ड दोनों जमीन पर मालिकाना हक साबित करने में नाकाम रहे हैं तो राज्य सरकार को जमीन का मालिक घोषित कर दिया जाए। साथ ही राज्य सरकार जमीन की मालिक होने के नाते यह तय करे कि विवादित भूमि का क्या करना है।

पीठ से हटाने की याचिका स्वीकारना न्याय की हत्या होती : जस्टिस मिश्रा

नई दिल्ली, प्रेट्र : भूमि अधिग्रहण कानून के प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही संविधान पीठ से नहीं हटने को उचित बताते हुए सुप्रीम कोर्ट के जज अरुण मिश्रा ने कहा कि न्यायाधीश को पीठ से हटाने संबंधी याचिका को स्वीकार करना न्याय प्रणाली की स्वतंत्रता के खात्मे की घोषणा होती।

उल्लेखनीय है कि विभिन्न किसान संगठनों की याचिकाओं में मामले की सुनवाई से जस्टिस अरुण मिश्रा को हटाने की अपील की थी। इसके पीछे दलील थी कि उन्होंने इसी मामले में पिछले साल फरवरी में ही एक फैसला दिया था। जिसके खिलाफ किसान सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ में अपील कर रहे हैं। ऐसे में उन्हें इस फैसले की सुनवाई में शामिल नहीं होना चाहिए। उनका मानना है कि इस मामले में बड़ी पीठ में सुनवाई के दौरान जज अपने ही दिए फैसले को लेकर पक्षपातपूर्ण रवैया अख्तियार कर सकता है। पांच सदस्यीय संविधान पीठ में जस्टिस मिश्रा के अलावा जस्टिस इंदिरा बनर्जी, विनीत सरन, एमआर शाह और एस.रवींद्र भट शामिल हैं। जजों ने कहा कि अगर वह जस्टिस मिश्रा को हटाने की अपील स्वीकार कर लेते तो भावी पीढ़ियां हमें कभी माफ नहीं करतीं।

पूरे साल खुला रहेगा करतारपुर कॉरिडोर

गुरदासपुर जिले के डेरा बाबा नानक में करतापुर कॉरिडोर को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता हुआ। समझौते के बाद गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव एससीएल दास और पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मोहम्मद फैजल हाथ मिलाते हुए। जागरण

महिंदर सिंह अर्लीभन्न, डेरा बाबा नानक (गुरदासपुर)

गुरुद्वारा श्री करतारपुर साहिब के खुले दर्शन के लिए बनाए गए कॉरिडोर को लेकर गुरुवार को यहां भारत और पाकिस्तान के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। भारतीय श्रद्धालुओं को वहां जाने के लिए वीजा की जरूरत नहीं होगी। यात्रा के दौरान उन्हें पासपोर्ट और ओसीआइ (ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया) कार्ड रखना जरूरी होगा। कॉरिडोर के रास्ते सिर्फ भारतीय नागरिक ही यात्रा कर सकते हैं। सुबह गए यात्रियों को शाम को वापस आना होगा। इस दौरान यह खुला रहेगा। भारत के कड़े विरोध के बावजूद श्रद्धालुओं से 20 डॉलर शुल्क वसूलने पर पाकिस्तान अड़ा हुआ है।

अंतरराष्ट्रीय सीमा पर जीरो लाइन पर हुई इस बैठक में विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय के अधिकारी शामिल थे। तय हुआ कि कॉरिडोर अधिसूचित दिनों को छोड़कर पूरे साल खुला रहेगा। भारत श्री करतारपुर साहिब जाने वाले श्रद्धालुओं की सूची दस दिन पहले पाकिस्तान को सौंपेगा। श्रद्धालुओं को यात्रा से चार दिन पहले मैसेज, ईमेल व फोन के माध्यम से सूचित किया जाएगा। भारत सरकार के ऑनलाइन पोर्टल 'prakashpurb550.mha.gov.in' पर आवेदन किया जा सकता है। ऑनलाइन पोर्टल अंग्रेजी और पंजाबी में होगा। श्रद्धालु ग्रुप में या फिर अकेले भी जा सकते हैं। भारत ने कॉरिडोर पर जीरो लाइन तक पुल बनाया है जबकि पाकिस्तान ने सिर्फ अस्थायी सड़क बनाई है। अधिकारियों ने उम्मीद जताई कि पाकिस्तान भी जल्द पुल का निर्माण करेगा ताकि श्रद्धालु हर मौसम में श्री करतारपुर साहिब जा सकें।

20 डॉलर फीस पर नहीं दूर हुआ गतिरोध : श्रद्धालुओं से 20 अमेरिकन डॉलर लेने के मुद्दे पर पाकिस्तान अब तक नहीं माना है। भारत ने पाकिस्तान सरकार से फीस माफ करने की मांग की है। जरूरी हुआ तो समझौते में संशोधन करने के लिए तैयार है। वहीं, एजेंसी के अनुसार पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मोहम्मद फैजल का कहना है कि बहुत ज्यादा खर्च करने के बाद 20 डॉलर का सर्विस शुल्क बहुत मामूली है। करतारपुर कॉरिडोर पर समझौते तक पहुंचना आसान नहीं था। बहुत तनावपूर्ण माहौल और कठिन दौर से गुजरने के बाद इस समझौते तक पहुंचे हैं।

कैप्टन ने कहा, फीस माफ करने पर विचार करें इमरान : पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने गुरुवार को बटाला में अपनी कैबिनेट की बैठक की। उन्होंने उम्मीद जताई कि पाकिस्तान सिख धर्म की भावनाओं और रिवायतों के मद्देनजर प्रस्तावित 20 डॉलर की फीस माफ कर देगा। उन्होंने कहा कि अकबर ने भी गैर मुस्लिम धर्मों की भावनाओं को समझते हुए जजिया टैक्स माफ किया था। पाक प्रधानमंत्री इमरान खान को इस पर विचार करना चाहिए। अमरिंदर ने 550वें प्रकाश पर्व पर 6 नवंबर को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने का फैसला किया है।

समझौते की शर्तें

- एक दिन में पांच हजार श्रद्धालु जा सकेंगे करतारपुर साहिब
- श्रद्धालु सुबह जाएंगे और शाम को वापस आना होगा
- बगैर वीजा जा सकेंगे भारतीय, कहीं और जाने की नहीं होगी अनुमति
- पासपोर्ट और इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवेल ऑथराइजेशन (ईटीए) साथ रखना होगा
- भारत 10 दिन पहले पाकिस्तान को देगा श्रद्धालुओं की सूची
- 11 हजार रुपये और सात किलो सामान ही साथ लेकर जा सकेंगे

अयोध्या में कल प्रज्वलित होंगे 5.51 लाख दीप

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

- राज्यपाल, मुख्यमंत्री और फिजी की उप सभापति समेत कई रहेंगे मौजूद
- 226 करोड़ की योजनाओं का होगा लोकार्पण और शिलान्यास

अयोध्या में दीपोत्सव के अवसर पर शनिवार को आयोजित कार्यक्रमों में राज्यपाल आनंदी बेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, फिजी गणराज्य की उपसभापति एवं सांसद वीना भटनागर, केंद्र और राज्य सरकार के मंत्री तथा अन्य प्रमुख लोग मौजूद रहेंगे। शनिवार शाम सात बजे से साढ़े सात बजे तक सभी घाटों और संपूर्ण अयोध्या में पांच लाख 51 हजार दीपों का प्रज्वलन होगा। इस मौके पर 226 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास होगा। गुरुवार को राज्य सरकार के प्रवक्ता ने अयोध्या दीपोत्सव पर होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दी।

शनिवार सुबह दस बजे से दो बजे तक भगवान श्रीराम के लीला चरित्र से जुड़ी विभिन्न झांकियों समेत भव्य शोभा यात्रा निकलेगी। यह यात्रा साकेत महाविद्यालय से शुरू होकर रामकथा पार्क में समाप्त होगी। इसमें कई देशों के कलाकार भाग लेंगे। मुख्यमंत्री पौने चार बजे से चार बजे तक शोभा यात्रा का अवलोकन करेंगे। इसके बाद श्री राम-सीता का राम कथा पार्क में हेलीकॉप्टर से प्रतीकात्मक अवतरण एवं भरत मिलाप का कार्यक्रम संपन्न होगा। सवा चार बजे से चार बजकर 40 मिनट तक राम कथा पार्क आगमन पर श्रीराम-जानकी का पूजन-वंदन, आरती और श्रीराम का प्रतीकात्मक राज्याभिषेक होगा। फिर शाम छह बजे तक परियोजनाओं का शिलान्यास, लोकार्पण और अतिथियों का संबोधन होगा। इसके बाद साढ़े छह से सात बजे तक नया घाट पर सरयू की आरती और पूजन किया जाएगा। राम की पैड़ी पर चार लाख दीपों का प्रज्वलन कर गिनीज बुक में रिकार्ड दर्ज कराया जाएगा। रात्रि आठ बजे राम की पैड़ी पर राम कथा का प्रदर्शन, सवा आठ बजे तक सरयू पुल से आतिशबाजी और फिर साढ़े आठ बजे से रात्रि दस बजे तक भारत, नेपाल, श्रीलंका, इंडोनेशिया एवं फिलीपींस की रामलीला का मंचन किया जायेगा। दीपोत्सव के तहत शुक्रवार को शाम छह बजे से गुप्तार घाट पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन एवं रामलीला का मंचन होगा।

राम की पैड़ी पर दीपोत्सव की इस तरह चल रही हैं तैयारियां। जीतू निषाद

हजारों स्वयंसेवकों व समन्वयकों ने संभाली कमान : 26 अक्टूबर को आयोजित होने वाले दीपोत्सव को लेकर गुरुवार को पैड़ी के घाटों पर दीयों को बिछाने का सिलसिला शुरू हो गया। दोपहर दो बजे के बाद स्वयंसेवकों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हुआ। कतारबद्ध तरीके से दीयों को लगाने का क्रम शुरू हुआ जो शाम होते-होते तकरीबन तीन लाख दीयों को बिछाने का कार्य पूरा कर लिया गया। इस दौरान स्वयंसेवकों में उल्लास रहा।

नेत्रहीन छात्राओं को किया जाता है देह व्यापार के लिए मजबूर

राज्य ब्यूरो, पटना

- प्रारंभिक जांच में हो गई है आरोप की पुष्टि, 2017 का है मामला
- मानवाधिकार आयोग ने डीएम से मांगी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट

पटना की नेत्रहीन छात्राओं पर देह व्यापार के लिए दबाव बनाने के एक मामले में राज्य मानवाधिकार आयोग ने पटना डीएम से प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की प्रगति रिपोर्ट मांगी है। मामले की सुनवाई आयोग के कार्यकारी अध्यक्ष उज्ज्वल कुमार दुबे के स्तर से की जा रही है। पटना विश्वविद्यालय परिसर स्थित मिंटो नेत्रहीन छात्रावास के छात्रों ने एक स्वयंसेवी संस्था की संचालिका पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसे नेत्रहीन छात्रों की देखरेख का जिम्मा दिया गया है। राज्य सरकार की ओर से इसके लिए संस्था को भुगतान भी किया जाता है। प्रारंभिक जांच में आरोप की पुष्टि भी हो गई है।

पीयू के नेत्रहीन छात्रावास में रहने वाले दिव्यांग छात्र सर्वजीत भाटिया एवं अन्य ने मानवाधिकार आयोग से उक्त शिकायत की। स्थानीय थाने में फरियाद नहीं सुने जाने के बाद छात्रों ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली और राज्य मानवाधिकार आयोग, पटना के पास अलग-अलग शिकायत की। छात्रों ने आवेदन में कहा है कि उन्हें विपरीत हालात में रहना पड़ रहा है। आरोप है कि स्वयंसेवी संस्था नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड बिहार की संचालिका जो पूर्व मंत्री की बेटी है, अनुदान के पैसे अपने पास रखकर नेत्रहीन विद्यार्थियों का शारीरिक और मानसिक शोषण करती है। इसके अलावा नेत्रहीन छात्राओं को देह व्यापार के लिए भी मजबूर करने का आरोप लगाया गया है।

प्रारंभिक जांच में आरोप की पुष्टि : शिकायत मिलने पर आयोग ने मामले की जांच का जिम्मा पटना डीएम को दिया। इसके बाद जिला सामाजिक कोषांग पटना के सदर की कार्यपालक दंडाधिकारी नीलू पॉल ने स्थल जांच के बाद आरोपों की पुष्टि की। नीलू पॉल की रिपोर्ट के मुताबिक छात्रावास की स्थिति काफी दयनीय है। वहां 20 से 25 विद्यार्थी रहते हैं। एक नेत्रहीन छात्र विद्यानंद पासवान के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया कि संचालिका नेत्रहीन छात्राओं को अपमानित करती है और गलत काम करने के लिए दबाव डालती है। यह मामला 2017 का बताया जा रहा है।

13 फरवरी के पहले मांगी रिपोर्ट : मामले की सुनवाई करते हुए मानवाधिकार आयोग के कार्यकारी अध्यक्ष उज्ज्वल कुमार दुबे ने पटना के डीएम से 13 फरवरी 2020 के पहले तक कार्रवाई की प्रगति रिपोर्ट मांगी।

वंशज बोले-वोट बैंक के लिए टीपू सुल्तान को निशाना बनाया जाना शर्मनाक

जागरण संवाददाता, कोलकाता : टीपू सुल्तान के वंशज मोहम्मद शाहिद का कहना है कि सुल्तान एक स्वतंत्रता सेनानी थे, जिनको वोटबैंक की राजनीति के लिए निशाना बनाया जाना शर्मनाक है। भाजपा नेता के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि इतिहास को कभी भी नष्ट नहीं किया जा सकता है। मैं इस मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री को पत्र लिखूंगा। मानहानि का केस भी दायर करूंगा।

दरअसल शाहिद का यह बयान बंगाल के मादिकेरी के विधायक और भाजपा नेता अप्पाचू रंजन द्वारा शिक्षा मंत्री एस सुरेश कुमार को लिखे एक पत्र की पृष्ठभूमि में दिया गया है। विधायक ने शिक्षा मंत्री को पत्र लिखकर इतिहास की पाठ्यपुस्तकों से टीपू सुल्तान के नाम को हटाने का प्रस्ताव दिया है। इसके जवाब में उनके वंशज ने कहा कि कुछ लोग वोट पाने के लिए सिर्फ वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, जो काफी शर्मनाक है। लोग इस बात से इन्कार नहीं कर सकते कि टीपू सुल्तान एक स्वतंत्रता सेनानी थे। इतिहास ऐसा ही है और भविष्य में भी ऐसा ही रहेगा। उन्होंने आगे कहा कि वह इस संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखेंगे और टीपू सुल्तान को निशाना बनाने वालों के खिलाफ मानहानि का मुकदमा भी दायर करेंगे। कुमार को लिखे पत्र में रंजन ने कहा है कि टीपू सुल्तान को एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में चित्रित किया गया है, जबकि इतिहास को गलत तथ्यों के साथ नहीं लिखा जाना चाहिए।

हत्यारोपित अशफाक ने सीरिया में भी की थी फंडिंग

जागरण संवाददाता, लखनऊ

कमलेश तिवारी के हत्यारोपितों से पूछताछ में लखनऊ पुलिस को कई चौंकाने वाली जानकारियां मिली हैं। पूछताछ में पता चला है कि हत्यारोपित अशफाक ने सीरिया में फंडिंग भी की थी। आरोपित ने नागपुर से पकड़े गए हत्या की साजिश के आरोपित आसिम के जरिए इस्लामिक स्टूडेंट एसोसिएशन (आइएसए) को रुपये भेजे थे। अशफाक ने अपने खास लोगों से सीरिया के नाम पर रुपये एकत्र किए थे।

एटीएस और एसटीएफ ने बुधवार पूरी रात अशफाक और मोइनुद्दीन से पूछताछ की। सभी आरोपितों का आमना-सामना कराया गया, जिसके बाद कई रहस्यों से पर्दा उठता चला गया। पूछताछ में आरोपित ने बताया कि सीरिया में उसने आइएसए के हमलावरों की मदद करने को रुपये एकत्र किए थे। हालांकि उसने किसी आतंकी संगठन से ताल्लुक होने की बात से इन्कार किया है। खुफिया एजेंसियों की पड़ताल में भी अब तक आइएस (इस्लामिक स्टेट) अथवा किसी अन्य आतंकी संगठन की भूमिका नहीं पाई गई है। गुरुवार को पुलिस ने कमलेश के हत्यारोपित मोइनुद्दीन और अशफाक को गुरुवार को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया। वहां मजिस्ट्रेट ने पुलिस को आरोपितों की दो दिन की कस्टडी रिमांड मंजूर कर दी, जिसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया।

शाहजहांपुर से दिल्ली पहुंचे दोनों आरोपितों का एक मददगार दिल्ली में भी मौजूद था। 20 अक्टूबर की रात ट्रेन से सफर कर दोनों दिल्ली के आनंद विहार स्टेशन पर उतर गए थे। अगले दिन दोनों दिल्ली में टहलते रहे। यहां से उन्हें मददगार ने पोरबंदर एक्सप्रेस का टिकट कराया और फिर आरोपित सूरत पहुंचे। सूरत में दोनों आरोपित अपने करीबियों के पास गए और वहीं रात गुजारी।

बरेली के बड़े मौलाना ने दिया था संरक्षण, गिरफ्तार : पुलिस ने हत्यारोपी मोईनुद्दीन व अशफाक के मददगार बरेली निवासी मौलाना कैफी अली को आखिरकार गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया। कमलेश हत्याकांड में कैफी अली सातवां आरोपित है, जिसे गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बरेली से नावेद रजा सिद्दीकी को भी हिरासत में लिया है। हत्यारोपितों ने घटना के बाद मौलाना कैफी अली से संपर्क किया था और बरेली जाकर उनसे मुलाकात भी की थी।

नावेद बना सहारा

पीलीभीत के मूल निवासी हत्यारोपितों को यहां रहने वाले उसी जिले के मूल निवासी नावेद का सहारा मिला। उसी के जरिये इलाज की व्यवस्था हुई और नेपाल भागने का रास्ता भी। हालांकि बाद में दोनों आरोपित परिजनों के कहने पर गुजरात लौटे। जांच में पता चला कि कमलेश का अशफाक का परिवार मूल रूप से पीलीभीत का रहने वाला है। कई साल पहले उसके पिता यहां से सूरत चले गए और परिवार वहीं बस गया। नावेद रजा सिद्दीकी भी पीलीभीत का मूल निवासी है। दोनों का यही कनेक्शन काम आया। कहा जा रहा है कि वे दोनों रिश्तेदार हैं। यही वजह रही कि नवेद ने कमलेश तिवारी के दोनों हत्यारोपितों अशफाक व मोइनुद्दीन की मदद की।

- सभी आरोपितों का कराया गया आमना सामना, खुले कई राज
- पुलिस को आरोपितों की दो दिन की कस्टडी रिमांड मिली
- आइएस या किसी अन्य आतंकी संगठन की भूमिका नहीं पाई गई है अब तक

दोनों आरोपितों की मदद करने में नावेद की बड़ी भूमिका थी। उसे पूरे प्रकरण की जानकारी थी। उसी ने फोन आदि का इंतजाम कराया और दोनों आरोपितों को कैफी के पास भेजा। हत्यारोपितों से ऐसी कई जानकारियां मिलने के बाद अब नवेद से पूछताछ की जा रही।

-डीके ठाकुर, एडीजी, एटीएस

शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन समेत तीन और भी थे निशाने पर

ज्ञान विहारी मिश्र, लखनऊ

- हिंदू समाज पार्टी के पश्चिमी यूपी प्रभारी और हरियाणा की महिला को मारने की थी योजना

कमलेश तिवारी के हत्यारोपितों के निशाने पर शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी समेत तीन लोग और भी थे। कमलेश की हत्या के कुछ दिन बाद वसीम को भी मारने की योजना थी। पूछताछ में पता चला है कि वसीम ने 'राम जन्मभूमि' नाम से एक फिल्म बनाई थी, जिसे पर काफी विवाद हुआ था। इससे कई कट्टरवादी संगठन नाराज थे। इसके अलावा हरियाणा की एक महिला भी इनकी हिटलिस्ट में थी।

सूत्रों के मुताबिक हत्यारोपितों की सूची में हिंदू समाज पार्टी के पश्चिमी यूपी प्रभारी गौरव गोस्वामी भी शामिल थे। अशफाक और मोईनुद्दीन ने गौरव से बात कर इटावा आने को कहा था, लेकिन किसी कारण से उन्होंने इन्कार कर दिया था। आरोपित कमलेश के साथ-साथ गौरव को भी मारने की तैयारी में थे। यही नहीं, आरोपित हरियाणा में रहने वाली महिला सोनू डांगर की भी हत्या करना चाहते थे। आरोपितों ने खुफिया एजेंसियों को बताया कि सोनू सोशल मीडिया पर धार्मिक टिप्पणी करती है, जिसके कारण उन्होंने महिला को मारने की योजना बनाई थी।

सोचा नहीं था इतना बड़ा मुद्दा बनेगा

आरोपितों ने पूछताछ में कहा कि उन्होंने इसका जरा भी इल्म नहीं था कि कमलेश की हत्या इतना बड़ा मुद्दा बन जाएगा। उन्हें लगा कि सामान्य हत्याकांड की तरह जिले की पुलिस उनके बारे में पता लगाएगी और फिर सबकुछ शांत हो जाएगा। हालांकि मददगारों से उन्हें पता चला कि उनके पीछे एसटीएफ, एटीएस व लखनऊ पुलिस के अलावा गुजरात व कर्नाटक की पुलिस भी पड़ी है तो उन्होंने सरेंडर करने की योजना बनाई थी।

माह के अंत तक पूरी हो जाएगी इंडियाबुल्स के खिलाफ जांच : केंद्र

जासं, नई दिल्ली : इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (आइबीएचएफएल) के प्रमोटर्स द्वारा की गई कथित वित्तीय अनियमितता के मामले में गुरुवार को केंद्र सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट में जवाब दाखिल किया। कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने शपथपत्र दाखिल कर कहा कि कंपनी के खिलाफ कई शिकायतें मिली हैं, जिनमें से कुछ की जांच की गई है।

मुख्य न्यायमूर्ति डीएन पटेल व न्यायमूर्ति सी हरिशंकर की पीठ के समक्ष मंत्रालय ने कहा कि अभी मामले में सभी शिकायतों की जांच चल रही है। आइबीएचएफएल की जांच अक्टूबर के अंत तक पूरी हो जाएगी। वहीं इंडियाबुल्स रियल एस्टेट लिमिटेड (आइबीआरईएल) की जांच नवंबर के अंत तक पूरी होगी। अगली सुनवाई 29 नवंबर को होगी।

मंत्रालय ने उक्त शपथ पत्र गैर सरकारी संगठन सिटिजन व्हिसल ब्लोअर फोरम की तरफ से दायर जनहित याचिका पर दिया। संगठन के सदस्यों में दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायमूर्ति एपी शाह, पूर्व नौसेना प्रमुख एडमिरल एल रामदास, पूर्व आइएएस अधिकारी अरुणा रॉय और अधिवक्ता प्रशांत भूषण शामिल हैं। याचिका में आइबीएचएफएल के प्रमोटर्स द्वारा की गई वित्तीय अनियमितताओं और उल्लंघनों की एसआइटी जांच की मांग की गई है।

तैयारी

धनतेरस के मौके पर शुक्रवार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इन निर्माण कार्यों की आधारशिला रखेंगे, वहां दो वर्ष में कुल 164 आवास बनाए जाएंगे

नया रायपुर में 505 करोड़ में बनेंगे वीवीआइपी आवास

नईदुनिया, रायपुर

- राजभवन, सीएम और स्पीकर हाउस समेत 164 भवनों का होना है निर्माण

छत्तीसगढ़ की नई राजधानी नवा (नया) रायपुर अटल नगर में 505 करोड़ की लागत से वीवीआइपी आवास बनाए जाएंगे। धनतेरस के मौके पर शुक्रवार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इन निर्माण कार्यों की आधारशिला रखेंगे। वहां कुल 164 आवास बनाए जाएंगे। निर्माण कार्य दो वर्ष में पूरा करने का लक्ष्य है। गुरुवार को पीडब्ल्यूडी मंत्री ताम्रध्वज साहू ने शिलान्यास कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया।

नवा रायपुर के सेक्टर 24 में राजभवन, मुख्यमंत्री निवास, विधानसभा अध्यक्ष व मंत्री समेत अफसरों के आवास के निर्माण का प्रस्ताव है। शुक्रवार को दोपहर 12 बजे मुख्यमंत्री बघेल इसे लिए भूमिपूजन करेंगे। भवनों के निर्माण की जिम्मेदारी पीडब्ल्यूडी को सौंपी गई है। पीडब्ल्यूडी ने टेंडर की प्रक्रिया पूरी कर ली है। अफसरों के अनुसारों के अनुदार नवंबर से निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा।

12 एकड़ में राजभवन और आठ एकड़ में सीएम हाउस : पीडब्ल्यूडी के अफसरों के अनुसार सेक्टर 24 में करीब 12 एकड़ में राजभवन और आठ एकड़ में सीएम हाउस का निर्माण किया जाएगा। राजभवन के निर्माण पर 90 करोड़ और सीएम हाउस के निर्माण पर 60 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। वहां 18 आला अफसरों के अभी बंगले बनाए जाएंगे।

सरकार बदली तो घटा दायरा : पूर्ववर्ती भाजपा सरकार ने सेक्टर-18 में सिविल लाइन यानी सीएम हाउस आदि का निर्माण का प्रस्ताव तैयार किया था। इसमें मुख्यमंत्री निवास का क्षेत्रफल 16 एकड़ रखा गया था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को जब इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने इस पर आपत्ति करते हुए सीएम हाउस का दायरा घाटकर आठ एकड़ कर दिया और पूरा प्रोजेक्टर सेक्टर 24 में ले आए।

भूपेश बघेल। फाइल फोटो

कल का सर्किट हाउस आज का राजभवन

छत्तीसगढ़ का मौजूदा राजभवन कभी रायपुर का सर्किट हाउस हुआ करता था। इसी तरह सिविल लाइ स्थित मुख्यमंत्री निवास राज्य निर्माण के समय रायपुर कलेक्टर का बंगला था। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद राज्य अतिथि गृह पहुना को सीएम हाउस के लिए तैयार किया गया था, लेकिन तत्कालीन मुख्यमंत्री अजीत जोगी को वह पसंद नहीं आया। इसके बाद मौजूदा सीएम हाउस को जोगी के निर्देश पर तैयार किया गया। जोगी कलेक्टर रहते वहां रह चुक थे।

मेरठ में फायरिंग से ग्रामीण की मौत, देशद्रोह का मुकदमा

जागरण संवाददाता, मेरठ

मेरठ के खजूरी में बुधवार रात रोडरेज के बाद हुई फायरिंग में घर की छत पर खड़े ग्रामीण की सीने में गोली लगने से मौत हो गई। गुरुवार सुबह इसका पता चलने पर लोगों में आक्रोश फैल गया। गांव के दो संप्रदायों के बीच तनाव बन गया। भीड़ इतनी गुस्से में थी कि एसपी देहात और सीओ के खिलाफ नारेबाजी कर उनको लौटा दिया। हस्तिनापुर विधायक दिनेश खटीक के हस्तक्षेप के बाद ग्रामीण शांत हुए। इसके बाद ही अफसर घटनास्थल का निरीक्षण कर पाए। पुलिस ने फायरिंग करने वालों पर हत्या, जानलेवा हमला और देशद्रोह में मुकदमा दर्ज कर एक आरोपित को हिरासत में ले लिया है।

बुधवार रात खजूरी निवासी मोहित त्यागी की कार में नोएडा के सुधीर की स्कार्पियो से टक्कर लग गई थी। सुधीर परीक्षितगढ़ में अपने दोस्त दानिश से मिलकर लौट रहा था। विवाद इतना बढ़ा कि सुधीर ने दानिश को कॉल किया। दानिश अपने साथ दूसरी स्कार्पियो और पांच बाइक पर युवकों को लेकर खजूरी पहुंच गया। युवकों ने मोहित की पिटाई शुरू कर दी। तभी ग्रामीण लाठी-डंडे लेकर आए और युवकों की घेराबंदी कर ली। युवकों ने लाइसेंसी राइफल से ग्रामीणों पर फायरिंग कर दी। साथ ही आरोप है कि पाकिस्तान के समर्थन में नारे भी लगाए।

अफसरों के बयान पर था गुस्सा

एसपी देहात अविनाश पांडेय और सीओ अखिलेश भदौरिया ने बयान दिया था कि आरोपितों ने पाक के समर्थन में नारे नहीं लगाए, वहीं ग्रामीणों ने इसका वीडियो दिखाने का दावा किया। मौके पर मौजूद विधायक दिनेश खटीक ने एसएसपी को फोन किया। इस पर एसएसपी अजय साहनी ने एसपी क्राइम रामअर्ज सिंह को मौके पर भेजा। इसके बाद पुलिस ने आठ हमलावरों के खिलाफ दूसरा मुकदमा दर्ज कर लिया, जिसमें जानलेवा हमला, हत्या और देशद्रोह की धारा लगाई गई।

छत्तीसगढ़ में अब 21 साल की उम्र में बन सकेंगे महापौर

नईदुनिया, रायपुर: नगरीय निकायों में महापौर और अध्यक्ष के अप्रत्यक्ष चुनाव पर छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल मंत्रिमंडल ने मुहर लगा दी है। इसके साथ ही सरकार ने महापौर पद के लिए आयु सीमा 25 से घटाकर 21 वर्ष कर दी है। नगरीय निकाय चुनाव दलीय आधार पर होंगे और ईवीएम की जगह मतपत्र से चुनाव कराया जाएगा।

जनमत
मुद्दा

क्या परंपरा को छोड़ आधुनिकता के प्रवाह में हम प्रकाश-पर्व के सही मायने भूलते जा रहे हैं?

mudda@jagran.com पर आप अपनी राय हमें भेज सकते हैं। मोबाइल से मैसेज भी कर सकते हैं। **MUDDA** लिखें, स्पेस देकर **YES** या **NO** लिखकर 57272 पर भेजें।

30 हजार इमारतें रेड जोन में हैं हिमाचल प्रदेश की। ये इमारतें भूकंप आने पर ढह सकती हैं। यह बात आइआइटी मुंबई के प्रोफेसर सीवीआर मूर्ति ने शिमला में आपदा जोखिम न्यूनीकरण की चुनौतियों विषय पर आयोजित कार्यशाला में कहीं।

सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, कश्मीर घाटी में कब तक जारी रहेगा प्रतिबंध

सख्त रुख ▶ अधिकारी राष्ट्रहित में पाबंदियां लगा सकते हैं, लेकिन इनकी समीक्षा होनी चाहिए

अटार्नी जनरल ने बताया कि प्रशासन स्पष्ट उत्तर देगा और मुद्दे के समाधान के अन्य तरीकों की तलाश करेगा

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर प्रशासन से से कहा कि अनुच्छेद 370 समाप्त किए जाने के बाद घाटी में इंटरनेट पर रोक सहित लगाए गए प्रतिबंध को वे कब तक जारी रखना चाहते हैं। शीर्ष कोर्ट घाटी में आवाजाही और संचार पर लगे प्रतिबंधों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था। कोर्ट ने कहा कि अधिकारी राष्ट्र हित में पाबंदियां लगा सकते हैं, लेकिन समय-समय पर इनकी समीक्षा भी होनी चाहिए।

जस्टिस एनवी रमण की अध्यक्षता वाली पीठ को अटार्नी जनरल केके वेणुगोपाल और सालिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि जम्मू-कश्मीर प्रशासन स्पष्ट उत्तर देगा और मुद्दे के समाधान के अन्य तरीकों की तलाश करेगा। इस पीठ में जस्टिस आर. सुभाष रेड्डी और जस्टिस बीआर गवई भी शामिल हैं। मेहता ने पीठ से कहा, 'पाबंदियों की रोजाना समीक्षा की जा रही है। करीब 99 फीसद क्षेत्रों में कोई प्रतिबंध नहीं हैं।'

याचिका दायर करने वाले कश्मीर टाइम्स के कार्यकारी संपादक अनुराधा भसीन की वकील वृंदा ग्रोवर ने मेहता की दलील का विरोध किया और कहा कि दो महीने से भी ज्यादा समय से घाटी में इंटरनेट पर प्रतिबंध जारी है।

कश्मीर टाइम्स के कार्यकारी संपादक अनुराधा भसीन की याचिका पर हो रही है सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट। फाइल फोटो

इस पर पीठ ने कहा, 'आपको स्पष्ट जवाब के साथ आना होगा। आपको इससे निपटने के लिए अन्य तरीके तलाशने होंगे। कितने समय तक आप ये प्रतिबंध लगाए रखना चाहते हैं? आप राष्ट्र हित में प्रतिबंध लगा सकते हैं लेकिन समय-समय पर उसकी समीक्षा की जानी चाहिए।'

कोर्ट ने 16 अक्टूबर को जम्मू-कश्मीर प्रशासन से कहा था कि वह उसके समक्ष उन आदेशों को रखे जिनके आधार पर राज्य में संचार प्रतिबंध लगाए गए। इसने संचार प्रतिबंध लगाने के आदेश और अधिसूचना रखने में विलंब को लेकर प्रशासन से सवाल किया था।

संविधान पीठ करेगी अनुच्छेद 370 और 35ए पर लंबित याचिकाओं की सुनवाई

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35-ए के प्रावधानों की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर पांच सदस्यीय संविधान पीठ सुनवाई करेगी। यही पीठ कश्मीर मुद्दे की सुनवाई करने जा रही है। अनुच्छेद 370 को केंद्र पांच अगस्त को निरस्त कर चुका है। एनजीओ वी दी सिटीजन ने 2014 में शीर्ष कोर्ट में याचिका दाखिल कर अनुच्छेद 35-ए की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी थी। बाद में इसी मुद्दे पर छह और याचिकाएं दाखिल की गईं।

इसी तरह कुमारी विजयलक्ष्मी झा ने 2017 में शीर्ष कोर्ट में दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर की। हाई कोर्ट ने अनुच्छेद 370 की वैधता को चुनौती देने वाली उनकी याचिका ठुकरा दी थी।

संविधान पीठ ने हाल ही में केंद्र के अनुच्छेद 370 समाप्त करने के फैसले की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं की सुनवाई के लिए 14 नवंबर की तारीख तय की। जस्टिस एनवी रमण की अध्यक्षता वाली पीठ ने गुरुवार को याचिकाएं पेश किए जाने पर कहा कि ये पुराने हैं और इनकी त्वरित सुनवाई की जरूरत नहीं है। जब संविधान पीठ अनुच्छेद 370 पर फैसला लेगा तो हमारा मानना है कि ये याचिकाएं नहीं टिक पाएंगी। ये याचिकाएं संविधान पीठ के सामने लंबित याचिकाओं के साथ सुनवाई के लिए पोस्ट की जाती हैं।

सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं में अनुच्छेद के प्रावधानों की वैधता को दी गई है चुनौती

हिरासत पर जल्द फैसला ले हाई कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट से अनुच्छेद 370 समाप्त किए जाने के बाद हिरासत में लिए गए लोगों को कोर्ट के सामने पेश करने का निर्देश देने की मांग करने वाली याचिकाओं पर जल्द फैसला लेने के लिए कहा है। हिरासत में लिए गए लोगों में एक एनआरआइ कारोबारी भी शामिल है।

पुंछ में सेना का हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त कमांडर समेत नौ अफसर बाल-बाल बचे

राज्य ब्यूरो, जम्मू

नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तानी गोलाबारी से उपजे हालात का जायजा लेने उत्तरी कमान के प्रमुख सहित सेना के नौ अधिकारियों को लेकर आ रहा सैन्य हेलीकॉप्टर पुंछ में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। सभी अधिकारी हादसे में बाल-बाल बच गए। हालांकि अधिकारियों को कुछ चोटें आई हैं। हेलीकॉप्टर क्रैश लैंडिंग के दौरान एक आम नागरिक भी घायल हुआ है।

जम्मू के पुंछ में गुरुवार दोपहर दो बजे एलओसी के हालात का निरीक्षण कर रहे आर्मी कमांडर के एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुवा में तकनीकी खराबी आ गई। सूझबूझ का परिचय देते पायलट ने हेलीकॉप्टर को उतारने की जद्दोजहद शुरू कर दी। पहाड़ी इलाके और जंगल के बीच पायलट ने हेलीकॉप्टर को बेदार में एक नाले में उतारने की कोशिश की। इसी दौरान हेलीकॉप्टर नीचे उतारते समय क्रैश लैंड हो गया।

पुलिस सूत्रों के अनुसार, सेना की उत्तरी कमान के जीओसी इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह के साथ कर्नल रैंक के दो अधिकारी तुषार शर्मा, बीआर नामबेर, कैप्टन रजत, ले. कर्नल समीर, पायलट सचिन कुमार, तीन नायक नीतिन, पवित्रता, रमेश कुमार थे। नाले में गिरने से हेलीकॉप्टर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। उसमें सवार सभी अधिकारी बच गए, लेकिन सभी को चोटें आई हैं। इस दौरान नाले में घराट चलाने वाला मुहम्मद अफजल भी घायल हो गया।

स्थानीय निवासी भी मदद के लिए पहुंचे : पुंछ के एसएसपी रमेश अंगराल ने बताया कि हादसा गंभीर था, लेकिन सौभाग्यवश सब सकुशल हैं। हादसे के बाद सबसे पहले स्थानीय निवासी घायलों की मदद के लिए आए। इसके बाद सेना और पुलिस स्टेशन की पार्टी भी त्वरित कार्रवाई करते हुए बचाव अभियान चलाने के लिए पहुंच गई। सैन्य अधिकारियों और घायल नागरिक को तुरंत प्राथमिक उपचार के लिए ले जाया गया। सभी को पास में स्थित सेना के मेडिकल सेंटर पहुंचाया। आर्मी कमांडर को बाद में दूसरे हेलीकॉप्टर से वापस ऊधमपुर के कमान अस्पताल ले जाया गया।

जम्मू संभाग के पुंछ जिले में मंडी इलाके के बेदार गांव में सेना का हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। घटनास्थल पर राहत अभियान चलाने के लिए सुरक्षाकर्मी व स्थानीय लोग भी पहुंचे। जागरण

सेना ने कहा-हेलीकॉप्टर में आई थी तकनीकी खराबी : जम्मू के पीआरओ डिफेंस लेफ्टिनेंट कर्नल देवेंद्र आनंद ने बताया कि हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी आ गई थी। ऐसे में पायलट ने समय रहते कार्रवाई करते हुए इमरजेंसी लैंडिंग करवाई। इसमें सवार सभी सैन्य अधिकारी सकुशल हैं। हेलीकॉप्टर में क्या तकनीकी खराबी आई है, यह जांच के बाद ही स्पष्ट होगी।

पाक की चौकी और लांचिंग पैड तबाह, तीन सैनिक ढेर

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर

उत्तरी कश्मीर में नियंत्रण रेखा (एलओसी) से सटे टंगडार (कुपवाड़ा) सेक्टर में गुरुवार को पाकिस्तानी सैनिकों ने ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल (बीडीसी) चुनाव प्रक्रिया में बाधा डालने का प्रयास करते हुए नागरिक इलाकों और अग्रिम सैन्य ठिकानों पर गोलाबारी की। भारतीय जवानों ने जवाबी कार्रवाई में टंगडार के सामने गुलाम कश्मीर के लाला एथमुकाम इलाके में एक पाक चौकी और एक आतंकी लांचिंग पैड को तबाह कर दिया। वहीं, तीन पाक सैनिकों के मारे जाने की भी सूचना है। इससे पहले पाक गोलाबारी में एक महिला की मौत हो गई और सात अन्य लोग जख्मी हो गए।

पाक सैनिकों ने टंगडार में द्रंगयारी और बलखंडी इलाके में तोप और मोर्टार से गोलाबारी की। इससे तीन मकान क्षतिग्रस्त हो गए और एक महिला समेत चार ग्रामीण जख्मी हो गए। चारों घायलों को सेना ने तुरंत निकटवर्ती अस्पताल पहुंचाया। जहां डॉक्टरों ने महिला को मृत लाया घोषित कर दिया। उसकी पहचान हमीदा के रूप में हुई है। इसके अलावा द्रंगयारी गांव में भी चार ग्रामीण गोलाबारी में जख्मी हुए हैं। इसके बाद भारतीय सेना ने कार्रवाई करते हुए टंगडार के सामने गुलाम कश्मीर में नीलम घाटी के लाला एथमुकाम इलाके को निशाना बनाया। कुछ ही देर में वहां की पाक चौकियों से आग की लपटें और धुएं के गुब्बार उड़ते नजर आने लगे। सूत्रों की मानें तो इस कार्रवाई में एथमुकाम स्थित एक लांचिंग पैड के अलावा एक पाक चौकी को भारी नुकसान पहुंचा है जबकि तीन पाक सैनिकों या आंतकियों के मारे जाने की सूचना है। भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई के बाद छह घंटे तक पाकिस्तानी बंदूकें खामोश रहीं, लेकिन शाम चार बजे के बाद पाक सैनिकों ने फिर गोलाबारी शुरू कर दी। इस बीच, पाकिस्तानी सैनिकों ने टंगडार के अलावा त्रेहगाम, कुपवाड़ा में भी अग्रिम भारतीय सैन्य चौकियों व नागरिक ठिकानों पर गोलाबारी की, जिसका भारतीय जवानों ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। गोलाबारी के उर से बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने बंकरों में शरण ले ली है।

रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता के अनुसार, जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचा है। सभी फील्ड कमांडरों को पाकिस्तान के दुस्साहस का मुहंतोड़ जवाब देने के लिए कहा गया है।

रावत ने किया चीन सीमा पर चौकियों का निरीक्षण

जागरण संवाददाता, चमोली

थलसेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने उत्तराखंड के चमोली जिले में चीन सीमा पर स्थिति अग्रिम चौकियों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने जवानों के साथ समय बिताया और स्थानीय लोगों से भी मुलाकात की। नीती घाटी में चीनी सैनिकों की घुसपैठ के सवाल पर उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में चीन के साथ किसी तरह के टकराव की बात नहीं है।

गुरुवार को थल सेनाध्यक्ष जनरल बिपिन रावत हेलीकॉप्टर से सीधे मलारी पहुंचे। यहां उन्होंने सेना के 'प्लांटेशन फॉर लाइवलीहुड' कार्यक्रम में शिरकत की। स्थानीय लोगों से मुलाकात कर समारोह में अखरोट और चिलगोजा के पौधों का रोपण किया। इस कार्यक्रम के तहत सीमावर्ती क्षेत्र में स्थानीय लोगों की मदद से एक लाख पौधों का रोपण किया जाना है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इस प्रोग्राम से क्षेत्र में पर्यावरण का संरक्षण तो होगा ही, स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिल सकेगा। इस दौरान स्थानीय लोगों ने जनरल बिपिन रावत से मोबाइल नेटवर्क न होने की समस्या उठाई। जनरल रावत ने कहा कि इस दिशा में हरसंभव कोशिश की जाएगी। उन्होंने साफ किया कि संचार नेटवर्क न होने की वजह सेना नहीं है। उन्होंने कहा कि सेना सीमांत क्षेत्रों के विकास के लिए लगातार काम कर रही है। जनरल रावत ने जवानों और स्थानीय लोगों को दीपावली की शुभकामनाएं भी दीं। दोपहर बाद वह हेलीकॉप्टर से दिल्ली रवाना हो गए।

चमोली जिले के मलारी गांव पहुंचने पर थलसेनाध्यक्ष बिपिन रावत को उपहार भेंट करते ग्रामीण। जागरण

बाड़ाहोती में हो रही है चीनी सैनिकों की घुसपैठ : नीती घाटी में बाड़ाहोती नाम की जगह पर चीनी सैनिकों की घुसपैठ सुर्खियां बनती रही हैं। पिछले साल जुलाई में चीनी सैनिकों ने इस क्षेत्र में पांच बार घुसपैठ की थी। गौरतलब है कि बाड़ाहोती 80 वर्ग किलोमीटर में फैला चारागाह है जहां पर स्थानीय लोग अपने जानवरों को लेकर आते हैं। वर्ष 2014, 2015 और 2016 में भी चीनी सेना की घुसपैठ को लेकर यह क्षेत्र सुर्खियों में रहा था।

श्रीनगर में आज शाम से दरबार बंद, चार से जम्मू में करेगा काम

राज्य ब्यूरो, जम्मू

ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर में शुक्रवार की शाम सचिवालय बंद हो जाएगा। इसके साथ ही जम्मू-कश्मीर का अंतिम दरबार मूव शुरू हो जाएगा। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में सरकार का दरबार जम्मू में चार नवंबर से काम करेगा।

श्रीनगर में 25 अक्टूबर को दरबार बंद होने के बाद वहां पर लोगों के कामकाज के लिए 28 अक्टूबर से शीतकालीन सचिवालय काम करने लगेगा। इसके लिए जम्मू कश्मीर सरकार ने गुरुवार को सरकारी आदेश जारी कर दिया है। एक केएएस अधिकारी समेत 11 अधिकारी और कर्मचारी लोगों के मसलों के समाधान के लिए श्रीनगर सचिवालय में सर्दियों के महीनों में काम करते रहेंगे। अधिकारियों और कर्मचारियों का वेतन उनके विभागों की ओर से ही जारी किया जाएगा।

मिली दो दिन की विशेष छुट्टी : जम्मू के सचिवालय कर्मचारी गुरुवार दोपहर अपने घरों में पहुंच गए। राज्य सरकार ने उन्हें दो दिन की विशेष छुट्टी दी है। दूसरी ओर श्रीनगर सचिवालय में गुरुवार को सरकारी विभागों के रिकॉर्ड को पैक कर दिया गया। अब सिर्फ कश्मीर के कर्मचारी ही काफिले में दो और तीन नवंबर को जम्मू आएंगे। इसके बाद चार नवंबर से जम्मू में दरबार काम करने लगेगा। यह जम्मू-कश्मीर का अंतिम दरबार मूव है।

- **जम्मू के सचिवालय कर्मचारी अपने घर पहुंचे**
- **श्रीनगर में 28 अक्टूबर से काम करेगा शीतकालीन सचिवालय**

28 को रवाना होंगे ट्रक

सरकारी रिकॉर्ड से भरे राज्य पथ परिवहन निगम (एसआरटीसी) के ट्रकों को 28 अक्टूबर को जम्मू रवाना कर दिया जाएगा। ये ट्रक देर शाम जम्मू सचिवालय पहुंच जाएंगे। इसके अलावा जिन कर्मियों की श्रीनगर सचिवालय में शीतकालीन ड्यूटी लगी है वह पूरी सर्दी काम करते रहेंगे।

फारूक की बहन, भांजे व भाई को घर से बाहर आने की नहीं मिली अनुमति

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर

नेशनल कांफ्रेंस के अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. फारूक अब्दुल्ला की बहन, भांजा और छोटे भाई को नजरबंद या एहतियातन हिरासत में रखे जाने से राज्य सरकार के अदालत में इन्कार के बावजूद पुलिस ने गुरुवार को उन्हें अपने घर से बाहर नहीं आने दिया। उन्हें मीडिया से बातचीत करने की भी अनुमति नहीं मिली।

खालिदा शाह, डॉ. फारूक अब्दुल्ला की बड़ी बहन हैं। खालिदा के पति स्व. जीएम शाह जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। पति की मौत के बाद ही खालिदा शाह को अवामी नेशनल कांफ्रेंस का संरक्षक बनाया गया था, जबकि उनके पुत्र मुजफ्फर शाह पार्टी के अध्यक्ष हैं। डॉ. मुस्तफा कमाल नेशनल कांफ्रेंस के महासचिव हैं और डॉ. फारूक अब्दुल्ला के सबसे छोटे भाई हैं।

गत चार अगस्त की मध्य रात्रि राज्य सरकार ने घाटी में कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए खालिदा शाह, मुजफ्फर शाह और डॉ. मुस्तफा कमाल को एहतियातन हिरासत में लिया या फिर नजरबंद किया था। खालिदा शाह, मुजफ्फर शाह और डॉ. मुस्तफा कमाल ने अपनी नजरबंदी के खिलाफ उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। गत बुधवार याचिका पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने बताया कि यह तीनों न तो नजरबंद हैं और न एहतियातन हिरासत में हैं।

घर के बाहर तैनात सुरक्षाकर्मियों ने रोका : इसके बाद गुरुवार को डॉ. मुस्तफा कमाल ने अपने भांजे मुजफ्फर शाह के साथ मिलकर पत्रकार वार्ता बुलाने का फैसला किया। यह वार्ता दोपहर एक बजे तय की गई, लेकिन इनमें से कोई भी अपने घर से बाहर नहीं आ सका। कहा जा रहा है कि तीनों को उनके घर के बाहर तैनात सुरक्षाकर्मियों ने रोक लिया। पुलिस अधिकारियों ने उन्हें घर से बाहर आने और किसी से बात करने की अनुमति नहीं दी।

लोन ने कहा, अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद मिलने की अनुमति मिली : नेकां के वरिष्ठ नेता और उत्तरी कश्मीर से सांसद मोहम्मद अकबर लोन ने बताया कि एक तरफ सरकार कहती है कि डॉ. मुस्तफा कमाल, मुजफ्फर शाह और खालिदा शाह को हिरासत में नहीं रखा गया है। दूसरी तरफ पुलिस इन्हें घर से बाहर नहीं आने दे रही है। इन तीनों को संयुक्त रूप से मीडिया से बात करनी थी, लेकिन पुलिस ने इसकी इजाजत नहीं दी। लोन ने कहा कि मैं जब अपने कुछ साथियों से मिलने मुजफ्फर शाह के घर गया तो पुलिसकर्मियों ने मुझे भी रोका। कुछ वरिष्ठ अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद ही हमें उनसे मिलने की अनुमति मिली।

आतंकियों की घुसपैठ की आशंका को लेकर नेपाल सीमा पर अलर्ट

संवाद सहयोगी, पिथौरागढ़ : कश्मीर में अनुच्छेद 370 खत्म किए जाने के बाद नेपाल सीमा से आतंकि.ों के भारत में प्रवेश की आशंका को देखते हुए भारत-नेपाल सीमा पर अलर्ट जारी कर दिया है। गुरुवार को पुलिस अधीक्षक आरसी राजगुरु ने सीमा क्षेत्र का निरीक्षण कर जवानों को मुस्तैद रहने के निर्देश दिए। अनुच्छेद 370 खत्म करने के बाद से ही पाक की बेचैनी और भारत में अशांति फैलाने की कोशिशों के मद्देनजर खासा एहतियात बरती जा रही है। पिछले दिनों गुप्तचर एजेंसियों से आतंकवादियों के नेपाल और बांग्लादेश की सीमा से भारत में घुसने की आशंका के इनपुट दिए गए थे। उत्तराखंड के सीमांत जिले पिथौरागढ़ की करीब 180 किलोमीटर लंबी सीमा नेपाल से लगी है। जिले में काली नदी दोनों देशों के बीच सीमा बनाती है। सीमा पर एसएसबी तैनात है, बावजूद इसके कई संवदेनशील स्थल हैं, जहां से घुसपैठ की आशंका रहती है।

'कलियुग के श्रवण कुमार' को आनंद महिंद्रा उपहार में देंगे स्पोर्ट्स कार

नई दिल्ली, आइएएनएस : महिंद्रा समूह के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने 'कलियुग के श्रवण कुमार' से प्रभावित होकर उन्हें एक स्पोर्ट्स कार बतौर उपहार देने की घोषणा की है। मैसूरु निवासी यह शख्स अपनी मां को स्कूटर से तीर्थयात्रा करा रहा है और इसके लिए उसने अपनी नौकरी भी छोड़ दी है।

- **महिंद्रा समूह के चेयरमैन ने ट्विटर पर खुद साझा की मैसूरु निवासी कृष्ण कुमार की कहानी**
- **लिखा, अगर आप मुझे उनसे मिलवा दें तो मैं उन्हें महिंद्रा केयूवी 100 एनएक्सटी भेंट करना चाहूंगा**

आनंद महिंद्रा ने 'कलियुग के श्रवण कुमार' की कहानी खुद साझा की। उन्होंने लिखा, 'एक खूबसूरत कहानी। यह मां के साथ-साथ अपने देश से से प्यार की कहानी है... अगर आप मुझे उनसे मिलवा दें तो मैं उन्हें महिंद्रा केयूवी 100 एनएक्सटी भेंट करना चाहूंगा, ताकि वह अपनी मां को आगे की यात्रा आराम से करवा सकें।' एक यूजर ने आनंद को जवाब देते हुए लिखा, 'जब मैंने इसे देखा तो मेरे मन में भी तत्काल यही बात आई... श्रवण कुमार की बजाय इनका नाम कृष्ण कुमार है... और कोई अंतर नहीं है।' एक अन्य यूजर ने लिखा, 'आनंद महिंद्रा सर, आम आदमी की सहायता करने और उसे प्रेरित करने के लिए मैं आपको सलाम करता हूं। लगभग दो साल पहले तीन पहिया वाहन को मोडीफायड स्कॉर्पियो में तब्दील करने पर आपने श्री मनोज को महिंद्रा सप्रो का उपहार दिया था।' आनंद की पोस्ट को 24 हजार से ज्यादा लाइक मिली हैं, जबकि इसे छह हजार से भी ज्यादा बार साझा किया गया है।

मां को स्कूटर पर बैठा कई प्रदेशों की तीर्थयात्रा करा चुके हैं कुमार : इंटरनेट पर उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार, मैसूरु निवासी कृष्ण कुमार ने मां को तीर्थयात्रा कराने के लिए पिछले साल जनवरी में बैंक की नौकरी छोड़ दी थी। दोनों मां-बेटा भारत के कई धार्मिक स्थलों की यात्रा कर चुके हैं। करीब सात महीनों से वह मां को स्कूटर पर बैठाकर यात्रा करवा रहे हैं और होटलों की बजाय मठों में रुकते हैं। मां-बेटे कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना व महाराष्ट्र आदि प्रदेशों की यात्रा कर चुके हैं।

मोदी की सलाह

पीएम ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये काशी के कार्यकर्ताओं से किया संवाद, कहा-राजनीति नहीं, समाजनीति के लिए जाएं लोगों के बीच

पुराने कार्यकर्ताओं के अनुभव का लाभ लें

जागरण संवाददाता, वाराणसी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के भाजपा कार्यकर्ताओं से गुरुवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये संवाद किया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि वे पुराने कार्यकर्ताओं की सूची बनाएं और उनके अनुभवों का लाभ उठाएं। साल में कम से कम एक बार अवश्य सम्मेलन कराएं। पीएम ने कहा कि मैं छुट्टी तो नहीं ले सकता, लेकिन अपनों से मिलने का मौका खोजता रहता हूं। उन्होंने सभी को दीप पर्व की बधाई दी और कार्यकर्ताओं के प्रश्नों का जवाब देकर उन्हें आगे बढ़ने का रास्ता बताया। इस दौरान उन्होंने आह्वान किया कि वे जनता के बीच सिर्फ राजनीति के लिए नहीं, बल्कि समाजनीति के लिए जाएं।

शहर उत्तरी विधानसभा की भाजपा कार्यकर्ता सुरेखा सिंह ने संवाद के दौरान कहा कि जब हम लोग जनसंघ के पुराने कार्यकर्ताओं के बीच जाते हैं तो वे भाव-विभोर हो जाते हैं। इस पर पीएम ने कहा कि हमारी पार्टी अचानक आगे नहीं बढ़ी है, बल्कि चार पीढ़ी ने इसमें अपने को खपा दिया। इसलिए जरूरी है कि पुराने कार्यकर्ताओं के साथ आप सभी बैठें और पार्टी का इतिहास पूछें। वे बताएंगे कि कैसे जीत तो दूर, दशकों तक वह जमानत भी नहीं बचा पाने की स्थिति में रहते थे। आप इनसे जुड़ेंगे तो जीवन में कभी भी निराश नहीं होंगे।

- **पीएम ने कहा, मैं छुट्टी तो नहीं ले सकता, पर अपनों से मिलने का मौका खोजता रहता हूं**

वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये वाराणसी के भाजपा कार्यकर्ताओं से संवाद करते पीएम नरेंद्र मोदी। एएनआइ

पीएम ने कहा कि अभी बहुत से लोग सरकारी योजनाओं तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। अतः कार्यकर्ता उनके बीच जाएं और उन्हें लाभ पाने का रास्ता बताएं। कुछ असहाय हैं तो उन्हें विभागों तक लेकर जाएं। लोगों में यह महसूस होना चाहिए कि जो 70 वर्ष में नहीं हुआ उसे इसी कार्यकाल में पूरा कर देना है।

अगला कदम विकास का : रोहनिया के विकास मिश्रा ने पूछा कि अगला कदम क्या होना चाहिए? इस पर पीएम ने कहा कि विकास पूछ रहा है तो अगला कदम विकास ही होगा। रोहनिया में संपन्न हुई गांधी संकल्प यात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि पहले दिन थकान हुई होगी, लेकिन दूसरे दिन वह थकान गायब हो गई होगी। तीसरे दिन तो नई ऊर्जा मिली होगी। इसे आप बरकरार रखेंगे तो पार्टी और स्वयं को नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। सेवापुरी के अजय कुमार सिंह के प्रश्न का जबाब देते हुए कहा कि विदेश में जो सम्मान मिलता है वह केवल एक प्रधानमंत्री को नहीं, बल्कि भारत के 130 करोड़ लोगों की ताकत है। भास्कर केसरी के प्रश्न का जबाब देते हुए पीएम ने कहा कि काशी के शहंशाहपुर गांव ने ही शौचालय के कार्य को इज्जतघर नाम दिया। कहा कि इससे उनको काम करने की प्रेरणा और ऊर्जा मिलती है।

आतंकी धमकियों को दिखाया ठेंगा

▶ प्रथम पृष्ठ से आगे

कश्मीर में 400 से अधिक उम्मीदवारों ने चुनाव मैदान में उतर कर आतंकियों की धमकियों व राजनीतिक दलों के बहिष्कार की घोषणाओं को ठेंगा दिखा दिया है। कश्मीर केंद्रित पीडीपी, नेशनल कांफ्रेंस के बाद कांग्रेस भी चुनाव से दूर रही। ऐसे में घाटी में बेहतर बदलाव के लिए ग्रामीण प्रतिनिधियों ने भारी उत्साह दिखाकर उन्हें एक्सपोज कर दिया। चुनाव मैदान में उतरी तीन राजनीतिक पार्टियों में भाजपा, पैंथर्स पार्टी और बहुजन समाज पार्टी शामिल थे। श्रीनगर से वीडियो कांफ्रेंसिंग के दौरान मुख्य निर्वाचन अधिकारी शैलेंद्र कुमार ने बताया कि मतदान पूरी तरह से शांतिपूर्ण रहा। पंचों और सरपंचों ने मतदान को लेकर भारी उत्साह दिखाया है। जम्मू संभाग के 148 ब्लॉकों में 52 में भाजपा, 8 में पैंथर्स और 88 निर्दलीय जीते हैं। वहीं, कश्मीर में 137 ब्लॉकों में से 118 निर्दलीय, भाजपा को 18 और कांग्रेस को 1 सीट मिली हैं।

मुस्लिम डिलीवरी ब्वाय से ग्राहक ने खाना नहीं लिया

हैदराबाद, प्रेट्र : फूड डिलीवरी एप के एक ग्राहक के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है। ग्राहक ने डिलीवरी ब्वाय से खाना लेने से इन्कार कर दिया क्योंकि वह मुस्लिम था। पुलिस निरीक्षक पी. श्रीनिवास ने कहा कि उन्हें स्विगी के एग्जिक्यूटिव मुदासिर सुलेमान से बुधवार को शिकायत मिली है। शिकायत में कहा गया है कि ग्राहक ने खाने का ऑर्डर सिर्फ इसलिए नहीं लिया क्योंकि डिलीवरी ब्वाय मुस्लिम था। पुलिस अधिकारी ने कहा कि हम ग्राहक के खिलाफ मामला दर्ज करने की प्रक्रिया में हैं और जल्दी ही एफआइआर दर्ज की जाएगी।

डिलीवरी ब्वाय ने इस मामले की जानकारी मुस्लिम संगठन मजलिस बाको तेहरीक के अध्यक्ष अमजद उल्लाह खान को दी। खान ने अपने ट्विटर अकाउंट में इस मामले को पोस्ट किया है। खाना लेने से इन्कार करने वाले ग्राहक से संपर्क नहीं हो पाया है। जिस रेस्तरां को खाने को आर्डर दिया गया था वह मुस्लिम द्वारा संचालित है।

खान ने ट्वीट में कहा है, 'ग्राहक ने चिकन-65 का ऑर्डर दिया था और एक हिंदू डिलीवरी ब्वाय भेजने का आग्रह किया था। लेकिन स्विगी ने मुस्लिम ब्वाय को भेज दिया और ग्राहक ने पार्सल लेने से मना कर दिया।'

संपर्क करने पर स्विगी ने कहा, 'हम विविधता को गले लगाते हैं और विभिन्न विचारों का सम्मान करते हैं। हर ऑर्डर स्थान और उपलब्धता के आधार पर डिलीवरी एग्जिक्यूटिव को दिया जाता है न कि खास पसंद के आधार पर। हम किसी आधार पर अपने साझेदारों और ग्राहकों के साथ भेदभाव नहीं करते।'

मध्य प्रदेश में भी हुई थी ऐसी घटना : इससे दो महीने पहले मध्य प्रदेश में खाद्य पदार्थ डिलीवर करने वाली एक अन्य कंपनी जोमाटो के साथ भी ऐसी ही घटना घटी थी। उस कंपनी के एक ग्राहक ने खाना इसलिए लौटा दिया था क्योंकि डिलीवरी ब्वाय गैर हिंदू था। कंपनी ने शिकायत का समाधान करने से मना कर दिया। कंपनी ने कहा था कि भोजन का कोई धर्म नहीं होता।

दैनिक जागरण

इच्छाएं सभी दुखों की जननी हैं

चुनाव नतीजों का संदेश

महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव नतीजे एक बार फिर यह कह रहे हैं कि विधानसभा चुनावों में राष्ट्रीय मुद्दे कभी-कभार ही कारगर होते हैं। आम तौर पर राज्य स्तर के चुनावों में एक बड़ी भूमिका क्षेत्रीय मसलों की होती है। क्षेत्रीय मसलों के अलावा जाति-बिरादरी भी अपना असर दिखाती है। यही कारण रहा कि चंद माह पहले लोकसभा चुनावों में महाराष्ट्र और हरियाणा में जोरदार प्रदर्शन करने वाली भाजपा इन राज्यों में अपेक्षा के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर सकी। महाराष्ट्र में उसे जितनी सीटों की उम्मीद थी उतनी नहीं मिल सकीं और हरियाणा में वह 75 पार के अपने लक्ष्य के करीब जाना तो दूर रहा, बहुमत तक भी नहीं पहुंच पाई। ऐसा क्यों हुआ, इसकी तह तक जाने के क्रम में भाजपा नेतृत्व को यह अवश्य देखना चाहिए कि जब खेती संकट में हो, रोजगार का सवाल गंभीर होता जा रहा हो और मंदी का माहौल लोगों की चिंताएं बढ़ा रहा हो तब फिर राष्ट्रीय मसले उसकी नैया नहीं पार करा सकते। यह सही है कि महाराष्ट्र में भाजपा इस बार पिछली बार के मुकाबले कहीं कम सीटों पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन उसका मौजूदा संख्याबल इतना नहीं कि वह शिवसेना के अनुचित दबाव का प्रतिकार कर सके। अगर शिवसेना के साथ खींचतान बढ़ी तो इसका असर सरकार के कामकाज पर पड़ सकता है।

अगर महाराष्ट्र और हरियाणा में भाजपा को मन मुताबिक नतीजे नहीं हासिल हो सके और उसके कई दिग्गज मंत्री भी चुनाव हार गए तो इसका एक अर्थ यह भी है कि लोगों को अपनी सरकारों से जो अपेक्षाएं थीं वे सही तरह पूरी नहीं हुईं। निःसंदेह यह भी दिख रहा है कि मतदाताओं ने विपक्षी नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोपों को अधिक महत्व नहीं दिया। इसकी एक वजह जातीय समीकरणों की भूमिका भी हो सकती है। यह सही है कि भारत सरीखे देश में केंद्र हो या राज्य सरकारें, वे न तो सबको संतुष्ट कर सकती हैं और न ही पांच साल में सभी समस्याओं को हल कर सकती हैं, लेकिन उन्हें इस तरह तो काम करना ही चाहिए कि उनमें जनता का भरोसा बढ़े। कम से कम हरियाणा में तो ऐसा होता नहीं दिखा। बेहतर हो कि भाजपा नेतृत्व अपनी राज्य सरकारों के कामकाज की समीक्षा करे। वह इसकी अनदेखी नहीं कर सकता कि तमाम कमजोरियों के बाद भी विपक्ष अपनी जमीन मजबूत करता दिख रहा है। विपक्ष और अधिक मजबूती हासिल कर सकता था, यदि कांग्रेस दिशाहीनता से मुक्त होकर अन्य विपक्षी दलों का सही तरह नेतृत्व कर रही होती। जो भी हो, यह अच्छा है कि विपक्ष महाराष्ट्र और हरियाणा में सत्तापक्ष को चुनौती देता और उसे आगाह करता दिखा।

विदेश में बंधक

अधिक रुपये कमाने की उम्मीद में बंगाल से पहले मुंबई गए और फिर वहां से सऊदी अरब और अब वे सभी वहां बंधक बन गए हैं। दरअसल सऊदी अरब के जेद्दा में 21 भारतीयों को बंधक बना लिया गया है जिनमें 20 लोग बंगाल के हैं, जबकि एक मुंबई का रहने वाला है। यही नहीं उनसे उनका वीजा एवं पासपोर्ट तक छीन लिया गया है। जेद्दा में बंधक बने सभी लोग पेशे से गोल्ड कारीगर हैं। सऊदी में नौकरी कर अधिक रुपये कमा कर अपने परिवार को खुशहाली देने के लिए वे लोग एक एजेंट के माध्यम से जेद्दा गए थे। इन 21 भारतीयों को सऊदी के गोल्ड मार्केट में नौकरी दिलाने का झांसा दिया गया और वे सभी झांसे में फंस भी गए। उन लोगों को यह भी पता नहीं चला कि वे तस्करों के चंगुल में फंस चुके हैं। वहां फंसे कारीगरों में बंगाल के हावड़ा जिले के चार, हुगली के दस, पूर्व बर्द्धमान के तीन, उत्तर और दक्षिण 24 परगना जिले के तीन हैं, जबकि एक मुंबई का ही रहने वाला है। ये लोग मुंबई गोल्ड मार्केट गहने तैयार करते थे। नेशनल एंटी ट्रैफिकिंग कमेटी के अध्यक्ष शेख जिन्नार अली का कहना है कि उन्हें शांतनु पाल के परिवार ने फोन किया था। उनके जरिये उन्हें पता चला कि दो साल पहले एक एजेंट की मदद से शांतनु जेद्दा के मुशाली फैक्ट्री में काम करने गए थे। वह टूरिस्ट वीजा के तहत वहां गए थे। वीजा पहले से ही एक्सपायर हो चुका है और लंबे समय से उन्होंने अपने परिजनों से बात नहीं की है। काफी प्रयासों के बाद उन्होंने अपने परिवार से बात की और बताया कि उनका पासपोर्ट और वीजा जेद्दा में लैंड करते ही उनसे ले लिया गया था। परिवार ने जेद्दा में भारतीय दूतावास में बात करने की कोशिश की, लेकिन असफल रहे। शांतनु के परिवार ने अली को बताया कि 21 लोगों को वहां अच्छी नौकरी का ख्वाब दिखाकर ले जाया गया था। कई प्रयास के बाद उस नंबर पर संपर्क हुआ जिससे शांतनु ने कॉल की थी। इस बाबत भारतीय विदेश मंत्रालय और बंगाल की सीएम को भी पूरी जानकारी दी गई है। उन्हें सही सलामत वापस लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। परंतु यहां एक सवाल यह उठता है कि लोग तस्करों के झांसे में क्यों फंस जाते हैं? सरकार को भी चाहिए कि ऐसे जालसाजों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे, ताकि फिर कोई गरीब इस तरह से बंधक न बन सके।

सऊदी अरब के जेद्दा में 21 भारतीयों को बंधक बना लिया गया है जिनमें 20 लोग बंगाल के हैं, जबकि एक मुंबई का रहने वाला है

पक्ष-विपक्ष को आईना दिखाता जनादेश

रशीद किदवई

जहां विधानसभा चुनावों में स्थानीय मुद्दों के बजाय राष्ट्रीय मसलों के दम पर बाजी जीतने का भाजपाई दांव चला नहीं वहीं विपक्ष ने अपने लिए जरूरी संजीवनी हासिल कर ली

महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव के परिणाम निश्चित ही वैसे नहीं हैं जैसे माने जा रहे थे। दोनों राज्यों के नतीजे ऐसे हैं कि सरकार गठन को लेकर खींचतान तय है। दोनों राज्यों के चुनाव नतीजे अगर भाजपा को अपनी रीति-नीति पर नए सिरे से विचार करने के लिए मजबूर करेंगे तो वे कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति पर भी असर डालने का काम करेंगे। पहले माना जा रहा था कि कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में जल्द ही राहुल गांधी की वापसी हो सकती है। वैसे भी सोनिया गांधी के स्वास्थ्यगत कारणों से कांग्रेस को एक पूर्णकालिक अध्यक्ष की तुरंत आवश्यकता महसूस हो रही थी। सोनिया गांधी खुद भी फरवरी 2020 से आगे कार्यकारी अध्यक्ष का दायित्व संभालने की इच्छुक नहीं हैं, लेकिन अब राहुल की वापसी में देरी हो सकती है। राहुल गांधी की वापसी की राह में सबसे बड़ी अड़चन उनके काम करने का तरीका और कांग्रेस के एक तबके को लेकर अविश्वास और तिरस्कार भाव है। दिलचस्प बात यह है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में वही तबका कामयाब भी हुआ है। सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी खुद के साथ अपनी कार्यशैली बदलने को तैयार हैं?

महाराष्ट्र और हरियाणा के विधानसभा चुनाव परिणाम दोनों ही प्रमुख राष्ट्रीय पार्टियों को कुछ संदेश दे रहे हैं। हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भरोसा जताने के लिए सोनिया बधाई की पात्र हैं। वहीं भाजपा ने मनोहर लाल खट्टर को फिर से भुनाने के प्रयास की कीमत चुकाई। भूपेंद्र सिंह हुड्डा मंझे हुए सियासतदां हैं, लेकिन राहुल गांधी ने उन्हें दरकिनार कर दिया था। मनोहर लाल खट्टर का तो भाजपा की 2014 की जीत में भी कोई खास योगदान नहीं था। उन्हें मुख्यमंत्री पद प्रदान किए जाने के बाद विधानसभा चुनाव के पहले सफल मुख्यमंत्री के रूप में प्रस्तुत किया गया, लेकिन चुनाव परिणामों ने दिखा दिया कि खट्टर जनता का दिल जीतने में असफल रहे। विधानसभा चुनाव अमूमन स्थानीय मुद्दों पर लड़े जाते हैं, लेकिन भाजपा ने जानबूझकर इन चुनाव में राष्ट्रीयता, अनुच्छेद 370 और पाकिस्तान को कड़ा जवाब देने जैसे तमाम मुद्दों का सहारा लिया। फिर भी ये मुद्दे काम कर सकते थे, यदि स्थानीय समस्याएं गहराती नहीं। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि विदर्भ (महाराष्ट्र) में किसानों की बदहाली, मानेसर (हरियाणा) में ऑटोमोबाइल सेक्टर की समस्याएं, रोजगार के घटते अवसर और दोनों राज्यों के प्रभुत्वशाली वर्गों यानी जाटों और मराठों की अनदेखी वास्तविक समस्याएं थीं। भाजपा को अब यह देखना होगा कि इन समस्याओं का समाधान कैसे हो?

विपक्ष के समाप्त हो जाने और एक पार्टी का शासन जैसी बातों के बीच हरियाणा के चुनाव परिणाम विपक्ष में आशा का संचार करने वाले हैं। हरियाणा में कौन सरकार बनाता है, इससे अलग वहां की जीत विपक्ष के निर्जीव शरीर में जान डालने का काम करने वाली है। सोनिया और राहुल गांधी निश्चित ही इस पर चिंतन-मनन कर सकते हैं कि उन्होंने हरियाणा में हुड्डा परिवार पर पहले भरोसा क्यों नहीं किया, जिन्होंने भाजपा की जीत का रास्ता रोक दिया। अब कांग्रेस को कैप्टन अमरिंदर सिंह, कमलनाथ, अशोक गहलोत और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जैसे स्थानीय दिग्गजों को ज्यादा महत्व देना चाहिए।

यह याद रखा जाना चाहिए कि 2004 और 2009 की कांग्रेसनीत संप्रग सरकार बनवाने और उसे दोबारा सत्ता में लाने में संयुक्त आंध्र प्रदेश प्रांत के वाईएस राजशेखर रेड्डी का बड़ा हाथ था। अगर कांग्रेस वहां जगन मोहन रेड्डी और चंद्रशेखर राव को पार्टी में बनाए रखने में सफल होती तो आज पार्टी दोनों तेलुगु भाषी राज्यों आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कहीं ज्यादा मजबूत होती और वहां उसकी ही सरकार होती।

अवधेश राजपूत

कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने महाराष्ट्र में नौ चुनावी सभाओं को संबोधित किया, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में उनकी रैली हो नहीं हो पाई और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष सीताराम केसरी के बाद यह पहली बार हुआ कि पूरे प्रचार अभियान के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष ने चुनाव प्रचार से ऐसी दूरी बनाए रखी।

चुनाव नतीजे बता रहे हैं कि मुंबई में पुरानी और ऐतिहासिक पार्टी कांग्रेस को लगातार समर्थन देने वाले आधार की जमीन खिसक गई है। लगता है कि वहां दलित, ईसाई, मुसलमान, उत्तरी एवं दक्षिण भारतीय मतदाताओं के बीच सिर्फ मुसलमानों तथा ईसाइयों के छोटे से गुट ने कांग्रेस को वोट दिए। इन परिस्थितियों की पूरी तरह अनदेखी करते हुए मुंबई में मिलिंद देवड़ा और संजय निरुपम बराबर सिर फुटौव्वल करते रहे। समझा जा सकता है कि अगर कांग्रेस मुंबई में ही थोड़ा ठीकठाक प्रदर्शन करती तो महाराष्ट्र में उसकी स्थिति कुछ और बेहतर हो सकती थी। निश्चित ही इस वक्त कांग्रेस को नए नेतृत्व की अत्यंत आवश्यकता है। इसके अलावा पार्टी में ऊपर से नीचे तक सांगठनिक पुनर्गठन और जिम्मेदारियां देने के साथ जवाबदेही तय करने की भी जरूरत है। कांग्रेस के साथ भाजपा को भी यह समझने की जरूरत है कि राष्ट्रीय मसलों के सहारे राज्यों के चुनाव नहीं जीते जा सकते। महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव नतीजे यह साफ-साफ कह रहे हैं कि मोदी सरकार के प्रति सकारात्मक रवैया रखने वाले मतदाता भी भाजपा की राज्य सरकारों के प्रति अपनी नाखुशी जाहिर करने में पीछे नहीं रहने वाले।

महाराष्ट्र और हरियाणा में विधानसभा चुनावों के कुछ राज्यों में विधानसभाओं के उपचुनाव भी उल्लेखनीय है। कुछ नतीजे तो बहुत दिलचस्प हैं और वे राजनीति को प्रभावित करने वाले भी हैं। मध्य प्रदेश के झाबुआ विधानसभा क्षेत्र में हुआ उपचुनाव इसका उदाहरण है। वहां से कांग्रेस उम्मीदवार कांतिलाल भूरिया की जीत के मायने कमलनाथ सरकार की मजबूती है। कांग्रेस को अब राज्य में अपने बलबूते पूर्ण बहुमत भी मिल गया है। दूसरी ओर कांग्रेस की आंतरिक राजनीति में इस जीत के दूसरे मायने हैं। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह गुट द्वारा अब भूरिया को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में पेश किया जाएगा जिससे ज्योतिरादित्य सिंधिया की अध्यक्ष पद की दावेदारी की काट की जा सके। याद रहे कि मध्य प्रदेश की राजनीति में प्रभावशाली सिंधिया खेमा अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी पेश करता रहता है। भूरिया की जीत के बाद उन्हें भी इस पद के दावेदार के तौर पर प्रस्तुत किया जा सकता है जो प्रदेश के आदिवासी समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं।

(लेखक ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में फेलो एवं वरिष्ठ स्तंभकार हैं)

response@jagran.com

बरकरार हैं कांग्रेस की चुनौतियां

सुरेंद्र किशोर

यदि कांग्रेस के पास कल्पनाशील नेतृत्व होता तो शायद जनता उसकी ओर कहीं अधिक आकर्षित होती

विधानसभा के चुनाव नतीजे कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर पर कायाकल्प के कोई ठोस संकेत नहीं दे रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस के लिए अच्छे संकेत तब माने जाते जब हरियाणा के ही अनुपात में उसे महाराष्ट्र में भी सीटें मिलतीं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जहां महाराष्ट्र में वह चौथे नंबर पर जाकर टिकी है वहीं हरियाणा में उसके प्रदर्शन में राष्ट्रीय नेतृत्व का योगदान मुश्किल से ही नजर आता है। निःसंदेह इसी के साथ इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि भाजपा का जहां महाराष्ट्र में दबदबा कम हुआ वहीं हरियाणा में वह बहुमत से पीछे रही। क्या यह एक गैर जाट को मुख्यमंत्री बनाने के भाजपा के प्रयोग की विफलता की निशानी है? जो भी हो, लोकतंत्र प्रेमियों के लिए यह कोई संतोष की बात नहीं है कि प्रतिपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी क्षेत्रीय उम्मीदों एवं पहचान की राजनीति के बल पर ही जिंदा रहे। आज प्रतिपक्ष जितना कमजोर और दिशाहीन है उतना इससे पहले कभी नहीं था। स्वस्थ लोकतंत्र के लिए यह कोई अच्छी बात नहीं है, पर इस स्थिति के लिए खुद कांग्रेस ही जिम्मेदार है। बीते लोकसभा चुनाव में करीब 12 करोड़ मत हासिल करने के बावजूद कांग्रेस यदि फिर से राष्ट्रीय स्तर पर एक मजबूत पार्टी के रूप में उभरती नहीं दिख रही तो यह अकारण नहीं है। समस्या कांग्रेस की 'काया' में नहीं, बल्कि उसकी 'आत्मा' में है।

वर्ष 2014 में हुए आम चुनाव के पहले सलमान खुर्शीद ने कहा था कि 'राहुल गांधी हमारे सचिन तेंदुलकर हैं', पर अभी हाल में उन्होंने कहा कि 'हमारे नेता ने हमें छोड़ दिया।' उनके हिसाब से राहुल ही हमें पुनः सत्ता दिलवा सकते हैं, लेकिन उन्हें महाराष्ट्र और हरियाणा में पार्टी की जीत की संभावना नहीं दिख रही थी। पिछले वर्षों में जब-जब कांग्रेस को चुनावी हार का सामना करना पड़ा तब-तब उसने यही कहा कि हम अपनी गलतियों से सीखेंगे, पर सीखने की बात कौन कहे, उन कारणों को भी याद नहीं रखा गया जो हार के मुख्य कारण रहे। 2013 में जब कांग्रेस की चार राज्यों में हार हुई तो राष्ट्रीय नेतृत्व ने कहा कि स्थानीय मुद्दों के असर के कारण ऐसा हुआ, पर जब बीते साल मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में उसकी जीत हुई तो यह बात नहीं कही गई। 2013 में जब दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की जीत हुई तो राहुल ने कहा था कि 'हम आम आदमी पार्टी से सबक लेंगे।' बाद में यही लगा कि उन्होंने 'आप' से इतना ही सीखा कि किसी पर आधारहीन आरोप लगा दो और मुकदमे लड़ने में अपना बहुमूल्य समय जाया करते रहो। कांग्रेस नेतृत्व ने एंटनी कमेटी की रपट से भी कोई सबक नहीं लिया, जबकि एंटनी रपट में ही कांग्रेस के पुनर्जीवन का उपचार मौजूद है। मुश्किल यह है कि पार्टी इस रपट पर सघन चर्चा को ही नहीं तैयार। यह 2014 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस की हार के बाद तैयार की गई थी। एंटनी ने अगस्त, 2014 में अपनी रपट हाईकमान को सौप दी, पर उस रपट को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया। रपट में अन्य बातों के अलावा जो दो मुख्य बातें थीं, उन पर यदि कांग्रेस हाईकमान ने चिंतन-मनन किया होता तो शायद पार्टी का कुछ कल्याण होता। ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने खुद को सुधारने की क्षमता खो दी है। वह एक खास ढर्रे पर चल चुकी है जिससे पीछे पलटना उसके लिए संभव नहीं है।

चार सदस्यीय एंटनी कमेटी की रपट में प्रमुख बात यह है कि 'कांग्रेस के बारे में मतदाताओं में यह धारणा बनी कि वह अल्पसंख्यक समुदाय की तरफ झुकी हुई है। इससे भाजपा को चुनावी लाभ मिला। धर्मनिरपेक्षता बनाम सांप्रदायिकता को लेकर कांग्रेस ने जो चुनावी मुद्दा बनाया वह उसके खिलाफ गया। इसके अलावा संप्रग सरकार के दौर में घोटालों की चर्चा ने भी नुकसान पहुंचाया।' क्या कांग्रेस ने एकतरफा धर्मनिरपेक्षता की अपनी रणनीति को छोड़कर संतुलित धर्मनिरपेक्षता की नीति अपनाई? क्या उसने कभी यह कहा कि भ्रष्टाचार के प्रति हमारी शून्य सहनशीलता की नीति है? उसने तो इसके विपरीत ही रवैया अपनाया। कांग्रेस नेताओं के खिलाफ जब-जब भ्रष्टाचार को लेकर मुकदमे हुए, छापामारी हुई, बरामदगी हुई, नेतागण जेल भेजे गए, तब-तब कांग्रेस नेतृत्व ने कहा कि 'यह सब बदले की भावना में आकर किया जा रहा है।' यह एक तथ्य है कि कांग्रेस ने चिदंबरम और डीके शिवकुमार के साथ खड़े होना पसंद किया। भ्रष्टाचार को लेकर जैसी सहनशीलता की नीति कांग्रेस ने आजादी के तत्काल बाद अपनाई वह समय के साथ बढ़ती चली गई। आज वह पराकाष्ठा पर है। कांग्रेस का प्रथम परिवार भी रिश्तेदार सहित आरोपों एवं मुकदमों के घेरे में है। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने यह कहकर भ्रष्टाचार के प्रति अपनी सहनशीलता प्रकट कर दी थी कि 'भ्रष्टाचार तो वैश्विक परिघटना है। सिर्फ भारत में ही थोड़े ही है!' 'मिस्टर क्लीन' नाम से चर्चित राजीव गांधी को अपनी सरकार पर लगे घोटालों के आरोपों के जवाब देने में ही समय बिताना पड़ा। 1989 में कांग्रेस की सत्ता ऐसे गई कि फिर उसे कभी लोकसभा में बहुमत नहीं मिल सका। बाद के वर्षों में कांग्रेस ने जोड़-तोड़ कर सरकारें बनानी शुरू कीं। एक समय मनमोहन सिंह ने यह माना था कि मिलीजुली सरकार में समझौते करने की मजबूरी होती है। मजबूरी की उसी धारा में कांग्रेस आज भी बह रही है। दूसरी ओर केंद्र में एक ऐसी सरकार है जिसके प्रधानमंत्री कहते हैं कि 'न खाऊंगा और न खाने दूंगा।' उन्होंने अपने मंत्रिमंडल को घोटालों से अब तक दूर रखा है। अधिकतर लोग पहले की और अब की सरकारों में अंतर देख रहे हैं। दूसरा अंतर देश की सुरक्षा के मोर्चे पर आया है। यदि पड़ोसी देश कोई दुःसाहस करता है तो मोदी सरकार नतीजों की परवाह किए बिना उसका प्रतिकार करती है। अनुच्छेद-370 और 35ए को निष्क्रिय करने के निर्णय से जिहादी आतंकवादियों से लड़ने में सुविधा हो रही है।

कांग्रेस को सर्वाधिक नुकसान वंशवाद को लेकर हो रहा है। यदि आज कांग्रेस के पास कल्पनाशील नेतृत्व होता और वह वाजिब मुद्दे चुनकर उन पर खुद को केंद्रित करता तो महाराष्ट्र और हरियाणा में जनता उसकी ओर कहीं अधिक आकर्षित होती। तब शायद इन दोनों राज्यों में चुनावों के पहले ही यह माहौल न बनता कि कांग्रेस के जीतने की संभावनाएं कम हैं।

(लेखक राजनीतिक विश्लेषक एवं वरिष्ठ स्तंभकार हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

संप्रदाय

संप्रदाय का अर्थ है-धर्म का पथ-विशेष। एक संप्रदाय साधक को या अनुयायी को एक पथ प्रदान करता है, जिस पर चलकर वह धर्म द्वारा निर्दिष्ट लक्ष्य तक पहुंच सके। एक ग्रंथ, एक उपासना, एक आचार-पद्धति जहां भी प्रचलित है, जहां भी कहा जाता है-कल्याण का यही मार्ग है, वह संप्रदाय है। संप्रदाय-शब्द न संकीर्णतायुक्त है और न हेय है। यह तो विवेकहीन लोगों की एक लंबी परंपरा ने इस शब्द के प्रति लोक में अरुचि पैदा कर दी। 'इस साधन एवं मार्ग के अलावा मानव का कल्याण संभव ही नहीं। दूसरे सभी मार्ग भ्रांत, हेय एवं त्याज्य हैं।'

यह मिथ्या भ्रम अहंकार एवं अविवेक के कारण पुष्ट हुआ और उसने इस शब्द के प्रति उपेक्षा उत्पन्न कर दी। सांप्रदायिक का अर्थ ही संकीर्ण मनोवृत्ति का व्यक्ति माना जाने लगा। 'हमारा मार्ग सर्वथा ठीक है। हमारा मंत्र, ग्रंथ, गुरु, उपासना, आचार त्रुटि रहित है। हमारे लिए यही सर्वश्रेष्ठ मार्ग है।' यह निष्ठा काफी हद तक आवश्यक हो सकती है, किंतु इस निष्ठा के साथ दूसरे मार्गों, मंत्रों, ग्रंथों, गुरुओं, उपासना एवं आचार-पद्धतियों से द्वेष अथवा घृणा नहीं होनी चाहिए। सांप्रदायिकता का अर्थ है-साधनपथा रूढ़। जो धर्म के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है, उसे कोई न कोई पथ तो अपनाना ही होगा।

शैव, वैष्णव, बौद्ध, जैन, सिख आदि ही संप्रदाय नहीं हैं। आज जिन्हें भ्रमवश धर्म का नाम दिया जाता है, वे यहूदी, ईसाई, इस्लाम, पारसी आदि भी संप्रदाय ही हैं, क्योंकि यह भी लक्ष्य तक पहुंचाने वाले पथ हैं। इनमें एक साधन, एक आधार-पद्धति प्रदान की जाती है। धर्म सार्वभौमिक वस्तु है। वह तो भूमि है, जिस पर नाना-पथ हैं। सब पथ भूमि पर हैं। अतः धर्म का मूल रूप सब संप्रदायों में स्वीकृत है, लेकिन पथों की अपनी विशेषताएं हैं। चलने वाले के अधिकार के अनुसार हैं ये पथ। संप्रदाय पथ है, भूमि नहीं। महापुरुष नूतन-पथ का निर्माण सदा से करते रहे हैं और करते रहेंगे। उसके नष्ट होने का अर्थ है प्रलय। धारण करने वाले तत्व का नाम धर्म है। वह नहीं रहेगा तो मनुष्यता मर जाएगी। वह तो नित्य है, सत्य है। इसीलिए 'धर्म' सनातन है।

डॉ. विजय प्रकाश त्रिपाठी

खानपान का बिगड़ता पैटर्न

फिर से

जंक फूड सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, लेकिन सब कुछ जानते-समझते हुए भी हम इन्हें खाने का मोह नहीं छोड़ पा रहे

जंक फूड सस्ते हैं, जल्दी बन जाते हैं और पेट भी भर जाता है। बिना किसी झंझट के बन जाने वाले इन खानों में सबसे ज्यादा पसंद किए जाते हैं इंस्टेंट नूडल्स। इनके बिना अपने जीवन को अधूरा समझने वाले लोगों को शायद नहीं पता कि ये असल में कितने खतरनाक हैं। ये इंस्टेंट नूडल्स दक्षिण-पूर्वी एशिया के बच्चों को अस्वस्थ रूप से दुबला या मोटा बना रहे हैं। फिलीपींस, इंडोनेशिया और मलेशिया की अर्थव्यवस्था सुधर रही है। और वहां रहन सहन का स्तर भी तेजी से बढ़ रहा है। फिर भी माता-पिता दोनों के कामकाजी होने की वजह से उनके पास अच्छा खाना बनाने के लिए न तो समय है और न ही अच्छी समझ, जिससे बच्चों को नुकसान पहुंच रहा है। यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के मुताबिक इन तीनों देशों में पांच और इससे कम उम्र के 40 प्रतिशत बच्चे कुपोषित हैं।

इंडोनेशिया के विशेषज्ञों का कहना है कि माता-पिता समझते हैं कि बच्चों का पेट भरना ही सबसे जरूरी चीज है। वे प्रोटीन, कैल्शियम और फाइबर जैसे जरूरी तत्वों के बारे में सोचते भी नहीं। इन देशों में इंस्टेंट नूडल्स के ये पैकेट काफी सस्ते मिल जाते हैं, लेकिन इनमें आवश्यक पोषक तत्वों और आयरन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्व काफी कम होते हैं। इनमें फैट और नमक की मात्रा तो बहुत ज्यादा होती है, लेकिन प्रोटीन की कमी होती है। वर्ल्ड इंस्टेंट नूडल्स एसोसिएशन के मुताबिक चीन के बाद पूरी दुनिया में इंडोनेशिया इंस्टेंट नूडल्स का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता था। यह आंकड़ा भारत और जापान दोनों की कुल खपत से भी ज्यादा है। पोषक तत्वों से भरपूर फल, सब्जियां, अंडे, डेयरी, मछली और मांस आहार से गायब हो रहे हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग नौकरियों की तलाश में शहरों में जा रहे हैं।

यूनिसेफ की रिपोर्ट भले ही एशिया के तीन देशों के बारे में हो, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि भारत भी एशिया का हिस्सा है और दुनिया भर में इंस्टेंट नूडल्स की खपत के मामले में 5वें स्थान पर भारत ही आता है। पहले स्थान पर चीन है, दूसरे पर इंडोनेशिया, तीसरे पर जापान चौथे पर वियतनाम और पांचवें पर भारत। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2015 में मैगी पर लगे बैन के बावजूद भी इंस्टेंट नूडल्स उद्योग 2010 से 2017 के बीच 7.6 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि के साथ सबसे आकर्षक रूप में उभरा।

आज भी खाना बनाने का मन नहीं होता, थक गए या जल्दी से कुछ बनाना होता है तो अधिकांश लोग इंस्टेंट नूडल ही बनाते हैं। खुद भी खाते हैं, बच्चों को भी खिलाते हैं। वे जरा भी नहीं सोचते कि इससे बच्चों की सेहत पर क्या असर पड़ेगा। हमें याद रखना होगा कि कोई भी चीज आसान नहीं होती। हर चीज की एक कीमत होती है। इन इंस्टेंट नूडल के आगे लगा हुआ 'इंस्टेंट' बच्चों के स्वास्थ के रूप में ये कीमत वसूल रहा है और माता-पिता अनजान हैं। इसलिए बच्चों के भविष्य के लिए जरूरी है कि माता-पिता उनके पेट भरने की चिंता छोड़कर इस बात की चिंता करें कि उन्हें पोषित कैसे रखें। और जवाब एकदम सरल है-देसी खाएं और देसी खिलाएं!

(आइचौक.इन से साभार)

सावरकर-विरोध की क्षुद्र राजनीति

प्रो. रजनीश कुमार शुक्ल के आलेख 'सावरकर को लांछित करने का अभियान' में सही तथ्य सामने रखे गए हैं। गांधी जी के सावरकर से मतभेद थे, यह सर्वविदित है। इसके बावजूद अंडमान से उनकी तथा उनके भाई गणेश सावरकर की रिहाई कराकर उन्हें भारत की मुख्य भूमि पर लाने का श्रेय भी उन्हीं को है। किंतु गांधी जी जैसा संतुलन उनके अनुयाइयों में कहां? इसीलिए मतभेदों के कारण सावरकर को बदनाम किया गया। अमेरिकी इतिहास में वाशिंगटन और जेफर्सन में मतभेद थे। वाशिंगटन ब्रिटिशों से दूरी बनाए रखने की पैरवी करते थे। जेफर्सन वैसे ब्रिटेन-विरोधी नहीं थे। किंतु इस कारण वाशिंगटन, जो प्रथम और बेहद लोकप्रिय राष्ट्रपति थे, ने जेफर्सन को बदनाम करने का कभी प्रयास नहीं किया। सावरकर को ऐसे सौजन्यवादी विपक्षी नसीब नहीं हुए। उनके माफीनामे वाला प्रकरण बिना आधार के उठाया गया। सर्वप्रथम यह कार्य मणिशंकर अय्यर ने 2007 में किया। सावरकर तो यह सब 70 साल पहले अपनी आत्मकथा में साफ-साफ बयान कर चुके थे। वह मानते थे कि जेल की सलाखों के पीछे यूं ही मर जाने से बेहतर है बाहर आकर अंग्रेजों का मुकाबला करना। उनके सामने उनके आदर्श शिवाजी का उदाहरण था। आगरा में बंदी जीवन बिता रहे शिवाजी ने औरंगजेब को छह बार माफीनामा भेजकर रिहाई की अपील की थी। पर वह उनकी शातिर चालों को समझता था। अतः रिहाई नहीं हुई। सावरकर के निरंतर आ रहे माफीनामों को देखकर वायसराय ने अपने होम-मेंबर सर क्रदोक को अंडमान भेजा। उन्होंने सावरकर के मन की थाह लेने के लिए उनसे कहा कि क्या वह भारत एवं यूरोप स्थित अपने क्रांतिकारी साथियों को हथियार डालने की अपील करने को तैयार हैं? थोड़ा सोचकर सावरकर ने ऐसा करने से इन्कार कर दिया। तब क्रदोक ने सरकार को रिपोर्ट भेजी कि सावरकर का कोई हृदय-परिवर्तन नहीं हुआ है तथा उनके माफीनामे आंख में धूल झोंकने की कोशिशें मात्र हैं। यहां माफीनामा प्रकरण समाप्त हो गया। किंतु इस बात के आधे तथ्यों को छुपाकर कांग्रेसी एवं कम्युनिस्ट उस शीर्ष क्रांतिकारी के चरित्र-हनन में लगे हैं। वास्तव में तो माफी कम्युनिस्ट नेताओं ने मांगी हैं। तमाम शीर्ष वामपंथी भारत छोड़ो आंदोलन से पूर्व ही माफी मांग-मांग कर छूटे।

अजय मित्तल, मेरठ

मेलबाक्स

सिंगल यूज प्लास्टिक

प्रधानमंत्री ने सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग बंद करने की अपील की थी, लेकिन इसका असर कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा है। इसका एक कारण बाजार में इसकी उपलब्धता और इसके विकल्प का अभाव है। प्लास्टिक कंपनियों को इसका उत्पाद बंद कर इसका विकल्प तैयार करना चाहिए। इससे कारोबार पर भी असर नहीं पड़ेगा और इसके नुकसान से भी बच सकेंगे। एक बार प्रयोग होने वाले प्लास्टिक का उत्पादन पूरी तरह बंद कर देना चाहिए।

राजन तिवारी, बदरपुर, नई दिल्ली

पुलिस का दर्द

केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा है कि पुलिस वालों के काम के घंटे तय किए जाएंगे। गृहमंत्री का यह बयान उचित है। सभी विभागों में काम के घंटे तय हैं, लेकिन पुलिस विभाग ऐसा है जिनके कर्मियों के काम के घंटे तय नहीं हैं। इस कारण काम के दबाव के कारण अधिकांश कर्मी चुस्त-दुरुस्त होकर अपना काम नहीं कर पाते हैं। पुलिसकर्मी भी एक सामाजिक प्राणी होता है। उसका भी एक परिवार होता है, लेकिन काम के घंटे तय न होने के कारण परिवार पर वह ध्यान नहीं दे पाता है। यह खुशी की बात है कि गृहमंत्री ने इस ओर ध्यान दिया है।

hemahariupadhyay@gmail.com

प्रशासन की विफलता

आज कोई भी व्यक्ति सुरक्षित नही है। चाहे वह उच्च पद पर आसीन व्यक्ति हो या कोई आम आदमी। इसका सबसे जीता जागता उदाहरण है कमलेश तिवारी की दिन दहाड़े हत्या। ऐसे में इसे किस दृष्टिकोण से देखा जाए, सरकार की कमी या प्रशासन की विफलता? कमलेश तिवारी ने धर्म विशेष को लेकर विवादित टिप्पणी की थी। इसके लिए उन्हें जेल में भी रहना पड़ा था, किंतु सवाल उठता है कि जिस मौलाना ने कमलेश तिवारी का सर कलम करने पर डेढ़ करोड़ का इनाम रखा था, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई?

anupamyadavay943@gmail.com

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल : mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. संपादकीय निदेशक-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 * इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त।

81 है झारखंड विधानसभा में चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या, जहां इसी वर्ष के आखिर तक विधानसभा चुनाव संभावित है। झारखंड राज्य विधानसभा में एक सदस्य मनोनीत भी करने का प्रावधान है जिसे मिलाकर यह संख्या 82 हो जाती है।

अवधेश कुमार
वरिष्ठ पत्रकार

आजकल

आखिर क्यों आया ऐसा चुनाव परिणाम

महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा के चुनाव परिणाम भाजपा के लिए संतोषजनक नहीं हैं। इन दोनों राज्यों में भाजपा बहुत बड़ी विजय की अपेक्षा कर रही थी। महाराष्ट्र में तो आरंभ से भाजपा शिवसेना गठबंधन बहुमत से आगे थी। हरियाणा का परिणाम भाजपा के लिए धक्का है। एक एक्जिट पोल को छोड़कर सभी ने हरियाणा में भाजपा के अच्छे बहुमत से सरकार में बने रहने की भविष्यवाणी भी कर दी। ऐसे में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि आखिर हुआ क्या?

प्रतीकात्मक

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले विधानसभा चुनावों के बाद महाराष्ट्र और हरियाणा में क्रमशः देवेंद्र फड़नवीस और मनोहर लाल को मुख्यमंत्री बनाकर पूरे देश को चौंकाया था। दोनों ने अपना कार्यकाल पूरा किया। दोनों मुख्यमंत्रियों पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा, सरकार भी भ्रष्टाचार के किसी बड़े पुष्ट आरोप से मुक्त रही। दोनों प्रदेशों की अर्थ दशा भी राष्ट्रीय औसत से बेहतर है। अनुच्छेद 370 तथा जम्मू कश्मीर को संभालने का मुद्दा देशव्यापी है, लेकिन हरियाणा के लिए इसका विशेष मायने इस रूप में था कि वहां शहीद होने वालों में हरियाणवी जवान दूसरे नंबर पर थे। ये दोनों मुख्यमंत्री प्रदेश में वर्चस्व रखने वाली जाति से संबंध नहीं रखते थे। न फड़नवीस मराठा थे और न मनोहर लाल जाट। भाजपा की सोच यह थी कि इन प्रदेशों की राजनीति को भी जातीय समीकरण से मुक्त कर राष्ट्रीयत्व, हिंदुत्व, विकास तथा इससे जुड़े स्वाभाविक मुद्दों पर लाया जाए। दोनों राज्यों में यह कोशिश सफल होती दिख रही थी। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण आंदोलन से एक बार लगा कि फड़नवीस सरकार शायद इसे ठीक से हैंडल नहीं कर पाएगी। फड़नवीस ने उनको आरक्षण दिया और मराठा आंदोलन खत्म हो गया। जाट आरक्षण का आंदोलन हरियाणा में हुआ। यह आंदोलन हिंसक हो गया। देश भर में इसकी आलोचना हुई, पर प्रदेश सरकार ने पुलिस को हिंसा के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई का जिम्मा देते हुए भी यही प्रकट किया कि उसे जाटों की मांग के प्रति सहानुभूति है। बावजूद जाटों के एक वर्ग का गुस्सा सरकार के प्रति कायम रहा।

इसका संकेत यह था कि जाट समुदाय का एक वर्ग मनोहर लाल सरकार के खिलाफ था। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वयं जाट नेताओं से भेंट की। उनको मनाया। बावजूद इसके जाटों का एक बड़ा वर्ग भाजपा के साथ आने को तैयार नहीं हुआ। हालांकि मनोहर लाल सरकार ने चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की भर्ती तथा स्थानांतरण का डिजिटलीकरण करके इसमें भ्रष्टाचार खत्म किया। नतीजन चतुर्थ श्रेणी में नेताओं की पैरवी बंद हो गई एवं हर जाति के योग्य लोगों को काम मिला। इसका संदेश तो अच्छा गया, लेकिन कुछ जाट नेताओं ने यह भ्रम फैलाया कि इसमें हमारा हक मारा गया है। यदि हमारा मुख्यमंत्री होता तो ऐसा नहीं होता। हालांकि उनके बीच ही एक वर्ग यह कहता रहा कि मनोहर सरकार हमारी विरोधी नहीं है। यह फैसला किसी जाति के विरोध या पक्ष में नहीं है और यही होना चाहिए।

माना जा सकता है कि इनकी संख्या कम थी। जाट हरियाणा में सत्ता पर वर्चस्व के अभ्यस्त थे, चाहे कांग्रेस के भूपेन्द्र सिंह हुड्डा की सरकार हो या उसके पहले आइएनएलडी का, सबमें उनकी तूती बोलती रही। मनोहर लाल सरकार में ऐसा नहीं हुआ। उसमें भूपेन्द्र सिंह हुड्डा ने अपना अंतिम चुनाव कहकर भावुक कार्ड खेला, वह काम कर गया। तो जाटों के बहुमत से जहां कांग्रेस जीत सकती थी, वहां उसे मत दिया और जहां जेजेपी जीत सकती थी वहां उसे। इसका परिणाम सामने है।

हालांकि यह मान लेना गलत होगा कि जाटों के एक तबके के खिलाफ जाने के कारण ही भाजपा को क्षति हुई। इसके साथ कई कारकों ने भूमिका निभाई। फड़नवीस सरकार ने भीमा कोरेगांव जैसे सुनियोजित हिंसक आंदोलन को जिस तरह नियंत्रित किया एवं माओवादियों के चेहरे उजागर किए उससे विचारधारा के आधार पर समर्थन करने वाले परंपरागत मतदाताओं का समर्थन बना रहा। शनि सिंगणापुर आंदोलन को भी सरकार ने नियंत्रण से बाहर नहीं आने दिया। भ्रष्टाचार के विरुद्ध भी महाराष्ट्र सरकार ने कई मामलों में तेजी से काम किया। मनोहर सरकार ने भी भूमि आवंटन घोटाला में ढींगरा आयोग बनाया जिसने रॉबर्ट वाड्रा सहित भूपेन्द्र सिंह हुड्डा और कई नेताओं एवं अधिकारियों को कठघरे में खड़ा किया। हुड्डा न्यायालय में चले गए एवं उस रिपोर्ट के सार्वजनिक करने पर रोक लग गई। ईडी ने कार्रवाई की है, पर प्रदेश में संदेश यह गया कि मनोहर लाल सरकार ने भ्रष्टाचारियों पर जिस तरह कार्रवाई करना चाहिए वैसे नहीं की। वर्ष 2014 के लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव में वाड्रा का भूमि व्यवसाय भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा मुद्दा था। मनोहर लाल कहते रहे कि हमारा उद्देश्य भ्रष्टाचार की संभावना को खत्म करना, तथा कानून सम्मत कार्रवाई करना है न कि किसी व्यक्ति विशेष को निशाना बनाना, लेकिन इस संदेश को सभी ने एक ही अनुसार नहीं लिया। स्वयं उनके कार्यकर्ता भी इस विषय पर सरकार से सहमत नहीं थे।

इन सबके बावजूद भाजपा का प्रदर्शन संतोषजनक हो सकता था यदि उसने उम्मीदवारों के चयन में सतर्कता बरती होती तथा पार्टी के अंदर के असंतोष के शमन का कदम उठाया होता। विधानसभा चुनावों में स्थानीय मुद्दों व उम्मीदवारों की भी भूमिका होती है। मनोहर सरकार के ज्यादातर मंत्रियों को लोगों का एक तबका बेहतर प्रदर्शन करने वाला नहीं मान रहा था। स्वयं खट्टर के व्यवहार को पार्टी कार्यकर्ता और नेता आलोचना करते थे। उनके कई मंत्रियों के व्यवहार की शिकायत केंद्रीय नेतृत्व से भी की गई। कई क्षेत्रों में लोग स्थानीय विधायक तथा उम्मीदवारों के प्रति असंतोष प्रकट करते थे। भाजपा के सदस्य कह रहे थे कि उम्मीदवारों के चयन में गलतियां हुई हैं। अगर चुनाव में किसी पार्टी के कार्यकर्ता और स्थानीय पदाधिकारी नाराज हो जाएं तो फिर उसका बेहतर प्रदर्शन करना मुश्किल होता है। कार्यकर्ता ही मतदान के दिन अपने मतदाताओं को मतदान केंद्र तक लाते हैं। दोनों राज्यों में भाजपा कार्यकर्ताओं-नेताओं के अंदर असंतोष था।

महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ गठबंधन के कारण कुछ विधानसभा क्षेत्रों में विद्रोह हुआ। भाजपा का एक तबका विधानसभा चुनाव में शिवेसना से गठबंधन नहीं चाहता था। फिर कोंकण क्षेत्र में नारायण राणे को खुली स्वतंत्रता देने के खिलाफ शिवेसना ने मोर्चा खोला, उनके बेटे के खिलाफ अपना उम्मीदवार उतार दिया तो अनेक जगह निर्दलीय के रूप में उम्मीदवार मैदान में थे। निर्दलीय ने भाजपा को काफी ज्यादा तथा शिवेसना को भी कुछ नुकसान पहुंचाया है। हरियाणा में भी यही स्थिति थी। लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी का नाम सबको एकजुट करने के लिए काफी था। इसलिए एकपक्षीय चुनाव परिणाम आया। विधानसभा चुनाव में ऐसा नहीं था। कार्यकर्ताओं के उदासीन होने का परिणाम हरियाणा में आठ प्रतिशत मतदान कम होने के रूप में सामने आया। भाजपा के प्रदर्शन खराब होने के पीछे यह सबसे बड़ा कारण था।

चेतावनी भरा है यह जनादेश

लोकमित्र
वरिष्ठ पत्रकार

महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे भले व्यापक उथल-पुथल को प्रदर्शित न करते हों, लेकिन इन नतीजों में मौजूदा राज्य सरकारों के प्रति मतदाताओं की नाराजगी जरूर दिख रही है। साथ ही ये नतीजे मीडिया के गलत अनुमानों की भी बड़ी बानगी हैं। जिस तरह लगभग सभी टीवी चैनल दोनों ही राज्यों में सत्तारूढ़ पार्टियों की सहज वापसी की घोषणा कर रहे थे, असल नतीजे उसे नकार रहे हैं। एक और बात स्पष्ट है कि भले ही इन दोनों राज्यों के विधानसभा चुनावों के नतीजे, इन प्रदेशों में काबिज सरकारों के कामकाज पर मतदाताओं की नाराजगी की मुहर हों, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इन नतीजों में केंद्र के लिए भी एक संदेश, एक चेतावनी मौजूद है।

अगर एग्जिट पोल की नजर से देखें तो करीब 95 फीसद अनुमान ध्वस्त हो गए। जिस महाराष्ट्र में कई मीडिया चैनल भाजपा और शिवसेना को 220 से लेकर 243 तक सीटें एग्जिट पोल में दे रहे थे, हकीकत में ये सीटें 160 के आसपास रही हैं। जबकि साल 2014 में शिवसेना और भाजपा ने मिलकर महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में 185 सीटें जीती थीं। बाद में 20 से ज्यादा विभिन्न पार्टियों के विधायक भी भाजपा में शामिल हो गए थे, तो अंततः जो भाजपा और शिवसेना का गठबंधन महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के मैदान में उतरा था, उसके खाते में करीब 207 सीटें थीं। लेकिन अगर ताजा नतीजों को 2014 के नतीजों के मुकाबले देखें तो महाराष्ट्र में भाजपा और शिवसेना दोनों की ही सीटें कम हुई हैं। भाजपा 122 से 105 पर आ गई है, इस तरह उसे 17 सीटों का नुकसान हुआ है। जबकि शिवसेना 63 से 56 सीटों पर आ गई है। इस तरह उसने भी सात सीटें पिछली बार के मुकाबले गंवाई हैं। हालांकि इन पंक्तियों के लिखे जाने तक यानी गुरुवार को संध्या साढ़े आठ बजे तक अंतिम नतीजे नहीं आए थे, फिर भी जो नतीजे ठोस रूप ले चुके थे जिसके मुताबिक भाजपा को पिछली बार के मुकाबले वोट प्रतिशत में भी दो फीसद से ज्यादा का नुकसान हुआ है। शिवसेना को भी करीब दो ही फीसद का नुकसान हुआ है। जबकि एनसीपी ने करीब करीब अपने वोट बैंक को बरकरार रखा है। कांग्रेस को करीब ढाई फीसद का नुकसान हुआ है। हरियाणा में तो नतीजों ने इससे भी ज्यादा हैरान किया है।

ज्यादातर एग्जिट पोल बता रहे थे कि भाजपा हरियाणा में दो तिहाई बहुमत के साथ चुनाव जीत रही है। लेकिन भाजपा को साधारण बहुमत भी नहीं मिला। संध्या साढ़े आठ बजे भाजपा 40 सीटों पर जीत/ बढ़त बनाए थी। यह अलग बात है कि उसे 2014 के मुकाबले हासिल मतों के मामले में जरूर फायदा हुआ है। जहां 2014 में भाजपा को हरियाणा में 33.2 फीसद मतों के साथ 47 सीटें मिली थीं, वहीं 2019 में 36.5 फीसद मतों के साथ 40 के आसपास सीटें मिली हैं। कांग्रेस को वर्ष 2014 में हरियाणा में 20.6 फीसद मतों के साथ 15 सीटें मिली थीं, जबकि 2019 में उसे लगभग 28.1 फीसद मतों के साथ करीब 31 सीटें मिली हैं। वर्ष 2014 में हुए मतदान में हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल को 19 सीटें मिली थीं, इस बार एक पर सिमट गई है। वास्तव में हरियाणा में किंग मेकर की भूमिका में जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी उभरी है, जो पिछले चुनाव में नहीं थी। मौजूदा चुनावों से कुछ दिन पहले बनी और अपने पहले ही प्रयास में उसने 10 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल की। माना जा रहा है कि हरियाणा की आगामी सरकार की चाबी जेजेपी के पास ही होगी। एक तरह से भाजपा और कांग्रेस उससे काफी ज्यादा मत पाकर भी समीकरणों के लिहाज से सरकार बनाने के लिए उसी पर निर्भर हैं।

इन विधानसभा चुनाव परिणामों को मतदाताओं द्वारा दिया गया 'चेतावनी जनादेश' कहा जा सकता है। इस जनादेश के कई मतलब हैं। इस जनादेश ने बता दिया है कि आम चुनाव में राष्ट्रीय मुद्दे भले कितनी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हों, लेकिन स्थानीय चुनावों में स्थानीय मुद्दे ही काम आते हैं।

(इमेज रिफ्लेक्शन सेंटर)

खरी-खरी

सहमे-सहमे से हैं धूल के कण!

कमलेश पाण्डेय

मेरे घर में इन दिनों धूल के कण डरे-सहमे से हैं। कल तक जो हर जगह छाती चौड़ी करके पसरे रहते थे, वे डर के मारे दुबक गए हैं किसी कोने में। जालों का भी यही हाल है। अलमारियां, रैक और ड्रॉवर के मुंह खौफ से खुले पड़े हैं। उनकी हर चीज बाहर ऐसी छितराई पड़ी हैं, मानो ईडी या इनकम टैक्स का छापा पड़ा हो। अच्छी-अच्छी चीजें दम साधे हुए हैं कि कहीं ओएलएक्स पर न निकाल दी जाए। या कि ऑनलाइन सेल की मार के कारण चलन से बाहर न हो जाएं। छोटा-बड़ा हर सामान उस कूड़ेदान को देखकर हिल जाता है, जो कूड़ेदान कल तक कोने में दुबका रहता है। चादर, पर्दों, कुशनों की लगातार धुलाई चालू है।

पूरा घर सफाई के एजेंटों ने हाईजैक कर रखा है। इनकी सरगना श्रीमतीजी को सुबह ही मैंने चंद मुस्तैद झाड़ू, पोंछे, डस्टर, फिनाइल, साबुन के साथ इन्हें कूच करने का ऑर्डर देते सुना। भाषण के कुछ तेजाबी जुमले मेरे कानों में पड़े तो जैसे एक झटके में उनका सारा मैल बाहर आ गया। कमांड बिल्कुल स्पष्ट था- धूल और गर्द का एक भी कण बचने न पाए।

श्रीमतीजी अभी कुछ भी सुन, बोल या कर नहीं रहीं, सिवाय सफाई के। गर्द को नेस्तनाबूद कर देने की उनकी मुहीम में उनके दो सहयोगी हैं और एक बाधा। सहयोगी है बाई और बाबू तथा बाधा हूं मैं। हालांकि मैं स्वयं को मन, वचन, कर्म से उनके किसी भी अभियान का कर्मठ कार्यकर्ता मानता हूं। पर सफाई के संदर्भ में अपना नजरिया एकदम उलट है। उनकी सफाई संबंधी जिद की व्याख्या मैं वृहतर सांसारिक परिप्रेक्ष्य में करता हूं तो धूल के जर्रे-जर्रे को घर से उड़ाकर बाहर बिखेर देना पर्यावरण विरोधी काम प्रतीत होता है। ऐसे ही घर को धोने से उपजा जलसंकट भी है जिसके प्रायश्चित स्वरूप पूरी सर्दी मुझे न नहाकर सफाई में बर्बाद जल के बराबर पानी बचाना पड़ता है।

एक आपत्ति जरा आर्थिक टाइप है। जरा सी बदरंग हुई, आंखों को यूं ही खटक गई हर शै को वे दरियादिली से बदल डालने के जोश से भरी होती हैं। इससे मेरी जेब खोखल हो जाती है। इसका उनके पास वजनदार तर्क भी है- कुछ नहीं तो कम से कम देश की मंदी का ही खयाल कर लो। वैसे भी मेरी आपत्तियों की क्या बिसात! घर में तो- होई हैं वही जो गृहिणी सोचि राखा। सो, मैं उनके सफाई आंदोलन में अन्ना का केजरीवाल बन दिल्लीवालों की तरह झाड़ू से सबकुछ साफ होते देख रहा हूं।

ट्वीट-ट्वीट

कम से कम अब तो विपक्षी नेताओं को ईवीएम, मीडिया और बाकी पहलुओं का रोना बंद कर देना चाहिए। जमीन पर विपक्ष मौजूद है। कमी है तो बस नेतृत्व की। पवार और हुड्डा ने दिखाया है कि निरंतरता के क्या मायने होते हैं।

बरखा दत्त@BDUTT

वर्ष 2014 और फिर 2019 में मोदी को मिला जनादेश वास्तविक बदलाव के लिए है। यह अवसर अनमोल है। समय आ गया है कि प्रभावी कानून व्यवस्था, विकेंद्रीकरण, सिविल सेवा सुधार और शिक्षा एवं स्वास्थ्य पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया जाए।

जयप्रकाश नारायण@JP_LOKSATTA

विधानसभा चुनाव के जनादेश का सार यही है कि भाजपा का अति-आत्मविश्वास भंग हुआ। कांग्रेस के लिए गांधी परिवार की बैसाखी वाली अनिवार्यता टूटी। आर्थिक-राजनीतिक मुद्दे, कृषि संकट-कृषक आक्रोश फिर राजनीति के केंद्र में लौटे। स्थानीय नेतृत्व-सरकारी कामकाज फिर अहम हुए।

राहुल देव@rahuldev2

प्रदीप शुक्ला
स्थानीय संपादक, झारखंड

झारखंड डायरी

अब नजरें झारखंड पर, दिलचस्प होगा चुनाव

महाराष्ट्र और हरियाणा के विधानसभा चुनाव नतीजों का झारखंड की राजनीति में भी व्यापक प्रभाव पड़ना तय है। अगले दो महीने में यहां भी नई सरकार का गठन होना है और ऐसे में यह नतीजे जहां विपक्ष में नई ऊर्जा का संचार करेंगे, वहीं राज्य में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और अधिक सतर्क होकर अपनी रणनीति को अमलीजामा पहनाएगी। अगले दो महीने अब देश भर के राजनीतिक पंडितों की नजर प्राकृतिक और खनिज संपदा की दृष्टि से धनधान्य प्रदेश पर जमी रहने वाली है। विधानसभा में सीटों की संख्या के लिहाज से झारखंड, हरियाणा से थोड़ा ही छोटा है, लेकिन भौगोलिक दृष्टि से उससे काफी बड़ा है। झारखंड प्राकृतिक रूप से बहुत खूबसूरत है और इस मौसम में यहां के जंगल, पहाड़, झरने, डैम किसी को भी मोहित कर सकते हैं। स्वाभाविक है कि राजनीतिक दलों के नेताओं के दौरे अब इस राज्य में बढ़ेंगे और एक-दूसरे पर हमले भी।

माना जा रहा है कि दीपावली के बाद किसी भी दिन राज्य में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो सकती है। सभी राजनीतिक दल पूरी तैयारी के साथ चुनाव मैदान में उतर चुके हैं। अभी गठबंधन बने नहीं हैं, लेकिन एक-दो दौर की बातचीत दोनों गठबंधनों के दलों में हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के साथ आजसू सीटों को लेकर मोलभाव कर रही है, वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस में सिर-फुटौव्वल की स्थिति है। झारखंड विकास मोर्चा को इसका अंदाजा हो गया है कि उसे विपक्षी गठबंधन में उन्हें उतना महत्व नहीं मिलेगा, जितना वह चाहते हैं, इसलिए झाविमो के अगुवा पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी एकला चलो की राह पर चलते दिखाई पड़ रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल, जनता जल यूनाइटेड समेत वामपंथी पार्टियां अभी खुद को आंक रही हैं।

एक दिन पहले ही भाजपा ने झामुमो और कांग्रेस के दो-दो विधायकों का पाला बदल करवाया है। इसके अलावा नौजवान मोर्चा के अध्यक्ष व विधायक भानू प्रताप शाही ने अपनी

पार्टी का विलय ही भाजपा में कर लिया। दो राज्यों के नतीजे आने के बाद राजनीतिक माहौल कुछ बदला-बदला नजर आ रहा है। बेशक, महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार बन गई है और हरियाणा में भी वह सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, लेकिन नतीजे वैसे नहीं हैं, जैसा कार्यकर्ता मानकर चल रहे थे।

इधर, हताश विपक्ष को दम मिल गया है। झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन कहते हैं कि इस परिणाम से यह साबित हो गया है कि प्रचंड प्रचार तंत्र, मजबूत धन तंत्र और राजनीतिक धोखाधड़ी से जनता को बहुत दिनों तक गुमराह नहीं किया जा सकता है। वह तंज करते हैं, जो विधायक जनता को धोखा देकर भाजपा के शरणार्थी शिविर में शामिल हुए हैं, उन लोगों ने आत्महत्या की है।

इस परिणाम का एक असर यह भी पड़ेगा, अब भाजपा की सहयोगी आजसू और ज्यादा मोलभाव करने की स्थिति में होगी। अभी तक भाजपा नेता जिस तरह से बयान दे रहे थे, उससे लग रहा था कि वह आजसू को बहुत ज्यादा महत्व देने के मूड में नहीं हैं। विपक्ष भी और ताकतवर गठबंधन के बाबत सोच सकता है। झामुमो और कांग्रेस जिस तरह आधी-आधी सीटों पर लड़ने की दावेदारी कर रहे थे, अब उनके रुख में भी बदलाव आ सकता है। वह अपना दिल बड़ा कर झाविमो, राजद और वाम पार्टियों को शामिल कर महागठबंधन बनाकर रघुवर दास के सामने डट सकते हैं।

इन दो राज्यों के चुनाव परिणाम से भारतीय जनता पार्टी भी अपनी चुनावी रणनीति पर पुनर्विचार कर सकती है। बाहर से जिताऊ प्रत्याशी खोजने के बजाय पार्टी के पुराने और निष्ठावान कार्यकर्ताओं को महत्व दे सकती है। हरियाणा में जिस तरह कद्दावर मंत्री और बाहर से आए तमाम बड़े चेहरों को जनता ने नकार दिया है, उससे यह तो साबित हो ही गया है जनता आपकी बंधक नहीं है, उस पर जिसे चाहे लाकर थोप दो। आखिर लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन है।

जागरण जनमत

कल का परिणाम

क्या सोशल मीडिया को आधार से जोड़ा जाना चाहिए?

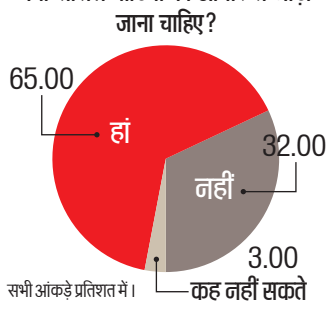

सभी आंकड़े प्रतिशत में।

आज का सवाल

क्या विधानसभा चुनाव के नतीजों से विपक्षी दलों का मनोबल बढ़ेगा?

अपनी राय और अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाकर **POLL** लिखें, स्पेस देकर **Y, N** या **C** लिखकर *57272* पर भेजें
Y -हां, **N**-नहीं, **C**-कह नहीं सकते

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।

जनपथ

उड़िए जमकर बंधु पर बिसरे नहीं जमीन,
वरना देकर भी बहुत जनता लेती छीन।
जनता लेती छीन अभी तो है यह झटका,
संभले ना यदि आप पड़ेगा मोटा फटका।
खुद के वादे आप सावधानी से पढ़िए,
उन्हें कीजिए पूर्ण और तब जमकर उड़िए!

– ओमप्रकाश तिवारी

जयंती

औषधीय अनुसंधान के जनक धन्वंतरि

धन्वंतरि को चिकित्सा पद्धति का जनक माना जाता है। पुराणों में तो इसका अनेक जगह पर विस्तारपूर्वक उल्लेख है ही, ब्रिटिश विशेषज्ञों ने भी इस बारे में अपनी पुस्तकों में जिक्र किया है कि भारत में अनेक बीमारियों का टीका लगाने की प्रथा बहुत पुरानी है

प्रमोद भार्गव
वरिष्ठ पत्रकार

समुद्र-मंथन के अंत में आयुर्वेदाचार्य धन्वंतरि देव और दानवों को हाथों में अमृत-कलश लिए मिले थे। दरअसल समुद्र-मंथन की घटना की जानकारी विश्व के उन सभी क्षेत्रों में फैल गई थी, जिनकी अपनी सत्ता थी। उस समय धन्वंतरि चिकित्सा क्षेत्र के बड़े वैद्य के रूप में विख्यात हो चुके थे। जिस तरह से समुद्र-मंथन के यात्रियों को विभिन्न देशों में पहुंचने पर कामधेनु गाय, उच्चैश्रवा घोड़ा, ऐरावत हाथी, कौस्तुभ मणि, कल्पवृक्ष, रंभा, लक्ष्मी, वारूणी, चंद्रमा, पारिजात वृक्ष, पांचजन्य शंख मिले, उसी प्रकार इस अल्पज्ञात क्षेत्र में धन्वंतरि मिले। हालांकि धन्वंतरि जिस औषधीय वन-प्रांतर में रहते थे, उस भूखंड में उरू, पुरू आदि पहले ही पहुंच गए थे। धन्वंतरि उन्हीं के वंशज थे। धन्वंतरि और इस क्षेत्र के मुखियाओं को जब देव व असुरों जैसे पराक्रमियों के आने की सूचना मिली, तो वे समझ गए कि इस समूह से किसी भी प्रकार का संघर्ष उचित नहीं है। अपितु इनसे बेहतर संबंध बनाना उचित है। बुद्धिमत्तापूर्ण इस पहल से धन्वंतरि ने भी समझा होगा कि उनके अब तक के जो भी औषधीय अनुसंधान हैं, उन्हें वैश्विक मान्यता तो मिलेगी ही, विश्व प्रसिद्ध देव व असुरों की चिकित्सा करने का भी अवसर मिलेगा।

श्रीमद् भगवत के अनुसार समुद्र मंथन की प्रक्रिया आगे बढ़ने पर, प्रकट होने वाले 14 रत्नों में से एक भगवान धन्वंतरि थे। धन्वंतरि और उनकी पीढ़ियों ने ऐसी अनेक वनस्पतियों की खोज व उनका रोगी मनुष्यों पर प्रयोग किए। इन प्रयोगों के निष्कर्ष श्लोकों में ढालने का उल्लेखनीय काम भी किया, जिससे इस खोजी विरासत का लोप न हो। इन्हीं श्लोकों का संग्रह 'आयुर्वेद' है। एक लाख श्लोकों की इस संहिता को 'ब्रह्म-संहिता' भी कहा जाता है। इन संहिताओं में सौ-सौ श्लोक वाले एक हजार अध्याय हैं। बाद में इनका वर्गीकरण भी किया गया। इसका आधार अल्प-आयु तथा अल्प-बुद्धि को बनाया गया। वनस्पतियों के इस उपचार विधियों का संकलन 'अथर्ववेद' भी है। अथर्ववेद के इसी सारभूत संपूर्ण आयुर्वेद का ज्ञान धन्वंतरि ने पहले दक्ष प्रजापति को दिया और फिर अश्विनी कुमारों को पारंगत किया। अश्विनी कुमारों ने ही वैद्यों के ज्ञान वृद्धि की दृष्टि से 'अश्विनी कुमार संहिता' की रचना की।

एक अन्य पुराण-कथा में उल्लेख है कि एक बार वायुयान से भूलोक पर दृष्टिपात करने पर इंद्र ने मनुष्यों को बड़ी संख्या में रोगग्रस्त पाया। उन्होंने धन्वंतरि को आयुर्वेद का संपूर्ण ज्ञान देने के लिए ज्ञान परंपरा की परिपाटी चलाने का अनुरोध किया। इसके बाद धन्वंतरि ने काशी के राजा दिवोदास के रूप में जन्म लिया और काशीराज कहलाए। अपने पिता विश्वामित्र की आज्ञा पाकर महर्षि सुश्रुत अपने साथ अन्यान्य एक सौ ऋषि-पुत्रों को लेकर काशी पहुंचे और वहां सुश्रुत ने ऋषि-पुत्रों के साथ धन्वंतरि से आयुर्वेद की शिक्षा ली। इसके बाद इस समूह ने लोक कल्याणार्थ संहिताओं एवं ग्रंथों की रचना की और उनके माध्यम से समस्त भूमंडल के लोगों को निरोगी बनाने की उपचार पद्धतियां शुरू कीं।

अथर्ववेद में भेषजों की उपयोगिताओं के वर्णन हैं। भेषजों के सुनिश्चित गुणों और उपयोगों का उल्लेख कुछ अधिक विस्तार से आयुर्वेद में हुआ है। यही आयुर्वेद भारतीय चिकित्सा विज्ञान की आधारशिला है। इसे उपवेद भी माना गया है। इसके आठ अध्याय हैं जिनमें आयुर्विज्ञान और चिकित्सा के विभिन्न पक्षों पर विचार किया गया है। इसका रचनाकाल पाश्चात्य विद्वानों ने ईसा से ढाई से तीन हजार वर्ष पुराना माना है। इसके आठ अध्याय हैं, इसलिए इसे 'अष्टांग आयुर्वेद' भी कहा गया है। आयुर्वेद की रचना के बाद पुराणों में सुश्रुत और चरक ऋषियों और उनके द्वारा रचित संहिताओं का उल्लेख है। सुश्रुत संहिता में शल्य-विज्ञान का विस्तृत विवरण है। इसी काल में चरक संहिता का प्रादुर्भाव माना जाता है। इसमें चिकित्सा विज्ञान विस्तृत रूप में सामने आया है। इसमें औषधियों की मात्रा और सेवन विधियों का भी तार्किक वर्णन है। इनका आज की प्रचलित चिकित्सा पद्धतियों से साम्य भी है। यहां तक कि कुछ विधियों में इंजेक्शन द्वारा शरीर में दवा पहुंचाने का भी उल्लेख है। यह वह समय था जब भारतीय चिकित्सा विज्ञान अपने उत्कर्ष पर था और भारतीय चिकित्सकों की भेषज तथा विष विज्ञान संबंधी प्रणालियां अन्य देशों की तुलना में उन्नत थीं। भूमि गर्भ में समाए अनेक खनिज पदार्थों के गुणों का ऋषि परंपरा ने गहन अध्यन किया था और रोग तथा भेषजों की मदद से उनके उपचार की दिशा में वैज्ञानिक ढंग से अनुसंधान किए। सुश्रुत और चरक की आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में अब गणना होने लगी है। यही कारण है कि एलोपैथी की दवा निर्माता कंपनियां भी सुश्रुत और चरक के अपने कैलेंडरों में शल्य क्रिया करते हुए चित्र छापने लगे हैं।

आखिर इतनी उत्कृष्ट चिकित्सा पद्धति होने के पश्चात भी इसका पतन क्यों हुआ? हमारे यहां संकट तब पैदा हुआ, जब तांत्रिकों, सिद्धों और पाखंडियों ने इनमें कर्मकांड से जीवन की समृद्धि का घालमेल शुरू कर दिया। इसके तत्काल बाद एक और बड़ा संकट तब आया, जब भारत पर यूनानियों, शकों, हूणों और मुसलमानों के हमलों का सिलसिला शुरू हो गया। इस संक्रमण काल में आयुर्विज्ञान की ज्योति नष्टप्राय हो गई। नए शोध व मौलिक ग्रंथों का सृजन थम गया। इन आक्रमणों के कारण जो अराजकता, हिंसा और अशांति फैली, उसके चलते अनेक आयुर्वेदिक ग्रंथ छिन्न-भिन्न हो गए। आयुर्विज्ञान की जो शाखाएं थीं, वे पंडे और पुजारियों के हवाले हो गईं, नतीजतन भेषज और जड़ी-बुटियों के स्थान पर तंत्र-मंत्र के प्रयोग होने लग गए।

इसके बाद जो रही-सही ज्ञान परंपराएं थीं, उन पर सुनियोजित ढंग से पानी फेरने का काम अंग्रेजों ने कर दिया। डॉ. धर्मपाल की पुस्तक 'इंडियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी' में लिखा है कि 1731 में बंगाल में डॉ. ओलिवर काउल्ट नियुक्त थे। काउल्ट ने लिखा है कि 'भारत में रोगियों को टीका देने का चलन था। बंगाल के वैद्य सुई से चेचक के घाव की पीब लेकर उसे टीका की जरूरत पड़ने वाले रोगी के शरीर में कई बार चुभोते थे। इस उपचार पद्धति को संपन्न करने के बाद वे उबले चावल की लेई सी बनाकर रोगी के घाव पर चिपका देते थे। इसके रोगी को बुखार आता था। वे रोगी को ठंडी जगह में रखते थे और उसे ठंडे पानी से नहलाते थे ताकि शरीर का ताप नियंत्रित रहे।

15 लाख का मुआवजा दिया जाएगा वन्यजीवों के हमलों में मारे गए वनकर्मियों के परिजनों को। इसके अलावा अब उन्हें पुलिस के समान अन्य सुविधाएं भी दी जाएंगी। उत्तराखंड सरकार ने इस संबंध में मसौदा राय के लिए वित्त विभाग को भेज दिया है।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
शुक्रवार 25 अक्टूबर 2019

आइए मिलकर मनाएं 'यह दिवाली अलग निराली'

- लंग केयर फाउंडेशन की वेवसाइट एलसीएफ.ओआरजी. इन पर देखें एक से बढ़कर एक उपाय
- देशभर के बच्चों से मांगे गए थे ईको फ्रेंडली दिवाली मनाने के कारगर उपाय
- वीडियो और पोस्टर अपलोड कर बच्चों ने दिए दिल को छू जाने वाले सुझाव, अब मिलेगा पुरस्कार

वीडियो और पोस्टर के जरिये देशभर के हजार से अधिक बच्चों ने इस कैंपेन में भाग लिया। सौ. एलसीएफ

अतुल पटैरिया, नई दिल्ली

यह दिवाली अलग और निराली कैसे मनाएं..., देशभर के हजारों स्कूली बच्चों ने लंग केयर फाउंडेशन की वेबसाइट यहदिवालीअलगनिराली.ओआरजी.इन पर एक से बढ़कर एक उपाय साझा किए हैं। इस वेबसाइट पर अपने वीडियो और पोस्टर अपलोड कर बच्चों ने जता दिया है कि पर्यावरण और स्वास्थ्य संरक्षण उनके लिए प्राथमिक और अति गंभीर विषय है।

बच्चों ने जिस बालसुलभ तरीके से अपनी बात रखी है, उनका यह अंदाज दिल को छू जाता है। लेकिन 6 से 18 साल की उम्र के ये बच्चे जो कह रहे हैं, वह बड़ों को भी गंभीरता पूर्वक समझ लेना चाहिए। दिवाली पर पटाखे छुड़ाने की परंपरा को इन बच्चों ने अब गैरजरूरी करार दिया है। कह रहे हैं कि ऐसी खुशी किस काम की, जो जीवन पर भारी पड़े। लिहाजा, किसी ने गुब्बारे छोड़ कर खुशी मनाने का तरीका सुझाया है तो किसी ने पौधा रोप कर खुशी मनाने का। किसी ने जरूरतमंदों को उपहार बांटने का, तो किसी ने बुजुर्गों को हंसाने, मिठाई बांटने, खिलौने खरीदने-बांटने, आंगन में रंगोली सजाने का। ऐसे चुनिंदा एक हजार संदेशों को लंग केयर फाउंडेशन ने वेबसाइट और सोशल मीडिया पर जारी किया है। दिवाली के बाद इन बच्चों को पुरस्कार प्रदान किया जाएगा।

पर्यावरण संरक्षण

लंग केयर फाउंडेशन के संस्थापक और मैनेजिंग ट्रस्टी प्रोफेसर डॉ. अरविंद कुमार ने दैनिक जागरण से इस कैंपेन के निहित उद्देश्यों को साझा करते हुए कहा, लंग केयर फाउंडेशन दरअसल बच्चों के माध्यम से उन सभी कारकों के प्रति जागरूकता का विस्तार करने में जुटा है, जो न केवल पर्यावरण के लिए चुनौती हैं बल्कि फेफड़ा (लंग) संबधित रोगों के कारक हैं। भारत में 25 फीसद स्कूली बच्चे अस्थमा का शिकार हैं। ऐसे में हमने बच्चों को ही अपना दूत बनाया है ताकि समाज इस गंभीर विषय को समझ सके और पर्यावरण व स्वास्थ्य संरक्षण की मुहिम का हिस्सा बन सके। 'यह दिवाली अलग निराली' कैंपेन हमने इसी उद्देश्य से लॉन्च किया। एक अक्टूबर से लेकर 25 तक देशभर के हजारों स्कूली बच्चों ने इसमें प्रतिभाग किया और वायु प्रदूषण को रोकने के अलावा प्लास्टिक पर लगाम लगाने के लिए रोचक सुझाव दिए।

एम्स, नई दिल्ली के भूतपूर्व प्रोफेसर डॉ. अरविंद कुमार सेंटर फॉर चेस्ट सर्जरी के अध्यक्ष और नई दिल्ली स्थित सर गंगाराम अस्पताल स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ रोबोटिक सर्जरी के निर्देशक भी हैं। कहते हैं, दिवाली के बाद फाउंडेशन अब इन सभी बच्चों को प्रमाणपत्र प्रदान कर इनके स्कूल का 'लंग एंबेसडर' घोषित करेगा। साथ ही इन्हें लंग केयर फाउंडेशन के 'बेस्ट क्लब' का सदस्य भी बनाएगा, ताकि जागरूकता का अधिक से अधिक विस्तार होता चले।

आप भी बन सकते हैं 'बेस्ट क्लब' के सदस्य : लंग केयर फाउंडेशन के अध्यक्ष प्रोफेसर डॉ. अरविंद कुमार ने बताया कि 6-18 वर्ष की आयु का कोई भी स्कूली बच्चा लंग केयर फाउंडेशन के 'बेस्ट क्लब' का सदस्य बन अपने स्कूल का 'लंग एंबेसरडर' बन सकता है। उसे फाउंडेशन की ओर से सदस्यता और प्रमाणपत्र दिया जाएगा व दीर्घकालीन मुहिम से जोड़ा जाएगा। इसके लिए फाउंडेशन की वेबसाइट 'डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट एलसीएफ डॉट ओआरजी डॉट इन' पर संपर्क करें। बच्चे अपना संदेश 40 सेकंड के वीडियो या पोस्टर के रूप में बेवसाइट पर अपलोड भी कर सकते हैं।

सरोकार की अन्य खबरें पढ़ें
www.jagran.com/topics/positive-news

अठन्नी जिन जाना, इ हौ मइया क खजाना...

जागरण विशेष ▶ धनतेरस पर आज से चार दिनों के लिए खुलेगा काशी स्थित स्वर्णमयी अन्नपूर्णेश्वरी मां का दरबार

प्रमोद यादव, वाराणसी

आज सुबह पांच बजे मंदिर के पट खुलने की प्रतीक्षा में, गुरुवार शाम से ही भक्तों की कतार एक किलोमीटर के पार विस्तार पा चुकी थी। साल में सिर्फ चार दिनों के लिए खुलने वाले काशी के स्वर्णमयी अन्नपूर्णेश्वरी दरबार में भक्तों का रेला उमड़ पड़ा है। मां के दर्शनों के साथ-साथ प्रसादस्वरूप सौभाग्यशाली अठन्नी पाने के लिए भक्तों की बेचैनी देखते ही बनती है। चार दिनों तक लंबी कतार लगी रहेगी। दर्शनार्थियों के बीच वितरण के लिए इस साल मंदिर प्रबंधन ने 4.50 लाख अठन्नियां मंगाई हैं।

बाबा विश्वनाथ के आंगन में विराजमान मइया अन्नपूर्णा कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी यानी धनतेरस पर भक्तों को प्रथम दर्शन देंगी। दर्शनों के लिए भक्तों की यह बेचैनी हो भी क्यों नहीं, जब माता के दरबार की शान में स्वयं बाबा विश्वनाथ याचक की भूमिका में खड़े हैं। काशीपुराधिपति को भी अन्नदान देने वाली मां अन्नपूर्णेश्वरी के दरबार से मिली अठन्नी (50 पैसा का सिक्का) भक्तों के लिए कुबेर के खजाने से कम नहीं है। मान्यता है कि काशी नगरी के पालन-पोषण को देवाधिदेव मां की कृपा पर ही आश्रित हैं। अन्नदात्री मां की ममतामयी छवियुक्त ठोस स्वर्ण प्रतिमा कमलासन पर विराजमान और रजत शिल्प में ढले भगवान शिव की झोली में अन्नदान की मुद्रा में है। दायीं ओर मां लक्ष्मी और बायीं तरफ भूदेवी का स्वर्ण विग्रह है। इस दरबार के दर्शन वर्ष में सिर्फ चार दिन धनतेरस से अन्नकूट तक ही होते हैं। इसमें पहले दिन धान का लावा, बताशा के साथ मां के खजाने का सिक्का प्रसादस्वरूप वितरित किए जाने की पुरानी परंपरा है। इसमें काशी ही नहीं, देश-विदेश से आस्थावानों का रेला उमड़ता है। अन्य दिनों में मंदिर के गर्भगृह में स्थापित प्रतीकात्मक प्रतिमा की दैनिक पूजा होती है। माना जाता है कि बाबा से पहले ही देवी अन्नपूर्णा यहां विराजमान थीं। वर्ष 1775 में काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण शुरू हुआ तब पार्श्व में देवी अन्नपूर्णा का मंदिर था। मां की स्वर्णमयी प्रतिमा की प्राचीनता का उल्लेख भीष्म पुराण में भी है। महंत रामेश्वरपुरी के अनुसार, वर्ष 1601 में मंदिर के महंत केशवपुरी के समय में भी प्रतिमा का पूजन हो रहा था।

जागरण विशेष की अन्य खबरें पढ़ें
www.jagran.com/topics/jagran-special

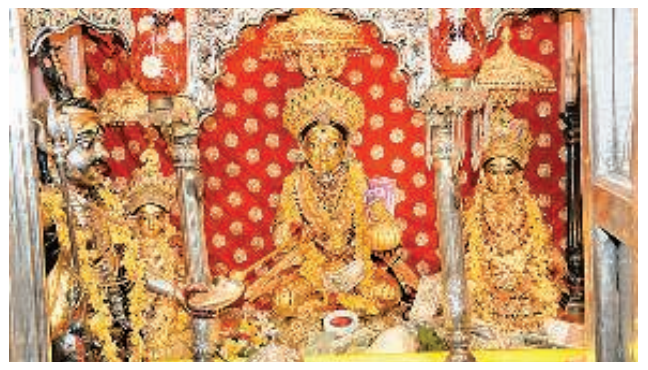

वाराणसी स्थित स्वर्णमयी अन्नपूर्णा दरबार की झांकी। जागरण

अन्न-धन का खजाना वितरित करते महंत रामेश्वर पुरी। जागरण

मां काली की शोभायात्रा के लिए तैयार है भागलपुर

शंकर दयाल मिश्रा, भागलपुर : 78 प्रतिमाएं कतार में। विसर्जन एक साथ। मंदिर व पूजा पंडालों से घाट तक पहुंचने में 24 घंटे से भी ज्यादा का वक्त। मां काली की प्रतिमाओं की इस शोभायात्रा के लिए भागलपुर (बिहार) न केवल बिहार, बल्कि अन्य राज्यों में भी प्रसिद्ध है। दिवाली की रात यहां छोटी-बड़ी 108 प्रतिमाएं स्थापित होती हैं, जिन्हें अगले दिन शोभायात्रा के रूप में विसर्जन के लिए ले जाया जाता है। मुख्य शोभायात्रा में 78 प्रतिमाएं कतार में लगती हैं। इस दौरान सड़क के दोनों किनारों और घर की छतों पर हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ लगी होती है। यह नजारा अद्भुत होता है। प्रतिमा वाले रथ (वाहन) को श्रद्धालु पूजा स्थल से रस्सी से खींचकर लाते हैं। यह परंपरा दशकों से चली आ रही है। अंग क्षेत्र (भागलपुर आसपास) में शक्ति की पूजा के महाभारत काल से होने का तार्किक प्रमाण है। इतिहासकार राजेंद्र सिंह कहते हैं कि अंग प्रदेश के राजा दानवीर कर्ण सुबह सूर्य की उपासना के बाद शक्ति की पूजा करते थे। तभी से यहां हर घर में परमेश्वरी की पूजा होती आई है। मां काली उसी परमेश्वरी का रूप हैं। कथावचक पंडित श्री मधुसूदनाचार्य बताते हैं कि काली पूजा दिवाली की अर्धरात्रि को होती है। माता का रंग काला है और वे काल को नियंत्रित करती हैं, इसलिए उनका नाम काली पड़ा।

राजगीर से दुनिया सुनेगी शांति का संदेश

आयोजन ▶ विश्व शांति स्तूप के स्वर्णजयंती समारोह में आज शिरकर करेंगे राष्ट्रपति कोविंद

हिरोशिमा और नागासाकी में हुए मानव संहार के बाद इसे जापानी गुरुजी ने बनवाया था

प्रशांत सिंह, नालंदा

बीते दिनों संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया से कहा था- हम उस देश के वासी हैं, जिसने दुनिया को युद्ध नहीं बुद्ध दिया है...। महात्मा बुद्ध की तपोभूमि से अब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद दुनिया को शांति का संदेश देंगे। मौका है राजगीर, बिहार स्थित विश्व शांति स्तूप के पचासवें वार्षिकोत्सव का।

समय का सूर्य भले ही राजगीर के विश्व शांति स्तूप की स्वर्णजयंती का संकेतक गढ़ चुका हो, लेकिन वे चुनौतियां मानवता के समक्ष आज भी उसी रूप में यथावत हैं, जैसी पचास साल पहले थीं। यह चुनौती है मानवता के संहारक युद्ध के विरुद्ध शांति कायम रखने की। 25 अक्टूबर को यहां जिस विश्व शांति स्तूप का पचासवां वार्षिकोत्सव मनाया जा रहा है, उसकी स्थापना जापान के निचिदात्सो फुजी गुरुजी ने दूसरे विश्वयुद्ध में हिरोशिमा व नागासाकी पर एटमी हमले के बाद की थी। पूरे विश्व को शांति का संदेश देना इसका परम ध्येय था।

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद वार्षिकोत्सव में शामिल होंगे और यहां पहुंचे दुनियाभर के शांतिदूतों को संबोधित करेंगे। फुजी गुरुजी के आह्वान पर छह मार्च 1965 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने इसकी नींव रखी थी और 1969 में 25 अक्टूबर को तत्कालीन राष्ट्रपति वीवी गिरि ने इसका उद्घाटन किया था।

राजगीर बौद्धों का महत्वपूर्ण तीर्थ है। करीब ढाई हजार से अधिक वर्ष पूर्व भगवान बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के पहले व बाद में दो बार राजगीर आए थे। यहां गृद्धकूट पहाड़ी का शिखर उनका प्रिय ध्यान स्थल था। यहीं वे अपने शिष्यों को शांति व अहिंसा की शिक्षा देते थे। इस विश्व शांति स्तूप की ऊंचाई 160 फीट है। स्तूप के निर्माण में कई देशों के लोगों ने श्रमदान किया था। निर्माण सामग्री को नीचे से पहाड़ी के शिखर तक ले जाने के लिए रोप वे का निर्माण किया गया था। गृद्धकूट के शिखर पर समतल जगह नहीं रहने के कारण स्तूप का निर्माण पास की रत्नागिरी पहाड़ी पर कराया गया। यहां से भगवान बुद्ध का प्रिय ध्यान स्थल एकदम सामने दिखता है। यही वजह है कि यह स्थान विश्व भर के बौद्ध धर्मावलम्बियों के लिए तीर्थ की तरह है।

आयोजन की तैयारी में अमेरिका, चीन, जापान, थाईलैंड, इटली समेत एक दर्जन से अधिक देशों के लोग शिरकत कर रहे हैं। आठ देशों के 40 भिक्षुओं का दल बोधगया से पदयात्रा कर जापानी मंदिर राजगीर आ चुका है। यह दल उसी रास्ते राजगीर पहुंचा, जिस रास्ते से बोधगया में ज्ञान प्राप्ति के बाद भगवान बुद्ध यहां आए थे। इस संकल्प और संदेश के साथ दुनिया के लोग जुट रहे हैं कि मानवता के बचे रहने का एकमात्र मंत्र विश्व शांति है। जापान के बौद्ध धर्म गुरु व प्रधान पुजारी निप्पोनजान म्योहोजी तथा अन्य बौद्ध भिक्षु विधिवत पूजा-अर्चना करेंगे।

बिहार के राजगीर का विश्व शांति स्तूप, यहीं आएंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। जागरण

अस्पताल में छोड़ गए थे मां-बाप, मासूम ने जीती कैंसर की जंग

जागरण संवाददाता, कोलकाता : बंगाल में कोलकाता के कोलकाता मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में दो वर्षीय बच्ची ने कैंसर को मात दे दी। उसका नाम है मीनू। उसे जन्म के बाद माता-पिता अस्पताल में ही छोड़ गए थे तब से यही उसका घर है। डॉक्टर, नर्स, स्वास्थ्य अधिकारी ही उसके रिश्तेदार हैं। बच्ची के बचने की कोई उम्मीद नहीं थी फिर भी दो महीने की उम्र में उसके पेट के ट्यूमर की सर्जरी की गई। इसके बाद पता चला कि यह कैंसर है। इसके बाद डॉक्टरों ने कीमोथेरेपी शुरू की। इस घटना के दो वर्ष होने को है और मीनू पूरी तरह से स्वस्थ है। हालांकि, उसके माता-पिता का अब भी कोई पता नहीं है। छोट सी मीनू का घर अब अस्पताल ही है।

जानकारी के मुताबिक मीनू का जन्म तीन अक्टूबर 2017 को कोलकाता अस्पताल में ही हुआ था। जन्म के बाद उसके कमर के नजदीक एक ट्यूमर मिला था। इसके बाद डॉक्टरों ने चर्चा के बाद के सर्जरी करने का निर्णय लिया। वहीं ट्यूमर की सफल सर्जरी के बाद डॉक्टरों को संदेह हुआ तो उन्होंने बायोप्सी कराई, जहां रिपोर्ट में पता चला कि उसे कैंसर है। तब से उसका कैंसर का इलाज शुरू किया गया। इस बीच उसके माता-पिता उसको अस्पताल में ही छोड़कर भाग गए।

चांद तक पहुंचा भारत, डाक विभाग आज भी साइकिल पर

पंकज दुबे, रायपुर

- डाकिया की भर्ती के लिए साइकिल चलाना किया है अनिवार्य

भारत चांद तक पहुंच गया लेकिन भारतीय डाक विभाग साइकिल युग से बाहर नहीं निकल पाया है। उस दौर में जब प्राइवेट फूड कंपनियों तक के डिलीवरी बॉय मोटरसाइकिल से सामग्री पहुंचा रहे हैं, डेढ़ सौ साल से भी अधिक पुराने डाक विभाग की भर्ती में साइकिल चलाने की अनिवार्यता युवाओं को चौंका रही है। ग्रामीण डाक सेवकों के भर्ती के नियम में लिखा है कि साइकिलिंग आनी जरूरी है। मोटरसाइकिल चलाने का अनुभव चलेगा, लेकिन शपथ पत्र देना होगा कि साइकिल चलाना आता है।

ग्रामीण डाक सेवकों की भर्ती के तहत छत्तीसगढ़ सर्किल में 1,799 पद भरे जाएंगे। यह पद रायपुर से लेकर बस्तर तक के पोस्ट ऑफिस के लिए हैं। इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसमें यह नियम लागू है।

विभाग परंपरागत ढर्रे पर : बदलते दौर को देखते हुए डाक सेवा में परंपरागत नियमों में बदलाव की जरूरत है। डाकिया को चिट्ठी, पार्सल आदि संबंधित पते पर पहुंचाने के लिए 180 रुपये साइकिल भत्ता प्रति माह मिलता है। लंबे समय से भत्ता नहीं बढ़ा है। प्रवर अधीक्षक रायपुर संभाग हरीश महावर का कहना है साइकिल के माध्यम से चिट्ठी का वितरण किया जा रहा है, इसमें बेहतर स्वास्थ्य और पर्यावरण को स्वच्छ रखने का संदेश छिपा है।

तर्क दिया कि साइकिल यात्रा गांव में सरल

विभाग का तर्क है कि साइकिल से हर जगह आसानी से पहुंचा जा सकता है। यह सस्ता और सुलभ साधन है। छत्तीसगढ़ के जनरल पोस्ट ऑफिस में 29 नियमित डाकिये हैं। कई साइकिल से चिट्ठी बांटते हैं, लेकिन कुछ स्वयं की बाइक से। बाइक वालों को पेट्रोल का खर्च खुद उठाना पड़ता है।

डाक विभाग का दायरा शहर से लेकर गांवों तक है। डाक सेवकों को कहीं भी जिम्मेदारी मिल सकती है। इसलिए साइकिलिंग का ज्ञान जरूरी है।

– हरीश महावर, प्रवर अधीक्षक, रायपुर संभाग।

सुरेश कुमार पर असमंजस बरकरार एक माह से नहीं आ रहे ऑफिस

कैलाश नाथ, चंडीगढ़

पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी सुरेश कुमार फिर चर्चा में आ गए हैं। वे करीब एक माह से ऑफिस नहीं आ रहे हैं। सुरेश की वजह से सरकार पहले ही पसोपेश में थी। चार विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के कारण लगी आचार संहिता की वजह से यह मामला ठंडा पड़ गया था, लेकिन परिणाम घोषित होने के साथ ही फिर उन्हें लेकर चर्चा शुरू हो गई है कि वे वापस दफ्तर आएंगे या नहीं।

चर्चा का विषय कुछ दिन पहले सुरेश की ओर से एक अंग्रेजी अखबार में लिखा गया लेख है। इसमें उन्होंने एक एनजीओ में अपनी रुचि दिखाई है। इसे लेकर भी चर्चा गर्म हो गई है कि क्या वे आगे अपनी सेवाएं नहीं निभाना चाहते? पहले उनके इस्तीफे की खबर आई थी, लेकिन बाद में सुल्तानपुर लोधी में हुई पंजाब कैबिनेट की बैठक में वह मुख्यमंत्री कैप्टन के साथ दिखाई दिए। सुरेश भले ही इससे पहले भी अपने पद से इस्तीफा दे चुके हों, लेकिन मुख्यमंत्री हमेशा उन्हें मनाने में कामयाब रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस का एक वर्ग इस बात से खुश है कि सुरेश अब आगे की पारी खेलने को तैयार नहीं हैं। यह वह वर्ग है, जिनकी नजर में सुरेश हमेशा ही खटकते रहे हैं।

सुरेश कुमार। फाइल

सेवानिवृत्त आइएएस अधिकारी सुरेश की नियुक्ति को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में चुनौती दी गई। अहम पहलू यह है कि सुरेश भले ही दफ्तर नहीं आ रहे हों, लेकिन अपने निवास से वह सरकारी फाइलें देखते रहे हैं। आचार संहिता होने के कारण सरकारी स्तर पर कामकाज भी ढीला था, लेकिन गुरुवार को चुनाव परिणाम आने के बाद से अब इसमें तेजी आने की उम्मीद है। ऐसे में सबकी निगाहें सुरेश की तरफ हैं कि वे वापस दफ्तर आएंगे या नहीं।

किसी भी तरह अपने साथ रखना चाहते हैं कैप्टन : 1983 बैच के आइएएस अफसर सुरेश कुमार ऐसे प्रशासनिक अधिकारी हैं, जिन्हें मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह किसी भी तरह से अपने से दूर नहीं जाने देना चाहते हैं। सुरेश 2016 में सेवानिवृत्त हुए थे। 2017 में जब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, तो सबसे पहली नियुक्ति सुरेश के रूप में की। उन्हें चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी के रूप में तैनात किया गया। आइएएस लॉबी में इसे लेकर खासी नाराजगी भी हुई, लेकिन कैप्टन ने इसकी परवाह नहीं की। उनकी नियुक्ति को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में भी चुनौती दी गई।

क्यों है कैप्टन को विश्वास : पंजाब के आइएएस अधिकारियों में सुरेश कुमार का नाम न सिर्फ सम्मान के साथ लिया जाता है, बल्कि उनकी छवि ईमानदार अधिकारी के रूप में है। अधिकारी हों या फिर राजनेता सभी उनका सम्मान करते हैं। सुरेश एक ही समय में प्रशासनिक, राजनीतिक व मीडिया का प्रेशर झेलने की क्षमता रखते हैं। यही कारण है कि कैप्टन उन पर विश्वास करते हैं।

अब दुनिया में धूम मचाएंगे कश्मीर के सेब और केसर

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर

- विदेशी कंपनी लुलू ग्रुप घाटी के किसानों से सीधे कर रही खरीदारी
- जल्द स्थापित होगा लॉजस्टिक हब, मनाया जाएगा कश्मीर वीक

नए कश्मीर का केसर, सेब, मसाले व अन्य उत्पाद अब दुनियाभर में धूम मचाएंगे। दुबई का लुलू ग्रुप कश्मीरी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए आगे आया है। ग्रुप सीधे किसानों से उत्पादों की खरीदारी कर रहा है। विदेशी कंपनियों ने घाटी में किसानों से सीधे उनकी फसल भी खरीदनी शुरू कर दी है। इसकी शुरुआत दुबई स्थित लुलू कंपनी ने की है। इसने घाटी से 200 मीट्रिक टन सेब खरीदा है। कश्मीरी केसर और कश्मीरी मसालों का भी यह ग्रुप आयात करेगा।

लुलू का अरब देशों में जबरदस्त आधार : लुलू का अरब देशों में जबरदस्त आधार है। यह समूह दुबई, ओमान, सऊदी अरब समेत मध्य पूर्व के विभिन्न देशों में 180 हाइपरमार्केट और शॉपिंग मॉल्स का मालिक हैं। समूह के मालिक युसूफ अली एमए हैं। ग्रुप के वरिष्ठ अधिकारियों के एक दल ने इसी माह की शुरुआत में कश्मीर का भी दौरा किया था।

जल्द आएंगी कुछ और विदेशी कंपनियां : राज्य प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि लुलू ग्रुप ने घाटी में कृषि और बागवानी उत्पादों की खरीद और फूड प्रोसेसिंग में निवेश करने की इच्छा जताई है। यह ग्रुप कश्मीरी केसर भी खरीद रहा है। कश्मीर में पैदा होने वाले मुश्कबुदजी चावल, काला जीरा, शहद और कुछ विशेष जड़ी-बूटियों को भी खरीदेगा। ग्रुप समूह जल्द घाटी में अपना लॉजस्टिक हब स्थापित करने जा रहा है। अगर सबकुछ के अनुसार लुलू समूह ने डिलिशियस सेब खरीदा है। पहली खेप 200 टन की है जो बीते सप्ताह निर्यात की गई है। यह सेब चंद दिनों में दुबई पहुंच जाएगा। यहां तक मेरी जानकारी है, यह पहला मौका है जब किसी विदेशी व्यापारिक समूह ने घाटी में आकर खरीदारी की हो। उम्मीद है कि कुछ और विदेशी कंपनियां निवेश करने आएंगी। संबंधित किसानों और व्यापारियों के साथ बातचीत लगभग पूरी हो चुकी है। लुलू समूह अपने शॉपिंग मॉल्स में कश्मीर प्रोमोशन वीक आयोजित कर रहा है। इससे कश्मीरी उत्पादों को बड़ा बाजार भी मिलेगा।

लुलू ग्रुप अब तक घाटी से 200 मीट्रिक टन सेब खरीद चुका है। फाइल

निगरानी

हर छह किलोमीटर की दूरी पर 50 पैन टिल्ट जूम कैमरा लगाए गए, 100-100 किमी के अंतराल पर तीन जगहों पर कंट्रोल रूम भी किए स्थापित

आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस वे पर नजर रखेगा 'पीटीजेड'

गौरव प्रताप सिंह, आगरा

यदि आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे पर सफर कर रहे हैं तो आपका मूवमेंट अब यूपीडा (उप्र एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण) के कैमरों की जद में रहेगा। घबराएं नहीं, यह आपकी प्राइवेसी में खलल नहीं डालेगा, लेकिन नियमों का पालन कराएगा और मुसीबत में सहायक बनेगा। हर छह किलोमीटर की दूरी पर पीटीजेड (पैन टिल्ट जूम) कैमरा लगा दिए गए हैं। तीन कंट्रोल रूम भी तैयार हैं, जिनका दीपावली के बाद उद्घाटन प्रस्तावित है।

ओवरस्पीडिंग और हादसे की शिकायत इस एक्सप्रेस-वे के बनने के बाद से ही आम है। देखा गया है कि 302 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेस-वे पर हादसा होता है तो पीड़ित को समय पर मदद नहीं मिल पाती है। इसी के दृष्टिगत अपर मुख्य सचिव और यूपीडा के सीईओ अवनीश अवस्थी के निर्देशन में यहां सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाने की कवायद शुरू की गई थी। एक्सप्रेस-वे पर अब 50 पीटीजेड कैमरे लग गए हैं। 100-100 किलोमीटर के अंतराल पर तीन जगहों पर कंट्रोल रूम भी स्थापित कराए गए हैं। कंट्रोल रूम में आगरा से लखनऊ तक आप किसी भी गाड़ी को लाइव देख सकते हैं। कंट्रोल रूम का उदघाटन होने के बाद इसमें आराम से देखा जा सकेगा कि कहां क्या चल रहा है। हादसा होने पर तत्काल एंबुलेंस भिजवाई जाएगी। अपराध होने पर कैमरे अपराधियों के मूवमेंट की पल-पल सूचना देंगे। पुलिस को उनकी लोकेशन देकर आराम से पकड़वाया जा सकेगा।

ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर नजर : कैमरा यह भी बता देगा कि कारचालक ने सीट बेल्ट पहनी है या नहीं। एक्सप्रेस-वे पर दस एएनपीआर (ऑटो नंबर प्लेट रीडर) भी लगवाए गए हैं। यह गाड़ी की स्पीड बताते हैं। वर्तमान में 100 की स्पीड यहां निर्धारित की गई है। इससे ऊपर गाड़ी चलाने वालों के नंबर यहां से एसपी ट्रैफिक ऑफिस को चालान को भेज दिए जाते हैं।

प्रतीकात्मक

कैमरे की खासियत

- 360 डिग्री पर घूम सकते हैं।
- रात में भी साफ तस्वीर लेने में सक्षम।
- तीन किमी आगे और तीन किमी पीछे की करेंगे निगरानी।
- गाड़ी का नंबर एकदम साफ दिखाते हैं।

302 किलोमीटर का आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे अब कैमरे की नजर में है। आगरा से लखनऊ तक किसी भी गाड़ी को लाइव देख सकते हैं। इससे लाभ यह होगा कि किसी के साथ हादसा होने पर कंट्रोल रूम को तत्काल जानकारी हो जाएगी। जल्द ही कंट्रोल रूम शुरू होने जा रहा है।

– केपी सिंह, सीनियर मैनेजर, यूपीडा

उत्तराखंड सरकार जैव विविधता संरक्षण पर खर्च करेगी 10 हजार करोड़

केदार दत्त, देहरादून : जैव विविधता के लिए मशहूर उत्तराखंड की इस धरोहर के संरक्षण की दिशा में सरकार ने गंभीरता के साथ कदम बढ़ाए हैं। प्रदेश में जैव विविधता से संबंधित 25 विभागों और बोर्ड के लिए अगले 10 साल के लिए 10159 करोड़ का प्लान तैयार किया है। इस अवधि के लिए 380 एक्शन प्लान और 114 रणनीति तय की गई हैं। जैव विविधता संरक्षण से संबंधित विभागों के कार्यों को भी एक्शन प्लान में शामिल किया गया है। समान कार्य वाले विभाग मिलकर प्लान को धरातल पर उतारने को जुटेंगे।

जैव विविधता संरक्षण की मुहिम को तेज करने और इसमें सभी विभागों व बोर्ड की सक्रिय भागीदारी के मद्देनजर उत्तराखंड जैव विविधता बोर्ड ने 'द एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट' (टैरी) के माध्यम से राज्य का 10 वर्षीय जैव विविधता प्लान तैयार कराया है। टैरी ने यह प्लान 10159 करोड़ रुपये का आंकलित किया है। अब जैव विविधता संरक्षण से जुड़े विभाग इसी के अनुरूप जैव विविधता संरक्षण से संबंधित कार्य कराएंगे।

दैनिक जागरण
सबरंग
नई दिल्ली, शुक्रवार, 25 अक्टूबर, 2019
सुझाव व प्रतिक्रिया के लिए लिखें :sabrang@nda.jagran.com
https://www.facebook.com/jagransabrang/

प्लान वीकेंड के

इस बार यहां चलें

टेन आर्टिस्ट टू फॉलो

राहुल इनामदार, सेबास्टियन वर्गीज, अंजू कौशिक, सतीश शर्मा, प्रतिभा सिंह, गीतांजलि कश्यप, नीरज दिवाते, मयंक चौहान सहित दस कलाकारों की कलाकृतियां जीवन के विविध रंगों को दर्शाती हैं। इन कलाकृतियों को देख दर्शक जीवन की गहराई में उतरते नजर हैं।
- कहां : सुरेंद्र पॉल आर्ट गैलरी, वसंत विहार।
- कब : 12 नवंबर तक, सुबह दस से शाम सात बजे तक।
- प्रवेश : निश्शुल्क।

प्राचीन कला महोत्सव

7वें अंतरराष्ट्रीय प्राचीन कला महोत्सव का आगाज होने वाला है। दो दिवसीय महोत्सव में रीला होत्ता, पंडित विश्व मोहन भट्ट, जर्मन कलाकार मथायस मुलर, शांतनु बोस, गीता चंद्रन जैसी प्रसिद्ध शख्सियतों की प्रस्तुति होगी। तो इस वीकेंड को संगीत की सुरधारा के साथ खास बना सकते हैं।
- कहां : श्रीराम सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट।
- कब : 30-31 अक्टूबर, शाम सवा छह बजे।
- प्रवेश : ऑनलाइन बुकिंग द्वारा।

त्रिशना सिंह की कलाकृतियां

दुनिया की खूबसूरती और चौंका देने वाले सौंदर्य को दर्शाती है त्रिशना सिंह की कलाकृतियां। अवनी की क्रूर मौत से प्रेरित दिल दहलाने वाले काम से लेकर प्राकृतिक व्यवस्था और मशीनों के अतिक्रमण की दुनिया के बीच, त्रिशना ने मोटरसाइकिल, मोर, बिल्ली की खोपड़ी को एंबेड किया है।
- कहां : एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट एंड लिटरेचर, सिरीफोर्ट इंस्टीट्यूशनल एरिया।
- कब : 2-11 नवंबर, सुबह 11 से शाम सात बजे तक।
- प्रवेश : निश्शुल्क।

12 कलाकारों की समूह प्रदर्शनी

12 प्रसिद्ध कलाकारों की बेहतरीन कलाकृतियां एक ही छत के नीचे देखने को मिलेंगी। इसमें तोशी चानना, मंजुला बजाज, मीनाक्षी राजेंद्र, प्रीति राजपूत, सरल मोहंती, रश्मि जोशी, नीता श्रीवास्तव, बी जया लक्ष्मी, विम्मी इंद्र, सोनी खन्ना और सरला चंद्रा की कलाकृतियां प्रदर्शित हैं। • कहां : आर्ट जंक्शन, द ललित, बाराखंभा। • कब : 1 नवंबर तक, सुबह 11 से शाम सात बजे तक। • प्रवेश : निश्शुल्क।

दीवाली जायकों वाली

खुशियों से भरी मिठास

जायका शौकीन दिल्ली-एनसीआर के शहरों को बस अवसर चाहिए कोई भी बहाना चाहिए बढ़िया खाने का। वैसे भी विशेष त्योहार-पर्व-उत्सव के मौके पर दिल्ली ज्यादा ही फूडी हो जाती है। रेस्त्रां भी उसी लिहाज से खास डिशिज के साथ तैयारी कर लेते हैं। सबरंग के इस अंक में दीपोत्सव के अवसर पर रेस्त्रां की तैयारी से रूबरू करा रही हैं

प्रियंका दुबे मेहता :

फिरनी

कुटी मिर्च का पनीर टिक्का

पनीर बर्फी

स्टिकी मैंगो राइस

रेस्त्रां में परंपरागत फील देने के लिए...दीवाली वाली...खानपान संस्कृति को दर्शाते हुए बहुत खास तैयारी की हुई हैं। मिठाई से लेकर नमकीन तक में विभिन्न प्रांतों का पारंपरिक टच त्योहारों को स्पेशल बना देता है। वैसे भी बगैर व्यंजनों के रोशनी के इस त्योहार की खुशियां अधूरी लगती हैं।

कुटी मिर्च का स्पेशल पनीर टिक्का : पंजाबी टिक्के को राजस्थानी स्टाइल में पेश करने के लिए रजौरी गार्डन स्थित मैलोगार्डन रेस्त्रां में विशेष रेसिपी तैयार की गई है। दीवाली पर वह पारंपरिक अनुभव देने के लिए पनीर टिक्के को दही, सरसों के तेल, हंग कर्ड और कुटी मिर्च के साथ अन्य मसालों में लपेट कर बनाया जा रहा है। पनीर को इन मसालों में कोट करके उसे फ्रीज में एक घंटे के लिए मैरिनेट किया जाता है और फिर तंदूर में पकाया जाता है। प्याज और मिंट चटनी के साथ इसका स्वाद दोगुना हो जाता है। कुछ और चटपटा खाने का मन है तो पालक पत्ता चाट का दीवाली विशेष प्रिपरेशन पेट भर देगा लेकिन मन नहीं। यहां पर इसके अलावा मुंह मीठा करने के लिए दीवाली विशेष फिरनी परोसी जाएगी।

पालक पत्ता चाट

जरा स्वास्थ्य का भी ख्याल रखें : डाइट पोडियम की शेफ व डाइटीशियन शिखा महाजन इस त्योहारी चमक के बीच हेल्दी रेस्पीज लांच कर रही हैं। यहां मलाईदार कोकोनट लड्डू से दीवाली मनाई जाएगी। मिठाई में होम मेड कॉपी कैट फरेरो रोशर है जो कि असल चॉकलेट की कैलोरी से भरा हुआ नहीं है बल्कि इसे पौष्टिक अंदाज में बनाया जा रहा है। कम कैलोरी की चॉकलेट बार, हेजलनट और न्यूट्रेला से बनाकर परोसा जाएगा। शिखा महाजन के मुताबिक जरूरी नहीं है कि त्योहार की मिठास के लिए तली भुनी मिठाइयां ही हों। वे पनीर से बर्फी बना रही हैं जो कि कम कैलोरी और ज्यादा प्रोटीन युक्त होगी।

देसी फिरनी व कोफ्ता-ए-लज्जत : अगर केवल खानपान से कुछ हटकर चाहिए तो इसके लिए पंचतारा होटल भी तैयार हैं। हयात रिजेंसी में में दीवाली पूरे उत्साह के साथ मनाई जाने की तैयारियां हैं। यहां दीवाली पार्टी में आपको खानपान, मौज मस्ती से लेकर गिफ्ट हैंपर्स तक सब मिलेगा। यहां त्योहार के दिन रंगोली डेकोरेशन और फोटोशूट की व्यवस्था भी की जा रही है। डिशेज में हेल्दी कोकोनट लड्डू मिलेंगे जोकि चुकंदर के साथ बनाए जा रहे हैं। बदाम का हलवा और कोफ्ता-ए-लज्जत विशेष तौर पर दीवाली के लिए तैयार किए जा रहे हैं। यहां आपको शाही फिरनी का स्वाद भी मिलेगा। कोफ्ता-ए-लज्जत को हेल्दी टच देने के लिए इसमें पालक, पनीर, सौंफ, कलौंजी से तैयार कोफ्तों को काजू, देसी घी टोमैटो प्यूरी और विभिन्न मसालों बनी ग्रेवी में डाला जाता है।

कैट फरेरो रोशर

नारियल लड्डू

ताज में हैंपर की मिठास : दीवाली और तोहफों का रिश्ता पुराना है। ऐसे में खान पान के साथ तोहफों को तड़का इस त्योहार को और भी खास बना देगा। इसके लिए दिल्ली के होटल ताज महल में दीवाली इसी तरह मनाने की तैयारी है। यहां बनाए गए हैंपर में बच्चों के लिए हैंपर है जिसमें उनके टेस्ट के साथ साथ पारंपरिक टच दिया गया है। इसमें ऑर्गेनिक मिठाइयों और डिशेज के साथ सीजंस ग्रीटिंग, फेस्टिव सरप्राइज, हैंडक्राफटेड कैंडल्स से दीवाली को रोशन कर सकते हैं।

बड़ों के लिए दिए जा रहे हैंपर में इन चीजों के साथ लग्जरी ब्यूटी एसेंशियल, एक्जोटिक क्रिस्टल वेयर के साथ साथ अन्य आइटम्स रखे गए हैं।

मलाका में राइस स्वीट डिश : गुरुग्राम के मलाका रेस्त्रां ने भी दीवाली की तैयारियां शुरू कर दी हैं। यहां दीवाली पर विशेष डिश से मुंह मीठा करवा जाएगा। स्टिकी मैंगो राइस में चावलों का स्वाद एक कुछ अलग होगा। इस मौसम में भी आम की स्लाइस से सजे रंगीन चावलों से बनी मिठाई आपका दिन बना देगी। यहां पर मेन मेन्यू में रोटी टिश्यू अलग अंदाज में एक टावर के रूप में टेबल पर आएगी।

रम और कॉफी की चाशनी में डूबे रसगुल्ले

इस दीवाली कुछ हटके हो जाए। आइए आपको कॉफी की ताजगी और रम का सुरूर गिलास में नहीं बल्कि रसगुल्ले की प्लेट में दिलाएं। जी हां, सेक्टर 29, गुरुग्राम के डीकोड रेस्त्रां की दीवाली स्पेशल डिशेज में एक है रसगुल्ला सोक्ड इन कॉफी एंड रम। इस डिश में रसगुल्ले की मिठास के साथ कॉफी की खुशबू और रम का फ्लेवर मिलेगा। इसके अलावा गुलाब जामुन भी नए अवतार में दिखेगा। आपकी टेबल पर रसमलाई की प्लेट आए लेकिन स्वाद गुलाबजामुन का मिले तो कैसा रहेगा। इसे आपको डीकोड करना है स्वाद से। मुंह में जाने के बाद पता चलता है कि यह पिस्टाशियो कोटेड गुलाबजामुन है जिसे दूध, कॉटन कैंडी और गुलाब की पंखुड़ियों से सजाया गया है। शेफ रमेश राणा के मुताबिक दीवाली पर खास अंदाज में मुंह मीठा करवाने के लिए इस तरह के प्रयोग किए गए हैं।

तेनाली जंक्शन पर पूजा संग मिठास

रेस्त्रां तेनाली जंक्शन में एक अलग पारंपरिक व फेस्टिव माहौल देखने को मिलेगा। अगर आप रेस्त्रां में थोड़ा जल्दी पहुंचते हैं तो वहां की पूजा में भी शामिल हो सकते हैं। यहां पर आंध्र प्रदेश के दीवाली विशेष पारंपरिक व्यंजनों का लुत्फ उठाया जा सकता है। आंध्र प्रदेश की मिठाइयां बब्बातलू और अरीसालू जैसी स्वीट डिशेज त्योहार में मिठास भरेंगी। मेनकोर्स में इस त्योहार पर लेमन राइस परोसा जाएगा जो कि वहीं के क्षेत्रीय अंदाज में बनाया जा रहा है।

बंजारा बदल देगा घर का नजारा

भ्रमित न हों, ये बर्ड हाउस नहीं हैंगिंग लैंप है जिसकी रंगी-बिरंगी रोशनी दीवाली की खुशियों को दोगुना कर देगी। जागरण

बाजार बड़े काम का

बांस के हैंगर पर लटके रंग-बिरंगे बर्ड हाउस देख एक पल को लगता है जैसे इसमें पक्षी रह रहे हों, लेकिन जैसे ही उसमें लाल, नीली, पीली रोशनी होती है, उसकी खूबसूरती देख लोग हतप्रभ रह जाते हैं। अरे, ये तो हैंगिंग लैंप है। रंग-बिरंगे फूल, लड़ियां, तोरण, कंदील, विंडचाइम और फूलदान भी। सब के सब एक से बढ़कर एक कलात्मकता लिए हुए। यही तो है गुरुग्राम स्थित बंजारा मार्केट की खासियत। दीवाली पर घर की सजावट में कोई कमी न रहे, इसके लिए दिल्ली के सरोजनी नगर, आया नगर और कृति नगर में तो खूब शॉपिंग की होगी, लेकिन इस दीवाली बंजारा मार्केट से खरीदारी कर के देखें। यहां एक से बढ़ कर एक कलात्मक सजावटी सामान बड़े बड़े शोरूम को भी मात दे रहे हैं।

बाजार पर लटकती तलवार से परेशान कारीगर

बंजारा मार्केट के कलाकार व विक्रेता राजबहादुर राजस्थान से हैं। वे पिछले 15 वर्षों से नए नए प्रकार के सजावटी सामान लोगों को उपलब्ध कराते आ रहे हैं। यहां ग्राहकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन यहां के कारीगरों को इस बात का डर है कि बाजार पर कुछ तत्वों की कुदृष्टि कहीं उनका कारोबार चौपट न कर दे।

कलात्मक चीजों का गढ़ : घरों की साज-सज्जा के लिए अब लोग महंगे शो पीस की जगह कलात्मक चीजों को तरजीह दे रहे हैं। छोटे-छोटे कारीगरों द्वारा तैयार विभिन्न राज्यों की परंपरागत कलाकृतियां उन्हें भा रही हैं। और इन कलात्मक चीजों का गढ़ है बंजारा मार्केट। झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले बंजारे करीब 17 वर्षों से अपनी कला के जरिये लोगों की दीवाली में रंग भरने का काम करते आ रहे हैं। ये बंजारे राजस्थान, मध्यप्रदेश और दक्षिण भारत से सामान लाकर उसे अपने हुनर से नया स्वरूप देते हैं। इस बाजार में उपलब्ध अधिकतर सामान इन बंजारों द्वारा ही डिजाइन किए हुए होते हैं। फिर चाहे फूलदान हो, फोटो फ्रेम या हैंगिंग लैंप। ये उन्हें तैयार कर उसे पेंट कर आकर्षक बनाते हैं।

घर को दे सकेंगे खास लुक : दीवाली पर घर को खास लुक देने के लिए यहां खूबसूरत फूलदान, कैंडल होल्डर, बर्ड हाउस, ज्वेलरी बॉक्स, मिट्टी के छोटे-बड़े बर्तन, लेडीज बैग, फोटो फ्रेम से लेकर फर्नीचर तक एक से बढ़कर एक आकर्षक डेकोरेटिव आइटम अपेक्षाकृत कम दामों में उपलब्ध हैं।

हैंडमेड आइटम्स की मांग : कलाकार कीरत और भूरा का कहना है कि इस बाजार में हैंडमेड विंडचाइम, पेंटिंग, कोलाज, तोरण जैसी चीजें दीवाली के अवसर पर डिमांड में हैं। अब लोग दीवाली पर पारंपरिक टच वाली कलात्मक वस्तुएं ज्यादा पंसद करने लगे हैं। यही वजह है कि इस बाजार में इस तरह की खरीदार करने वाले ग्राहक खासतौर पर आते हैं।

कपड़ों के फूल और रंग-बिरंगी लड़ियां : आर्टिफिशियल फूल एक बार खरीद लो तो कई साल चलते हैं, इसलिए लोग दरवाजे पर लगाने के लिए ज्यादातर इन्हीं फूलों का चयन करते हैं। लेकिन बंजारा बाजार में कपड़ों से तैयार रंग-बिरगें तरह-तरह के फूल और लड़ियां देख ऐसा लगेगा जैसे वे ऑरिजनल हों।

खूबसूरती ऐसी कि उन्हें खरीदे बिना रह नहीं पाएंगे। कलाकार पंकज कहते हैं कि राजस्थान में दीवाली के अवसर पर कपड़ों से बने सामान से घर सजाए जाते हैं। यहां के सामान में भी आप राजस्थानी झलक देख सकते हैं। लोग भी उस परंपरा का अनुसरण करते हुए इन चीजों के प्रति रुचि दिखा रहे हैं।

विदेशियों को भा रही यहां की चमक : बंजारों द्वारा तैयार विभिन्न मूर्तियां और भारतीय संस्कृति को सुशोभित करने वाली आकर्षक वस्तुएं विदेशी पर्यटकों को खूब भा रही हैं। इस बाजार में प्राचीन भारत से संबंधित मूर्तियां भी उपलब्ध हैं। इटली से आई अमीलिय के मुताबिक वे इस तरह की चीजों की शॉपिंग राजस्थान से करते थे, लेकिन गुरुग्राम में भी इसकी उपलब्धता देकर उन्हें खुशी हो रही है। वहीं उनके साथ आए बेरेटा को भारतीय कलात्मक वस्तुएं आकर्षित करती हैं।

प्रियंका दुबे मेहता

गुरुग्राम के बंजारा मार्केट में हाथों से तैयार लैंप व सजावटी सामान

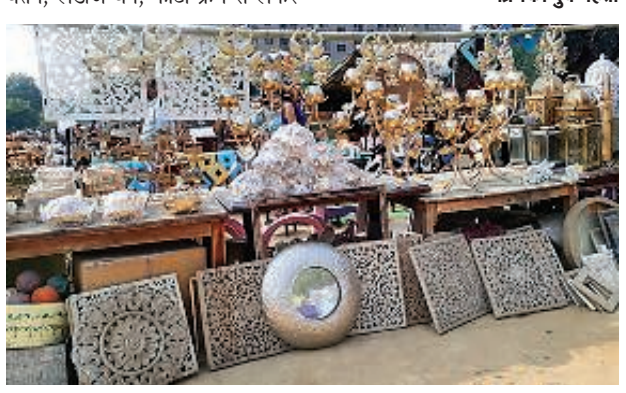

आधी आबादी के संघर्ष को कला में उतार देती हूं

किरण दीक्षित थापर

• दिल्ली की कोई बात जो आपको खलती है?
...प्रदूषण। मीडिया प्रदूषण को लेकर हो हल्ला मचाए हुए है, पर मुझे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई। मैं लोगों से पूछती हूं तो उनका जवाब भी मेरे जवाब से मिलता हुआ ही होता है। यहां के बाग बगीचे मुझे बेहद पसंद हैं। हरी मखमली घास पर बैठकर घंटों गुजार देती हूं। दिल्ली बहुत खूबसूरत शहर है। यदि प्रदूषण है भी तो इसे मिलकर खत्म करना होगा।

बातचीत

स्त्री शक्ति रूपा है। परिस्थितियां चाहें कितनी भी प्रतिकूल हों वे धैर्य के साथ उनका मुकाबला कर अपनी पहचान बनाने का दमखम रखती हैं। महिला संघर्ष और सफलता की कुछ ऐसी ही अनगिनत तस्वीरें इंडिया हैबिटेट सेंटर में दर्शकों के आकर्षण का केंद्र बनी। दिल्ली में जन्मीं, लंदन में 30 साल तक पढ़ाने के बाद पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन में रह रहीं 69 वर्षीय किरण दीक्षित थापर की ये कलाकृतियां महिला सशक्तीकरण की अलख जगाती हैं। हाल ही में दिल्ली आईं किरण दीक्षित से संजीव कुमार मिश्र ने बातचीत की। प्रस्तुत हैं प्रमुख अंश :-

• आपकी प्रदर्शनी का केंद्र महिला संघर्ष है, ऐसा क्यों?
वैसे तो मुझे मानव के साथ-साथ प्रकृति और पशुओं पर भी कलाकृति बनाने का शौक है। लेकिन विगत कई वर्षों से हम स्त्री-पुरुष समानता की बात सुन रहे हैं। दिल्ली में इसे लेकर काफी प्रदर्शन भी हुए, लेकिन हकीकत में देखेंगे तो ऐसा कुछ नहीं है। मेरी नजर में महिलाओं को समानता का अधिकार मिलना बड़ा मसला है। आप किसी भी फील्ड में देख लीजिए, महिलाओं को कहां समानता का अधिकार प्राप्त है? पुरुषों को यह समझना होगा कि उन्हें महिलाओं को सम्मान देना ही होगा। यही सब सोचकर मैंने महिला संघर्ष को अपनी कलाकृतियों का केंद्र बिंदु बनाया है। इससे अगर लोगों की सोच में बदलाव आता है तो मुझे खुशी होगी।

• महिला संघर्ष को दर्शकों से रूबरू कराने की प्रेरणा कहां से मिली?
मेरी मां मेरी प्रेरणा स्रोत रही हैं। उन्होंने जिंदगी की हर एक परिस्थितियों का डटकर मुकाबला किया। जब मैं युवा थी तब परिस्थितियां कुछ ऐसी बन गई थीं कि मां की मैं आलोचना किया करती थी। लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ कि वह बहुत बहादुर थीं। फिर मैंने उन जैसी अन्य महिलाओं को देखा तो पाया कि ये अपने दिनों में बहादुर रही हैं। तसलीमा नसरीन हों या अमृता प्रीतम इन सब की जिंदगी कठिन रास्तों वाली रही है। इनके जैसा कदम उठाना अन्य महिलाओं के लिए कठिन होता है।

• सर्कस गर्ल, गर्ल्स ऑन साइकिल, बर्ड ऑफ माइ इमेजिनेशन को दर्शक सराह रहे हैं? इसके पीछे के निहितार्थ को बताएं?
मैं शांति निकेतन में प्रकृति के सान्निध्य में रहती हूं। यहां हर दो महीने बाद प्रवासी पक्षी आते हैं। मैं सजग होकर सिर्फ इन पक्षियों को ही नहीं देखती, देश दुनिया में हो रहे बदलावों पर भी नजर रखती हूं। आदिवासी महिलाओं ने एक प्रदर्शन किया था। जिसमें लड़कियां चिल्लाते हुए प्रदर्शन का नेतृत्व कर रही थीं। इसने मुझे इस कदर प्रेरित किया कि मैंने इसे अपनी कलाकृति का हिस्सा बना लिया। सिर्फ आदिवासी ही नहीं, गांव-देहात की साइकिल चलाती लड़कियां, पंजाब में धान रोपती महिलाओं पर भी मैंने कलाकृतियां बनाई हैं।

• दिल्ली को किस तरह अपनी यादों में सहेजा हुआ है?
-दिल्ली से तो दिल का रिश्ता है। मां और पिता जी बंटवारे के दौरान रावलपिंडी से दिल्ली आ गए थे। मेरे सभी रिश्तेदार यहीं रहते हैं। मां करोल बाग में मृत्युपर्यंत रहीं। दिल्ली से मैं 1969 में लंदन गई। वहां क्राफ्ट डिजाइन पढ़ाया करती थी। फिर सन् 2000 में लंदन से वापस भारत आ गई और पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन को अपना ठिकाना बना लिया। दिल्ली में मेरी कलाकृतियों की यह तीसरी प्रदर्शनी है। इसके पहले साल 2017 में ललित कला अकादमी में मेरी कलाकृतियों की प्रदर्शनी लगी थी।

राष्ट्रीय संस्करण
शुक्रवार 25 अक्टूबर 2019
दैनिक जागरण
बिजनेस
www.jagran.com

सोना 75 रुपये सुधरा, चांदी 110 रुपये उछली

नई दिल्ली, प्रेट्र : त्योहारी सीजन में बढ़ी मांग के बीच गुरुवार को सोना 75 रुपये सुधरकर 38,945 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। चांदी भी 110 रुपये उछलकर 46,520 रुपये प्रति किलोग्राम पर जा पहुंची। सराफा बाजार के कारोबार के बारे में एचडीएफसी सिक्युरिटीज के सीनियर एनालिस्ट (कमोडिटीज) तपन पटेल ने कहा कि त्योहारी मांग बढ़ने और डॉलर के मुकाबले रुपये के टूटने के चलते निवेशकों ने सोने की खरीद बढ़ाई।

ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में यह छलांग बड़ी सफलता है। अगले तीन वर्षों में हमारा लक्ष्य शीर्ष 25 में आने का है।
— अमिताभ कांत
सीईओ, नीति आयोग

सेंसेक्स	39,020.39	निफ्टी	11,582.60	सोना (प्रति दस ग्राम)	₹ 38,945	चांदी (प्रति किलोग्राम)	₹ 46,520	डॉलर	₹ 71.02
▼ 38.44		▼ 21.50		▲ ₹75		▲ ₹110		▼ ₹0.11	

क्रूड (ब्रेंट) प्रति बैरल	$ 61.49

कारपोरेट हलचल

पावरग्रिड को महारत्न का दर्जा

ट्रांसमिशन क्षेत्र के पीएसयू पावरग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को महारत्न पीएसयू का दर्जा प्राप्त हुआ है। इसका एलान केंद्रीय ऊर्जा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) आरके सिंह ने कंपनी के स्थापना दिवस के मौके पर किया। महारत्न का दर्जा मिलने से कंपनी प्रबंधन को अधिक स्वायत्तता और अधिकार मिलेंगे।

दिल्ली ट्रांसको की वेंडर मीट

दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड ने अपनी कार्यप्रणाली में सुधार और पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से अपने वेंडर्स के साथ एक दिवसीय इंटरैक्टिव सत्र का आयोजन किया। सत्र की अध्यक्षता डीटीएल की चेयरपर्सन श्रीमती पद्मिनी सिंगला ने की। सिंगला ने कहा कि डीटीएल पहले से ही ई-टेंडरिंग की पद्धति अपना चुकी है और घरेलू स्तर पर प्रतिस्पर्धी निविदाओं के माध्यम से ही सारे ठेके दे रही है।

मुश्किल ▶ यूएस सिक्युरिटीज ने भी अपनी तरफ से शुरू की जांच

एनएफआरए करेगा इन्फोसिस मामले में शिकायतों की जांच

नए घटनाक्रमों पर गुरुवार को कंपनी के शेयरों में हुई करीब ढाई प्रतिशत गिरावट

नई दिल्ली, प्रेट्र : वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों से घिरी दिग्गज आइटी कंपनी इन्फोसिस लिमिटेड पर देश-विदेश में जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है। एक तरफ सरकार ने नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी (एनएफआरए) को इन्फोसिस में हुई कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच का जिम्मा सौंपा है। दूसरी तरफ अमेरिका में भी यूएस सिक्युरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (यूएस सेक) ने व्हिसलब्लोअर्स के आरोपों पर जांच शुरू कर दी है। इन खबरों के चलते गुरुवार को घरेलू शेयर बाजार में कंपनी के शेयर करीब ढाई प्रतिशत तक टूट गए।

एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा कि एनएफआरए को इन्फोसिस के अकाउंट्स में गड़बड़ी और अनुचित कारोबारी गतिविधियों की जांच के लिए कहा गया है। एनएफआरए कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के तहत आता है। ऑडिटिंग प्रोफेशन के लिए बनाया गया यह स्वतंत्र नियामक मंत्रालय के निर्देश के अनुसार या स्वतः संज्ञान के आधार पर ऑडिटर्स से जुड़ी वित्तीय अनियमितताओं की जांच कर सकता है।

इन्फोसिस ने गुरुवार को कहा कि पूंजी बाजार नियामक सेबी ने उससे व्हिसलब्लोअर्स की शिकायतों के बारे में कुछ अतिरिक्त जानकारियां मांगी हैं। इसके अलावा वह इस बात से भी अवगत है कि अमेरिका के फेडरल कोर्ट में कंपनी के खिलाफ एक मामला दायर किया गया है और कंपनी पूरी क्षमता के साथ खुद का बचाव करने के लिए तैयार है। अमेरिका स्थित रोजेन लॉ फर्म ने कहा था कि वह इन्फोसिस के स्थानीय निवेशकों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए एक मुकदमा दायर करने की तैयारी कर रही है।

पिछले महीने मिले थे पत्र : कंपनी के बोर्ड मेंबर्स ने 30 सितंबर को दो शिकायती पत्र प्राप्त किए थे। इन पत्रों में अनुचित गतिविधियों की शिकायत की गई थी। इन्हें 10 अक्टूबर को कंपनी की ऑडिट कमेटी के सामने पेश किया गया और इसके अगले दिन इस बारे में कंपनी के नॉन एक्जीक्यूटिव सदस्यों को भी अवगत कराया गया। शिकायत पत्र में आरोपितों के ई-मेल और वॉइस रिकॉर्डिंग मौजूद होने की बात कही गई है।

सीईओ-सीएफओ ने ऐसा कहा था... : व्हिसलब्लोअर्स के मुताबिक सीईओ और सीएफओ ने कहा कि बोर्ड के सदस्य तकनीकी बातों को नहीं समझते। जब तक शेयर की कीमत ऊपर रहेगी, वे खुश रहेंगे। वे लोग बेकार के तर्क रखेंगे, इसके लिए आप सिर्फ सिर हिलाते रहिए बाकी सब नजरंदाज कर दीजिए।

पहले भी लगते रहे हैं आरोप : कंपनी पर इससे पहले भी वित्तीय अनियमितता के आरोप लग चुके हैं। हाल में ही कंपनी द्वारा इजरायल की ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी कंपनी पनाया की खरीद के समय भी अनियमितताओं के आरोप लगे थे। उस दौरान भी व्हिसलब्लोअर की ओर से ही शिकायत आई थी। इसे कंपनी की इंटरनल कमेटी ने निराधार बताया था। इसके अलावा 2017 में कंपनी के फाउंडर्स और पूर्व-प्रबंधन के बीच तनाव पैदा हो गया था।

ये हैं आरोप

- जुलाई-सितंबर तिमाही के दौरान अधिक मुनाफा दिखाने के लिए व्हिसलब्लोअर्स से वीजा लागतों को कम करने के लिए कहा गया
- 353 करोड़ रुपये के रिवर्सल को भी नजरंदाज करने के लिए दबाव डाले जाने की बात कही गई है
- अधिकारियों ने मुनाफा बढ़ाकर स्टॉक्स की ऊंची कीमत बनाए रखने के लिए गैरकानूनी कदम उठाए
- वेरिजॉन, इंटेल और संयुक्त उपक्रमों जैसे बड़े सौदों में हेराफेरी की गई, ऑडिटर्स और कंपनी बोर्ड से संवेदनशील जानकारियां छिपाई गईं
- पारेख ने कर्मचारियों से कहा था कि बोर्ड के सामने बड़ी डील के आंकड़े और महत्वपूर्ण वित्तीय जानकारियां नहीं रखी जाएं

शेयर बाजारों पर दिखा चुनाव परिणामों का असर

मुंबई, प्रेट्र : महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों का इंतजार कर रहे निवेशकों का उत्साह फीका पड़ जाने का असर घरेलू शेयर बाजारों पर गुरुवार को दिखा। दिन के कारोबार में बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 486 अंकों के उतार-चढ़ाव में कारोबार करने के बाद 38.44 अंक यानी 0.10 फीसद फिसलकर 39,020.39 अंक पर स्थिर हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) के 50 शेयरों वाले निफ्टी में भी 21.50 अंकों यानी 0.19 प्रतिशत की गिरावट आई। दिन के कारोबार के आखिर में एनएसई का निफ्टी 11,582.60 अंकों पर बंद हुआ।

विशेषज्ञों का कहना था कि महाराष्ट्र में सहयोगी शिवसेना के साथ बहुमत का आंकड़ा पार कर जाने के बावजूद सत्तारूढ़ भाजपा को उम्मीद के अनुरूप सीटें नहीं मिलीं। इसके अलावा हरियाणा में भाजपा अकेले दम पर बहुमत के बेहद करीब पहुंचकर ठहर गई, जिसके चलते निवेशकों का उत्साह फीका पड़ा। इसके अलावा कई राज्यों में उपचुनाव का भी असर शेयर बाजारों पर देखा गया।

बीएसई में आइटी और बैंकिंग सेक्टर के शेयरों में सबसे ज्यादा गिरावट आई। यस बैंक, एसबीआइ और इंडसइंड बैंक के शेयर 5.76 प्रतिशत तक टूट गए। जानकारों के मुताबिक कमजोर आर्थिक संकेतकों के अलावा गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम सेक्टर को झकझोड़ दिया। सुप्रीम कोर्ट के नए फैसले के मुताबिक दूरसंचार कंपनियां अब दूरसंचार विभाग यानी डीओटी को एजीआर के मद में करीब 92,000 करोड़ रुपये की रकम का भुगतान करेंगी। इस फैसले के बाद वोडाफोन आइडिया के शेयर धड़ाम हो गए। भारती एयरटेल के शेयरों ने सेंसेक्स पैक में सबसे बड़ी बढ़त लेकर विशेषज्ञों को चौंकाया।

जानकारों के मुताबिक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मोर्चे पर भारत की 14 अंकों की छलांग और फिच द्वारा भारत का विकास दर अनुमान घटाने संबंधी खबरों का भी मिलाजुला असर शेयर बाजारों पर दिखा। आशिका स्टॉक ब्रोकिंग के इक्विटी रिसर्च प्रेसिडेंट पारस बोथरा ने कहा कि हरियाणा और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों में सत्तारूढ़ दल के कमजोर प्रदर्शन का असर देखा गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद टेलीकॉम सेक्टर को बड़ी निराशा हुई है। इस सेक्टर का अभी जो हाल है, उसे देखते हुए सरकार को कोई ठोस कदम उठाना होगा।

प्रतीकात्मक

- हरियाणा में भाजपा के उम्मीद से कमजोर प्रदर्शन के चलते शेयर बाजारों में निवेशक रहे सुस्त
- सेंसेक्स में 38.44 और निफ्टी में दर्ज की गई 21.50 अंकों की गिरावट

मारुति के लाभ में आठ वर्षों की सबसे बड़ी तिमाही गिरावट

नई दिल्ली, प्रेट्र : ऑटो सेक्टर के तिमाही वित्तीय नतीजों में मंदी का साया उभरकर सामने आता दिख रहा है। देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड (एमएसआइएल) के शुद्ध लाभ में आठ वर्षों की सबसे बड़ी तिमाही गिरावट हुई है। कंपनी के मुताबिक वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर, 2019) में उसका का कंसोलिडेटेड शुद्ध मुनाफा 38.99 प्रतिशत घटकर 1,391.1 करोड़ रुपये रह गया। पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में कंपनी का मुनाफा 2,280.20 करोड़ रुपये रहा था। इससे पहले वित्त वर्ष 2011-12 की दूसरी तिमाही में कंपनी के शुद्ध मुनाफे में 56 प्रतिशत की बड़ी गिरावट आई थी।

चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में कंपनी का परिचालन राजस्व 25.19 प्रतिशत घटकर 16,123.2 करोड़ रुपये रह गया। पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में इस मद में मारुति सुजुकी को 21,553.7 करोड़ रुपये हासिल हुए थे। जहां तक कारों की बिक्री संख्या का सवाल है, तो समीक्षाधीन तिमाही में कंपनी ने 30.2 प्रतिशत गिरावट के साथ 3,38,317 यूनिट कारों की बिक्री की।

30.99
प्रतिशत लुढ़क गया चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में शुद्ध लाभ

25.19
प्रतिशत की गिरावट आई इस अवधि के दौरान परिचालन राजस्व में

घटी बिक्री का असर कंपनी के नतीजों पर दिखा। प्रतीकात्मक

इसलिए कमजोर रहे नतीजे : नतीजों के बारे में मारुति सुजुकी इंडिया के चेयरमैन आरसी भार्गव ने कहा कि चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही और पहली छमाही के नतीजे पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि के मुकाबले बेहद खराब रहे हैं। चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही की बिक्री में 22 प्रतिशत की गिरावट देखी गई है। इसका असर बाकी सभी चीजों पर दिखा है।

भार्गव के मुताबिक इस वर्ष वाहन उद्योग ने कई वजहों से बिक्री में बड़ी गिरावट देखी। एक्विजिशन की लागत बढ़ना, सुरक्षा एवं प्रदूषण को लेकर कड़े मानदंड, बीमा खर्च और कई राज्यों में रोड टैक्स बढ़ोतरी जैसी वजहों के चलते वाहन उद्योग के सामने बड़ी मुश्किलें आई हैं। फाइनेंस की कमजोर उपलब्धता के कारण कई लोग चाहकर भी वाहन नहीं खरीद पा रहे हैं। इसके अलावा बैंकों ने भी आरबीआइ की तरफ से रेपो रेट में कटौती का पूरा फायदा अभी तक ग्राहकों को नहीं दिया।

लिब्रा पर संसदीय समिति के सामने पेश हुए जुकरबर्ग

वाशिंगटन, आइएएनएस : फेसबुक ने अमेरिका की एक संसदीय समिति के सामने अपनी प्रस्तावित क्रिप्टो करेंसी लिब्रा का बचाव किया है। अमेरिकी संसद की वित्तीय सेवा समिति के समक्ष कंपनी के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने कहा कि वे समिति के सभी सदस्यों की शंकाओं का निवारण किए बगैर लिब्रा पर कदम नहीं बढ़ाएंगे। कुछ सदस्य उनसे सहमत नहीं दिखे। जुकरबर्ग से पूछा गया कि हाल ही में कई बड़ी कंपनियों ने लिब्रा से हाथ क्यों खींच लिए हैं। इस पर उन्होंने कहा कि यह बेहद जोखिम भरा कदम है। हालांकि सुनवाई पूरी तरह से फेसबुक की डिजिटल करेंसी लिब्रा के बारे में थी। लेकिन समिति के सदस्यों ने उनसे कंपनी की नीतियों, आचरण और बाजार में प्रभुत्व से जुड़े सवाल भी किए। वित्त मंत्री स्टीवन न्यूचिन और फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पॉवेल जैसे दिग्गजों ने डिजिटल करेंसी लांच करने की तैयारी के लिए कंपनी की खिंचाई की है।

रेटिंग एजेंसी फिच ने भी घटाया भारत का जीडीपी विकास दर अनुमान

नई दिल्ली, प्रेट्र : अग्रणी रेटिंग एजेंसी फिच रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए भारत की आर्थिक विकास दर का अनुमान घटाकर 5.5 प्रतिशत कर दिया है। इसी वर्ष जून में फिच ने 6.6 प्रतिशत विकास दर का अनुमान लगाया था। हालांकि एजेंसी ने यह भी कहा कि पिछले कुछ समय के दौरान सरकार ने कॉरपोरेट टैक्स घटाने के अलावा सुधार के जो अन्य कदम उठाए हैं, उससे विकास को जल्द गति मिलती दिखाई देगी।

फिच ने गुरुवार को जारी बयान में कहा कि अगले वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक विकास दर 6.2 प्रतिशत और उसके अगले वित्त वर्ष में 6.7 प्रतिशत रहने का अनुमान है। फिच के मुताबिक देश की अर्थव्यवस्था में दिख रही सुस्ती का आधार व्यापक है। घरेलू व्यय और मांग में कमी दिख रही है। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) की लगातार कमजोर होती माली हालत की वजह से अर्थव्यवस्था की विकास दर को चोट पहुंची है। रेटिंग एजेंसी ने उम्मीद जताई कि कॉरपोरेट टैक्स में कटौती किए जाने और सरकारी उपायों से अर्थव्यवस्था को धीरे-धीरे बढ़ावा मिलेगा।

प्रतीकात्मक

- चालू वित्त वर्ष के लिए लगाया 5.5 प्रतिशत विकास दर का अनुमान
- कहा - एनबीएफसी संकट के कारण अर्थव्यवस्था को लगी चोट

भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर को लेकर फिच का ताजा अनुमान भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) के अनुमान से भी कम है। आरबीआइ ने इसी महीने देश की जीडीपी विकास दर 6.1 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया था। केंद्रीय बैंक का यह भी कहना था कि वित्त वर्ष 2020-21 में विकास दर 7.2 प्रतिशत के स्तर पर पहुंच सकती है।

गौरतलब है कि पहले इसी महीने अग्रणी रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने भी चालू वित्त वर्ष के लिए देश की जीडीपी विकास दर का अनुमान घटाकर 5.8 प्रतिशत कर दिया था। इससे पहले एजेंसी ने विकास दर अनुमान 6.2 प्रतिशत रखा था। मूडीज का भी कहना था कि घरेलू मोर्चे पर खपत में आई कमी और एनबीएफसी सेक्टर पर दबाव के चलते अर्थव्यवस्था में सुस्ती आ रही है। उससे पहले पिछले महीने एशियाई विकास बैंक (एडीबी), रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड्स एंड पूअर्स (एसएंडपी) और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आइएमएफ) भी चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की जीडीपी विकास दर का अनुमान घटा चुके हैं।

एडीबी के अनुमानों के मुताबिक चालू वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक विकास दर 6.5 प्रतिशत रहने वाली है। वहीं, एसएंडपी का मानना है कि विकास दर 6.3 प्रतिशत रहेगी। लेकिन इन सभी अनुमानों में फिच एकमात्र एजेंसी है, जिसने सबसे कम 5.5 प्रतिशत विकास दर का अनुमान लगाया है।

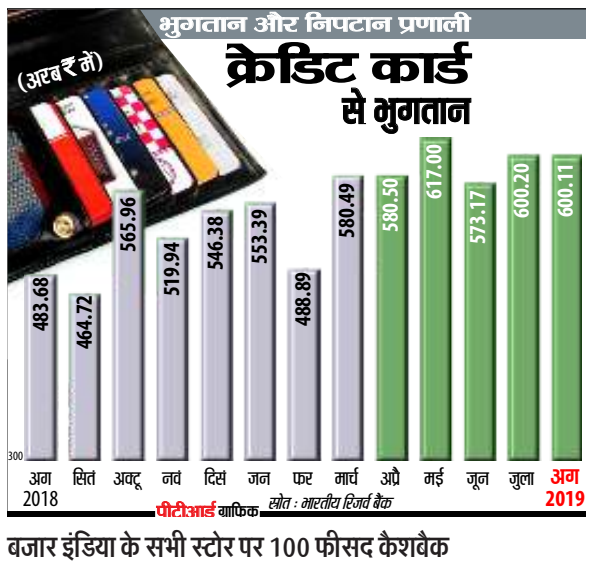

बजार इंडिया के सभी स्टोर पर 100 फीसद कैशबैक

नई दिल्ली (वि) : इस दीपावली पर बजार इंडिया अपने सभी स्टोरों पर बंपर उपहार बांट रही है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए बजार इंडिया ने दिवाली के मौके पर 100 फीसद कैशबैक का ऑफर देने का एलान किया है। इसके अलावा सुनिश्चित उपहार भी दिए जा रहे हैं।

वित्त मंत्री ने किया जीएसटी को और सरल बनाने का वादा

नई दिल्ली, प्रेट्र : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सरकार वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को और सरल बनाने की बात कही है। उनका कहना है कि इससे वर्ल्ड बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग और सुधरेगी। इंडेक्स में इस साल 14 स्थानों की छलांग के साथ भारत की रैंकिंग 63वीं रही है।

वित्त मंत्री ने कहा, 'जीएसटी में यह समझना सतत प्रक्रिया का हिस्सा है कि मुश्किलें कहां हैं। हम यह भी देख रहे हैं ऑनलाइन रिटर्न फाइल करने में क्या दिक्कतें आ रही हैं। इसलिए जीएसटी में लगातार सुधार की प्रक्रिया भी चल रही है। जीएसटी अनुपालन को आसान बनाने की दिशा में कई कदम उठाए जा रहे हैं।' उन्होंने कहा कि कारोबार शुरू करने के पैमाने पर भारत की रैंकिंग में बस एक स्थान का सुधार हुआ है। इसे सुधारने की दिशा में प्रयास किए जाएंगे। आयकर के मामले में वित्त मंत्री कुछ कहने से इन्कार कर दिया। वित्त मंत्री ने बताया कि इन्सॉल्वेंसी प्रक्रिया के तहत संपत्ति अटैच करने के मामले में ईडी और कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के बीच टकराव को खत्म करने का प्रयास भी किया जा रहा है।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले से टेलीकॉम सेक्टर में खलबली

नई दिल्ली, एजेंसियां : एजीआर पर सुप्रीम कोर्ट के गुरुवार के फैसले से पूरे टेलीकॉम सेक्टर में खलबली मच गई है। टेलीकॉम उद्योग की शीर्ष संस्था सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीओएआइ) ने कहा है कि उद्योग पहले से ही चार लाख करोड़ रुपये के कर्ज तले दबा हुआ है। ऐसे में यह देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट के इस झटके से उद्योग जगत उबर पाएगा या नहीं।

टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल का कहना है कि शीर्ष अदालत के इस फैसले से उद्योग की व्यवहार्यता ही खत्म हो जाएगी। वहीं, वोडाफोन आइडिया का कहना है कि वह सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ समीक्षा याचिका दायर करने की संभावनाओं पर विचार करेगी। हालांकि फैसले के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया है कि अब इस मामले पर कोई और मुकदमेबाजी नहीं होगी।

फैसले पर निराशा जाहिर करते हुए भारती एयरटेल ने कहा, 'टेलीकॉम सेवा प्रदाता (टीएसपी) कंपनियों ने सेक्टर को स्थापित करने पर अरबों रुपये खर्च किए हैं। वे अपने ग्राहकों को विश्वस्तरीय सेवा मुहैया करा रही हैं। यह फैसला ऐसे वक्त में आया है जब पूरा सेक्टर वित्तीय दबाव में है। इस फैसले से पूरे सेक्टर की व्यवहार्यता पर बुरा असर पड़ेगा।' एयरटेल का कहना था कि जिन 15 टेलीकॉम कंपनियों पर इस फैसले का असर होना है, उनमें से इस वक्त निजी क्षेत्र में सिर्फ दो कंपनियां परिचालन में रह गई हैं।

वहीं, वोडाफोन आइडिया ने चेताया है कि गुरुवार के इस फैसले से सेक्टर की राजस्व आय पर दूरगामी असर होंगे। कंपनी ने यह भी कहा कि वह इस फैसले के खिलाफ समीक्षा याचिका की संभावनाओं पर विचार करेगी। एक बयान में कंपनी ने कहा, 'जैसे ही यह फैसला हमें उपलब्ध हो जाता है, हम इसका अध्ययन करेंगे। हम अपने कानूनी सलाहकारों से मशविरा करेंगे और उसके बाद अगले कदम पर फैसला करेंगे। अगर अध्ययन के बाद मजबूत तकनीकी आधार मिले, तो हम फैसले के खिलाफ समीक्षा याचिका दायर करने पर भी विचार करेंगे।'

सीओएआइ के महानिदेशक राजन मैथ्यूज ने कहा कि अदालत का यह फैसला वह लाठी है जो टेलीकॉम सेक्टर की कमर तोड़ देगा। मैथ्यूज ने कहा कि मौजूदा तनाव की स्थिति में यह फैसला उद्योग के लिए विनाशकारी होगा। डेलॉय इंडिया में प्रौद्योगिकी मीडिया और दूरसंचार (टीएमटी) के लीडर हेमंत जोशी ने कहा कि यह पहले से घाटे में चल रहे दूरसंचार उद्योग पर और दबाव बढ़ाएगा।

- सीओएआइ ने कहा - फैसला ऐसी लाठी है जो सेक्टर की कमर तोड़ देगा
- एयरटेल ने कहा - सेक्टर की व्यवहार्यता पर पड़ेगा बहुत बुरा असर
- वोडाफोन का मत - फैसले की पुनर्विचार याचिका पर करेंगे विचार

मामला क्या है

टेलीकॉम कंपनियों को अपनी कमाई का एक हिस्सा लाइसेंस फीस और स्पेक्ट्रम शुल्क के मद में सरकार को देना होता है। इस शुल्क को एजीआर कहते हैं। टेलीकॉम कंपनियों और सरकार के बीच एजीआर में शामिल मदों को लेकर लगभग दो दशकों से मतभेद है। यह मामला आखिरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां कोर्ट ने एजीआर तय करने के सरकार के तरीके को वैध ठहराया। ऐसे में अब टेलीकॉम कंपनियों को एजीआर के बकाया मद में सरकार को करीब 92,000 करोड़ रुपये का भुगतान करना होगा।

तरीका

गेहूं और धान की जगह दलहन और तिलहन की खेती को बढ़ावा, घोषित एमएसपी को किसानों तक पहुंचाने की सख्त जरूरत

फसल विविधीकरण के सहारे पूर्ण खाद्य सुरक्षा पर बल

सुरेंद्र प्रसाद सिंह, नई दिल्ली

केंद्र सरकार ने धान और गेहूं की जगह वैकल्पिक दलहनी व तिलहनी फसलों के सहारे पूर्ण खाद्य सुरक्षा पर जोर देने का फैसला किया है। चालू रबी सीजन में फसलों की बोआई से पहले किसानों को इन फसलों की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने दलहनी व तिलहनी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में पर्याप्त वृद्धि की घोषणा की है। लेकिन घोषित एमएसपी को किसानों तक पहुंचाने की प्रणाली में सुधार करना अभी बाकी है। कृषि सुधार के दूसरे चरण में इसे मजबूत बनाया जा सकता है।

फसल विविधीकरण का यह अभियान कृषि क्षेत्र में सुधार की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इसी के तहत सरकार ने गेहूं के एमएसपी के मुकाबले दलहनी व तिलहनी फसलों के समर्थन मूल्य में ज्यादा वृद्धि की है। दरअसल, देश में गेहूं व चावल की पैदावार जरूरत से कहीं ज्यादा हो रही है, लेकिन दालें और खाद्य तेलों की जरूरतें घरेलू पैदावार से पूरी नहीं हो पाती हैं। इसके लिए सालाना लगभग एक लाख करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है।

तिलहन की लगातार घटती पैदावार और बढ़ती मांग एक गंभीर चुनौती है। प्रतीकात्मक

सरकार ने चालू रबी सीजन की फसलों के लिए घोषित गेहूं के एमएसपी में मात्र 85 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की है जबकि तिलहनी व दलहनी फसलों के समर्थन मूल्य में 225-325 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की है। इसका उद्देश्य किसानों को तिलहन और दलहन की खेती को बढ़ावा देना है। गेहूं की पैदावार जहां 10 करोड़ टन होती है तो धान की 11 करोड़ टन से अधिक पर पहुंचती है। इसके मुकाबले दालों की कुल पैदावार 2.30 करोड़ टन होती है जिससे घरेलू मांग पूरी नहीं हो पाती है। जिसके लिए दालें आयात करनी पड़ती हैं।

इसी तरह तिलहन की लगातार घटती पैदावार और बढ़ती मांग एक गंभीर चुनौती है, जिससे निपटने के लिए आयात ही एकमात्र रास्ता है। खाद्य तेलों की सालाना कुल घरेलू मांग का लगभग 65 फीसद आयात करना पड़ता है। इसके लिए सरकारी खजाने 80-90 हजार करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है। इन जिंसों की आयात निर्भरता घटाने के लिए सरकार ने एक व्यापक योजना तैयार की है। इसके तहत ही दलहनी व तिलहनी फसलों की खेती को बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है।

इंडियन काउंसिल आफ एग्रीकल्चरल रिसर्च (आइसीएआर) के डायरेक्टर जनरल डाक्टर त्रिलोचन महापात्र का कहना है 'तिलहनी व दलहनी फसलों के लिए तकनीकी जानकारी व बेहतर इनपुट के साथ समर्थन मूल्य का होना जरूरी है। इसके सहारे इन फसलों की खेती को बढ़ावा मिल सकता है। पिछले दो सालों के दौरान दालों पर जोर दिया तो गया दलहन के मामले में देश आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ गया है।' लेकिन कटाई सीजन के दौरान कीमतें बहुत नीचे आ जाने और सरकारी खरीद न होने किसान निराश होना स्वाभाविक है।

कृषि क्षेत्र में सुधार के दूसरे चरण में उपज की खरीद पर जोर दिए जाने की जरूरत है। खाद्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि दालों का बफर स्टॉक का गठन इसी क्रम में किया गया है। तिलहनी फसलों की खरीद के लिए सरकारी एजेंसी नैफेड की तैयारी रहती है। लेकिन खेती कम होने की वजह से विफल रही है, जिसे आगे बढ़ाने पर बल दिया जा रहा है।

चालू पेराई सीजन में घटेगा चीनी का उत्पादन

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

चालू पेराई सीजन में देश में चीनी के उत्पादन में 12.38 फीसद तक की गिरावट का अनुमान है। वर्ष 2019-20 के दौरान चीनी का उत्पादन 2.80 से 2.90 करोड़ टन रहने की संभावना है। महाराष्ट्र जैसे प्रमुख राज्यों में गन्ना उत्पादन में कमी की आशंका चीनी के उत्पादन में आने वाली गिरावट की मूल वजह है। केंद्रीय खाद्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक पिछले पेराई सीजन में 3.31 करोड़ टन चीनी का उत्पादन हुआ था, उसमें इस बार कमी आ सकती है।

पिछले दो वर्षों से चीनी के अत्यधिक उत्पादन के चलते घरेलू बाजारों में स्टॉक बहुत बढ़ गया है। जिससे चीनी मिलों को लागत से कम मूल्य पर चीनी बेचने को बाध्य होना पड़ रहा है। चीनी उद्योग को घाटे से उबारने के लिए सरकार ने कई तरह की रियायतों के साथ राहत पैकेज की घोषणा की है। लेकिन इस बार उत्पादन कम होने से मिलों को थोड़ी राहत मिल सकती है। पेराई सीजन की शुरुआत के साथ ही खाद्य मंत्रालय ने सभी गन्ना उत्पादक राज्यों से उनकी पैदावार का ब्योरा लेने के बाद चीनी उत्पादन का अनुमान लगाया है। चीनी उत्पादन में दूसरे सबसे बड़े राज्य महाराष्ट्र में गन्ने की खेती पर सूखा और बाढ़ का प्रभाव पड़ा है, जिससे खेतों में खड़ी गन्ने की फसल प्रभावित हुई है। खाद्य मंत्रालय के मुताबिक चालू सीजन में महाराष्ट्र में 40 लाख टन कम चीनी का उत्पादन हुआ है। चालू सीजन में मिलों में पूरी रफ्तार से पेराई 15 नवंबर से शुरू हो सकेगी। फिलहाल 534 मिलों में चीनी का उत्पादन हो रहा है।

चालू चीनी मार्केटिंग सीजन में गन्ने का उचित व लाभकारी मूल्य (एफआरपी) 275 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। गन्ने की एफआरपी किसानों को कानूनी रूप से मिलनी तय होती है, जिसका भुगतान करना मिलों के लिए अनिवार्य होता है। गन्ने मूल्य का भुगतान 10 फीसद के रिकवरी दर पर दिया जाता है, इससे अधिक की प्रति अंक की रिकवरी पर 2.75 रुपये का भुगतान करना पड़ता है।

28 दिन का समय मिला है इजरायल में पूर्व सेना प्रमुख बेनी गैंट्ज को अगली सरकार बनाने के लिए। इजरायल की 120 सदस्यीय संसद कनेसेट में गैंट्ज की मध्यमार्गी ब्लू एंड व्हाइट पार्टी को 33 सीटें मिली हैं।

भारत विरोधी गतिविधि भड़काने वाले देशों को चेतावनी

जयप्रकाश रंजन, नई दिल्ली

- पाकिस्तान की तरफ से सक्रिय कश्मीर सेल पर भारत ने किया आगाह
- लंदन में भारतीय उच्चायोग के सामने प्रदर्शन की तैयारी पर जताई चिंता
- कनाडा, ब्रिटेन में कश्मीर व खालिस्तान समर्थकों को एकजुट कर रहा पाक

कश्मीर मुद्दे को लेकर दुनिया के कई देशों में उभरी भारत विरोधी ताकतों को देखते हुए भारत ने उन देशों की सरकारों को उन्हें काबू करने की सख्त हिदायत दी है। भारत ने ब्रिटेन, कनाडा समेत उन सभी देशों से कहा है कि उन्हें भारत के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों को देखते हुए उसके खिलाफ चलाई जाने वाली विरोधी गतिविधियों पर लगाम लगाने की मुकम्मल व्यवस्था करनी चाहिए। भारत ने इस बारे में अपनी बात सख्ती से तब रखी है जब कई देशों से इस तरह की सूचनाएं आ रही हैं कि पाकिस्तान ने विदेशों में फिर से अपने 'कश्मीर सेल्स' को सक्रिय करना शुरु कर दिया है। कई देशों में कश्मीर को लेकर रोटी सेंकने वाले समूहों और खालिस्तान समर्थक समूहों के बीच गठबंधन बनने की बात भी सामने आ रही है।

कश्मीर मुद्दे पर लंदन में पाकिस्तान समर्थकों की एक बड़ी भीड़ ने 15 अगस्त को भारतीय उच्चायोग के सामने हिंसक प्रदर्शन किया था। अब वहां फिर से भारतीय उच्चायोग के सामने प्रदर्शन करने की तैयारी है। इस पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा कि, 'यह बेहद गंभीर मामला है और हमें इस पर काफी चिंता है। हमने ब्रिटिश सरकार से अपनी चिंता के बारे में बताया है कि किसी भी प्रदर्शन आदि से उच्चायोग के सामान्य कामकाज पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। हमें उम्मीद है कि ब्रिटिश सरकार इस बार ज्यादा सक्रिय होगी।' कुमार का यह वक्तव्य तब आया है जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने मामले का संज्ञान लिया है।

भारत उन देशों के साथ भी संपर्क में है जहां पाकिस्तान के समर्थन से कश्मीर सेल्स सक्रिय हो चुके हैं। इन देशों को चेताया गया है कि कश्मीर मुद्दे को भड़काने में एक खास राष्ट्रीय पहचान के लोग जिस तरह से बड़े पैमाने पर जुड़ रहे हैं वह आगे खतरनाक परिणाम दिखा सकता है। प्रवक्ता रवीश कुमार ने इस पर दो टूक कहा, 'पाकिस्तान ने लगभग अपने हर विदेशी दूतावास में कश्मीर सेल्स खोल रखे हैं। इनका मुख्य उद्देश्य स्थानीय नागरिक जो पाकिस्तान के नागरिक नहीं हैं बल्कि अन्य देश के नागरिक हैं, उन्हें उकसाने का है।' माना जा रहा है कि ब्रिटेन और कनाडा इस तरह की गतिविधियों के सबसे बड़े केंद्र के तौर पर उभर रहे हैं। कनाडा में कश्मीर और खालिस्तान समर्थकों का गठजोड़ फिर से सक्रिय हो चुका है। यह ग्रुप दो दशक पहले होता था लेकिन इन्हें काबू में करने की कूटनीतिक क्षमता भारत ने दिखाई थी। हाल ही में संपन्न हुए चुनाव में कुछ ऐसे सांसद दोबारा चुनाव जीतकर आए हैं जो खुलेआम खालिस्तान का समर्थन करते हैं। इससे वहां भारत विरोधी भावनाओं के और भड़कने की आशंका है।

भारत ने कश्मीर मुद्दे पर अमेरिकी संसद में चली सुनवाई और उसमें कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले पर हुई बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी पर भी अफसोस जताया है। भारत ने कहा है कि जिस तरह से कुछ सांसदों ने टिप्पणी की है वह दर्शाता है कि उन्हें कश्मीर की स्थिति का ज्ञान नहीं है। दूसरी तरफ तुर्की और मलेशिया को भी कश्मीर मुद्दे पर बगैर तथ्यात्मक जानकारी के टिप्पणी करने से बाज आने के लिए आगाह किया गया है। तुर्की की तरफ से कई बार कश्मीर पर बेहद आपत्तिजनक टिप्पणियां आई हैं जिनके बारे में भारत ने कहा है कि वह तथ्यों पर आधारित नहीं हैं। एक दिन पहले ही भारत ने तुर्की जाने वाले भारतीय पर्यटकों को वहां की स्थिति से आगाह किया है। तुर्की के साथ कारोबारी समझौतों की भी समीक्षा की जा रही है।

भारतीय उच्चायोग पर प्रदर्शन की अनुमति देने से इन्कार

लंदन, प्रेट्र : कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान समर्थकों के भारतीय उच्चायोग के बाहर प्रदर्शन को ब्रिटिश पुलिस ने अनुमति देने से इन्कार कर दिया है। लंदन में रहने वाले पाकिस्तान समर्थक दीवाली के दिन इस प्रदर्शन के लिए कई हफ्ते से योजना बना रहे थे लेकिन प्रशासन ने उनकी तैयारियों से पानी फेर दिया है। इससे पहले लंदन के पाकिस्तानी मूल के मेयर सादिक खान ने भी इस प्रदर्शन से नाइत्तेफाकी जाहिर की थी। कहा था कि इस तरह के प्रदर्शन से लंदन का सांप्रदायिक सौहार्द प्रभावित होगा और मतभेदों की लकीर गहरी होगी।

प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने बुधवार को संसद में कहा था कि इस तरह के प्रदर्शनों में हिंसा होने से इन्कार नहीं किया जा सकता, इसलिए इस प्रदर्शन को स्वीकार नहीं किया जाएगा। इससे पहले कंजरवेटिव पार्टी के सांसद बॉब ब्लैकमैन ने हाउस ऑफ कॉमंस में प्रदर्शन में होने वाली हिंसा को लेकर प्रधानमंत्री के समक्ष चिंता जताई थी। उन्होंने 15 अगस्त को भारतीय उच्चायोग के समक्ष इन्हीं संगठनों के प्रदर्शन की याद दिलाई थी जिसमें उच्चायोग की ओर पत्थर फेंके गए थे और नुकसान पहुंचाया गया था। उन्होंने पीएम से मामले में हस्तक्षेप की मांग की थी।

मलेशिया के प्रधानमंत्री महातिर मुहम्मद के कश्मीर पर विवादित बयान के बाद दोनों देशों के रिश्तों में आई तल्खी के बीच अजरबैजान की राजधानी बाकू में विदेश मंत्री एस जयशंकर की अपने मलेशियाई समकक्ष सैफुद्दीन अब्दुल्ला से मुलाकात हुई। एएनआइ

मैत्रीपूर्ण ढंग से सुलझाया जाए मलेशिया-भारत तनाव : अनवर इब्राहिम

कुआलालंपुर, एजेंसियां : पार्टी कियादिलन रकयत (पीकेआर) के अध्यक्ष और संसद सदस्य अनवर इब्राहिम ने कहा है कि मलेशिया और भारत के बीच तनाव को मैत्रीपूर्ण तरीके से सुलझा लिया जाना चाहिए क्योंकि यह देश की अर्थव्यवस्था के लिए अहम है।

- पीकेआर अध्यक्ष ने कहा, यह देश की अर्थव्यवस्था के लिए है अहम

'मलय मेल' की रिपोर्ट के मुताबिक, अनवर ने कहा कि प्रधानमंत्री महातिर मुहम्मद द्वारा कश्मीर पर अपनी टिप्पणी वापस लेने से इन्कार संभवतः मलेशिया में कुछ समूहों की भावनाओं का प्रतिनिधित्व है। अनवर ने आगे कहा कि महातिर ऐसे नेता के तौर पर जाने जाते हैं जो अपने विचारों पर दृढ़ रहते हैं। बता दें कि पिछले महीने संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए महातिर मुहम्मद ने कहा था कि भारत ने आक्रमण करके कश्मीर पर कब्जा कर लिया है। उनके इस बयान पर भारत ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। वहीं, भारतीय कारोबारियों ने मलेशियाई पाम ऑयल के आयात का बहिष्कार करने का आह्वान किया है। मलेशिया दुनिया में पाम ऑयल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है जबकि भारत उसका सबसे बड़ा उपभोक्ता है। इस तनाव का सीधे तौर पर फायदा इंडोनेशिया को होगा जो दुनिया में पाम ऑयल का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है।

उधर, मलेशिया के अंतरराष्ट्रीय व्यापार और उद्योग मंत्री दारेल लीकिंग ने कहा कि मलेशिया भारत के साथ तनाव का मसला सुलझाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि तनाव के बावजूद इस साल 16 देशों के बीच व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे जिनमें भारत भी शामिल है। लीकिंग ने कहा कि रीजनल कांप्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप (आरसीईपी) को लेकर बातचीत सही दिशा में चल रही है और अंतिम समझौते में सभी देशों को शामिल होना चाहिए। इनमें आसियान के 10 देश और एशिया पैसिफिक के छह देश (चीन, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया, आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड) शामिल हैं। आरसीईपी सम्मेलन चार नवंबर को बैंकॉक में आयोजित होगा। लीकिंग ने कहा कि सम्मेलन से पहले कुछ भी हो सकता है, लेकिन सभी 16 देश मुक्त व्यापार समझौते की ओर अग्रसर हैं। लीकिंग ने बताया कि उन्होंने हाल में भारत के व्यापार मंत्री पीयूष गोयल से द्विपक्षीय संबंधों में नई दिल्ली की चिंताओं पर अनौपचारिक बातचीत की थी और आगे भी बातचीत जारी रखेंगे। वहीं, मलेशिया के पाम ऑयल मंत्री ने कहा कि उनकी सरकार भारत के शीर्ष खाद्य तेल व्यापार संगठनों से बातचीत करने के लिए एक प्रतिनिधिमंडल भेजने पर विचार कर रही है।

इस बीच, मलेशिया के आवासीय एवं स्थानीय निकाय उपमंत्री राजा कमारुल बहरीन ने कश्मीर नीति पर प्रधानमंत्री महातिर मुहम्मद का यह कहते हुए बचाव किया कि उन्होंने एक सम्मानित राजनेता के तौर पर भाषण दिया था। कश्मीर के लोगों के लिए बोलना प्रधानमंत्री का दायित्व है जिन पर लंबे समय तक जुल्म किया गया है। उन्होंने कहा कि अब मलेशिया उस नीति को जारी नहीं रखेगा जिसके तहत उसे तीसरी दुनिया का देश माना जाता है।

न्यूज गैलरी

यमन की लड़ाई में पांच हजार से ज्यादा बच्चों की मौत : यूनिसेफ

सना, एएनआइ : मन में सरकार और हाउती विद्रोहियों के बीच जारी जंग में अभी तक पांच हजार से ज्यादा बच्चों की मौत हो चुकी है। बच्चों के लिए काम करने वाली संयुक्त राष्ट्र (यूएन) की संस्था यूनिसेफ की यमन में प्रतिनिधि सारा बेयसोलेव न्यांत ने बुधवार को कहा, यमन में हालात अत्यंत दयनीय हैं। युद्ध के कारण पिछले चार वर्षों में हजारों बच्चे घायल भी हुए हैं। वर्ष 2015 में सरकार और हाउती विद्रोहियों के बीच शुरू हुई जंग के कारण करीब पांच लाख बच्चों को स्कूल छोड़ना पड़ा। यूनिसेफ की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्तमान में यमन में करीब 20 लाख बच्चे गंभीर कुपोषण के शिकार हैं। (एएनआइ)

ईयू ने उइगर कार्यकर्ता को मानवाधिकार सम्मान से नवाजा

स्ट्रॉसबर्ग : यूरोपीय संघ (ईयू) की संसद ने चीन की जेल में बंद उइगर कार्यकर्ता इल्हाम तोहती को प्रतिष्ठित मानवाधिकार सम्मान से नवाजा है। यूरोपीय संसद के अध्यक्ष डेविड सासोली ने गुरुवार को इसकी घोषणा की। चीन के शिनजियांग प्रांत में उइगर समुदाय के लिए आवाज उठाने वाले तोहती उम्रकैद की सजा काट रहे हैं। अलगाववाद भड़काने के आरोप में उन्हें 2014 में जेल में डाल दिया गया था। अर्थशास्त्र के प्रोफेसर रहे तोहती उइगरों के लिए ज्यादा स्वायत्तता की मांग करते रहे हैं। यूरोपीय संसद मानवाधिकारों की रक्षा के लिए काम करने वाले लोगों को 1988 से यह सम्मान दे रही है। यह सम्मान रूस के प्रसिद्ध विद्रोही नेता आंद्रेई सखारोव के नाम पर दिया जाता है (रायटर)

जिहादियों से नागरिकता छीनेगा डेनमार्क

स्टाकहोम : डेनमार्क की संसद ने गुरुवार को एक कानून पारित किया है जिसमें सरकार को दोहरी नागरिकता रखने वाले संदिग्ध जिहादियों का नागरिक दर्जा छीनने का अधिकार दिया गया है। इस कानून का मुख्य उद्देश्य सीरिया और इराक में आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट की तरफ से लड़ रहे डेनमार्क के नागरिकों पर अंकुश लगाना है। कानून के तहत डेनमार्क सरकार ऐसे जिहादियों की विदेश में रहते हुए नागरिकता वापस ले लेगी और इसमें किसी अदालती आदेश की आवश्यकता नहीं होगा। नागरिकता वापस ले लेने पर ऐसे संदिग्ध जिहादी डेनमार्क में लौट नहीं सकेंगे। सीरिया और तुर्की के बीच तनातनी के बीच डेनमार्क तत्काल यह कानून लाया है। (एएफपी)

रूसी एजेंट मारिया बुतिना अमेरिकी जेल से होगी रिहा

वाशिंगटन : जासूसी के आरोप में सजा काट रही रूसी एजेंट मारिया बुतिना को शुक्रवार को अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित जेल से रिहा कर दिया जाएगा। वह वर्ष 2016 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में रूसी दखल की जांच के दौरान गिरफ्तार और दोषी करार दी गई पहली रूसी नागरिक है। हालांकि मारिया का कहना है कि वह दोनों देशों के संबंध मजबूत करने की कोशिश कर रही थी। (एएफपी)

बांग्लादेश में किशोरी की हत्या मामले में16 को मौत की सजा

फैसला ▶ 18 साल की नुसरत ने मौलवी के खिलाफ की थी दुष्कर्म की शिकायत

अर्जी वापस नहीं लेने पर आरोपितों ने पीड़िता को जिंदा जला दिया था

ढाका, एएफपी : बांग्लादेश की एक अदालत ने मदरसे में किशोरी को जिंदा जलाने के मामले में गुरुवार को 16 लोगों को मौत की सजा सुनाई। 18 साल की नुसरत जहां रफी ने मदरसे के मौलवी के खिलाफ दुष्कर्म की शिकायत की थी। शिकायत वापस नहीं लेने पर उसे केरोसिन डालकर जिंदा जला दिया गया था। इस घटना के खिलाफ देशभर में आक्रोश देखने को मिला था। राजधानी ढाका समेत कई शहरों में विरोध प्रदर्शन हुए थे। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने आरोपितों को न्याय के दायरे में लाने का भरोसा दिया था।

बांग्लादेशी मीडिया के अनुसार, छोटे से कस्बे फेनी की रहने वाली नुसरत ने मदरसे के मौलवी सिराज-उद-दौला के खिलाफ पुलिस थाने में शिकायत दी थी। इस शिकायत के दो हफ्ते बाद गत छह अप्रैल को हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था। इस मामले में फेनी की अदालत के जज ममनूर रशिद ने गुरुवार को फैसला सुनाया। सजा पाने वालों में मौलवी सिराज भी शामिल है। उसी ने नुसरत की हत्या की साजिश रची थी। बचाव पक्ष के वकीलों ने कहा है कि वे इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देंगे।

बांग्लादेश में एक मदरसे में नुसरत जहां रफी को जिंदा जलाने के मामले में सजा सुनाए जाने के बाद फेनी कस्बे की अदालत से बाहर आता एक दोषी। रायटर

मदरसे की छत पर लगाई थी आग : साजिशकर्ता नुसरत को मदरसे की छत पर ले गए और शिकायत वापस लेने का दबाव बनाया। नुसरत के इन्कार करने पर उसके हाथ-पैर बांध दिए गए और केरोसिन डालकर आग लगा दी गई। 80 फीसद जली नुसरत को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां गत दस अप्रैल को उसने दम तोड़ दिया था।

62 दिन में आया फैसला : नुसरत जहां हत्याकांड की सुनवाई फास्ट ट्रैक अदालत ने की। अदालत ने महज 62 दिन में अपना फैसला सुना दिया।

सजा पाने वालों में सत्तारूढ़ अवामी दल के कार्यकर्ता भी : इस हत्याकांड में जिन 16 लोगों को मौत की सजा सुनाई गई है, उनमें दो महिलाएं, मदरसे के छात्र और सत्तारूढ़ अवामी लीग पार्टी के कुछ कार्यकर्ता भी शामिल हैं। इनमें से कुछ नुसरत की हत्या को अंजाम देने में शामिल थे, जबकि कुछ वारदात के दौरान मदरसे के गेट पर पहरा दे रहे थे।

कैटलोनिया का झंडा लेकर हांगकांग में आजादी की मांग

हांगकांग, रायटर : हांगकांग में गुरुवार को हजारों प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर कैटलोनिया का झंडा लेकर प्रदर्शन किया। ये लोग आजादी की लड़ाई साथ लड़ने का नारा लगा रहे थे। इस लिहाज से हांगकांग के प्रदर्शनकारियों ने स्वतंत्र कैटलोनिया राष्ट्र की मांग का भी समर्थन कर दिया। हांगकांग में पांच महीने से लगातार आंदोलन चल रहा है। इस आंदोलन में जोर-शोर से लोकतंत्र की मांग की जा रही है। पूर्व ब्रिटिश उपनिवेश होने की वजह से जनता को लोकतंत्र के जायके का पता है। आंदोलनकारियों का एक वर्ग आजादी की भी मांग कर रहा है। यहां के आंदोलनकारियों ने गुरुवार को स्पेन के कैटलोनिया इलाके की मांग से खुद को जोड़ लिया। संपन्न कैटलन आबादी अरसे से पृथक राष्ट्र की मांग कर रही है और आंदोलन चला रही है।

आंदोलनकारी पर हमला : हांगकांग में लोकतंत्र समर्थक आंदोलनों में शामिल रहे स्टैनले हो पर अज्ञात लोगों ने हमला कर उन्हें बुरी तरह से घायल कर दिया है। स्टैनले को गिराकर कई लोग उनके दोनों हाथों पर कूदते रहे, इससे उनके दोनों हाथ बुरी तरह से जख्मी हो गए हैं, हड्डी टूटने की भी आशंका है। हांगकांग में अगस्त से आंदोलनकारियों पर अज्ञात लोगों का यह आठवां हमला है।

महिला पत्रकार गिरफ्तार: हांगकांग में लोकतंत्र समर्थक आंदोलन कवर कर रहीं महिला पत्रकार हुआंग शीक्विंग को चीन लौटते ही गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने कई महीने तक हांगकांग में रहकर आंदोलन की रिपोर्टिंग की थी। उनकी लिखी दो रिपोर्ट को चीन सरकार ने आपत्तिजनक माना और उन्हीं के चलते कार्रवाई की। शीक्विंग चीन में मीटू..अभियान से भी जुड़ी रही हैं।

किसी भी सूरत में पीएम पद से नहीं दूंगा इस्तीफा : इमरान

इस्लामाबाद, प्रेट्र : पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने सेना के समर्थन का हवाला देते हुए कहा है कि वह किसी भी सूरत में इस्तीफा नहीं देंगे। उनका यह बयान उलेमा-ए-इस्लाम (जेयूआइ-एफ) प्रमुख फजलुर रहमान द्वारा किए जाने वाले सरकार विरोधी धरने को लेकर आया है। रहमान ने 2018 के आम चुनाव में हेर-फेर का दावा करते हुए इमरान से इस्तीफे की मांग की है। 31 अक्टूबर को उनके नेतृत्व में किए जाने वाले आजादी मार्च को पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी समेत सभी विपक्षी पार्टियों ने समर्थन दिया है।

मार्च को लेकर दिए बयान में इमरान ने कहा, 'मेरे इस्तीफे का तो सवाल ही नहीं उठता है। धरना एजेंडा आधारित है और उसे विदेश से समर्थन मिल रहा है।' उन्होंने यह भी कहा कि जेयूआइ-एफ की इस योजना के चलते भारत में खुशी की लहर है। भारतीय मीडिया उनके विरोध-प्रदर्शन पर पहले ही जश्न मना रही है। इमरान के मुताबिक, लोगों का ध्यान कश्मीर मुद्दे से हटाने के लिए यह किया जा रहा है। एक मीडिया रिपोर्ट में खान ने धरने की पीछे की मंशा पर कहा, 'हमें समझना होगा कि इससे किसको फायदा मिलने वाला है।'

इमरान खान। फाइल

उन्होंने कहा 'मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि मौलाना फजलुर की समस्या क्या है। मुझे विपक्ष का भी एजेंडा समझ में नहीं आ रहा। मंहगाई और बेरोजगारी बड़ी समस्याएं हैं। मेरी सरकार इनका समाधान करने का प्रयास कर रही है।' इसके बाद इमरान भारत पर बेबुनियाद आरोप लगाते हुए कहा, 'पहली बात, भारत मौलानाओं का विरोधी है, लेकिन फजलुर के विरोध प्रदर्शन से भारतीय खुश हो रहे हैं। देखिए, मौलाना फजलुर के विरोध प्रदर्शन को लेकर भारतीय मीडिया किस तरह खुशी मना रहा है।

नवाज शरीफ के बाद बेटी मरयम की भी तबीयत बिगड़ी

लाहौर, प्रेट्र : पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी मरयम की भी तबीयत बिगड़ गई है। उन्हें भी उसी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनके पिता का इलाज चल रहा है। लाहौर की कोटलखपत जेल में सात साल की सजा काट रहे शरीफ को सोमवार रात तबीयत बिगड़ने पर यहां सर्विसेज अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनके रक्त में प्लेटलेट्स घटकर खतरनाक स्तर पर पहुंच गए थे।

एक्सप्रेस ट्रिब्यून अखबार में गुरुवार को छपी खबर के अनुसार, मरयम (45) को बुधवार को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इससे पहले उन्होंने पाकिस्तान की भ्रष्टाचार रोधी एजेंसी राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) से अपनी बीमार पिता से मिलने की इजाजत मांगी थी, लेकिन उनके अनुरोध को खारिज कर दिया गया था। प्रधानमंत्री इमरान खान के निर्देश पर पंजाब प्रांत के गृह विभाग ने उन्हें अपने पिता से मिलने की अनुमति दी थी। अस्पताल में अपने पिता को देखने के बाद उनकी भी तबीयत बिगड़ गई।

ब्रिटेन में ट्रक कंटेनर में मिले शव चीनी नागरिकों के

लंदन, रायटर : ब्रिटेन में एक ट्रक कंटेनर से बरामद 39 शवों की पहचान कर ली गई है। सभी चीनी नागरिक बताए जा रहे हैं। इनमें आठ महिलाएं और बाकी पुरुष थे। ब्रिटिश पुलिस के साथ ही चीन के विदेश मंत्रालय ने भी इसकी पुष्टि कर दी है।

एसेक्स पुलिस ने बुधवार को मध्य लंदन से करीब 32 किलोमीटर दूर स्थित ग्रेज औद्योगिक क्षेत्र में पहुंचे एक ट्रक कंटेनर से शव बरामद किए थे। ट्रक के 25 वर्षीय ड्राइवर को हत्या के संदेह में गिरफ्तार कर लिया गया है। जांचकर्ता ट्रक ड्राइवर से पूछताछ कर रहे हैं। जांच से जुड़े एक सूत्र ने बताया कि ड्राइवर का नाम मो रॉबिंसन है। वह उत्तरी आयरलैंड के पोर्टडाउन का रहने वाला है। पुलिस का कहना है कि ट्रक ने गत शनिवार को उत्तरी वेल्स के हॉलीहेड शहर से ब्रिटेन में प्रवेश किया था। इसी शहर के रास्ते आयरलैंड से वाहन ब्रिटेन में दाखिल होते हैं। यह ट्रक बुल्गारिया के पोर्ट शहर जीब्रुज से चला था। अक्सर शरणार्थी ट्रकों में छुपकर ब्रिटेन में अवैध रूप से दाखिल होने का प्रयास करते हैं। पीटीआइ के अनुसार, बुल्गारिया के संघीय अभियोजक कार्यालय ने कहा, 'अभी यह साफ नहीं हो पाया है कि लोगों को कंटेनर में कब बैठाया गया था और यह भी पता नहीं चल सका है कि क्या यह बुल्गारिया में हुआ था या नहीं?'

तीन स्थानों पर मारे गए छापे : मामले की जांच-पड़ताल के सिलसिले में पुलिस ने उत्तरी आयरलैंड में तीन स्थानों पर छापे मारे हैं। नेशनल क्राइम एजेंसी के अनुसार, यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि इसमें किस संगठित अपराध गिरोह का हाथ था।

रेफ्रिजरेटेड था ट्रक कंटेनर

पीटीआइ की खबर के अनुसार, जिस ट्रक कंटेनर से शव बरामद किए गए थे, वह रेफ्रिजरेटेड था। रोड एंड हॉलेज एसोसिएशन के मुख्य कार्यकारी रिचर्ड बर्नेट ने कहा कि रेफ्रिजरेटेड कंटेनर में तापमान शून्य से 25 डिग्री सेल्सियस से भी कम रहा हो सकता है। इतने कम तापमान में किसी का कंटेनर में रहना यकीनन विकट होगा।

जलवायु फंड की कमी से जूझ रहा यूएन

पेरिस, एपी : जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए संयुक्त राष्ट्र (यूएन) आवश्यक फंड की कमी से जूझ रहा है। इसकी मुख्य वजह अमेरिका द्वारा दी जाने वाली सहयोग राशि में भारी कटौती है। ट्रंप प्रशासन अमेरिका की पूर्ववर्ती सरकार द्वारा घोषित तीन अरब डॉलर (करीब 21 हजार करोड़ रुपये) की सहायता राशि में दो अरब डॉलर (करीब 14 हजार करोड़ रुपये) की कटौती का निर्णय ले चुकी है। इससे ग्रीन क्लाइमेट फंड के तहत लक्षित की गई दस अरब डॉलर (करीब 70 हजार करोड़ रुपये) की धनराशि जुटा पाना मुश्किल हो रहा है।

विकसित देश गुरुवार से यहां शुरू हुई दो दिवसीय बैठक के दौरान जलवायु फंड में कमी की भरपाई को लेकर चर्चा कर रहे हैं। इस बैठक में मेजबान फ्रांस के अलावा ब्रिटेन, जर्मनी और अन्य यूरोपीय देश शामिल हैं। यह बैठक यूएन के सालाना जलवायु सम्मेलन से करीब एक महीने पहले आयोजित की गई है।

यूएन का सालाना सम्मेलन चिली की राजधानी सैंटियागो में होना है। ग्रीन क्लाइमेट फंड के तहत अभी तक जुटाए गए सात अरब डॉलर ग्लोबल वार्मिंग के असर को कम करने के लिए खर्च किए जा चुके हैं।

विवाद खत्म

वैली ऑफ द फॉलेन में तानाशाह को दफनाए जाने पर उठे थे सवाल, अब दूसरे कब्रिस्तान में पत्नी की कब्र के बगल में दफनाए गए

कब्र से निकाले गए स्पेन के तानाशाह फ्रैंको के अवशेष

मैड्रिड, रायटर : स्पेन में गुरुवार सुबह बेहद गुपचुप तरीके से पूर्व तानाशाह जनरल फ्रांसिस्को फ्रैंको के अवशेष सरकारी कब्रगाह से खोदकर बाहर निकाले गए। कड़ी सुरक्षा के बीच हुई इस प्रक्रिया में एक पादरी, फोरेंसिक विशेषज्ञ, न्याय मंत्री डोलोरेस डेलगादो और फ्रैंको के परिवार के 22 लोग मौजूद थे। वैली ऑफ द फॉलेन स्मारक से निकाले जाने के बाद फ्रैंको के अवशेष मिंगोरुबियो कब्रिस्तान में उनकी पत्नी की कब्र के बगल में दफनाए गए। इस दौरान उनके सहयोगियों ने फ्रैंको अमर रहें के नारे भी लगाए।

देश की सोशलिस्ट सरकार लंबे समय से फ्रैंको की कब्र को उस स्मारक से निकालने की कोशिश में थी, जिसे उनके आदेश पर ही बनवाया गया था। हाल में सत्तारूढ़ पार्टी ने इसके लिए संसद से भी अनुमति ले ली थी। 1939 से 1975 के बीच स्पेन पर शासन करने वाले फ्रैंको के परिवार ने इस पर नाराजगी जताई है। उन्होंने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दी थी, जिसे खारिज कर दिया गया था। उनके पोते ने कहा कि सरकार आगामी चुनाव में थोड़े से वोट हासिल करने के लिए यह सब कर रही है। स्पेन के लोगों में भी इसको लेकर मतभेद है। 43 फीसद लोग जहां इसके समर्थन में थे वहीं 32.5 फीसद लोगों ने इसका विरोध जताया। कुछ लोगों ने वैली ऑफ द फॉलेन में तानाशाह को दफनाए जाने पर सवाल उठाया। वर्ष 1936 से 1939 तक चले गृहयुद्ध में फ्रैंको ने हिटलर और मुसोलिनी द्वारा समर्थित विद्रोहियों का नेतृत्व किया था। 1939 में उन्होंने स्पेन की सत्ता हासिल की और 1975 में अपनी मृत्यु तक उस पर काबिज रहे। वैली ऑफ फॉलेन में उनकी कब्र के बगल में गृहयुद्ध में मारे गए अन्य लड़ाकों के भी शव दफनाए गए थे।

स्पेन में गुरुवार को पूर्व तानाशाह जनरल फ्रांसिस्को फ्रैंको के अवशेषों को मिंगोरुबियो कब्रिस्तान की ओर ले जाते लोग। इस दौरान फ्रैंको के परिवार के 22 लोग भी मौजूद थे। रायटर

ब्रिटेन में 12 दिसंबर को हो सकते हैं चुनाव

लंदन, प्रेट्र : ब्रिटेन में प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने 12 दिसंबर को चुनाव कराने का प्रस्ताव किया है। उन्होंने यह प्रस्ताव गुरुवार को अपने आवास पर कैबिनेट की बैठक के बाद सार्वजनिक किया। उन्होंने कहा, वह चाहते हैं कि सांसद अच्छी तरह ब्रेक्जिट को लेकर यूरोपीय यूनियन के साथ हुए समझौते का अध्ययन और चर्चा करें। अगर चुनाव की तारीख पर सहमति बन जाती है तब भी सांसदों को ब्रेक्जिट के समझौता मसौदे पर चर्चा का वक्त मिलेगा। वैसे इस मसौदे को संसद बुधवार को पारित कर चुकी है। लेकिन इससे पूर्व संशोधन प्रस्ताव पारित हो जाने से अब 31 अक्टूबर को यूरोपीय यूनियन से अलगाव नहीं हो सकेगा।

संशोधन प्रस्ताव के मद्देनजर यूरोपीय यूनियन ने भी संकेत दिए हैं कि उसे ब्रेक्जिट की तारीख आगे बढ़ाने में कोई आपत्ति नहीं है। नई तारीख संभवतः 31 जनवरी हो सकती है। प्रधानमंत्री बनने के बाद से जॉनसन लगातार दावा कर रहे थे कि 31 अक्टूबर को वह हर हाल में यूरोपीय यूनियन से अलगाव की प्रक्रिया पूरी करेंगे लेकिन अब वह संभव नहीं रह गया है।

स्थायी संघर्ष विराम के बाद ट्रंप ने तुर्की से हटाए प्रतिबंध

वाशिंगटन, एएफपी : अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तुर्की के खिलाफ लगाए गए सभी प्रतिबंध हटा लिए हैं। सीरिया में स्थायी संघर्ष विराम पर तुर्की के सहमत होने के बाद उन्होंने यह कदम उठाया। ट्रंप ने बुधवार को ह्वाइट हाउस में कहा, 'मैंने कोषागार मंत्री को आदेश दिया है कि तुर्की पर लगाए गए प्रतिबंध हटा लिए जाएं, जो पूर्वोत्तर सीरिया में कुर्दों के खिलाफ तुर्की के सैन्य अभियान के जवाब में लगाए गए थे।'

- पूर्वोत्तर सीरिया में सैन्य अभियान को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ने लगाए थे प्रतिबंध

ट्रंप ने गत 14 अक्टूबर को प्रतिबंध लगाने के साथ ही तुर्की से पूर्वोत्तर सीरिया में अपना सैन्य अभियान बंद करने को कहा था। ट्रंप के कहने पर तुर्की ने संघर्ष विराम की घोषणा की थी। तुर्की ने सीरिया से लगती अपनी सीमाओं को सुरक्षित क्षेत्र बनाने के लिए गत नौ अक्टूबर को कुर्दों के खिलाफ सैन्य अभियान शुरू किया था। वह कुर्द लड़ाकों को आतंकी मानता है।

ट्रंप के फैसले के बाद तुर्की ने छेड़ा था सैन्य अभियान : ट्रंप ने इस माह की शुरुआत में सीरिया से अमेरिकी सैनिकों की वापसी का एलान किया था। उस समय उन्होंने कहा था कि वह नहीं चाहते कि तुर्की और कुर्दों की लड़ाई में अमेरिकी सैनिक फंसे। उनके इस फैसले के बाद तुर्की ने उत्तरी सीरिया में सैन्य अभियान छेड़ दिया था।

ट्रंप के इस फैसले की कई अमेरिकी सांसदों ने तीखी आलोचना की थी। उन्होंने कहा था कि यह कुर्दों के साथ विश्वासघात है, जो सीरिया में आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट (आइएस) के खिलाफ लड़ाई में अमेरिका के मुख्य सहयोगी थे।

रूसी सेना ने शुरू की गश्त : वाशिंगटन पोस्ट अखबार के अनुसार, पूर्वोत्तर सीरिया में रूसी सेना ने गश्त शुरू कर दी है। यह कदम तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन और उनके रूसी समकक्ष व्लादिमीर पुतिन के बीच हुए एक समझौते के तहत उठाया गया है।

मेरे करियर में महेंद्र सिंह धौनी भाई ने हमेशा मेरी बहुत मदद की है।
— शाहबाज नदीम, भारतीय स्पिनर

कोहनी की चोट के कारण निशिकोरी का सत्र समाप्त

टोक्यो, आइएएनएस : जापान के शीर्ष टेनिस खिलाड़ी केई निशिकोरी चोट के कारण इस सत्र किसी अन्य प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं लेंगे। 29 वर्षीय निशिकोरी 2007 में पेशेवर खिलाड़ी बने थे। उन्होंने सोमवार को बताया था कि मई में हुए साल के दूसरे ग्रैंडस्लैम फ्रेंच ओपन के बाद उनकी कोहनी में सूजन आ गई थी और अब उन्हें सर्जरी की जरूरत पड़ेगी। टोक्यो के एक अस्पताल में मंगलवार को निशिकोरी ने सर्जरी कराई।

टी-20 की कमान रोहित को, शिवम नया चेहरा

तैयारी ▸ बांग्लादेश के खिलाफ टी-20 सीरीज के लिए विराट को आराम, सैमसन की चार वर्ष बाद वापसी

टेस्ट टीम की कप्तानी करेंगे विराट कोहली, नदीम को नहीं मिला मौका

मुंबई, प्रेट्र : भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआइ) ने गुरुवार को बांग्लादेश के खिलाफ आगामी टी-20 और टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। उम्मीद के मुताबिक नियमित कप्तान विराट कोहली को टी-20 सीरीज में आराम दिया गया है, जबकि उनकी जगह रोहित शर्मा कमान संभालेंगे। हालांकि, विराट दो मैचों की टेस्ट सीरीज में वापसी करेंगे। टी-20 टीम में विकेटकीपर रिषभ पंत के कवर के तौर संजू सैमसन को शामिल किया गया है, जबकि युजवेंद्रा सिंह चहल की टीम में वापसी हुई है। इस बीच शिवम दुबे टीम में नया चेहरा होंगे।

भारत ने अक्टूबर 2018 से सभी प्रारूपों में 56 मैच खेले हैं, जिसमें से 48 में कोहली खेले हैं। रांची टेस्ट के दौरान नवनियुक्त बीसीसीआइ अध्यक्ष सौरव गांगुली ने विराट के आराम के मुद्दे पर कहा था कि यह कप्तान पर ही निर्भर करेगा कि वह क्या चाहते हैं। मुंबई के ऑलराउंडर शिवम दुबे को पहली बार टी-20 टीम में शामिल किया गया है। उन्हें चोटिल हार्दिक पांड्या की जगह मौका मिला है। टी-20 टीम में मुंबई के तेज गेंदबाज शार्दुल ठाकुर को भी शामिल किया गया है जबकि ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा को आराम दिया गया है।

भुवी और बुमराह के फिट होने में समय लगेगा : चयनसमिति के अध्यक्ष एमएसके प्रसाद ने कहा कि अनुभवी तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार चोट से उबरकर अगली सीरीज (वेस्टइंडीज के खिलाफ) में वापसी कर सकते हैं। उन्होंने इसके साथ ही कहा कि तेज गेंदबाजी के अगुआ जसप्रीत बुमराह की वापसी में अभी समय लगेगा।

सैमसन ने जड़ा था दोहरा शतक : सैमसन ने हाल में विजय हजारे ट्रॉफी में केरल के लिए दोहरा शतक जड़ा था। उन्हें पंत के बाद दूसरे विकल्प के रूप में चुना गया है। चयन से पहले बीसीसीआइ के एक अधिकारी ने कहा था कि अगर रिषभ और संजू दोनों टीम में होंगे तो इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। ये दोनों आइपीएल में भी एक साथ खेल चुके हैं। रिषभ को संक्षिप्त प्रारूप में सीमित सफलता मिली है, लेकिन भविष्य को देखते हुए हमें उन्हें खिलाने की जरूरत है। उन्होंने कहा था कि साथ ही संजू में मैच का रुख बदलने की काबिलियत है। विश्व टी-20 को ध्यान में रखते हुए टीम प्रबंधन को अन्य विकल्प भी देखने की जरूरत है क्योंकि हर कोई जानता है कि अब समय महेंद्र सिंह धौनी से आगे देखने का है। कोहली टीम में नहीं हैं तो सैमसन को 'बैकअप' बल्लेबाज के रूप देखा जा रहा है।

शंकर पर भारी शिवम : मुंबई के शिवम दुबे ने छोटे प्रारूप में ऑलराउंडर के दूसरे विकल्प में विजय शंकर को पछाड़ दिया है। सूत्र ने कहा था कि हर कोई सहमत है कि शिवम की गेंदबाजी अभी तक अंतरराष्ट्रीय स्तर की नहीं है और वह हार्दिक की वैराइटी के करीब भी नहीं है, लेकिन वह बायें हाथ के खिलाड़ी हैं जो सकारात्मक चीज है और वह बड़े छक्के जड़ सकते हैं। वहीं टेस्ट टीम में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पदार्पण करने वाले झारखंड के शाहबाज नदीम को बाहर कर दिया गया है।

ऐसा है पूरा कार्यक्रम : तीन नवंबर से नई दिल्ली में शुरू होने वाली तीन मैचों की टी-20 सीरीज (दो अन्य मैच राजकोट और नागपुर में) के अलावा बांग्लादेश की टीम विश्व चैंपियनशिप के अंतर्गत दो टेस्ट मैच (इंदौर और कोलकाता) में खेलेगी। अंतरराष्ट्रीय टी-20 सीरीज का पहला मैच तीन नवंबर को दिल्ली, दूसरा सात नवंबर को राजकोट और तीसरा मैच 10 नवंबर को नागपुर में खेला जाएगा। टेस्ट सीरीज का पहला मैच 14 नवंबर से इंदौर और दूसरा टेस्ट 22 नवंबर से कोलकाता में होगा।

टी-20 टीम

रोहित शर्मा (कप्तान), शिखर धवन, केएल राहुल, संजू सैमसन, श्रेयस अय्यर, मनीष पांडे, रिषभ पंत (विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर, क्रुणाल पांड्या, युजवेंद्रा सिंह चहल, राहुल चाहर, दीपक चाहर, खलील अहमद, शिवम दुबे, शार्दुल ठाकुर।

टेस्ट टीम

विराट कोहली (कप्तान), रोहित शर्मा, मयंक अग्रवाल, चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे, हनुमा विहारी, रिद्धिमान साहा, रवींद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन, कुलदीप यादव, मुहम्मद शमी, उमेश यादव, इशांत शर्मा, शुभमन गिल, रिषभ पंत।

बांग्लादेश के खिलाफ टी-20 सीरीज के लिए कप्तान बनाए गए रोहित शर्मा। फाइल फोटो

पंत को मौका देंगे और धौनी भी हमसे सहमत : प्रसाद

▸ मुख्य चयनकर्ता ने कहा हार्दिक की जगह फिट हैं शिवम

मुंबई, प्रेट्र : चयनसमिति के अध्यक्ष एमएसके प्रसाद ने गुरुवार को साफ किया कि वह रिषभ पंत को लंबे समय तक मौका देने की मंशा रखते हैं और कहा कि महेंद्र सिंह धौनी भी युवाओं को अवसर प्रदान करने के चयनकर्ताओं के रवैये से सहमत हैं। धौनी ने 50 ओवरों के विश्व कप के बाद से खुद को चयन के लिए अनुपलब्ध रखा है। चयनसमिति ने गुरुवार को बांग्लादेश सीरीज के लिए पंत के साथ संजू सैमसन को भी विकेटकीपर के तौर पर टी-20 टीम में शामिल किया है।

प्रसाद ने कहा कि वह पहले ही कह चुके हैं कि अब धौनी से आगे सोचने की जरूरत है और उनके टीम में चयन में यह प्रतिबिंबित होता है। उन्होंने कहा कि विश्व कप के बाद मैंने साफ कर दिया था कि हम अब आगे बढ़ रहे हैं। हम युवाओं को मौका दे रहे हैं और देखिए वे टीम में खुद को स्थापित कर रहे हैं। रिषभ पंत अच्छा कर रहा है और संजू सैमसन की टीम में वापसी हुई है, मुझे पूरा विश्वास है कि आप हमारी विचार प्रक्रिया को समझ रहे होंगे। हमारी निश्चित तौर पर धौनी से बातचीत हुई और उन्होंने भी युवाओं को बढ़ावा देने के हमारे फैसले पर सहमति जताई। पंत का पक्ष लेते हुए प्रसाद ने कहा कि विश्व कप के बाद मेरी इस पर स्पष्ट राय थी कि अब हम पंत को आगे बढ़ाएंगे। इसलिए हम अब भी उसका पक्ष लेंगे और देखिए वह अच्छी प्रगति कर रहा है। यह सही है कि वह कुछ मैचों में हमारी उम्मीदों के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर पाया लेकिन आप किसी का पक्ष लेकर ही एक खिलाड़ी को तैयार कर सकते हैं। इसलिए हमें यकीन है कि वह सफल रहेगा। धौनी के भविष्य के बारे में इस पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज ने कहा कि यह पूरी तरह से उनका फैसला होगा। प्रसाद ने कहा कि घरेलू क्रिकेट में खेलना और लय हासिल करना या संन्यास पर विचार करना सब कुछ पूरी तरह से उनका निजी फैसला होगा। हमने पहले ही भविष्य के लिए खाका खींच दिया है।

पांच सदस्यीय चयनसमिति ने ऑलराउंडर शिवम दुबे को पहली बार मौका दिया है। प्रसाद ने कहा कि आपने देखा है कि पहले हमारे पास हार्दिक पांड्या थे, इसके बाद हमने विजय शंकर को भी आजमाया। हम सभी इस पर सहमत थे, हमें जिस भूमिका के लिए खिलाड़ी चाहिए उसमें वह (दुबे) फिट बैठता है। वह आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करता है। वेस्टइंडीज में भारत-ए सीरीज और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे (भारत-ए के लिए) में उनका प्रदर्शन शानदार रहा।

मुख्य चयनकर्ता एमएसके प्रसाद। प्रेट्र

बीसीसीआइ के बिना कुछ नहीं आइसीसी : धूमल

▸ नवनियुक्त बीसीसीआइ कोषाध्यक्ष अरुण ने बताई अपनी योजनाएं

▸ प्रथम श्रेणी क्रिकेटरों की हालत पर सुधार करने की बात कही

नई दिल्ली, प्रेट्र : बीसीसीआइ के नवनियुक्त कोषाध्यक्ष अरुण धूमल के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आइसीसी) की नीतियों के निर्धारण में भारत की भूमिका नहीं होना चिंता की बड़ी बात है। उन्होंने साथ ही भारत की अहम भूमिका नहीं होने पर वैश्विक संस्था की प्रासंगिकता पर सवाल भी उठाए। नए अध्यक्ष और पूर्व दिग्गज क्रिकेटर सौरव गांगुली की अगुआई में नए प्रशासकों के पदभार संभालने के बाद धूमल ने अपनी प्राथमिकताओं पर बात की, जिसमें बीसीसीआइ के दुनिया का सबसे अमीर बोर्ड होने के बावजूद बोर्ड के राजस्व में इजाफा करना शामिल है।

आइसीसी के संचालन की रूप रेखा तैयार करने के लिए नवनियुक्त कार्य समूह से भारत की गैरमौजूदगी के संदर्भ में धूमल ने कहा कि क्या हमने कभी कल्पना की थी कि आइसीसी के खाके के निर्धारण में बीसीसीआइ का कोई मत नहीं होगा। कभी इसकी कल्पना नहीं की गई थी। बीसीसीआइ के बिना आइसीसी क्या है? उन्होंने साथ ही स्पष्ट कर दिया कि जहां तक 2023-2031 के भविष्य दौरा कार्यक्रम का सवाल है तो वह आइसीसी के साथ नहीं हैं। नए प्रस्ताव में प्रत्येक वर्ष विश्व टी-20 और प्रत्येक तीन साल में वनडे अंतरराष्ट्रीय विश्व कप के आयोजन का प्रावधान है।

आइसीसी से सहमत नहीं : माना जा रहा है कि आइसीसी इसी योजना के साथ 2023-2028 के वैश्विक मीडिया अधिकार बाजार में उतरेगा और स्टार स्पोर्ट्स जैसे संभावित प्रसारणकर्ताओं से उसे अधिक राजस्व मिलने की उम्मीद है। धूमल ने कहा कि हम टूर्नामेंटों की संख्या बढ़ाने के संदर्भ में आइसीसी के नए प्रस्ताव से सहमत नहीं हैं। धूमल ने कहा कि गैरजरूरी खर्चों पर लगाम कसना उनकी प्राथमिकता में शीर्ष पर है। वह इस पैसे का इस्तेमाल प्रथम श्रेणी क्रिकेटरों की वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए करना चाहते हैं।

खर्चों के बढ़ने से हैरान : बीसीसीआइ के पूर्व अध्यक्ष अनुराग ठाकुर के भाई धूमल पिछले कुछ वर्षों में विधिक खर्चों के बढ़ने से भी हैरान हैं। बीसीसीआइ के कोषाध्यक्ष ने कहा कि मेरा लक्ष्य बीसीसीआइ के राजस्व में इजाफा करना है, क्योंकि राजस्व स्थिर हो गया है, जबकि खर्चों में इजाफा हुआ है। प्रशासनिक और विधिक खर्चों पर ध्यान देने की जरूरत है। धूमल ने कहा कि कुछ अन्य मुद्दों पर भी ध्यान देने की जरूरत है, जिसमें कर दायित्व और अतीत की आइपीएल फ्रेंचाइजियों के साथ मुद्दे भी शामिल हैं।

प्रथम श्रेणी क्रिकेट पर ध्यान देने की जरूरत : धूमल भी गांगुली के इस विचार से सहमत दिखे कि प्रथम श्रेणी क्रिकेटरों का ध्यान रखने की जरूरत है और इसलिए उन्हें अधिक वित्तीय संसाधनों की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हमें राजस्व में इजाफा करने की जरूरत है जिससे कि प्रथम श्रेणी क्रिकेटरों को फायदा हो सके क्योंकि हम उनके बीच अधिक राशि वितरित कर पाएंगे, क्योंकि उनका ध्यान रखने की जरूरत है। इस राशि पर अभी फैसला नहीं किया गया है, लेकिन धूमल को भरोसा है कि एक बार सीनियर सदस्यों और शीर्ष परिषद की बैठक के बाद उनके पास यह आंकड़ा होगा। उन्होंने कहा कि हमें अध्यक्ष और शीर्ष परिषद के अन्य सदस्यों के साथ बैठने और राशि पर फैसला करने की जरूरत है, लेकिन यह राजस्व में इजाफे पर निर्भर करेगा, क्योंकि हमें देखना होगा कि हम द्विपक्षीय सीरीज और अन्य आइसीसी टूर्नामेंटों से कितनी कमाई कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर पिछले कुछ वर्षों में विधिक खर्चों में इजाफा हुआ है। खर्चे की राशि से मैं ही नहीं, बल्कि सभी सदस्य हैरान हैं। इस पर गौर करने की जरूरत है और हम निश्चित तौर पर ऐसा करेंगे।

अरुण सिंह धूमल। फाइल फोटो

आक्रामक बल्लेबाजी से अपनी पहचान बनाना चाहते हैं दुबे

मुंबई, प्रेट्र : मुंबई के युवा क्रिकेटर शिवम दुबे ने भारतीय टीम में चुने जाने के बाद कहा कि उन्हें आक्रामक बल्लेबाजी करना पसंद है और वह अपनी इस 'पॉवर हिटिंग' शैली को कभी नहीं छोड़ेंगे, जिसने उन्हें भारतीय टीम में शामिल कराने में अहम भूमिका निभाई। दुबे को भारत-ए टीम में अपने शानदार प्रदर्शन के बूते पहली बार भारतीय टीम में चुना गया।

26 साल के दुबे ने अपने चयन के बाद कहा कि मेरी आक्रामक शैली नैसर्गिक है और मैं इस पर काम करता हूं। मेरे पिता हमेशा मुझे आक्रामक बल्लेबाज बनाना चाहते थे और फिर यह मेरी शैली बन गई। मुझे पॉवर हिटिंग पसंद है। उन्होंने कहा कि मैं भगवान और अपने पिता का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। विशेषकर मेरे पिता को जिन्होंने हमेशा मेरा समर्थन किया और यह उन्हीं का सपना था कि मैं भारत के लिए खेलूं। मैं टीम में चुने जाने की उम्मीद कर रहा था। मुझे अपने चयन का भरोसा था। मेरा प्रदर्शन अच्छा रहा था, इसलिए मैं टीम में चुना गया। दक्षिण अफ्रीका के महान ऑलराउंडर जैक कैलिस को आदर्श मानने वाले दुबे ने कहा कि मैं कड़ी मेहनत करना जारी रखूंगा। मैंने अभी अपने लक्ष्य तय नहीं किए हैं। इस समय मैं खुश हूं। बतौर ऑलराउंडर मुझे पूरी तरह से केंद्रित होना होगा और साथ ही अच्छी फिटनेस भी बनाए रखनी होगी।

शिवम दुबे फाइल फोटो

अब मैं 'कुशल बल्लेबाज' बनने की कोशिश नहीं करना चाहता हूं : संजू सैमसन

नई दिल्ली, प्रेट्र : संजू सैमसन को अपने करियर में कई बार निराशा का सामना करना पड़ा और अब उन्हें इन उतार-चढ़ाव से कोई परेशानी भी नहीं होती। चार साल के अंतराल बाद भारतीय टीम में वापसी करने वाला यह खिलाड़ी 'कुशल बल्लेबाज' बनने की कोशिश भी नहीं करता। सैमसन ने भारत के लिए एकमात्र मैच जुलाई 2015 में टी-20 के रूप में खेला था जब कम अनुभवी टीम ने जिंबाब्वे का दौरा किया था। तब वह 19 साल के थे।

इसके बाद से इस विकेटकीपर बल्लेबाज के लिए सफर उतार-चढ़ावों भरा रहा है जिन्हें अनुशासनहीनता के आधार पर केरल टीम से भी बाहर कर दिया गया था। वह निरंतर अच्छा प्रदर्शन भी नहीं कर सके और इस बीच उनकी फिटनेस भी अच्छी नहीं रही। इस दौरान उन्होंने बेहतरीन पारियां भी खेलीं। इसी तरह की एक पारी इस महीने में विजय हजारे ट्राफी में सर्वश्रेष्ठ व्यक्तिगत स्कोर से रही जिसमें उन्होंने नाबाद 212 रन बनाए। सैमसन अब 24 साल के हैं। उन्होंने गुरुवार को कहा कि अगर आपका करियर सुरक्षित और आसान राह वाला रहता है तो आप बहुत कम चीजें सीखते हो। मैंने पिछले चार से पांच वर्षों में काफी चीजें सीखी हैं अगर आप काफी बार विफल होते हो तो आप जानते हो कि कैसे फिर से वापसी की जाए और कैसे सफल हुआ जाए।

मैं अपनी जिंदगी में काफी बार विफल हुआ हूं, इसलिए मैं जानता हूं कि कैसे उठकर अच्छा प्रदर्शन किया जाए। यह मेरे लिए फायदे की चीज रही। महान क्रिकेटर राहुल द्रविड़ सहित कई ने सैमसन की तारीफ की लेकिन प्रदर्शन में निरंतरता की कमी उनके खिलाफ जाती रही। दिनेश कार्तिक की वापसी के बाद रिषभ पंत के आने से वह पिछले दो वर्षों में भारत की सीमित ओवरों की टीम से बाहर रहे। कोहली को बांग्लादेश के खिलाफ टी-20 सीरीज से बाहर रखा गया है जिससे सैमसन के विशेषज्ञ बल्लेबाज के तौर पर खेलने की उम्मीद है जिसमें पंत विकेटकीपिंग करेंगे।

भारतीय बल्लेबाज संजू सैमसन। फाइल फोटो

बीसीसीआइ अध्यक्ष गांगुली के साथ बातचीत को लेकर उत्सुक हैं कोहली

योजना

▸ कहा, सौरव टीम की जरूरतों को अच्छे से जानते हैं

▸ गांगुली ने विराट को बताया था भारतीय क्रिकेट का सबसे अहम व्यक्ति

▸ पहली बार होगी दोनों दिग्गजों में मुलाकात

मुंबई, प्रेट्र : भारतीय कप्तान विराट कोहली ने गुरुवार को कहा कि वह बीसीसीआइ के नवनियुक्त अध्यक्ष और पूर्व कप्तान सौरव गांगुली के साथ 'शीर्ष स्तर और पेशेवर' चर्चा को लेकर उत्साहित हैं। राष्ट्रीय क्रिकेट टीम की भविष्य की योजनाओं को लेकर गांगुली और कोहली के जल्द ही मुलाकात करने की उम्मीद है।

बुधवार को बीसीसीआइ अध्यक्ष के रूप में पदभार संभालने के बाद गांगुली ने कोहली को भारतीय क्रिकेट का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति करार देते कहा था कि वह कप्तान के लिए चीजें आसान करने के लिए हैं, मुश्किलें खड़ी करने के लिए नहीं। कोहली ने गुरुवार को यहां एक प्रचार कार्यक्रम के दौरान कहा कि मैं अब उनसे मिलूंगा। मैं अच्छी चर्चा को लेकर उत्साहित हूं। वह ऐसे व्यक्ति हैं जो पहले काफी क्रिकेट खेल चुके हैं, जो उस स्थिति को जानते हैं जिसमें हम हैं, टीम की क्या जरूरत है, भारतीय क्रिकेट की क्या जरूरत है। उन्होंने कहा कि इसलिए आपको अच्छी, पेशेवर, शीर्ष स्तर की चर्चा की जरूरत है। यह स्वस्थ चर्चा होगी क्योंकि मैं अभी खेल रहा हूं और वह पहले खेल चुके हैं, इन चीजों को लेकर आपसी समझ होगी। अतीत में उनके साथ मेरी अच्छी चर्चा हुई है और इस बार भी मुझे ऐसी ही उम्मीद है। गांगुली चाहते हैं कि कोहली आइसीसी टूर्नामेंट में भारत के लिए ट्रॉफी जीतें।

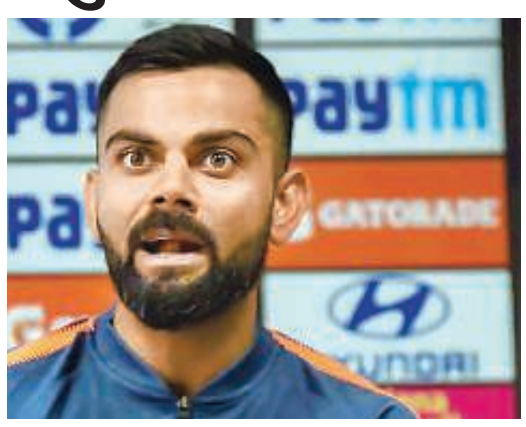

भारतीय कप्तान विराट कोहली। फाइल फोटो

श्रीलंका के खिलाफ शुरुआत करेगा गत चैंपियन भारत

दुबई, प्रेट्र : गत चैंपियन भारतीय टीम अंडर-19 विश्व कप में खिताब के बचाव की शुरुआत 19 जनवरी को दक्षिण अफ्रीका के ब्लोमफोंटेन के मैनगौंग ओवल में श्रीलंका के खिलाफ करेगी। चार बार के चैंपियन भारत को ग्रुप-ए में न्यूजीलैंड, श्रीलंका और पहली बार खेल रहे जापान के साथ रखा गया है। 16 टीमों का टूर्नामेंट 17 जनवरी से शुरू होगा, जिसमें भारत 21 और 24 जनवरी को क्रमशः जापान और न्यूजीलैंड से भिड़ेगा। फाइनल मुकाबला नौ फरवरी को खेला जाएगा। पिछले चरण की उप विजेता और तीन बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया का सामना ग्रुप-बी मुकाबले में वेस्टइंडीज से होगा, जिसमें इंग्लैंड और पदार्पण कर रही नाइजीरिया भी शामिल है।

ग्रुप-सी में पाकिस्तान को बांग्लादेश, जिंबाब्वे और स्कॉटलैंड से खेलना होगा। मेजबान दक्षिण अफ्रीका 17 जनवरी को अफगानिस्तान के खिलाफ शुरुआती मैच खेलेगा। संयुक्त अरब अमीरात और कनाडा ग्रुप-डी की दो अन्य टीमें हैं। टूर्नामेंट के दूसरे चरण को सुपर लीग और प्ले टूर्नामेंट में विभाजित किया गया है। चार में से प्रत्येक ग्रुप से शीर्ष दो टीमें सुपर लीग में जगह बनाएंगी, जबकि बची हुई टीमें प्लेट चैंपियनशिप में खेलेंगी। पोचेफस्ट्रूम में जेबी मार्क्स ओवल दो सुपर लीग क्वार्टर फाइनल, दोनों सेमीफाइनल और फाइनल की मेजबानी करेगा।

अंडर-19 विश्व कप

ग्रुप-ए : भारत, न्यूजीलैंड, श्रीलंका, जापान।

ग्रुप-बी : ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, वेस्टइंडीज, नाइजीरिया

ग्रुप-सी : पाकिस्तान, बांग्लादेश, जिंबाब्वे, स्काटलैंड

ग्रुप-डी : अफगानिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त अरब अमीरात, कनाडा।

साक्षात्कार

अभी बहुत मेहनत करने व फोकस रखने की जरूरत है : यशस्वी

मुंबई के लिए खेलने वाले 17 साल के यशस्वी जायसवाल ने विजय हजारे ट्रॉफी के जरिये लिस्ट-ए क्रिकेट में पदार्पण किया। इस दौरान उन्होंने अपने पहले ही टूर्नामेंट में छह पारियों में 112.80 की औसत और 104.05 के स्ट्राइक रेट से 564 रन बनाए, जिसमें तीन शतक और एक अर्धशतक शामिल रहा। उन्होंने झारखंड के खिलाफ दोहरा शतक (203) भी जड़ा। 17 साल के बायें हाथ के बल्लेबाज यशस्वी उत्तर प्रदेश के भदोही के रहने वाले हैं और 10 साल की उम्र में क्रिकेट खेलने का सपना संजोय मुंबई पहुंचे थे। वहां उनका शुरुआती सफर काफी मुश्किलों भरा रहा। उन्होंने टेंट में जमीन पर सोकर रातें गुजारीं तो खाली पेट दिन भी काटे। गुजारा करने के लिए उन्होंने गोलगप्पे तक बेचे, लेकिन क्रिकेट खेलने के सपने को धुंधला नहीं पड़ने दिया। क्रिकेट कोच ज्वाला सिंह के संपर्क में आने के बाद उनके सपने को पहचान मिली। आज यशस्वी भारत के सबसे तेजी से उभरते हुए प्रतिभाशाली बल्लेबाज माने जाते हैं। विजय हजारे ट्रॉफी में प्रदर्शन व अन्य मुद्दों पर **यशस्वी जायसवाल से उमेश राजपूत** ने खास बातचीत की। पेश हैं प्रमुख अंश :-

● **आपको उम्मीद थी कि लिस्ट-ए क्रिकेट में आपका पदार्पण इतना शानदार होगा?**

-इतने अच्छे पदार्पण की उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन अच्छे प्रदर्शन का भरोसा जरूर था। मैंने सिर्फ यही सोचा था कि मुझे सिर्फ अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना है और गेंद को उसकी मेरिट के हिसाब से खेलना है।

● **आपके कोच ज्वाला सिंह ने आपको इसके लिए कोई सुझाव दिए थे?**

-हां, उन्होंने मानसिक रूप से मुझे काफी अच्छी तरह से तैयारी कराई थी। उन्होंने मुझसे कहा था कि किसी हाल में मौका गंवाना मत। जितना हो सके अंत तक खेलना और अपने पर भरोसा रखना।

● **आप भारत में लिस्ट-ए क्रिकेट में शतक और दोहरा शतक जड़ने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। आपको इन रिकॉर्ड के बारे में पता था?**

-नहीं, मुझे रिकॉर्ड बनाने के बारे में कुछ पता नहीं था। हां, लेकिन मुझे खुशी हुई कि मैंने अच्छा प्रदर्शन किया।

● **23 अक्टूबर को आपके कोच का जन्मदिन था, तो क्या आपका प्रदर्शन उनके लिए तोहफे की तरह था?**

-जी, आप ऐसा कह सकते हैं। हालांकि, इस बारे में ना तो उन्होंने कुछ कहा था और ना ही मैंने कुछ सोचा था। मैं बस खेल रहा था और किस्मत से ऐसा हो गया। सर बहुत खुश हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि यह बहुत अच्छी शुरुआत मिली है, लेकिन अभी बहुत दूर तक जाना है। इसलिए अभी बहुत मेहनत करने और फोकस बनाए रखने की जरूरत है।

● **लेकिन, आपकी टीम फाइनल तक नहीं पहुंच पाई?**

-हां, बुरा तो लग रहा है कि हम इतना अच्छा खेलने के बाद भी क्वालीफाई नहीं कर पाए। बारिश की वजह से हम क्वार्टर फाइनल से आगे नहीं बढ़ पाए। लेकिन, हमारी टीम बहुत अच्छा खेली और मुझे सभी से काफी समर्थन मिला। मैं खासकर एमसीए (मुंबई क्रिकेट संघ) का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि चयनकर्ताओं ने मेरा चयन किया और मुझे ऊपर खेलने का मौका दिया।

● **क्या विजय हजारे ट्रॉफी में पदार्पण से पहले आप पर कुछ दवाब था?**

-दवाब तो बहुत था, क्योंकि मुंबई की टीम में जगह बनाना आसान नहीं होता।

● **पिछले साल सचिन तेंदुलकर ने आपको घर बुलाकर अपने ऑटोग्राफ वाला बल्ला दिया था। क्या क्रिकेट के भगवान से मिला यह तोहफा आपके लिए अच्छी किस्मत लेकर आया?**

-जब मैं सचिन सर से मिला तो मैं बहुत खुश था, उनके साथ बिताया समय मेरे लिए बेहद अमूल्य है। उनसे मिलने के बाद मेरा क्रिकेट भी बदल गया है।

● **आपके शतक मनाने का जश्न युवराज सिंह और सचिन से मिलता-जुलता है, तो क्या यह स्वाभाविक है या आप उनकी कॉपी करते हैं?**

-मुझे इस तरह जश्न मनाना अच्छा लगता है। हां, सचिन सर के जश्न मनाने के अंदाज को मैं थोड़ा कॉपी करता हूं।

● **अपने सफर से कितने संतुष्ट नजर आते हैं और आपके परिवार को इसकी कितनी खुशी है?**

-अभी मैं संतुष्ट नहीं हो सकता। अभी मुझे बहुत कुछ करना है। हालांकि, मम्मी-पापा जरूर खुश हैं और बोलते हैं कि और मेहनत करूं और अच्छा प्रदर्शन करूं।

● **आपको लेकर ज्वाला सिंह काफी सख्त रहते थे। क्या अब उन्होंने आपको कुछ छूट दी है?**

-वह अभी भी काफी सख्त हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वह मुझे कुछ भी नहीं करने देते हैं। हालांकि, अब उन्होंने मुझे मैदान पर गॉगल्स पहनने की छूट दे दी है, जो पहले नहीं थी। अब उन्होंने मुझे खुद गॉगल्स लाकर गिफ्ट किए।

● **आपका अगला लक्ष्य भारत के लिए खेलने का है या आइपीएल टीम में आने का।?**

-भारत के लिए खेलने का सपना सभी का होता है, लेकिन उसकी एक प्रक्रिया है और यदि प्रक्रिया ठीक होगी तो सपना भी पूरा होगा। मैं बस अपनी प्रक्रिया को ठीक रखना चाहता हूं। साथ ही आइपीएल टीम में भी आने की बात चल रही है। उम्मीद है इस साल आइपीएल की किसी टीम में जगह बना सकूंगा।

टीमें अच्छा खेलेंगी, तभी दर्शक देखने आएंगे : एटीके कोच हबास

कोलकाता, आइएएनएस : इंडियन सुपर लीग (आइएसएल) टीम एटीके के मुख्य कोच एंटोनियो हबास ने अपने खिलाड़ियों से बेहतर प्रदर्शन करने को कहा है ताकि उसके दर्शक स्टेडियम में आएं और मैच देख सके। दो बार की चैंपियन एटीके को अपने पहले मैच में केरला ब्लास्टर्स के खिलाफ 1-2 से हार का सामना करना पड़ा था।

हम ओलंपिक में क्वालीफाई करने के लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं। उम्मीद है हम कामयाब होंगे।
– रानी रामपाल, महिला हॉकी खिलाड़ी

लियोन मेसी के रिकॉर्ड गोल से बार्सिलोना जीता

फुटबॉल डायरी ▶ यूएफा चैंपियंस लीग के मैच में स्लाविया प्राग को 2-1 से हराया

मैच के दौरान फुटबॉल को काबू करने का प्रयास करते लियोन मेसी। रायटर

लियोन इस लीग में लगातार 15 सत्र में कम से कम एक गोल करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए

प्राग, एएफपी : सुपरस्टार स्ट्राइकर लियोन मेसी के रिकॉर्ड गोल से बार्सिलोना ने यूएफा चैंपियंस लीग के ग्रुप-एफ में स्लाविया प्राग को 2-1 से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया। मेसी ने तीसरे ही मिनट में स्लाविया के गोलकीपर ओंद्रेज कोलार को छकाकर बार्सिलोना को बढ़त दिलाई। वह चैंपियंस लीग में लगातार 15 सत्र में कम से कम एक गोल करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए। पहले हाफ तक टीम 1-0 से आगे रही।

दूसरे हाफ के पांचवें मिनट में लुकास मासोपस्ट के बेहतरीन पास को गोल में बदलकर यान बोरिल ने स्लाविया की मैच में वापसी करा दी। स्लाविया के विंगर पीटर ओलायिंका हालांकि 57वें मिनट में आत्मघाती गोल कर बैठे जिससे बार्सिलोना ने 2-1 की बढ़त बना ली, जो निर्णायक साबित हुई। बार्सिलोना ग्रुप-एफ में तीन मैचों में सात अंक के साथ शीर्ष पर चल रहा है। टीम ने इंटर मिलान पर तीन अंक की बढ़त बना रखी है जिसने बोरुसिया डोर्टमंड को 2-0 से हराया। स्लाविया की टीम एक अंक के साथ अंतिम पायदान पर है।

लिवरपूल ने जेन्क को 4-1 से करारी शिकस्त दी

जेन्क (बेल्जियम) : मौजूदा यूरोपीयन चैंपियन लिवरपूल ने यूएफा चैंपियंस लीग के ग्रुप-ई के मैच में आरसी जेन्क को 4-1 से करारी शिकस्त दी। बेल्जियम के क्लब के खिलाफ मिडफील्डर एलेक्स ओक्सलेड चेंबरलिन ने दो गोल दागे। इस जीत के बाद इंग्लिश क्लब ग्रुप तालिका में छह अंकों के साथ दूसरे पायदान पर काबिज है। चौथे पायदान पर मौजूद जेन्क के पास केवल एक अंक है। चेंबरलिन ने लिवरपूल को मुकाबले की दमदार शुरुआत दिलाई और दूसरे मिनट में ही गोल करके अपनी टीम को बढ़त दिला दी।

पहले हाफ में हालांकि, लिवरपूल अपनी बढ़त को दोगुना नहीं कर पाई। मेहमान टीम के लिए दूसरा हाफ भी दमदार रहा। 57वें मिनट में चेंबरलिन ने मुकाबले का दूसरा गोल किया जो इस लीग में लीवरपूल का 200वां गोल था। लिवरपूल ने अपने आक्रमण तेज कर दिए। 77वें मिनट में सादियो माने को मौका मिला और उन्होंने गोल करने में कोई गलती नहीं की।

मुहम्मद सलाह ने 87वें मिनट में मेहमान टीम का चौथा गोल किया। जेन्क की ओर से एकमात्र गोल 88वें मिनट में ओडे ने किया। हालांकि, मैच के दौरान लिवरपूल के कुछ प्रशंसकों ने बेल्जियम के डिवॉक ओरिजी को लेकर नस्ली टिप्पणी की थी और क्लब ने इसको लेकर निंदा की है।

अन्य मुकाबलों में ग्रुप-एच में वेलेंसिया और लिली के बीच खेला गया मुकाबला 1-1 से ड्रॉ पर समाप्त हुआ। हालांकि, वेलेंसिया की टीम को 84वें मिनट के बाद से 10 खिलाड़ियों के साथ खेलना पड़ा क्योंकि मुक्टार रेड कार्ड मिलने के कारण मैदान से बाहर हो गए थे। मैच में वेलेंसिया का खाता डेनिस चेरिशेव ने 63वें मिनट में गोल करके खोला। जवाब में ननितेमो ईकोन ने इंजुरी टाइम (90+5वें मिनट) में गोल कर वेलेंसिया के हाथों टीम को हार से बचा लिया। इसके अलावा ग्रुप-जी के मुकाबले में बेनफिका ने ल्योन को 2-1 से हरा दिया। बेनफिका के लिए राफा सिल्वा (चौथा मिनट) और पिज्जी (85वें मिनट) ने गोल किए, जबकि मेंफिस डीपे (70वां मिनट) ने ल्योन के लिए एकमात्र गोल किया।

चीन 2021 में क्लब विश्व कप की मेजबानी करेगा : शंघाई : फीफा ने अपने विस्तारित 24 टीमों के क्लब विश्व कप के पहले टूर्नामेंट की मेजबानी चीन को सौंपी है। फुटबॉल की वैश्विक संस्था फीफा के अध्यक्ष जियानी इनफेंटिनो ने गुरुवार को इसे 'ऐतिहासिक फैसला' करार दिया। फीफा के इस फैसले को फुटबॉल की दुनिया में चीन के बढ़ते रुतबे के तौर पर देखा जा सकता है और यह देश के अकेले दम पर फीफा विश्व कप की मेजबानी का रास्ता साफ कर सकता है। इनफेंटिनो ने शंघाई में फीफा परिषद की बैठक के बाद यह घोषणा की। यह परिषद फुटबॉल की वैश्विक संस्था की फैसले करने वाली इकाई है। इस फैसले का मतलब है कि दुनिया के कुछ शीर्ष क्लब और उनके बड़े स्टार खिलाड़ी दो साल में चीन में खेलते हुए नजर आएंगे।

भारत को फीफा रैंकिंग में दो स्थानों का नुकसान

नई दिल्ली, प्रेट्र : भारतीय फुटबॉल टीम गुरुवार को जारी नवीनतम फीफा रैंकिंग में दो स्थान के नुकसान से 106वें पायदान पर खिसक गई। इस महीने फीफा विश्व कप क्वालीफायर में खराब रैंकिंग वाली बांग्लादेश की टीम के खिलाफ 1-1 से ड्रॉ खेलने के बाद भारत की रैंकिंग में गिरावट आई है। सितंबर में एशियाई चैंपियनशिप में कतर के खिलाफ भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए गोलरहित ड्रॉ खेला था, लेकिन बांग्लादेश के खिलाफ इस प्रदर्शन को दोहराने में सफल रहा। बांग्लादेश को इस ड्रॉ से फायदा हुआ है।

बेल्जियम के ड्रिस मर्टेस ने मेराडोना का रिकॉर्ड तोड़ा

साल्जबर्ग (ऑस्ट्रिया) : बेल्जियम के ड्रिस मर्टेस ने इटली के क्लब नापोली के लिए गोल करने के मामले में महान खिलाड़ी डिएगो मेराडोना को पीछे छोड़ दिया। मर्टेस ने रेड बुल साल्जबर्ग के खिलाफ हुए यूएफा चैंपियंस लीग के मैच में यह कीर्तिमान स्थापित किया। नापोली ने यहां खेले गए टूर्नामेंट के ग्रुप-ई के मैच में साल्जबर्ग को 3-2 से मात दी। मर्टेस ने इस मैच में दो गोल किए। मर्टेस अब नापोली के लिए सबसे ज्यादा गोल करने वाले दूसरे नंबर के खिलाड़ी बन गए हैं। मेराडोना ने नापोली के लिए 116 गोल किए थे। क्लब के लिए सबसे अधिक गोल मारेक हैमसिक (122) ने किए हैं। मर्टेस ने मुकाबले में नापोली को दमदार शुरुआत दिलाई और 17वें मिनट में पहला गोल किया। हालांकि, पहला हाफ समाप्त होने से पहले मेजबान टीम वापसी करने में कामयाब रही। मैच के 40वें मिनट में ईर्लिंग ब्राउट हालैंड ने पेनाल्टी को गोल में बदलकर अपनी टीम को बराबरी दिला दी। मर्टेस ने 64वें मिनट में गोल करके मेहमान टीम की वापसी कराई। साल्जबर्ग ने 72वें मिनट में गोल करके स्कोर को एक बार फिर बराबरी पर ला खड़ा किया। एक मिनट बाद लोरेंजो इनसिग्ने ने गोल किया और मेजबान टीम फिर वापसी नहीं कर पाई। नापोली ग्रुप तालिका में शीर्ष पर कायम है।

लीग बचाने आगे आया अंतरराष्ट्रीय संघ

अभिषेक त्रिपाठी, नई दिल्ली

प्रो वॉलीबॉल लीग

- **वीएफआइ के गैर जिम्मेदाराना रवैये के कारण शुरू नहीं पाया दूसरा सत्र**
- **अंतरराष्ट्रीय संस्था एफआइवीबी के पदाधिकारी 31 अक्टूबर को आएंगे भारत, करेंगे कई मुद्दों पर चर्चा**

सफलतापूर्वक पहला सत्र होने के बाद अधर में अटकी प्रो वॉलीबॉल लीग (पीवीएल) को संयुक्त रूप से कराने वाला भारतीय वॉलीबॉल संघ (वीएफआइ) और बेसलाइन वेंचर्स के बीच हुए मतभेदों को खत्म करने के लिए अंतरराष्ट्रीय वॉलीबॉल संघ (एफआइवीबी) के पदाधिकारी भारत आ रहे हैं जिनसे इस लीग को फिर से शुरू कराने की उम्मीद है।

इस साल फरवरी में पीवीएल का पहला सत्र शुरू हुआ था, लेकिन भारतीय वॉलीबॉल संघ (वीएफआइ) के गैर जिम्मेदाराना रवैये के कारण इस लीग के साथ ही खिलाड़ियों का भविष्य भी अंधकार में पड़ गया। एफआइवीबी का प्रतिनिधिमंडल 31 अक्टूबर को दिल्ली आएगा, जिसमें अंतरराष्ट्रीय संस्था के अध्यक्ष ऐरी एस ग्रेका भी मौजूद रहेंगे। इस बैठक में 11 एजेंडे होंगे, जिसमें पीवीएल के शुरू होने और टीम मालिकों से मिलना भी शामिल है। इसके अलावा भारत में इस खेल को किस तरह से लोकप्रिय बनाया जाए, इस तरह की चीजों पर चर्चा की जाएगी। एफआइवीबी ने वीएफआइ के सचिव और कार्यकारी सदस्यों को ई-मेल के जरिये इस बैठक की जानकारी दी।

बैठक के पहले सत्र में पीवीएल, राष्ट्रीय पुरुष टीम, अंडर-23 टीम, बेसलाइन वेंचर्स पर बातचीत होगी। फिर दूसरे सत्र में एफआवीबी के पदाधिकारियों की पीवीएल के टीम मालिकों से मुलाकात होगी। इससे पहले एक सूत्र ने कहा था कि वीएफआइ के सचिव रामअवतार जाखड़ निजी फायदे के लिए इस लीग की राह रोक रहे हैं। इस लीग को कराने की जिम्मेदारी बेसलाइन वेंचर्स और वीएफआइ की थी और इसके लिए दोनों के बीच 10 साल का करार भी हुआ था, लेकिन जाखड़ लीग के दूसरे सत्र को शुरू करने के लिए सहमति नहीं दे रहे हैं।

दूसरे सत्र के लिए प्रायोजक, टीम के मालिक, खिलाड़ी, प्रसारणकर्ता, एफआइवीबी सभी तैयार हैं, लेकिन जाखड़ तैयार नहीं हैं। पीवीएल के सीईओ जॉय भट्टाचार्य ने लीग के दूसरे सत्र की तारीखों के लिए वीएफआइ के सचिव को इस साल मार्च में ई-मेल लिखकर तारीखें देने का आग्रह किया था। इसमें भट्टाचार्य ने लिखा था कि हम एक या दो फ्रेंचाइजियों को और बढ़ाना चाहते हैं। दो फ्रेंचाइजी पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बंगाल और छत्तीसगढ़ से हो सकती हैं।

फिर इसके बाद भट्टाचार्य ने टीम के मालिकों के साथ बैठक करके खिलाड़ियों को रिटेन करने को लेकर भी ई-मेल किया। खिलाड़ियों की नीलामी की तारीखों की भी जानकारी दी गई।

फेडरर 17वीं बार बासेल टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में

टेनिस डायरी

बासेल, एएफपी : स्विट्जरलैंड के दिग्गज टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर ने राडू एल्बोट पर एकतरफा जीत के साथ 17वीं बार स्विस इंडोर टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। अपने घरेलू टूर्नामेंट में फेडरर की यह लगातार 22वीं जीत है। नौ बार के चैंपियन फेडरर ने 9000 दर्शकों की मौजूदगी में बासेल टूर्नामेंट के प्री-क्वार्टर फाइनल में एल्बोट को 63 मिनट में 6-0, 6-3 से हराया।

दुनिया के पूर्व नंबर एक खिलाड़ी फेडरर क्वार्टर फाइनल में शुक्रवार को स्टेन वावरिंका और फ्रांसेस टियाफो के बीच होने वाले मैच के विजेता से भिड़ेंगे। 38 वर्षीय फेडरर ने कहा, 'मैं बहुत खुश हूं। इस टूर्नामेंट मेरी शुरुआत अच्छी रही है। मैं अभी शानदार खेलता आया हूं। अगर मेरा सामना वावरिंका से होता है तब भी मैं खुश हूं। मुझे उसके खिलाफ खेलना अच्छा लगता है। मैं आगे भी ऐसा ही मुकाबला करना चाहूंगा। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में भी मैं इसी जोश और जज्बे के साथ अपना खेल खेलता रहूंगा। मेरे प्रशंसकों का भी धन्यवाद जिन्होंने हर समय हर परिस्थितियों में मेरा समर्थन किया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि उन्हें मैं कभी निराश नहीं करुंगा।'

मैच जीतने के बाद दर्शकों का अभिवादन करते दिग्गज टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर। एएफपी

नडाल ने अपनी शादी को लेकर कहा, हमने शानदार दिन बिताया

नूर-सुल्तान (कजाखिस्तान), आइएएनएस : स्पेन के दिग्गज टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल का मानना है कि उन्होंने और उनकी पत्नी सिस्का पेरोलो ने अपनी शादी के दिन को अच्छी तरह से बिताया और मेहमान के साथ भी अच्छी तरह से समय व्यतीत किया। 14 साल एक साथ रहने के बाद नडाल ने अपनी बचपन की दोस्त पेरोलो से हाल ही में शादी की थी। उन्होंने गुरुवार को कहा, 'हमने काफी मस्ती की थी जो लोग यहां आए थे, उनके साथ भी हमरा समय अच्छा व्यतीत हुआ। हम लंबे समय से शादी करने के बारे में सोच रहे थे। यह शानदार दिन था। अब मेरा ध्यान सत्र के बचे टूर्नामेंटों पर है।' नडाल यहां एक चैरिटी मैच में नोवाक जोकोविक के खिलाफ खेलेंगे।

विविध

देश की रक्षा में अहम भूमिका अदा करती है आइटीबीपी

ग्रेटर नोएडा स्थित 39वीं वाहिनी में मनाए गए आइटीबीपी के स्थापना दिवस पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री रहे मुख्य अतिथि

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा

ग्रेटर नोएडा में आइटीबीपी के स्थापना दिवस पर करतब दिखाते जवान। राजेश गौतम

अमित शाह की जगह आए किशन रेड्डी

आइटीबीपी के स्थापना दिवस समारोह में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को आना था। हरियाणा विधान सभा चुनाव के परिणाम को लेकर केंद्रीय गृहमंत्री ने अपना ग्रेटर नोएडा दौरा रद कर दिया। वह दिल्ली में पार्टी की बैठकों में व्यस्त हो गए। अमित शाह की जगह केंद्रीय गृह राज्यमंत्री जी किशन रेड्डी समारोह में आए।

भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आइटीबीपी) सभी केंद्रीय पुलिस बलों में काफी अहम भूमिका निभाती है। यह सरहदों पर पिछले 57 वर्षों से देश की सुरक्षा कर रही है। इसके जवान नौ हजार फीट की ऊंचाई पर विषम परिस्थितियों में भी तैनात रहते हैं। इसके साथ ही आपदा के समय में देश के विभिन्न हिस्सों में लोगों की सेवा करते हैं। ये बातें मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने गुरुवार को आइटीबीपी के 58वें स्थापना दिवस पर जवानों को संबोधित करते हुए कहीं। स्थापना दिवस पर ग्रेटर नोएडा स्थित 39वीं वाहिनी में परेड का आयोजन किया गया।

केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि आइटीबीपी ने पंजाब में आतंकवाद को समाप्त करने में अहम भूमिका निभाई थी। यही काम अब जम्मू-कश्मीर में कर रही है। इसके जवानों ने अफगानिस्तान में भारतीय दूतावास के आसपास न जाने कितने आत्मघाती हमलों को नाकाम किया है। आइटीबीपी अमरनाथ यात्रा से लेकर कैलाश मानसरोवर यात्रा में भी अहम भूमिका अदा करती है। इसके जवान विशेष प्रशिक्षण के जरिये चीनी भाषा बोल सकते हैं।

आइटीबीपी के महानिदेशक एसएस देसवाल ने कहा कि बल का गठन वर्ष 1962 में किया गया था। तब से लेकर आज तक जवान चुनौतीपूर्ण सीमा पर देश की रक्षा कर रहे हैं। जवान हिमालय में सजग प्रहरी के तौर पर जिम्मेदारी निभा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में वर्ष 2009 से आज तक कई नक्सलियों के खिलाफ कई सफल ऑपरेशन कर चुके हैं।

वहीं, केंद्रीय राज्य मंत्री ने परेड की सलामी ली। इसमें सभी सीमांत की टुकड़ियों ने भाग लिया। इनमें महिला, कमांडो, स्कीइंग, माउंटेनियरिंग, पैराट्रूपर्स, डॉग स्क्वाइड व अश्वरोही सवार दस्ते शामिल रहे। इस दौरान आइटीबीपी के छह अधिकारियों को वीरता के लिए पुलिस पदक, छह को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक, 24 को सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक और आठ को यूनियन होम मिनिस्टर्स मेडल फॉर एक्सीलेंस इन पुलिस ट्रेनिंग के मेडल से विभूषित किया गया। सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण केंद्र की ट्रॉफी एसटीएस, शिवपुरी (मध्य प्रदेश) ने प्राप्त की। स्वच्छता ट्रॉफी 38वीं वाहिनी, राजनंदगांव को मिली। 13वीं वाहिनी, लिंगडम को सर्वश्रेष्ठ बॉर्डर बटालियन, 26वीं वाहिनी लुधियाना को सर्वश्रेष्ठ नॉन बॉर्डर बटालियन और 38वीं वाहिनी राजनंदगांव को सर्वश्रेष्ठ एएनओ बटालियन घोषित किया गया। इस दौरान बल की वर्षभर की उपलब्धियों की वार्षिक विषेशांक पुस्तिका का भी विमोचन किया गया।

अरुणाचल में चीन के नजदीक 18 सड़कें बनाने का प्रस्ताव पास

जासं, ग्रेटर नोएडा : आइटीबीपी के 58वें स्थापना दिवस पर जवानों को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह राज्यमंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि सरकार अरुणाचल में चीन के नजदीक 18 सड़कें बनाने का प्रस्ताव पास कर चुकी है। इससे आइटीबीपी को काफी मदद मिलेगी।

उन्होंने कहा कि सरकार आइटीबीपी को अधिक शक्तिशाली बनाना चाहती है। अरुणाचल में जो 18 सड़क बनाई जानी हैं, उनकी लंबाई 1607 किलोमीटर होगी। इनको बनाने में 1175 करोड़ रुपये की लागत आएगी। बल को जल्द ही दो हेलीकॉप्टर दिए जाएंगे। ये राशन से लेकर अन्य उपकरणों को दुर्गम स्थान में ले जाने में मदद करेंगे। उन्होंने कहा कि आइटीबीपी के लिए प्राथमिकता के आधार पर विभिन्न सीमाओं में 20 हजार करोड़ रुपये की लागत से 45 नए सड़कें भी बनाए जाने की योजना है। वर्ष 2014 से अब तक लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक 23 नए बॉर्डर आऊटपुट पोस्ट बनाए गए हैं।

हनी ट्रैप की आरोपित श्वेता के लॉकर से 47 लाख नकद और मिले

नईदुनिया, भोपाल

मध्य प्रदेश की सियासत से लेकर ब्यूरोक्रेसी में हड़कंप मचाने वाले बहुचर्चित हनी ट्रैप मामले की एक आरोपित श्वेता विजय जैन के भोपाल स्थित एक लॉकर से पुलिस को 47 लाख रुपये नकद मिले हैं। गुरुवार को खोले गए लॉकर में लाखों रुपये मूल्य के जेवर और कुछ पैन ड्राइव भी मिले हैं। गौरतलब है इससे पहले मंगलवार को भी श्वेता के एक लॉकर से साढ़े 13 लाख बरामद किए गए थे।

- **पैन ड्राइव भी बरामद, कई रसूखदारों की वीडियो रिकॉर्डिंग होने का शक**

बताया जाता है कि इन पैन ड्राइव में कई रसूखदारों की वीडियो रिकॉर्डिंग हो सकती है, जिनके आधार पर हनी ट्रैप से जुड़ी महिलाएं लोगों को ब्लैकमेल करती थीं। इन पैन ड्राइव को एसआइटी ने अपने कब्जे में ले लिया है। सभी पैन ड्राइव को हैदराबाद फॉरेंसिक लैब में जांच के लिए भेजा जाएगा।

मामले की जांच कर रहे विशेष जांच दल (एसआइटी) के सामने अभी इंदौर के इंजीनियर हरभजन सिंह के अलावा कोई दूसरा फरियादी ऐसा नहीं आया है, जिसने इन महिलाओं के खिलाफ शिकायत की हो। जांच एजेंसी ने महिलाओं से लंबी पूछताछ की है, पर अब तक उन लोगों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी, जिन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा था।

बच्चे को बीमार बताकर श्वेता ने मांगी अंतरिम जमानत

हनी ट्रैप मामले में आरोपित श्वेता स्वप्निल जैन की तरफ से इंदौर में सेशन कोर्ट में अंतरिम जमानत के लिए आवेदन प्रस्तुत हुआ। इसमें गुहार लगाई कि आरोपित के बच्चे की तबीयत खराब है और सास भी गंभीर बीमारी से पीड़ित है। ऐसी स्थिति में आरोपित को सात दिन की अंतरिम जमानत पर छोड़ा जाए। अभियोजन की तरफ से एजीपी अभिजीतसिंह राठौर ने जमानत आवेदन पर आपत्ति दर्ज करते हुए तर्क दिया कि अंतरिम जमानत का कोई प्रावधान ही नहीं है। इस पर आरोपित के वकील ने आपत्ति का जवाब देने के लिए समय ले लिया। अब 31 अक्टूबर को सुनवाई होगी। गौरतलब है कि हनी ट्रैप मामले में पुलिस ने छह आरोपितों पर धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोपों में केस दर्ज किया है। सभी आरोपित जेल में हैं।

टूजी घोटाले में सीबीआइ की अपील पर सुनवाई शुरू

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

टूजी स्पेक्ट्रम घोटाले में निचली अदालत के फैसले के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआइ) की याचिका पर गुरुवार को सुनवाई शुरू हुई। सीबीआइ की तरफ एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) संजय जैन ने पैरवी की और मामले में दर्ज एफआइआर व सीबीआइ की तरफ से दाखिल आरोपपत्र को न्यायमूर्ति बृजेश सेठी की पीठ के समक्ष पढ़ा। कुछ समय तक हुई जिरह के बाद पीठ ने सुनवाई को 1 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दिया। आरोपपत्र में सरकारी अधिकारियों, निजी कंपनियों एवं व्यक्तिगत लोगों के बीच टूजी लाइसेंस आवंटन के लिए हुई आपराधिक साजिश का जिक्र किया गया है।

मार्च 2011 में गठित पटियाला हाउस की विशेष सीबीआइ अदालत ने 21 दिसंबर, 2017 को पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा एवं राज्यसभा सदस्य कनीमोझी समेत सभी 17 आरोपितों को बरी कर दिया था। वहीं ईडी द्वारा दर्ज किए गए मनी लांड्रिंग मामले में डीएमके प्रमुख एम करुणानिधि की पत्नी दयालू अम्मल, विनोद गोयनका, आसिफ बलवा, फिल्म प्रोड्यूसर करीम मोरानी, पी. अमृथम, कलाईग्नर टीवी के निदेशक शरद कुमार को बरी किया गया था। निचली अदालत के फैसले को सीबीआइ एवं ईडी ने मार्च 2018 में हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। सीबीआइ का आरोप था कि टूजी स्पेक्ट्रम के आवंटन से कोष को 30984 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था। वहीं, ईडी का आरोप था कि 200 करोड़ रुपये की मनी लांड्रिंग हुई थी।

रॉबर्ट वाड्रा से जुड़े मामले में सुनवाई टली

संवाद सूत्र, जोधपुर : कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा व रॉबर्ट की मां मौरीन वाड्रा से जुड़े मामले में स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी व महेश नागर की याचिका पर राजस्थान हाई कोर्ट में सुनवाई समयाभाव की वजह से नहीं हो पाई। अगली सुनवाई चार नवंबर को होगी। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से एएसजी राज दीपक रस्तोगी व एएएसजी भानु प्रताप बोहरा ने इस मामले में मेरिट पर बहस करने की मांग कोर्ट से की। कोर्ट ने अधिक मामले सूचीबद्ध होने के कारण और पूर्व में कोर्ट द्वारा तारीख दिए जाने का हवाला देते हुए बहस करवाने से इन्कार कर दिया। वाड्रा की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक चार नवंबर तक बढ़ गई है।

जस्टिस मनोज कुमार गर्ग की कोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन अन्य मामलों के चलते सुनवाई नहीं हुई। इस पर एएसजी राज दीपक रस्तोगी ने कड़ी आपत्ति जताई।

अयोग्य करार विधायकों की बात सुनने को तैयार हैं विस अध्यक्ष

नई दिल्ली, प्रेट्र : कर्नाटक विधानसभा अध्यक्ष ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि उन्हें अपने पूर्ववर्ती केआर रमेश कुमार द्वारा अयोग्य ठहराए गए 17 विधायकों की सुनवाई करने में कोई कठिनाई नहीं है और वह मुद्दे पर नए सिरे से विचार कर सकते हैं। राज्य में कांग्रेस-जदएस सरकार गिराने के लिए जवाबदेह 17 विधायकों को पूर्व विस अध्यक्ष ने अयोग्य ठहरा दिया था। विश्वास मत हारने के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री कुमारस्वामी को इस्तीफा देने पड़ा और उसके बाद वहां भाजपा सरकार बनी। शीर्ष कोर्ट ने दलबदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य ठहराए जाने को चुनौती देने वाली विधायकों की याचिका पर सुनवाई शुक्रवार तक टाल दी।

कर्नाटक विधानसभा अध्यक्ष की ओर से पेश सालिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जस्टिस एनवी रमण की अध्यक्षता वाली पीठ से कहा कि संविधान की योजना के तहत विधायक के पास इस्तीफा देने का अधिकार है विधानसभा अध्यक्ष उसे स्वीकार करेंगे। विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष वी. हेगडे कागेरी हैं। सुनवाई कर रही पीठ में जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस कृष्ण मुरारी भी शामिल हैं।

शीर्ष कोर्ट अयोग्य ठहराए गए 17 विधायकों की याचिका पर सुनवाई कर रहा है। बहस के दौरान कुमारस्वामी की ओर से पेश वकील राजीव धवन ने पीठ के सामने मुद्दा उठाया कि विधायक द्वारा पेश इस्तीफा शुद्ध नहीं हो तो क्या विधानसभा अध्यक्ष उसे नजरअंदाज कर सकता है? उन्होंने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष के पास इस्तीफे के पीछे की मंशा क्या है उसे देखने का अधिकार है।

मौसम विशेष

पंजाब, राजस्थान, हरियाणा व दिल्ली में हल्की हवाओं तथा छिटपुट बादलों के साथ शीतल सुबह में धुंध रहेगी। दिन आरामदायक बना रहेगा। प्रदूषण में हल्की वृद्धि जारी रहेगी। रात का मौसम शीतल रहेगा। जम्मू-कश्मीर व हिमाचल प्रदेश में सुबह ठंडी और दिन सहज रहेगा।

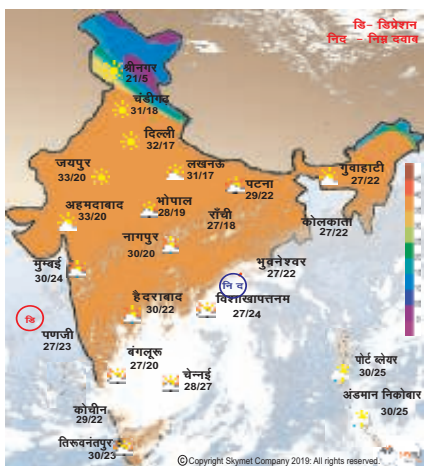

भारत के मुख्य शहरों का तापमान:

शहर		शहर	
मुम्बई	29/24/ध	अहमदाबाद	32/17/ध
कोलकाता	30/23/स्ना	बड़ौदा	30/22/ध
चेन्नई	33/25/ध	नागपुर	31/20/ध
हैदराबाद	31/22/ध	इन्दौर	26/19/स्ना
बंगलूरु	28/20/स्ना	रांची	27/23/स्ना
त्रिवेन्द्रम	31/23/ध	पटना	32/22/स्ना
गुवाहाटी	29/21/ध	जमशेदपुर	32/25/ध
गंगटोक	12/-2/ध	पुणे	29/21/ध

राष्ट्रीय संस्करण

दैनिक जागरण

शुक्रवार 25 अक्टूबर 2019

आजकल

16

www.jagran.com

देश के पहले आम चुनावों की प्रक्रिया का किया गया श्रीगणेश

आजादी के बाद भारत में लोकतंत्र की स्थापना के लिए 1951 में आज ही चुनावी प्रक्रिया शुरू हुई जो फरवरी 1952 तक चली। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू के नेतृत्व में 4500 सीटों पर चुनाव हुए। इनमें लोकसभा की 489 और बाकी सीटें राज्य विधानसभाओं की थी।

अंतरिक्ष यान डिस्कवरी सकुशल धरती पर लौटा

2000 में नासा द्वारा अंतरिक्ष में भेजा अंतरिक्ष यान एसटीएस-92 डिस्कवरी 13 दिन के मिशन के बाद आज ही सकुशल धरती पर वापस लौटा। इसमें एक पायलट और एक कमांडर के अलावा पांच मिशन विशेषज्ञ सवार थे। इसका वजन 11.5 लाख किग्रा था।

चित्रकारी की दुनिया के जादूगर थे पाब्लो पिकासो

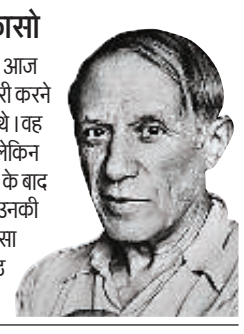

दुनिया के इस सबसे मशहूर चित्रकार का जन्म 1881 में आज ही स्पेन के मलागा में हुआ। किशोरावस्था से ही चित्रकारी करने लगे। सेरेमिक आर्टिस्ट, कवि और स्टेज डिजाइनर भी थे। वह चित्रकारी में उच्च स्तर की शिक्षा लेने के लिए मेड्रिड अकादमी गए लेकिन पढ़ाई बीच में छोड़कर स्पेन आ गए। 1900 में पेरिस से स्पेन लौटने के बाद उन्होंने कई व्यंग्यात्मक और महिलाओं की अद्भुत तस्वीरें बनाई। उनकी सबसे चर्चित पेंटिंग रहस्यमयी तरीके से मुस्कुराती महिला मोनालिसा की है। आज उनकी हर एक पेंटिंग की कीमत करोड़ों रुपये है। आठ अप्रैल 1973 को फ्रांस में उनका निधन हुआ।

इधर-उधर की

रोम में बिल्लियों ने बचाई मालिक की जान

रोम, एजेंसी : जानवरों के विशिष्ट गुणों में से एक उनमें पूर्वाभास की क्षमता का होना भी है। किसी बड़ी आपदा, घटना के घटित होने से पहले ही वे उसे भांप लेते हैं और उसकी आहट से लोगों को वाकिफ करने के लिए अजीब हरकतें करने लगते हैं। रोम के कैंपो लिग्योर में रहने वाला एक परिवार अपनी पालतू बिल्लियों की इस खूबी का कायल हो गया है। इस परिवार के पास सिंबा और मोस नामक दो बिल्लियां हैं। रात में पूरा परिवार सो रहा था। जोरदार बारिश हो रही थी। इसी दौरान अपनी अप्रत्याशित हरकतों से इन बिल्लियों ने परिवार को जगा दिया। बाहर की दीवार से गिरते प्लास्टर ने परिवार को किसी अनहोनी की आशंका लगी। वे सब तुरंत बाहर आए। दरअसल तेज बारिश से भूस्खलन हुआ था, जो बस्ती के कई घरों को लीलता हुआ आगे बढ़ रहा था। यह परिवार बिल्लियों के जगाने पर निकल भागा लेकिन घर के बाहर कीचड़ में फंस गया। हालांकि बाद में राहत और बचावकर्मियों ने इन्हें सकुशल बाहर निकाल लिया।

आविष्कार ▶ ब्रिटेन के वैज्ञानिकों को खास डिवाइस विकसित करने में मिली सफलता

'कृत्रिम पत्ती' से तैयार होगी साफ गैस

गैस से पेट्रोल के वैकल्पिक ईंधन को बनाने में मिलेगी मदद

प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से प्रेरित है यह डिवाइस। प्रतीकात्मक

लंदन, प्रेट्र : दुनिया में आबादी बढ़ने के साथ वाहनों का प्रयोग भी लगातार बढ़ता जा रहा है। इससे जीवाश्म ईंधन की खपत तेजी से हो रही है और प्रदूषण में भी इजाफा हो रहा है। दुनियाभर के वैज्ञानिक इसका विकल्प तलाशने का प्रयास कर रहे हैं। इस कड़ी में ब्रिटेन के वैज्ञानिकों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल, उन्होंने एक ऐसी 'कृत्रिम पत्ती' डिवाइस विकसित कर ली है, जिसके जरिये ऐसी साफ गैस तैयार की जा सकती है, जो वर्तमान में जीवाश्म ईंधन से ही बनाई जाती है। ऐसी गैस का वर्तमान में व्यापक स्तर पर प्रयोग किया जा रहा है। वैज्ञानिकों का दावा है कि इस गैस के जरिये ऐसा स्थाई तरल ईंधन तैयार किया जा सकता है जो भविष्य में पेट्रोल का विकल्प बन सकता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक, यह डिवाइस सूरज की रोशनी से गैस तैयार करती है।

वैज्ञानिकों के अनुसार, यह डिवाइस कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के जरिये बेहद आसान तरीके से साफ गैस तैयार कर सकती है। यह सौर ईंधन के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित हो सकता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक, इस प्रक्रिया से सिनगैस निकलती है।

ब्रिटेन स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ कैंब्रिज के शोधकर्ताओं द्वारा तैयार इस डिवाइस के बारे में नेचर मैटेरियल्स नामक जर्नल में विस्तार से प्रकाशित किया गया है। इसमें बताया गया है कि यह 'कृत्रिम पत्ती' डिवाइस सूरज की रोशनी से ऊर्जा प्राप्त करती है। हालांकि, यह दिन में बादलों की मौजूदगी में भी काम करने में समक्ष है।

प्रदूषण होगा कम : वर्तमान में प्रयोग होने वाले ईंधन से निकलने वाली गैसें वातारण को प्रदूषित भी करती हैं। वैज्ञानिकों का दावा है कि उनकी डिवाइस से तैयार सिनगैस वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त नहीं करती है। इससे प्रदूषण को कम करने में भी मदद मिलेगी। इस गैस का प्रयोग कई चीजों जैसे ईंधन, दवाओं, प्लास्टिक और उर्वरक तैयार करने में किया जाता है। कैंब्रिज में प्रोफेसर इरविन रीसनर के मुताबिक, हो सकता है कि आपने सिनगैस के बारे में न सुना हो, लेकिन इसकी मदद से रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं का उपभोग अवश्य करते होंगे। हमने जो खोज की है उसके जरिये वैश्विक कार्बन चक्र को बंद किया जा सकता है। बकौल रीसनर, यह डिवाइस प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से प्रेरित है, जो एक कुदरती प्रक्रिया है। इसमें पेड़-पौधे सूरज की रोशनी का इस्तेमाल कर कार्बन डाइऑक्साइड से खाना बनाते हैं।

इस तरह करती है काम

वैज्ञानिकों के मुताबिक, इस कृत्रिम पत्ती में दो प्रकाश अवशोषक लगाए गए हैं, जो पौधों में मौजूद अणुओं के समान काम करते हैं। इसमें एक उत्प्रेरक का प्रयोग किया गया है। जब यह डिवाइस पानी में डाली जाती है तो इसका एक प्रकाश अवशोषक उत्प्रेरक का प्रयोग कर ऑक्सीजन उत्पन्न करता है। वहीं, दूसरा अवशोषक रासायनिक क्रिया करता है। शोधकर्ताओं ने पाया कि इस डिवाइस के प्रकाश अवशोषक कम रोशनी में भी कार्य करने में सक्षम है। इस अध्ययन के मुख्य लेखक व पीएचडी छात्र विर्जिल आंद्रेई के मुताबिक, इसका मतलब यह है कि इस डिवाइस का प्रयोग केवल उन देशों में नहीं होगा, जहां मौसम अमूमन गर्म रहता है और न ही इसका इस्तेमाल केवल गर्मी के मौसम तक सीमित रहेगा। इसे आप बादलों की मौजूदगी में और दुनिया के किसी भी देश में इस्तेमाल कर सकते हैं।

फिल्म रिव्यू

मेड इन चाइना

मुख्य कलाकार : राजकुमार राव, मौनी रॉय, सुमीत व्यास, परेश रावल, बमन ईरानी, गजराव राव, अमायरा दस्तूर
निर्देशक : मिखिल मुसाले
अवधि : 2 घंटे 8 मिनट

'बैंड बाजा बारात', 'गुरु' जैसी कई फिल्में हैं, जो एक आम इंसान के बिजनेस की दुनिया का खिलाड़ी बनने की कहानियों को दर्शा चुकी हैं। उसी तर्ज पर है फिल्म 'मेड इन चाइना'। गुजराती फिल्म 'रॉन्ग साइड राजू' के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीत चुके मिखिल मुसाले ने इसका निर्देशन किया है। कहानी गुजरात की पृष्ठभूमि पर रची गई है। फिल्म की शुरुआत होती है ग्लोरियस गुजरात के लिए रखे गए इंडो-चाइना कल्चरल समारोह में चीन से आए जनरल की मौत से, जो सूप पीने से होती है। कहानी बढ़ती है रघुवीर मेहता (राजकुमार राव) की ओर, जो बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहता है। उसके परिवार में पत्नी रुक्मिणी (मौनी रॉय) और एक बेटा हैं। रघुवीर के बड़े पापा (मनोज जोशी) और भाई वनराज (सुमीत व्यास) अमीर बिजनेसमैन हैं, जो रघुवीर के बेटे की स्कूल फीस भरने में मदद करते हैं। रघु कई बिजनेस में हाथ आजमा चुका है, लेकिन असफलता ही हाथ लगी है। वह बिजनेस सिखाने वाले स्पीकर चोपड़ा (गजराज राव) के वीडियोज का फैन है। एक दिन वनराज उसे चीन लेकर जाता है। वहां एक डील के सिलसिले में उसकी मुलाकात सफल बिजनेसमैन तन्मय शाह (परेश रावल) से होती है। रघुवीर को तन्मय शाह से सफलता का मंत्र मिल जाता है। चीन में ही उसकी मुलाकात एक चीनी बिजसनेसमैन से होती है, जो सेक्स पावर बढ़ाने की दवा बेचता है। भारत लौटकर रघुवीर उस दवा की मदद से एक ऐसा सूप बनाता है, जो पौरुष शक्ति बढ़ाने में कारगर होता है। इसे बेचने के लिए वह सेक्सोलॉजिस्ट डॉ. वर्दी (बमन ईरानी) की मदद लेता है। यह बिजनेस उसे किस ओर लेकर जाता है, कहानी उसी पर आगे बढ़ती है।

फिल्म की शुरुआत अच्छी हुई है, लेकिन चीन से लौटने के बाद कहानी रघुवीर के बिजनेसमैन बनने के सपने से भटकते हुए सेक्स एजुकेशन की ओर बढ़ जाती है। नामी डॉक्टर वर्दी का बिना दवाई की जांच किए उसे अपने क्लीनिक में बेचने के लिए तैयार हो जाना गैरजिम्मेदाराना लगता है।

फिल्म की कमजोर और बिखरी हुई स्क्रिप्ट को राजकुमार राव ने अपने अभिनय से संभालने की कोशिश की है। मौनी रॉय खूबसूरत लगी हैं। छोटे से किरदार में परेश रावल अपनी छाप छोड़ते हैं। गजराज राव के किरदार को लेखक ठीक से गढ़ नहीं पाए। मनोज जोशी और सुमीत व्यास अपने किरदारों में जंचे हैं, पर उन्हें स्क्रीन पर जगह कम मिली है। फिल्म के कुछ संवाद, जैसे- 'सपना सेवपुरी नहीं होता है, उसे सस्ता मत समझो। जो अपने सपने को सस्ता समझते हैं, वह भेड़ बन जाते हैं', 'बिजनेस नहीं आसान इतना समझ लीजिए, आग का दरिया है और आपको स्कूबा डाइविंग करके जाना है' सुनने में दिलचस्प लगते हैं। 'ओढ़नी...' और 'सनेड़ो...' गाना फिल्म में गुजराती फ्लेवर बनाए रखने में मदद करते हैं।

-प्रियंका सिंह

★★★★★ उत्कृष्ट ★★★★ बहुत अच्छी ★★★ अच्छी ★★ औसत ★ औसत से कम

मुद्दे से भटकती कहानी

शोध अनुसंधान

टीबी की जांच का तेज और सटीक तरीका ईजाद

वैज्ञानिकों ने टीबी की जांच का तेज और सटीक तरीका ईजाद किया है। खून में चार प्रोटीन और एंटी-टीबी एंटीबॉडी के स्तर को आधार बनाते हुए इस जांच को विकसित किया गया है। इस जांच से शरीर में सक्रिय टीबी यानी एटीबी का पता लगाया जा सकेगा। एटीबी वह स्थिति होती है, जब शरीर में टीबी के बैक्टीरिया सक्रिय हो जाते हैं। दुनिया में एक करोड़ से ज्यादा लोग इससे पीड़ित हैं। हर साल 10 लाख से ज्यादा लोगों की इससे मौत हो जाती है। वैज्ञानिकों ने कहा कि टीबी के ज्यादातर मरीज अपेक्षाकृत कम संसाधन वाले देशों में है। इन देशों में बीमारी की जांच बड़ी समस्या है। जांच के कई तरीकों में महंगे उपकरणों की जरूरत होती है, जिनकी व्यवस्था इन देशों के लिए मुश्किल है। वहीं जांच के इस नए तरीके से मात्र दो डॉलर (करीब 140 रुपये) में 30 मिनट के भीतर ही नतीजा मिल सकता है। - प्रेट्र

मांसपेशियों को कमजोर बनाती है विटामिन डी की कमी

विटामिन डी की कमी से हड्डियां ही नहीं मांसपेशियां भी कमजोर होती हैं। ताजा शोध के मुताबिक, 60 साल या इससे ज्यादा उम्र के लोगों में विटामिन डी की कमी से मांसपेशियों की गतिविधि पर असर पड़ता है। बड़ी उम्र में सही से चलने-फिरने और अन्य कार्यों को करने में सक्षम बने रहने में मांसपेशियों की अहम भूमिका रहती है। शोध में पाया गया कि जिन लोगों के शरीर में विटामिन डी कम होता है, उनमें मांसपेशियों के कमजोर होने की आशंका 40.4 फीसद तक रहती है। वहीं विटामिन डी की मात्रा पर्याप्त होने की स्थिति में यह आशंका आधी रह जाती है। मांसपेशियों की गतिविधियों में गड़बड़ी का संबंध भी विटामिन डी की कमी से पाया गया। वैज्ञानिकों का कहना है कि आमतौर पर मांसपेशियों की कमजोरी को नजरअंदाज कर दिया जाता है। विटामिन डी से इसका संबंध सामने आने से इस ओर भी लोग ध्यान देने के लिए प्रेरित होंगे। - एएनआइ

हैकर्स का हथियार बन सकते हैं स्मार्ट बल्ब, खरीदारी में बरतें सावधानी

रहें सतर्क

- भारतीय मूल के शोधकर्ताओं के अध्ययन में आया सामने
- स्मार्ट बल्ब के जरिये चुराई जा सकती हैं निजी जानकारियां

न्यूयार्क, आइएएनएस : त्योहारी सीजन में बाजार में उच्च तकनीक वाले तरह-तरह के रोशनी के सामान आ रहे हैं। इन्हीं में शुमार स्मार्ट बल्ब भी ग्राहकों को बहुत लुभा रहे हैं, लेकिन इनका प्रयोग करने में जरा सावधान रहें। ये स्मार्ट बल्ब आपकी निजी जानकारियां चुरा सकते हैं। भारतीय मूल के शोधकर्ता के एक अध्ययन से सामने आया है कि हैकर्स का अगला मुख्य हथियार स्मार्ट बल्ब हो सकता है। कुछ स्मार्ट बल्ब बिना स्मार्ट होम हब के ही होम नेटवर्क से जुड़ जाते हैं। स्मार्ट होम हब एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है, जिसके माध्यम से घर की सारी ऑटोमैटिक चीजें जुड़ी होती हैं।

अमेरिका के सैन एंटोनियो में टेक्सास यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और इस अध्ययन के प्रमुख लेखक मुर्तुजा जडलीवाला के मुताबिक, स्मार्ट बल्ब इंफ्रारेड क्षमताओं से लैस हो सकता है और अधिकांश उपयोगकर्ता यह नहीं जानते हैं कि अदृश्य तरंग स्पेक्ट्रम को नियंत्रित किया जा सकता है। इससे हैकर्स उन लाइट का दुरुपयोग कर सकते हैं। हैकर्स इंफ्रारेड लाइट को नियंत्रित कर कोई भी कमांड भेज सकते हैं। वे या तो आपके कंप्यूटर से डाटा चोरी कर सकते हैं या स्मार्ट होम हब से जुड़े अन्य उपकरणों को खराब कर सकते हैं। शोधकर्ताओं के मुताबिक, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आपको हैकिंग का पता भी नहीं चलेगा और सारा डाटा हैक हो गया है। अमूमन हम यही मानते हैं कि हमारा डाटा इंटरनेट के माध्यम से हैक हो सकता है। इससे बचने के लिए अच्छे एंटी वायरस, अन्य टूल्स व सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं, लेकिन अगर स्मार्ट बल्ब की तरंगों के जरिये ही हैकिंग कर ली जाए तो इसका पता ही नहीं चल पाएगा।

इस वर्ष के शुरुआत में ही अमेजन इको उस समय सुर्खियों में आया था, जब यह बताया गया था कि इसके माध्यम से उपभोक्ताओं की बातचीत को हजारों कर्मचारियों द्वारा रिकॉर्ड किया गया और सुना गया। अब शोधकर्ताओं को स्मार्ट लाइट में आपकी जानकारी चुराने के सुराग का पता चला है। पिछले वर्ष स्मार्ट लाइट का वैश्विक कारोबार आठ अरब डॉलर का था। अगले दस सालों में इसके 28 अरब डॉलर तक बढ़ जाने की उम्मीद है।

पोलियो वायरस के एक और प्रकार का पूरी तरह खात्मा

लंदन, रायटर : विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने विशेषज्ञ पैनल की रिपोर्ट के आधार पर पोलियो वायरस के एक और प्रकार के पूरी तरह खत्म होने की घोषणा की है। इस उपलब्धि को ऐतिहासिक बताते हुए डब्ल्यूएचओ ने जल्द ही विश्व के पोलियो मुक्त होने की उम्मीद जताई है। डब्ल्यूएचओ पोलियो वायरस को दो वर्गों में रखता है। इनमें एक वाइल्ड पोलियो वायरस है और दूसरा नॉन वाइल्ड पोलियो वायरस। घातक वाइल्ड पोलियो वायरस भी तीन तरह का है। इनमें से अब दो का खात्मा हो चुका है।

ग्लोबल कमीशन फॉर द सर्टिफिकेशन ऑफ पोलियो इरैडिकेशन ने पिछले हफ्ते वाइल्ड पोलियो वायरस टाइप-3 (डब्ल्यूपीवी-3) पर पूरी तरह काबू पाए जाने की जानकारी दी थी। इस वायरस के संक्रमण का आखिरी मामला 2012 में नाइजीरिया में सामने आया था। डब्ल्यूएचओ के अनुसार, डब्ल्यूपीवी-2 का उन्मूलन 2015 में ही हो गया था। लेकिन डब्ल्यूपीवी-1 के संक्रमण के मामले अफगानिस्तान और पाकिस्तान में अब भी सामने आ रहे हैं। इन तीनों ही तरह के वायरस से लकवा और जान का खतरा बना रहता है।

मस्तिष्क में अल्जाइमर के संकेतकों का लगाया पता

नई दिल्ली, आइएसडब्ल्यू : भारतीय वैज्ञानिकों ने मस्तिष्क में अल्जाइमर के प्रमुख संकेतकों का पता लगाया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इनके बारे में जानकारी होने से हम अल्जाइमर में एंटीऑक्सीडेंट की भूमिका का पता लगाने के साथ-साथ इस बीमारी को बढ़ने से रोक सकते हैं। अल्जाइमर धीरे-धीरे व्यक्ति की याददाश्त को प्रभावित करता है। विश्व के लाखों लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं। भारत में भी बुजुर्गों की बढ़ती आबादी के लिए यह एक बड़ी बीमारी बन रही है। वर्तमान में इसका कोई इलाज उपलब्ध नहीं है, इसलिए शुरुआती चरणों में ही इसका निदान बेहतर प्रबंधन में मदद कर सकता है। मस्तिष्क में एंटीऑक्सीडेंट की भूमिका का पता लगाने के लिए वैज्ञानिक शक्तिशाली इमेजिंग विधियों का प्रयोग करते हैं।

भविष्य की इलेक्ट्रिक कार

प्रमुख कार निर्माता कंपनी टोयोटा ने जापान की राजधानी टोक्यो में आयोजित मोटर शो में भविष्य की इलेक्ट्रिक कार एलएफ-30 का मॉडल प्रदर्शित किया। विंग दरवाजों के साथ एलएफ-30 को फ्यूचरिस्टिक लुक के साथ डिजाइन किया गया है। इसकी आंतरिक साज-सज्जा भी बेहद खूबसूरत है। कंपनी की पहली बीइवी (बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन) को अगले साल बाजार में उतारने की योजना है। फिलहाल कंपनी ने इंजन से जुड़ी कोई जानकारी नही दी है। रायटर

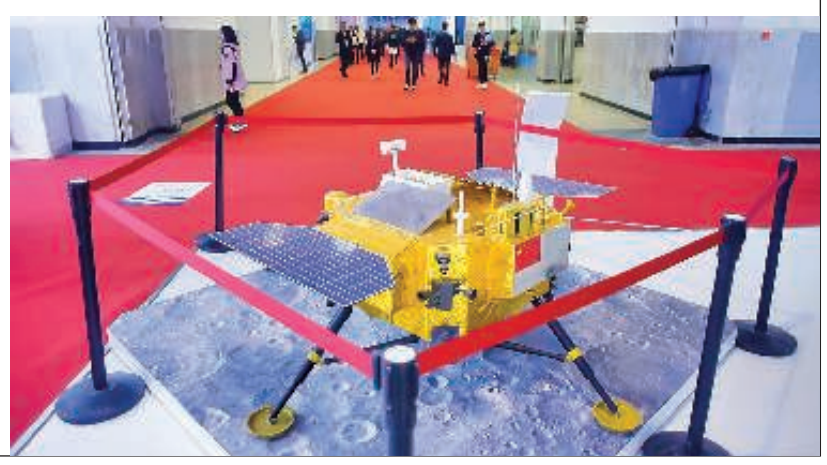

चीन ने दिखाया चांग-4 का मॉडल

चीन की राजधानी बीजिंग में इंटरनेशनल हाईटेक एक्सो में चांग-4 का मॉडल पेश किया गया। चीन ने चंद्रमा के सुदूर क्षेत्र में चांग-4 की सफलतापूर्वक लैंडिंग की थी। इसका नाम चाइना की चंद्रदेवी के नाम पर रखा गया है। इस मॉडल को देखने के लिए खास तौर से यहां छात्रों की भीड़ उमड़ रही है। एएफपी

स्क्रीन शॉट

'महाभारत' में द्रौपदी बनेंगी दीपिका पादुकोण

महाभारत पर टीवी धारावाहिक बन चुके हैं, जिन्हें श्रीकृष्ण के नजरिये से दर्शाया गया है। अब फिल्म निर्माता मधु मंतेना 'महाभारत' फिल्म का निर्माण करने जा रहे हैं, जिसे द्रौपदी के नजरिये से बानाया जाएगा। दो या अधिक भागों में बनने वाली इस फिल्म में दीपिका पादुकोण द्रौपदी की भूमिका निभाएंगी। द्रौपदी बनने को लेकर दीपिका खासी उत्साहित हैं। उनके मुताबिक, 'महाभारत को पौराणिक कथाओं और सांस्कृतिक प्रभाव के लिए जाना जाता है। जीवन के कई सबक हमें महाभारत से मिले हैं, जो पुरुषों के दृष्टिकोण से रहे हैं। इसे नए दृष्टिकोण के साथ समझना बहुत महत्वपूर्ण होगा।' फिल्म का पहला भाग वर्ष 2021 में दिवाली पर रिलीज करने की योजना है। दीपिका फिल्म निर्माता मधु मंतेना के साथ सह-निर्माण भी करेंगी। मधु मंतेना का कहना है, 'पौराणिक कहानी को फिर से दिखाना बड़ी जिम्मेदारी है। दीपिका अगर इस फिल्म का हिस्सा नहीं बनतीं, तो हम इसे इतने महत्वाकांक्षी स्तर पर नहीं बनाते। हम जल्द ही इस फिल्म से जुड़ी बाकी क्रिएटिव टीम की घोषणा करने के लिए तत्पर हैं।' अगले साल दीपिका फिल्म 'छपाक' और '83 में नजर आएंगी।

'दबंग 3' की वजह से 'राधे' के एलान में हुई देरी : सलमान खान

सलमान खान 'दबंग 3' के बाद फिल्म 'राधे' में भी पुलिस अधिकारी की भूमिका में नजर आएंगे। संजय लीला भंसाली की फिल्म 'इंशाल्लाह' बंद होने के बाद सलमान ने ट्वीट किया था कि वह ईद पर जरूर मिलेंगे। अब उनकी फिल्म 'राधे' ईद पर रिलीज होगी। बुधवार को मुंबई में 'दबंग 3' के ट्रेलर लांच पर सलमान ने कहा कि 'दबंग 3' और 'राधे' दोनों ही पुलिस अधिकारी के इर्दगिर्द गढ़ी गई फिल्में हैं। अगर राधे का एलान पहले कर दिया जाता तो 'दबंग 3' कहीं न कहीं पीछे छूट जाती। 'दबंग 3' पर फोकस बनाए रखने के लिए 'राधे' के एलान में देरी की गई।' राधे को 'वांटेड' से जोड़कर देखा जा रहा था। इस पर सलमान ने स्पष्ट किया कि यह किसी फिल्म की सीक्वल नहीं है। अभिनेता महेश मांजरेकर की बेटी सई मांजरेकर 'दबंग 3' में सलमान के साथ डेब्यू कर रही हैं। सोनाक्षी सिन्हा ने 2010 में आई 'दबंग' से अपने फिल्मी करियर का आगाज किया था। 'दबंग 3' का निर्देशन प्रभु देवा कर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने सलमान को 'वांटेड' में निर्देशित किया था।

पुरुष का किरदार मिलेगा, तो वह भी करेंगी भूमि

अभिनेत्री भूमि पेडणेकर जल्द ही आयुष्मान खुराना की फिल्म 'बाला' में नजर आएंगी। फिल्म में अपने रोल की वजह से भूमि को लोगों की आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। इन आलोचनाओं के बाद भूमि ने कहा है कि लोगों को फिल्म देखने के बाद ही समझ आएगा कि उनका किरदार आखिर है क्या? अभी से आलोचना का कोई फायदा नहीं है। फिल्म का ट्रेलर आने के बाद से ही भूमि को अपने सांवले अपीयरेंस की वजह से सोशल मीडिया पर आलोचनाओं का शिकार होना पड़ रहा है। भूमि का कहना है, 'फिल्म में किसी भी तरह से डार्क स्किन का मजाक नहीं बनाया गया है। बल्कि हमने समाज में व्याप्त गोरे रंग का मिथ तोड़ने का प्रयास किया है। हमारे देश में लोगों का फेयर स्किन के लिए पागलपन है। फिल्म में समाज की इसी सोच को सामने लाने का प्रयास किया गया है।' भूमि कहती हैं, 'मैं देख रही हूं कि मेरी फिल्म 'सांड की आंख' को लेकर भी फालतू की आलोचना की जा रही है। मैं नहीं सोचती कि सही और गलत कुछ होता है। मैं एक एक्टर हूं, इसलिए मैं कई सारे किरदार निभा सकती हूं। अगर ऐसा नहीं होता तो 'दम लगा के हईशा' में मैं नहीं होती, मेरी जगह कोई और वह रोल करता।' अपनी डेब्यू फिल्म 'दम लगा के हईशा' के लिए भूमि ने 30 किलो वजन बढ़ाया था। इसी तरह उन्हें 'सांड की आंख' में बूढ़ी शूटर का किरदार निभाने के लिए जटिल प्रोस्थेटिक मेकअप प्रक्रिया से गुजरना पड़ा। भूमि कहती हैं, 'मेरी सारी फिल्में एक-दूसरे से अलग हैं। अगर मुझे एक पुरुष का किरदार निभाना पड़ेगा तो वह भी निभाऊंगी।

हीरो की मौजूदा इमेज को चुनौती दे रहे हैं नवाज

अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी संजीदा किस्म की भूमिकाओं के लिए जाने जाते हैं। पहली बार वह कॉमेडी फिल्म 'मोतीचूर चकनाचूर' में अपनी छवि से अलग दिखाई देंगे। नवाज कहते हैं, 'इस फिल्म की स्टोरी मुझे रोचक लगी, इसलिए मैं इस फिल्म से जुड़ा। मुझे खुशी है कि फिल्म ने बॉलीवुड में हीरो की स्टीरियोटाइप इमेज को चुनौती दी है। हम लोग मानते आए हैं कि हीरो लंबा, गोरा और हैंडसम होता है। लेकिन मैं हीरो तो हूं, पर न तो लंबा हूं, न ही गोरा। अंग्रेजी भी मुश्किल से बोल पाता हूं। लोगों को फार्मूला फिल्में भी पसंद आती हैं, जिनमें चार गाने हों, थोड़ी कॉमेडी हो और हैप्पी एंडिंग हो। सिर्फ बजट और लोकेशन बदल गए हैं। पहले शादियां स्विटजरलैंड में होती थीं और अब मेरठ और लखनऊ में हो रही हैं। मैंने 'मोतीचूर चकनाचूर' को कमर्शियल होने के कारण हां कहा था।'

अध्ययन

6.6 करोड़ साल पहले हुई थी सामूहिक विनाश की घटना, पृथ्वी के वातावरण में बढ़ गई थी सल्फर की मात्रा, जिससे महासागर भी हुए थे प्रभावित

उल्कापिंडों के गिरने से अम्लीय हुए थे महासागर

प्रतीकात्मक

वाशिंगटन, प्रेट्र : 6.6 करोड़ साल पहले पृथ्वी में उल्कापिंडों के गिरने से हुई सामूहिक विनाश की घटना में कई जीव-जंतुओं का समूल नाश हो गया था। इस दौरान पृथ्वी के वातावरण में सल्फर की मात्रा बढ़ गई थी, जिससे यहां के महासागर और ज्यादा अम्लीय हो गए थे। एक नए अध्ययन में शोधकर्ताओं ने यह दावा किया है।

अमेरिका की येल यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने कहा, 'लाखों साल पहले अंतरिक्ष से अत्यधिक मात्रा में उल्कापिंड़ों के गिरने से पृथ्वी के लगभग तीन चौथाई जीव-जंतु और वनस्पतियां विलुप्त हो गई थीं। साथ ही इन उल्कापिंडों से निकली सल्फर गैस पूरे वातावरण में फैल गई थी। इसी कारण महासागरों का पानी भी अम्लीय हो गया था।'

पीएनएएस नामक जर्नल में प्रकाशित अध्ययन में बताया गया है कि 'क्रेटेशियस-पेलोजीन' यानी सामूहिक विनाश का संबंध महासागरों के पीएच स्तर में तेज गिरावट से है, जो इस बात को और पुख्ता करता है कि इसी कारण समुद्र का पानी अम्लीय हो गया था। माना जाता है कि क्रेटेशियस-पेलोजीन के बाद सैकड़ों जीव पृथ्वी से विलुप्त हो गए थे। सूक्ष्म रूप में इसे 'के-पीजी विलुप्ति' भी कहा जाता है।

ऐसे किया अध्ययन : इस अध्ययन के लिए शोधकर्ताओं ने के-पीजी विलुप्ति की घटना से पहले के प्लैंकटन के जीवाश्मों की रासायनिक संरचना का विश्लेषण किया और बाद में समुद्री पर्यावरण में आए बदलावों का डाटा तैयार किया। प्लैंकटन उन जीवों को कहते हैं जो जलधारा द्वारा प्रवाहित होते रहते हैं। ये जीव समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र का अहम हिस्सा होते हैं।

समुद्री जीव हुए थे प्रभावित: इससे पहले अध्ययन में पाया गया था कि कुछ समुद्री जीवों का सामूहिक विनाश की घटना के दौरान सफाया हो गया था। इन जीवों बाहरी आवरण कैल्शियम कार्बोनेट यानी कैल्सीफायर से बना हुआ था। नए अध्ययन में यह दावा किया गया है ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि समुद्र का पानी बहुत ज्यादा अम्लीय हो गया था। शोधकर्ताओं के अनुसार, यह एक महत्वपूर्ण खोज है क्योंकि ये कैल्सीफायर समुद्री खाद्य शृंखला का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और आज भी हमारे पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए हुए हैं।

दूर होंगे मतभेद : शोधकर्ताओं ने कहा, 'नए निष्कर्ष सामूहिक विनाश की घटना के दौरान समुद्र में अम्लीकरण के परिणामों के बारे में मौजूदा दो सिद्धांतों के बीच के अंतर को स्पष्ट करते हैं। स्ट्रेंजेलोव ओशियन सिद्धांत के मुताबिक, के-पीजी घटना के बाद सागर मृत हो गया था और इसमें कार्बन पोषक तत्वों की सामान्य साइकलिंग बंद हो गई थी।' लेकिन समुद्र की सतह पर भोजन के लिए आने वाले कई जीवों पर इसका असर नहीं पड़ा था, जबकि दूसरे सिद्धांत 'लिविंग ओशियन' के अनुसार, के-पीजी घटना में बड़ी प्लैंकटन प्रजातियां मारी गई थीं और कार्बनिक पदार्थों के चक्र बाधित हो गया था, लेकिन इसके बाद भी गहरे समुद्र में रहने वाले जीव बचे रहे। नए अध्ययन में शोधकर्ताओं ने कहा कि सामूहिक विनाश की घटना में कैल्सीफायर भी प्रभावित हुए थे। सामान्यतः इन जीवों पर अम्ल का ज्यादा असर नहीं देखा जाता। इसका मतलब है कि समुद्र का पानी बहुत ज्यादा अम्लीय होने से ये जीव प्रभावित हुए होंगे।